राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ६५ वां दिवस [संख्या २८

शुक्रवार, दिनांक २२-३-१९६८

विधानसभा की बैठक म. पू. ११ बजकर ४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सामान्य प्रशासन, विधि, कृषि, मुख्य मंत्री कार्यालय, विद्युत, शिक्षा, आयुर्वेद, सहकारी, उद्योग, नियुक्ति व यातायात विभाग)

श्री उपाध्यक्ष :

प्रश्न : माननीय श्री भैरोंसिंह।

सरप्लस कर्मचारी

७४१. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या एफ. १ (२६) जी.ए. । सी. । ६६ दिनांक १३ जुलाई, सन् १९६७ के क्रम में किस-किस विभाग से कितने-कितने कर्मचारियों को सरप्लस घोषित किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है और क्यों ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इनमें कितने भूतपूर्व सैनिक हैं और इनको कब-कब नियुक्त किया गया था ?

(ग) इनके पुनर्वास के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): उपाध्यक्ष जी, इसका पूरा उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया है, और विलम्ब लगेगा क्योंकि काफी जगहों से उत्तर प्राप्त करना है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगित करने में मुझे आपत्ति नहीं है पर इसमें काफी भूतपूर्व सैनिक आ गये हैं और वे दर दर भटक रहे हैं, इनके रिहेबिलिटेशन का प्रश्न है, किसी प्रकार उन्हें जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेट किया जाय यह मुख्य चीज मैं चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके ऊपर हम जल्दी ध्यान दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ७४२।

राजवी श्री रूपसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखें)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ७४३।

Page No. 2

श्री पृथ्वीसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७४४

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चुन्नीलाल जेलिया :

कस्बा खण्डार में बिजली

७४५. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार ने ऐसी नीति अपनाई है कि चार हजार की आबादी वाले ग्राम अथवा तहसील हैड क्वार्टर पर विद्युत दी जावेगी ?

(२) यह निर्णय राज्य सरकार ने कब और किस वर्ष में लिया ?

(३) क्या राज्य सरकार के यह इल्म में है कि कस्बा खण्डार चार हजार की आबादी से अधिक आबादी वाला एवं तहसील हैड क्वार्टर है तथा इसमें थाना एवं अस्पताल व हायर सैकेन्डरी स्कूल भी हैं ?

(४) राज्य सरकार को इस कस्बे में विद्युत दिये जाने में क्या कठिनाई है ?

(५) इस कस्बे को विद्युत कब तक दे दी जावेगी ?

राज्य मंत्री (श्री जयकिशन) : (१) जी नहीं।

(२) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार यह कस्बा चार हजार से कम आबादी का है। अन्य बातें ठीक हो सकती हैं।

(४) अर्थाभाव एवं योजना का लाभप्रद न होना।

(५) निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री चुन्नीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह खण्डार की जनगणना बताई उसके अनुसार खण्डार कस्बे में तहसील हैड क्वार्टर है, थाना, अस्पताल और हायर सेकेन्डरी स्कूल भी है, तो ऐसे कस्बे की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान क्यों नहीं है। ऐसे कस्बे में बिजली लगाना अनिवार्य है फिर भी इस कस्बे की उपेक्षा क्यों की जा रही है। उस कस्बे के ऊपर सरकार कब ध्यान देगी ?

श्री जयकिशन : यह सवाई माधोपुर से ४० किलोमीटर पर है इसलिये ४० किलोमीटर लाइन लाने के लिये जैसे दूसरी ऐसी जगहों के लिये प्रावधान होगा वैसे ही उसके लिये भी कार्य किया जायगा। बिजली हर गांव में होना आवश्यक है, हर गाँव बिजली चाहता है पर बिजली योजनाबद्ध तरीके से जायगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४ हजार की आबादी तक के कस्बों में विद्युत् देने का प्रावधान था ?

श्री जयकिशन : जी नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या ऐसी योजना नहीं है कि तहसील हैड

Page No. 3

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

क्वार्टर्स में बिजली पहुंचाने के लिये प्राथमिकता दी जाय ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : तहसील हैड क्वार्टर्स को बिजली से जोड़ सकना एक अमुक समय में संभव नहीं है क्योंकि कई तहसील हैड क्वार्टर्स आइसोलेटेड जगह पर हैं। तृतीय पंच वर्षीय योजना में ५ हजार तक की आबादी वाले कस्बों को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया था, उसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

(अनेक माननीय सदस्य प्रश्न करने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी पक्ष के नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : धन्यवाद।

मैं तो इतना ही जानना चाहता था कि जनसंख्या को ही पहले प्राथमिकता देते हैं, यह असुविधाजनक प्रश्न है तो भी पूछूंगा सही। पर जनसंख्या को ही प्राथमिकता देते हैं या तहसील हैड क्वार्टर्स हैं उनके सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तो तहसील हैड क्वार्टर्स को प्राथमिकता देना आवश्यक नहीं है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसा कि मैंने निवेदन किया था, तृतीय पंच वर्षीय योजना में सोचा गया था कि पांच हजार की आबादी वाले कस्बों को प्राथमिकता दी जाय पर बाज मर्तबा कई कस्बे एक दम आइसोलेटेड होते हैं, उनको लिया जाय तो अनइकोनोमिकल हो जाता है। रहा सवाल तहसील हैड क्वार्टर्स को जोड़ने का, तहसील हैड क्वार्टर्स को जोड़ने का प्रयत्न तो करते हैं कि इनको जोड़ा जाय, प्राथमिकता दी जाय पर वहां तभी संभावना हो सकती है कि तहसील हैड क्वार्टर जनरेटर से कितनी दूर है।

श्री दौलतराम सारण : क्या इस इलाके में बिलली देने से कृषि उत्पादन की बढ़ने की संभावना नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : हो सकती है, संभावना हो पर धनाभाव के कारण कई स्कीम्स को हाथ में नहीं लिया जाय तो इसको यह नहीं माना जाता।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि इसमें बिजली पहुंचाने से खनिज उद्योग की बड़ी संभावना है ?

श्री हरिदेव जोशी : सारी संभावनाओं से पहला सवाल है धनाभाव का। धन की सबसे पहले आवश्यकता है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि वहाँ बिजली देने से खनिज उद्योगों के पनपने से अर्थ लाभ की बड़ी संभावना है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने उत्तर सुना नहीं उसमें कहा गया कि वह स्कीम अनइकोनोमिकल है इसलिये नहीं लिया।

श्री चुन्नीलाल : क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर से शिवपुरी को इलेक्ट्रिसिटी की लाइन दी गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : ३३ के. वी. लाइन ले जाने का मतलब यह नहीं कि उसको टेप किया जा सके।

राजकीय कन्या विद्यालय बालोतरा का भवन

७४६. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) राजकीय कन्या विद्यालय बालोतरा में कक्षावार छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है और कुल कितनी है ?

(२) इस विद्यालय के भवन में कुल कितने कमरे हैं और किस-किस साइज के ?

(३) क्या राज्य सरकार इस भवन को उपयुक्त और पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो उपयुक्त और पर्याप्त भवन की व्यवस्था कब तक करदी जायगी ?

(४) क्या इस भवन के अभाव के संबंध में स्थानीय जनता अनेक बार प्रार्थना कर चुकी है और मौके पर मुख्य मन्त्री, वित्त मंत्री व भूतपूर्व कृषि मंत्री ने भवन की शीघ्र व्यवस्था करने के आश्वासन भी दिए थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) :

(१) इस स्कूल में लड़कियों की संख्या इस प्रकार हैः—

अष्टम	सप्तम	षष्ठम		पंचम		चतुर्थ	
		अ	ब	अ	ब	अ	ब
१७	२१	२७	२६	२३	२२	४०	३६

तृतीय		द्वितीय		प्रथम			
अ	ब	अ	ब	अ	ब	स	योग
५५	५३	४५	४१	५४	६१	६०	५८४

कुल अध्यापिकायें १० हैं।

(२) कुल कमरे ३ हैं। जिनका नाप इस प्रकार हैः—

२ कमरे १५'×३०') करीबन
१ कमरा १०'×१५')

(३) शाला भवन अपर्याप्त हैं। जिसके लिये उप निदेशक (महिला) के निरीक्षण के दौरान वहां के नगरपालिका अध्यक्ष से परामर्श किया गया एवं उन्हें यह सलाह दी कि जनता के सहयोग से अतिरिक्त भवन व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाय। अभी भवन व्यवस्था अपर्याप्त होने से शाला संचालन दो पारी में होता है।

(४) आश्वासन के अनुसार यथा-सम्भव आर्थिक सहयोग भवन निर्माण के लिये दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री दौलतराम सारण : क्या जनता की तरफ से भवन निर्माणार्थ सहयोग न मिलने पर राज्य सरकार इसकी व्यवस्था नही करेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूरी बिल्डिंग बनाने के बारे में सरकार अभी भी आर्थिक कठिनाई के कारण नहीं कर सकेगी। इस लिए हम जनता के सहयोग की बात आपके सामने रखते हैं और मैं भी जब पिछली बार गया था तो लोगों ने आश्वासन दिया था और उसी आधार पर मैंने उनसे कहा था।

श्री दौलतराम सारण : ठीक है, आर्थिक सहयोग आप माँगें। और जनता सहयोग दे लेकिन जहां आर्थिक सहयोग जनता की तरफ से प्राप्त नहीं हो, तो ऐसी

(श्री दौलतराम सारण)

हालत में राज्य सरकार आवश्यक नहीं समझती कि इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों के लिए केवल तीन कमरों का मकान हो ?

श्री शिवचरण माथुर : जहां इस प्रकार की दिक्कत होती है तो स्कूल को दो पारियों में उपयोग किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन तीन पारियां कर दें तो भी संख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : लेकिन लोग भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं जब वहां गया था तो मुझे बताया गया कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि व्यवस्था की जायगी लेकिन कई वर्षों से यह स्थिति चलती चली आ रही है और व्यवस्था न करना खेदजनक है। अगर एक कमरा एक वर्ष में भी बना दें तो भी स्कूल बन जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

तहसील गोगुन्दा एवं कोटड़ा में आयुर्वेदिक औषधालय

७४७. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील गोगुन्दा व कोटड़ा में कहाँ कहां आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटड़ा के मांडवा ग्राम के औषधालय में व्यवस्था के बारे में विभाग को लिखा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि इस औषधालय में दवाइयों का गबन किया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि का और इसके लिए वैद्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मन्त्री, आयुर्वेद विभाग (श्री कन्हैयालाल) : (१) तहसील गोगुन्दा या कोटड़ा में निम्न औषधालय हैं:—

गोगुन्दा	कोटडा
१—कड़दा	१—गुरां
२—तरपाल	२—बेकरियां
३—नादेश्मा	३—माण्डवा
४—मदराड़ा	४—मालया काचोरा
५—सायरा	५—वास

(२) विभाग में पंचायत समिति कोटड़ा द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) इस औषधालय में औषध गबन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर सुनाई नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवेन्द्र कुमार : बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। फिर से बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर को दुबारा पढ़ें। सदस्यगण शांत रहें।

(मन्त्री महोदय द्वारा दुबारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : समझ में नहीं आता ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मन्त्री महोदय पेट पर पट्टी बंधवालें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम ।

तहसील सुजानगढ़ के ग्रामों में बिजली

७४८. **श्री रावतराम** (छापर-सु.) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के तहत तहसील सुजानगढ़ (जिला चूरू) के कितने गांवों को बिजली देने का प्रावधान है ? गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) पंचायत समिति सुजानगढ़ की ओर से कितने गांवों में बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव सरकार के पास आये हैं ? पंचायत समिति के प्रस्तावों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मन्त्री, विद्युत (श्री जयकिशन शर्मा (१) **अर्थाभाव के कारण सन् १९६७-६८ में नवीन गांवों के विद्युतीकरण हेतु कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है ।**

(२) पंचायत समिति के प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रावतराम : पंचायत समिति के प्रस्ताव की प्रतिलिपि नहीं मिली । आप प्रस्ताव बतादें ।

श्री जयकिशन : मैं प्रस्ताव पढ़ कर सुना सकता हूं लेकिन जो बिजली देने का प्रश्न है वह पंचायत समिति के प्रस्तावों से कोई अधिक सम्बन्ध नहीं रखता है क्योंकि बिजली जो दी जाती है उसके बहुत से कारण होते हैं । अगर आपको इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नजर आती है जिससे कि आपके गांवों में बिजली मिलती हो तो मैं पढ़ कर सुनाता हूं ।

श्री दौलतराम सारण : आपको कोई अच्छी बात नजर नहीं आती ।

श्री जयकिशन : अगर कोई पंचायत समिति एक करोड़ का प्रस्ताव पास करे तो राज्य सरकार के पास इतना धन नहीं है कि पंचायत समिति के हरेक प्रस्ताव को इम्पलीमेंट कर सके ।

श्री दौलतराम सारण : विद्युत देने का क्या आधार बना रखा है ?

श्री जयकिशन : उनके रिटर्न्स, आस-पास में बिजली और दूसरे साधनों को देखा जाता है ।

श्री रावतराम : मेरा प्रश्न था कि क्या पंचायत समिति सुजानगढ़ से कोई प्रस्ताव आया । आपने कहा कि आया । तो आपके पास और किसी पंचायत समिति का है नहीं यही एक है । दूसरी बात क्या इस चालू साल के लिए इस पंचायत समिति एरिया सुजानगढ़ तहसील में विद्युतीकरण योजना के लिए कोई आपके पास प्रावधान है ?

श्री जयकिशन : १९६७–६८ में विद्युतीकरण के लिए ग्रामों के अन्दर कोई ऐसी योजना इस पंचायत समिति के लिए नहीं है।

श्री रावतराम : मैं १९६८-६९ के लिए पूछ रहा हूं।

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : १९६८-६९ के लिए जब नया बजट स्वीकार होकर और उसके अन्दर जो प्रावधान लोनिंग एजेन्सीज द्वारा लोन का जो है वह कमिटमेंट जब तक न हो तब तक कोई नई योजना नहीं बन सकती।

श्री रावतराम : १९६८-६९ में ग्रामों में विद्युतीकरण के लिए कितनी रकम है ?

श्री हरिदेव जोशी : २५ लाख।

श्री दौलतराम सारण : चूरू के लिए प्रावधान है ?

श्री हरिदेव जोशी : कोई ब्रेक अप आज तक नहीं किया है।

श्री दौलतराम सारण : योजना बनाने के खर्चे का अनुमान नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : मगर सवाल है कि पैसा कितना मिलेगा ? जैसे वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम चाहते हैं कि लोनिंग एजेन्सीज से लोन मिले और वह सम्भव है मिल जाय। लेकिन तब तक सम्भव नहीं है जब तक उनका कमिटमेंट न आ जाय।

श्री दौलतराम सारण : क्या आपने कोई फेज्ड प्रोग्राम तय नहीं किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : फेज्ड प्रोग्राम फंड्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। जब तक वह चीज नहीं आती है तब तक प्रायोरटी तय नहीं होती।

श्री दौलतराम सारण : आप प्रायोरटी तय न करें लेकिन आपने कोई योजना तो बना रखी होगी, फेज्ड प्रोग्राम तय किया होगा, इसके बाद यह, इसके बाद वह। आप कह रहे थे कि कुछ आधार हैं विद्युत देने के, तो उसके अनुसार फेज्ड प्रोग्राम बना रखा होगा।

श्री हरिदेव जोशी : उसके अनुसार कमिटमेंट नहीं की जा सकती है।

श्री दौलतराम सारण : क्या आपका फेज्ड प्रोग्राम है ? कोई प्रोग्राम नहीं है ? केवल एक लम्प सम।

श्री हरिदेव जोशी : जब तक फंड्स अवेलेबल नहीं हो जाते हैं...

श्री दौलतराम सारण : इसमें आपका कोई प्रोग्राम है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : अगले वर्ष का प्रोग्राम पैसे की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

श्री दौलतराम सारण : खेदजनक स्थिति है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हजारों रुपए खर्च हुए हैं।

प्रश्न संख्या ७४९

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत गाड़िया !

Page No. 8

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विशनोई !

शिक्षा विभाग का मासिक पत्र

७५०. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग का विभागीय गजट "शिविरा" एक मुख्य मासिक पत्र है ? अगर हां तो वह किस उद्देश्य से निकाला जाता है ? इसका सालाना औसत खर्च एवं आमदनी क्या है।

(२) इस पत्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिये शिक्षा विभाग क्या-क्या कदम उठा रहा है ? तथा इसके विकास के लिये अब तक क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

(३) इस पत्र में शिक्षकों के अच्छे लेख आकर्षित करने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

(४) क्या यह सत्य है कि इस पत्र के फरवरी १९६६ के अंक में परीक्षाएं एवं उनका रूप, एवं जुलाई अगस्त १९६७ के अंक में प्रौढ़ शिक्षा एक समस्या एवं समाधान नामक लेख किसी शिक्षक द्वारा दिये गये थे ? अगर हां, तो इन समस्याओं के बारे में शिक्षा विभाग द्वारा क्या सक्रिय कदम उठाये गये हैं ? क्या इस शिक्षक को इन लेखों के लिये प्रोत्साहन देने हेतु कोई पुरस्कार दिये गये थे ? अगर हां, तो क्या क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या शिक्षा विभाग शिक्षकों द्वारा आज की शिक्षा की पद्धति एवं उसमें सुधार की आवश्यकता के बारे में स्वतन्त्र रूप से लेख आकर्षित करने के लिये कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखता है ? अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(६) लेख लिखने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन हेतु क्या-क्या पुरस्कार दिये जाने की योजना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिव चरण माथुर): (१) जी हां। उद्देश्य विभागीय रीति नीति, नियम, आदेश आदि की अध्यापकों को जानकारी व विभागीय रीति नीति के निर्धारण में विचारशील शिक्षकों, शिक्षाविदों व शिक्षाधिकारियों का सक्रिय योग, देश विदेश की शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी, विशेषज्ञों तथा अनुभवी शिक्षकों द्वारा लिखित अन्य रचनाओं द्वारा शिक्षक का अनवरत सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण। शैक्षिक लेखन की ओर अध्यापकों की रुचि को मोड़ना व प्रोत्साहित करना। सालाना औसत खर्च ६०,००० रुपये और आमदनी ६०,००० रुपये है।

(२) पत्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिये अध्यापकों को कम मूल्य में पत्रिका दी जा रही है। अधिक से अधिक अध्यापक ग्राहक बने इसके लिये समय-समय पर उनसे अपील की जाती है और विभागीय पत्रिकाओं में विज्ञापन द्वारा तथा परिपत्रों के माध्यम से पत्र की उपयोगिता समझाई जाती है। सामग्री, साज सज्जा व मुद्रण आदि का स्तर उत्तरोत्तर ऊंचा व श्रेष्ठ बनाया जा रहा है। अध्यापकों की रचनाओं को स्थान दिया जा रहा है। सीधी बातचीत के अन्तर्गत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु अपर निदेशक द्वारा शिक्षकों के प्रश्नों के

Page No. 9

(श्री शिवचरण माथुर)

उत्तर सीधे दिये जाते हैं। आदि।

(३) रचनाएं बराबर आमंत्रित की जाती हैं, पत्रिका में सूचना देकर भी और व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर भी लेखकों को उचित पारिश्रमिक दिया जाता है।

(४) यह सत्य है। प्रत्येक लेख में प्रस्तावित सुझावों पर कदम उठाना विभाग के लिये आवश्यक या सम्भव नहीं है। ये विचार या सुझाव व्यक्तिगत होते हैं। पत्रिका सृजनात्मक चिन्तन का साधन है और एक वैचारिक मंच के रुप में कार्य करती है। विभाग शिक्षक लेखकों के व्यक्तिगत विचारों व सुझावों को सार्वजनिक हित की सम्भावना को दृष्टि में रखकर प्रकाश में लाता है। प्रकाशित विचारों का कहां कैसे उपयोग हो यह सम्बंधित शिक्षकों, शिक्षाविदों व शिक्षाधिकारियों के ही निर्णय की बात है। प्रसंगान्तर्गत प्रकाशित लेखों पर पारिश्रमिक क्रमशः २५ और ३० रुपये मन्जूर किया गया है।

(५) आज की शिक्षा पद्धति के सुधार हेतु स्वतंत्र रुप से लेख आमंत्रित करने को नया शिक्षक के कई विशेषांक तथा दृश्य श्रव्य शिक्षा, मुरजांकन, प्रोढ़ शिक्षा, निदेशन, शिक्षक प्रशिक्षण आदि प्रकाशित किये जा चुके हैं और अप्रेल १९६९ तक की योजना शिक्षक में प्रकाशित हो चुकी है, अर्थात् जनवरी १९६८ का अंक शिक्षक संगठनों पर आ रहा है, अप्रेल में शिक्षा के सामाजिक आधारों पर विचार होगा, इसी प्रकार उसके बाद जुलाई १९६८, अक्टूबर १९६८, जनवरी १९६९ व अप्रेल १९६९ के चार अंकों में विद्यालय संगम कक्षा प्रयोग, स्वायत्त विद्यालय तथा शिक्षा में आधुनिकता विषयों पर विशेष रूप से तथा अन्य विषयों पर भी लेख प्रकाशित होंगे। अधिक अच्छे लेखक आकर्षित हों इसके लिये उचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

(६) रचनाओं में अनुवाद के लिये पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके प्रोत्साहन के लिये स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित किये गये हैं या किये जा रहे हैं और किये जाने की योजना चालू है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो लेख आते हैं और उस पत्रिका में लेते हैं उसके लिए कमेटी है क्या ? कौन विचार करता है कि यह लेख छापा जाय ?

श्री शिवचरण माथुर: संपादकीय मंडल है, सारे लेखों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, लेखों का प्रकाशन पत्रिका में करता है। मैं मानता हूं कि यह पत्रिका शिक्षकों व दूसरे शिक्षा संबंधी लोगों में काफी लोकप्रिय है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि आपने जो उद्देश्य बताए हैं, उसकी पूर्ति के लिए जितना इस पत्रिका का विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ ?

श्री शिवचरण माथुर: साधनों की दृष्टि से जितना विकास संभव है, किया जा रहा है और आगे भी काफी संभावना मौजूद है, हम साधनों को एक्स्प्लोइट करने को तैयार हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई: आपकी तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं है इसलिए आज अच्छे शिक्षकों के लेख नहीं आते।

श्री शिवचरण माथुर: जहां तक संभव हो सकता है अच्छे लेखों के लिए अच्छा

(श्री शिवचरण माथुर)

पारितोषिक दिया जाता है। इरादा है कि अच्छे लेख आएं और उनकी उपयोगिता को देखकर और अधिक पारितोषिक दिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका मूल्यांकन कौन करता है, कोई समिति है ?

श्री शिवचरण माथुर: विभाग करता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: तो फिर प्रगति हो गई। आपका विभाग शिक्षकों द्वारा विभाग की आलोचना पसंद करेगा क्या ? इसके लिए कोई नानआफीशियल बोडी हो जो इन लेखों का मूल्यांकन करे जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

श्री शिवचरण माथुर: मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं नहीं मानता कि इस पत्रिका में अच्छे लेख नहीं छपते। यह पत्रिका शिक्षकों में काफी पापुलर हुई है, इसकी मांग बढ़ती जा रही है।

श्री मूलचंद डागा: क्या इस प्रकार की जो पत्रिका निकलती है उसका विशेष अंक माननीय सदस्यों के लिए उपलब्ध करने की जरूरत है।

श्री शिवचरण माथुर: पैसे देंगे तो आपको भी मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचंद बाफना।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मेरा प्रश्न नं० ७४९ रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : समय बच जायगा तो ले लेंगे। श्री फूलचंद बाफना।

पाली जिले में कुड आयल की कमी

७५१. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में करीब १५०० पम्पिंग सेट लगे हुए हैं परन्तु गत १२ महीनों से उन्हें कुड आइल-नियमित रुप से नहीं मिल पा रहा है और यदि मिलता भी है तो निश्चित दर से बहुत ऊंची दर से हाथ आता है।

(२) क्या यह सही है कि ऊंची दर से कुड अइल मिलता है तब भी उसके साथ कुड आइल लेने वालों को लुब्रिकेशन आइल जबरदस्ती दिया जाता है ?

उप मंत्री, उद्योग(श्री भीमसेन) : (१) बीच में थोड़ी कठिनाई आ गई थी। अब यह पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य सरकार के पास ऊंचे दर से बेचने के सम्बन्ध में शिकायत नहीं आई है।

(२) जी नहीं ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार के पास नहीं आई।

श्री फूलचंद बाफना : सरकार के पास शिकायत नहीं है लेकिन परिस्थिति इस तरह की जरूर है।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जब सरकार के पास शिकायत नहीं आई तो मैं क्या कह सकता हूं लेकिन मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार पिछले वर्ष के अंदर १९६६-६७ में सोजत रोड और रानी में जो दो डिपोज हैं वहां सोजत रोड

(श्री हरिदेव जोशी)

में २४० किलो लिटर और रानीमें १४५ किलोलिटर क्रूड आइल दिया गया और इस साल सोजत में ९४४ और रानी में ३४२ किलोलिटर पहुंचा है। डबल से भी ज्यादा पहुंचा है फिर तो कमी नहीं होनी चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई: माँग कितनी थी ?

श्री फूलचंद बाफना : लुब्रिकेशन आइल लेना भी उसको साथ जरूरी है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी: इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं आई।

श्री उपाध्यक्षः श्री जयनारायण सालोदिया।

शिक्षा निरीक्षक करौली द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

७५२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा निरीक्षक करौली ने नवम्बर १९६६ से अगस्त सन् १९६७ तक बिना एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे तीन बार में करीब २०० अध्यापकों की नियुक्ति की जिससे योग्य, पुराने, ट्रेन्ड अध्यापक नौकरी पाये बिना रह गये ? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत किस मजबूरी में ?

(२) क्या यह सही है कि बाद में शिक्षा निरीक्षक ने एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज को लिखा कि उनको २०० ट्रेन्ड अध्यापक चाहिए जिस पर एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज ने जिन अध्यापकों को पहले ही शिक्षा निरीक्षक ने ले लिया था उनके नाम भेज दिये और उनकी नियुक्ति बाद में नियमानुसार की गई ?

(३) क्या यह भी सही है कि जिन अध्यापकों को नवम्बर १९६६ से अगस्त १९६७ तक बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के निरीक्षक ने रखा था उनको इन महिनों का वेतन अब तक नहीं मिल रहा है क्योंकि एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज उनको एक्स श्री फार्म नहीं देता है, इसलिये अध्यापक परेशान हैं ? क्या सरकार उनकी परेशानी दूर करने के लिये कदम उठायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (१) जी हां, ऊपर निदेशक के आदेशानुसार सीधे आवेदन पत्र मांगे गये। आवेदन पत्रों पर मेरिट के अनुसार अग्रिम रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई। इनमें पुराने योग्य अनुभवी अध्यापक भी आ गये। पुराने अध्यापक केवल मेरिट अंकों अथवा अपूर्ण प्रार्थना पत्रों के कारण ही रह सकते हैं।

(२) जी हां।

केवल नवम्बर १९६६ अथवा नियुक्ति के प्रथम माह के कुछ दिनों के वेतन न मिलने का मामला नियोजन विभाग से विचाराधीन है। शिक्षा विभाग इसमें प्रयत्नशील है।

श्री जयनारायण सालोदिया : किन परिस्थितियों में एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज से नहीं पूछा और सीधी भर्ती कर दी ?

श्री शिवचरण माथुर : इस सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी किया गया था और प्रेस्काइब्ड फार्म में एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज

(श्री शिवचरण माथुर)

का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें दर्ज होता है और जिस अध्यापक का नंबर उसमें नहीं होता है तो उसकी दरख्वास्त रद्द की जाती है इसलिए आवश्यक है कि नियोजन कार्यालय के मार्फत होकर आते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो २०० अध्यापक भर्ती किए गए वे नियोजन कार्यालय के मार्फत थे ?

श्री शिवचरण माथुर : प्रेसक्राइब्ड फार्म में कालम हैं उसमें नियोजन कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना पड़ता है। उसका मतलब वह उसके मार्फत आया है इस लिये उनका नियोजन कार्यालय के मार्फत आना ही माना जा सकता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : दो नंबर में आपने जी हां कहा है । फिर नियोजन कार्यालय से नाम क्यों मांगे गए ? आपने कहा कि फार्म में जो कालम है और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें तो पर्याप्त है, फिर बाद में उनके नाम क्यों मांगे गए ?

श्री शिवचरण माथुर : कोई एम्पलायमेंट एक्सचेंज से टैली करने में हर्ज है क्या ? उसमें २०० अध्यापक एम्पलायमेंट एक्सचेंज के मार्फत आए, इसलिए उनको मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक एक अध्यापक से ५००) ५००) रुपए लेकर सीधी भर्ती की गई और जिन लोगों के नाम नियोजन कार्यालय में बरसों से पड़े हैं उनको नहीं लिया गया। जो लोग क्लर्कों और निरीक्षकों से मिले और ५००)५००) उनसे लिए हैं उनकी सीधी भर्ती की गई।

श्री शिवचरण माथुर : कोई वेग आरोप लगाने से मतलब सिद्ध नहीं होता। आपके पास शिकायत हो तो लिखकर दें किसने ५००) रुपए दिए और किसने लिए तो मैं जांच कराऊंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह बिल्कुल स्पष्ट है और कार्यवाही से साबित होता है। नियोजन कार्यालय में हजारों अध्यापकों की लिस्ट ५ साल से पेंडिंग है और उन्होंने बाद में भी शिक्षा प्राप्त की है उनको नहीं लिया गया और जो मैट्रिक ट्रेन्ड नहीं उनको सीधा ले लिया गया।

श्री शिवचरण माथुर : आपके पास शिकायत हो तो बताएं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं कह रहा हूं, मेरे पास शिकायत है। यह करौली के शिक्षणालय का इन्सपेक्टर है। यह इस काम के लिये बदनाम है। इसके लिये यहां हाउस में भी प्रश्न उठा था। पोस्टर निकले हैं उनके खिलाफ छूआछूत के आरोप भी हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो सीधी भरती की गई है उनसे खुले रूप से रुपया लिया है।

श्री शिवचरण माथुर : आप स्पष्ट आरोप लगा कर मुझे दे दीजिये, मैं इन्क्वायरी करा लूंगा। वैसे सीधी भरती में कोई अनियमितता नहीं हुई है। जो भी प्रेस्क्राइब्ड फार्म में एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज के नम्बर के उल्लेख करने का खाना है वह इसेंशियल है। अब नियुक्तियां पैसा लेकर की गई हों तो आप

(श्री शिवचरण माथुर)

स्पेसिफिक कोई उदाहरण दें, मैं निश्चित रूप से आश्वासन देता हूं कि उसकी जांच की जावेगी ।

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर उनका वेतन क्यों रुका हुआ है ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं समझता हूं यह नीति का प्रश्न है और ऐसी आम शिकायतें हैं कि सरकार की नीति भी तो होनी चाहिये । फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ड कोई प्रायोरिटी होनी चाहिये । नयों को रख लेते हैं, पुरानों की सुनवाई नहीं करते । फिर भ्रष्टाचार तो स्पष्ट ही है । पहले वाले को लटकता रख दिया, बाद वाले को रख लिया, यह तो पक्षपात की नीति स्पष्ट है ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस सिलेक्शन के और नियुक्ति के लिये नीति है और नियम हैं । मैरिट पर लेते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज की मार्फत जो लिस्ट आती है उसी में से सिलेक्शन हो सकता है । डाइरेक्ट किसी को भी नहीं लिया जा सकता यह सरकार की निर्धारित नीति है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह निश्चित रूप से सही है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर आप जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनको सजा देने को तैयार क्यों नहीं है जिन्होंने सीधी भरती की ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री शिवचरण माथुर : आप समझने की कोशिश करिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : समझ कर ही तो निवेदन किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समय लिया गया है इसमें ।

श्री शिवचरण माथुर : जो भी आवेदन पत्र आये उनमें एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज के नम्बर थे ।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह कोई वेल्यू नहीं रखता । एम्पलोयमेंट की लिस्ट से ही आप ले सकते हैं, ऐसे आदेश हैं ।

श्री श्रवणलाल : जिस तरह से सवाल का उत्तर दिया गया इससे साफ है कि इस शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से व्याप्त है । इस पर समय समय पर यहां चर्चा की जा चुकी है । यहां सवाल इस बात का है कि एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज से आपने लिस्ट क्यों नहीं ली । यहां तो हमेशा ऐसी धांधलीबाजी चलती है ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य ।

श्री श्रवणलाल : अब आप कहते हैं कि फार्म में रजिस्ट्रेशन नम्बर का खाना था, अब अगर वह था तो फिर आपने लिस्ट क्यों मांगी । इसके अलावा बगैर ट्रेनिंग पास किये लोगों को भी लिया गया है और ट्रेन्ड को दर गुजर किया गया है इससे साफ जाहिर है कि रिश्वतें लेकर लोगों को नियुक्तियां दी गई हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : इस प्रश्न के दो पहलू सामने आ रहे हैं। एक यह कि एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज के थ्रू लिया गया या नहीं। इसके लिये हमारे आवेदनपत्र में कालम है जिसमें रजिस्ट्रेशन नम्बर देना आवश्यक है।

दूसरा यह कि क्या रिश्वत लेकर अपोइन्टमेन्ट दिये गये। इस बात की आप शिकायत कीजिये, नाम लीजिये किसने ली हम एक्शन लेंगे, जांच करेंगे, किसी को छिपाने का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि बिना एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज की लिस्ट के डाइरेक्ट भरती नहीं की जा सकती फार्म में कालम देकर भी नहीं की जा सकती।

श्री विजयसिंह रावत : मैं जानना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, कि जो यह दलील दी गई कि फार्म में कालम था पर उसमें भी आपने सीरियल नम्बर वालों को न लेकर ६३, ६४ और ६५ वाले एस टी सी ट्रेण्ड तक को न लेकर ६५, ६६ वालों को लिया है। और दूसरा......

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री विजयसिंह रावत : यह आरोप लगाया गया कि एक एक टीचर से पांच पांच सौ रुपया लेकर भरती किया गया और यह कहा कि शिकायत आवेगी तो जांच कर लेंगे। यह न्यायोचित नहीं है। जब माननीय सदस्य चुनौती देते हैं तो आप इसी आधार पर जानकारी करें, जांच करें और इस पर जो जो अधिकारी दोषी पाये जावें उनको दण्ड दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आपने संक्षेप में निवेदन कर दिया। अब अपना स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत : पर आप यह न करके सदन को गलत सूचना देते हैं, गुमराह करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार जी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि रिश्वत के मामले साबित होने असम्भव है......

श्री रघुनाथ विश्नोई : असम्भव तो नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वैसे असंभव कुछ नहीं होता, पर बहुत मुश्किल जरूर कहा जा सकता है और जिस तरह से रिश्वत देना लेना चला है उस आधार पर मालूम करना भी बहुत मुश्किल है। मान लिया जावे दो अध्यापकों की योग्यता बिलकुल एक सी है, समान है उस समान योग्यता में एक दफा भी आप बता दें आपने कभी लाट ड्रा किया है। यह निष्पक्षता होती। पर यहां तो आपने बिड को प्रोत्साहन दिया जो रुपया ज्यादा देगा उसको प्राथमिकता दे देते हैं। एक निष्पक्षता सिद्ध करने के लिये मेरे ख्याल में दो तीन उदाहरण भी तो आप ऐसे दीजिये कि कभी आपने समान योग्यता वालों में से छांटने के लिये कभी लाट्स ड्रा किया हो। जैसा हम करते हैं चुनावों के सम्बन्ध में।

Page No. 15

श्री केदारनाथ : एम्पलोयमेन्ट एक्स-चेन्ज से हर व्यक्ति को ३ एक्स कार्ड लेना अनिवार्य है क्या इन में से सब ने ये कार्ड लिये थे ?

श्री शिवचरण माथुरः हमने इस मामले में इसके लिये एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज से बैठकर चर्चा की है। वैसे भी एक्स कार्ड लेना आवश्यक है । पर हमारी कोई मंशा नहीं है किसी भी करप्ट अफसर को शील्ड करने की पर कोई हमारे पास स्पेसिफिक शिकायत हो तभी तो जांच करनेवाली बात सामने आती है । जनरल तौर पर कह देना कि सारी की सारी नियुक्तियाँ पैसा लेकर हुई हैं, यह ठीक नहीं मालूम पड़ता।

श्री जयनारायण सालोदियाः एक प्रश्न ।

श्री उपाध्यक्षः अब आपने बहुत प्रश्न पूछ लिये । १५ मिनिट ले लिये एक एक प्रश्न में ।

श्री जयनारायण सालोदियाः क्या शिक्षा मन्त्री यह बतावेंगे कि श्री एक्स कार्ड उनको पहले नहीं मिले थे, आपने इनके बिना ही अपोइन्टमेन्ट दे दिये, और जब अब उनका पेमेन्ट रुक गया है तो आप अब उनके लिये प्राप्त कर रहे हैं ये श्री एक्स कार्ड हालांकि कइयों को अभी भी नहीं मिल पाये हैं । आप के अधिकारी पहली की डेट में ये कार्ड मांग रहे हैं और एम्प्-लोयमेन्ट एक्सचेन्ज विभाग इसके लिए तैयार नहीं है । इसके सम्बन्ध में आपका क्या कहना है । क्या आप उनको हटा-वेंगे ?

श्री शिवचरण माथुरः श्री एक्स कार्ड के बिना नौकरी पर नहीं लिया जा सकता। इससे इन्कार नहीं हूं । पर श्री एक्स कार्ड मिल जाते हैं तो नियुक्तियां वैध हैं इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : ६६ का मामला है यह उपाध्यक्ष महोदय । पर आज तक श्री एक्स कार्ड नहीं मिल पाये हैं । फिर आपको क्या कहना है ?

श्री उपाध्यक्षः अगला प्रश्न ।

श्री श्रवणलाल: मामला गम्भीर है उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री जयनारायण सालोदिया: ये मन्त्री महोदय चुप्पी लगाकर बैठे हैं एन्क्वायरी करावेंगे आप उत्तर क्यों नहीं देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: अगर आपको इसमें डाउट है तो नियमों में प्रावधान है । और किसी तरह से प्रश्न को उठा सकते हैं । बहुत से प्रश्न अभी बचे हुए हैं । इसलिये इसको यहीं समाप्त किया जाता है ।

श्री विजयसिंह रावत: आसन की ओर से कोई प्राटेक्शन नहीं होता है ऐसे गम्भीर मामलों पर । आपकी ओर से आदेश होने चाहिए कि आप इस पर जांच कीजिए श्री एक्स नहीं मिला उसके अन्दर घोटाले हैं ।

श्री जयनारायण सालोदियाः दो साल हो गये हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती है...

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन कर दूं......

श्री उपाध्यक्ष ; आर्डर प्लीज अगला प्रश्न पूछ लिया है ।

श्री शंकरलाल

प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था

७५३. **श्री शंकरलाल (जैतारण):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था पंचायत समितियों के आधीन रहने से बिगड़ी है ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के आधीन प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक और विद्यार्थी पंचायत समितियों के प्रशासन से बहुत असंतुष्ट हैं ?

(३) क्या सरकार प्राथमिक शालाओं को पंचायत समितियों के प्रशासन से हटाने पर विचार कर रही है ?

(४) क्या सरकार प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं को जिला परिषद के आधीन रखने पर विचार करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) :

(१) पूर्णतः यह कहना तो असत्य होगा कि प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था पंचायत समितियों के आधीन रहने से बिगड़ी है क्योंकि शिक्षा में विस्तार तथा साधनों की न्यूनता के कारण संभव है अपेक्षित व्यवस्था पंचायत समितियों द्वारा नहीं हो सकती हो ।

(२) यह बात राजस्थान के प्रत्येक भाग के लिए सही नहीं कही जा सकती । कहीं कहीं से पंचायत समिति के अध्यापकों में असन्तोष की भावना प्रतिलक्षित होती है ।

(३) सरकार का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(४) सरकार का ऐसा भी कोई विचार नहीं है ।

श्री शंकरलाल : जब सरकार इसको स्वीकार करती है कि पंचायत समितियों के आधीन प्राथमिक शालाओं की स्थिति बिगड़ी है तो सरकार उसकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री शिवचरण माथुर: मैंने निवेदन किया कि पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्था बिगड़ी है लेकिन कहीं कहीं शिकायतें आती हैं उनको सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिए बजाय इसके कि उनको पंचायत समितियों से निकाल लें सुधारने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं बहुत जल्दी ही जिला परिषदों के प्रमुख और शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा और क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं और किस प्रकार से उनको सुधारा जा सकता है इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके टीचर्स केवल चुनाव प्रचार करने के लिए और राजनैतिक पार्टियों......

श्री उपाध्यक्ष: अलग प्रश्न । नैक्स्ट श्री विजयसिंह मकराना !

श्री मूलचन्द डागा: क्या सरकार यह निश्चित करती है कि जहां जहां नगरपालिकायें हैं उन नगरपालिकाओं को प्राथमिक पाठशालायें देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री उपाध्यक्ष: अलग प्रश्न है श्री विजय-सिंह मकराना।

श्री रामनारायण चौधरी: क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि स्थिति बिगड़ी है जैसा कि उन्होंने माना भी है और कहा है कि शिकायतें आई हैं तो शिकायत होना एक अलग बात है और स्थित बिगड़ना अलग बात है।

श्री शिवचरण माथुर: स्थिति बिगड़ी है ऐसा नहीं माना जा सकता है। हां, कहीं कहीं शिकायतें आई हैं और उनके ऊपर विचार करना जरूरी है।

श्री दौलतराम सारण: क्या यह सही है कि सरपंच की और प्रधान की इन प्राथमिक शालाओं में कोई दखलन्दाजी नहीं है केवल बी०डी०ओ० ही उनमें दखलन्दाजी करते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर: जी नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह; उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह प्राईमरी एजूकेशन का मखौल किया जा रहा है यह एक बड़ी दुखद समस्या है। मेरे ख्याल से शिक्षा एक महान महत्वपूर्ण चीज है और इसका संबंध राष्ट्र के निर्माण से है यह प्राथमिक शिक्षा का इस तरह से मखौल करके पंचायतों को देकर अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चारित्रिक निर्माण और भविष्य निर्माण हमारे समाज का और राष्ट्र का बिल्कुल बिस्मार आप कर रहे है। शिक्षा मंत्रीजी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अर्थ का अनर्थ कर रहे है। क्या हो रहा है ? यह एजूकेशन नहीं है। जब तक आप शिक्षक को स्थान समाज में नहीं देते मैं तो लम्बी चौड़ी लेक्चरबाजी नहीं करना चाहता हूं। यह तो सामान्य व्यवस्था है, इसमें अर्थ का अनर्थ है और मेरे ख्याल से कोई लाभ नहीं है इस तरह की एजूकेशन से।

श्री दौलतराम सारण: प्राथमिक शिक्षा निर्वाचित पंचायत समिति के अधीन रहने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह केवल मखोलबाजी है और नारेबाजी है, पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सर्विसेज के नियंत्रण में वहां की शिक्षण संस्थायें हैं। बिलकुल यह मखोलबाजी को बात है।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री विजय-सिंह मकराना।

श्री विजयसिंह (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्या गलती की जो मुझसे आपने दस ऊठक बैठक करवादी। क्या मुख्य मंत्री जी से प्रश्न पूछना भी गुनाह है ?

प्रश्न संख्या ७५४.

एस. डी. ओ. की पदोन्नति

७५४. **श्री विजयसिंह (मकराना):** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि श्री सुखदेव आर्य को एस. डी. ओ. मेड़ता ग्राम चुनावों के २-३ माह पूर्व लगाया गया ?

(२) क्या यह सही है कि सन् ६७ के ग्राम चुनावों में वे ही मेड़ता निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर भी रहे ?

(३) क्या यह सही है कि उन्होंने ग्राम

(श्री विजयसिंह)

चुनावों में मत गणना में भारी पक्षपात किया जिसकी शिकायत वर्तमान एम. एल. ए. मेड़ता ने मुख्य सचिव, राजस्थान, चुनाव आयुक्त राजस्थान, जिलाधीश नागौर व चुनाव आयुक्त भारत सरकार को की ?

(४) क्या यह सही है कि माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने श्री नाथूराम मिर्धा द्वारा की गई चुनाव याचिका के फैसलों में श्री आर्य के खिलाफ पक्षपात करने, झूठ बोलने, अनियमितता करने के आक्षेप लगाये हैं ?

(५) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने श्री आर्य की पदोन्नति करके उन्हें ए. डी. एम. नागौर बना दिया है ?

(६) क्या राज्य सरकार श्री आर्य को बरखास्त कर उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (१) इनकी नियुक्ति २-११-६६ को की गई।

(२) जी हां।

(३) इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

(४) राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है अतः जो रिमार्क्स फैसले में दिये गये हैं उनके बारे में जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।

(५) नियमानुसार वरिष्ठता के आधार पर इन्हें अस्थायी रूप से अतिरिक्त कलेक्टर नागौर नियुक्त किया गया है।

(६) जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय नहीं हो इस संबंध में कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि जिस किसी भी आर. ए. एस. या आई. ए. एस. अधिकारी को हाईकोर्ट के द्वारा......

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दिया है।

श्री विजयसिंह रावत : स्ट्रिक्चर पास किये जायें और उसको पदोन्नति किया जाये क्या इसको आप उचित समझते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने उत्तर सुना नहीं।

श्री विजयसिंह रावत : सुना है।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर समझा नहीं।

श्री विजयसिंह रावत : हाईकोर्ट के रिमार्क्स हैं और जब कि एक कोर्ट ने एडवर्स रिमार्क्स दिये हैं तो किस आधार पर पदोन्नति की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिया गया है और जो हाईकोर्ट के मामले में रिमार्क्स हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील पेन्डिंग होने से कोई इन्क्वायरी नहीं करा सकते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रमोशन के मामले में तो उपाध्यक्ष महोदय मैं सरकार के डिस्क्रिशन का क्वेश्चन नहीं,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करता लेकिन एक तरफ हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर्स हों और उसके साथ ही साथ एकदम सीनियोरिटी की लिस्ट को लेकर पदोन्नति की जाती है यह व्यवस्था क्या शोभनीय है सरकार के लिए या यह व्यवस्था यह मैं कहूं कि लोगों को बताने के लिए कि हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर्स हैं वह बलाये ताक रखे जाते हैं और हम तो पदोन्नति करेंगे क्योंकि यह हमारा आदमी है और हमारे कहने के माफिक चलता है। अगर यह भावना लेकर किया गया है तो सरकार के लिए यह शोभनीय चीज नहीं है। यह तो रूल आफ ला है। आखिरकार हाईकोर्ट का कोई इन्टरिम जजमेन्ट है, एक स्टेज खतम होती है उस को इग्नोर करके पदोन्नत करना चाहें मुख्य मंत्री जी आपके लिए शोभायमान नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं निवेदन करूं कि इसमें शोभायमान का प्रश्न खड़ा नहीं होता। जो न्यायोचित बात है वही की जानी चाहिए और जब कि हाईकोर्ट का स्ट्रिक्चर या जो भी रिमार्क्स हैं जिस समय में जिस वजह से दिये वे सुप्रीम कोर्ट में पेन्डिग है उसकी वजह से किसी को सजा दी जाये प्रमोशन नहीं देकर कि जो सीनियोरिटी केस पर आम तौर से प्रमोशन्स दिये जाते हैं और यह प्रमोशन दिया गया है एडहाक बेसिस पर याने टेम्पोरेरी है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता है इस सम्बन्ध में उनका प्रमोशन रोका नहीं जा सकता है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह भी निवेदन करदूं कि इलेक्शन कमीशन ने पहले उन रिमार्क्स के बारे में इनक्वायरी करने के लिए लिखा था लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अन्दर अपील दायर हुई तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ने कहा कि जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता है फरदर इन्क्वायरी नहीं कि जानी चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: साउन्ड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिन्सिपल्स पर यह कामनसेन्स का प्रपोजीशन है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं हो तब तक क्या पदोन्नति रुकी नहीं रह सकती थी या अगर आपका डिस्क्रिशन सुप्रीम है वह तो है ही आपके हाथ में। आप जो चाहें कर सकते है लेकिन साउन्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई चीज है। बेसिक कामनसेन्स के प्रिन्सिपल के अनुसार मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट के डिसीजन को इस तरह फलाउट करना और पदोन्नति करना आप समझते हैं कि यह आपके लिए शोभनीय है? यह साउन्ड कामनसेन्स के प्रिन्सिपल्स के विपरीत है।

श्री भैरोंसिह: क्या यह सही है कि श्री सुखदेव मिर्धा की तरफ से इन स्ट्रीक्चर्स को रिमूव करने के लिए अलग से कोई अपील दायर नहीं कि गई और यह भी सही है कि जो इलेक्शन पिटीशन की गई हैं उसमें एस० डी० ओ० के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये गये हैं उनको डिलीट कराने के लिए कोई बात नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष: सुखदेव आर्य है मिर्धा नहीं।

श्री भैरोंसिह: हैं तो मिर्धा ही लेकिन आर्य लिखते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह कनेक्टेड मेटेरियल है। इसलिए जब वहां से फैसला

Page No. 20

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होगा उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करती है कि फर्दर इन्क्वायरी की जा सकती है और तभी निर्णय किया जा सकता है अगर हम आज उनकी वजह से इनको सजा देने की कार्यवाही कर देते हैं तो उसका असर उसकी अपील पर भी पड़ता है...

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन्होंने अपनी पिटीशन के अन्दर इस प्रकार की प्रेयर नहीं की है कि इन स्ट्रिक्चर्स को डिलीट किया जाय तो इन स्ट्रिक्चर्स पर आर्ग्यूमेंट करने का सवाल ही नहीं पैदा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इनके लिए जरूरी नहीं है कि ये अपील करें कि स्ट्रिक्चर्स को रिमूव किया जाय। अगर हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है अगर वह डिवीजन ही चैन्ज होता है तो सारे सरकम्स्टान्सेज ही बदल जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : डिसीजन दूसरे पाइन्ट पर है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मुख्य मन्त्रीजी कृपया यह उत्तर दे दें कि उन्होंने जो पदोन्नति की है यह साउन्ड एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धान्त के अनुसार की गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि टेम्परेरिली जो पोस्ट खाली हुई है सीनियोरिटी केबेसिस पर उनको प्रमोट किया गया है, और किसी को भी सजा देने वाली बात आये तो उसको चार्जशीट दी जायगी, एक्स्प्लेनेशन मांगा जायगा, यह सारा प्रोसीजर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तक ने कहा था जब कि अपील नहीं हुई थी तो एन्क्वायरी का आर्डर किया था तो वह एन्क्वायरी करनी होगी। पहले यह कहा जाय कि इस आदमी को प्रमोट नहीं किया जाय या और कोई सजा दी जाय ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) विपक्ष के नेता माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : जो कुछ भी उत्तर दिया है यह मैं समझता हूं। यह बीटिंग दी बुश है। वे उत्तर नहीं दें तो मैं समझ सकता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि साउन्ड एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं, इतना उत्तर दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि उनको प्रमोट नहीं करना उचित नहीं था।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि उनसे सीनियर आफिसर बैठे हुए हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया गया और इनको यह इनाम स्वरूप प्रमोशन दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य शायद प्रश्न को समझ नहीं पाये हैं। ये सीनियर थे और पोस्ट खाली हुई थी।

श्री रामचन्द्र आर्य : और इनसे भी सीनियर हैं।

श्री विजयसिंह : इनको नागौर में लगाने की क्या आवश्यकता थी ?

Page No. 21

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां पर जगह खाली थी वहां पर लगा दिया।

श्री विजय सिंह : वहां पर जो ए० डी० एम० थे उनका वहां से ट्रान्सफर किया गया और उनको वहां पर लगाया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री विजयसिंह रावत : किसी भी अधिकारी के खिलाफ चुनावों में घोटाला और पक्षपात के आरोप के स्ट्रिक्चर्स जो हाई कोर्ट के अन्दर पास हुए उसके बारे में सरकार ने गलती करके उसकी जो पदोन्नति की है तो क्या सरकार अपनी गलती को रिवाइज करके उनको रिवर्ट करने का प्रयत्न करेगी और नागौर से हटाने का प्रयत्न करेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका उत्तर मिलना चाहिये कि क्या उनसे सीनियर और योग्य आफिसर हैं या नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : इसके सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह पूछना है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है मुख्य मन्त्रीजी इस फैसले को गलत समझते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे समझने और न समझने का कोई प्रश्न नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले को गलत कैसे कह सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है।

श्री मदनसिंह दांता : यह बतायें कि गलत है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत ! आप प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं कि मुख्य मन्त्रीजी ठीक समझते हैं या नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : हम समझते हैं ठीक है आप नहीं कहें कि ठीक है। जब ठीक फैसला दिया है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो उस फैसले को मानना चाहिए।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि इनके खिलाफ और भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था की शिकायत आप से है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी जान बूझ कर उत्तर को टाल रहे हैं, और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका उत्तर आना चाहिये।

श्री विजयसिंह : इन्हीं व्यक्ति के खिलाफ अभी थोड़े दिन पहले सदन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे कि इन्होंने बहुत से घोटाले किये हैं इन्हीं जैसे व्यक्ति को नागौर में लगाने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत !

प्रोफेसर केदार !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : इसी से रेलेवेन्ट क्वेश्चन यह है कि अपील मेमो में यह ग्राउन्ड नहीं है तो हाईकोर्ट का फैसला स्टैन्ड करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसकी काग्नीजेन्स नहीं ले सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मुख्य मन्त्रीजी ने उत्तर दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया है। इसका उत्तर आना चाहिये। उत्तर दें। इनको यह गलत तरीके से पदोन्नति दी गई है और सीनियर आफिसर बैठे हुए हैं उनको नहीं दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार ७५६।

श्री विजयसिंह रावत : इनका उत्तर तो आये कि ग्राउन्ड्स ही नहीं बताये गये हैं अपील में तो......

श्री उपाध्यक्ष : कानूनी प्रश्न है, आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह (मकराना) : प्रोफेसर केदार ने यह पूछा है कि यह कामन सेन्स की बात है कि इस तरह का होना चाहिये तो क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी में कामन सेन्स नहीं है?

श्री जयकृष्ण (राज्य मन्त्री) : प्रोफेसर केदार के प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं।

प्रश्न संख्या ७५५

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रोफेसर केदार !

ग्राम अमरपुरा तहसील सूरतगढ़ को बिजली देने पर व्यय

७५६. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) क्या विद्युत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) गांव अमरपुरा राठान, तहसील सूरतगढ़ में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत बिजली देने पर कितना खर्चा हुआ ?

(२) इस गांव में कितने मकान है और कितने ट्यूबवैल्स हैं तथा कितने मकान मालिकों ने बिजली का उपयोग किया है ?

(३) क्या यह सही है कि वहां बिजली आने से से पूर्व कोई भी ट्यूब वैल्स नहीं था ?

राज्यमंत्री, विद्युत (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (१) लगभग १२००० रुपया।

(२) मकानों की संख्या के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है आबादी जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर १२१६ है। ट्यूब वैल्स नहीं हैं। दो मकानों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(३) जी हां।

श्री केदारनाथ : इस गांव को प्रायोरिटी देने का क्या आधार है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह गांव बाढ़ के करीब था उधर की तरफ बसा हुआ था तो गांव के अन्दर काफी भूमि थी और नाली की बाढ़ आजाने की वजह से दो बार ६६ और ६७ में यह बाढ़ से काफी ग्रसित हुआ और सम्पूर्ण ग्राम जो था वह जलमग्न हो गया। उसके बाद ग्रामवसियों ने यह प्रार्थनापत्र दिया कि इस गांव के अन्दर बिजली पहुंचाई जाय इसलिए दी गई।

श्री केदारनाथ : बिजली कब दी गई और बिजली आने पर कितने लोगों ने कनेक्शन लिये ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने बताया है कि दो कनेक्शन दिये हैं।

श्री केदारनाथ : चार साल में दो कनेक्शन दिये गये तो तो क्या यह पेइंग प्रोपोजिशन है १२ हजार रुपये के खर्चे के बाद वह भी दो रिश्तेदारों को आपस में ?

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत मंत्री) : मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि बिजली बाढ़ से पहले दी गई और बिजली जो देने को थी लेकिन बाढ़ के कारण पूरा का पूरा गांव डूब गया इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकी।

श्री रामचन्द्र आर्य: क्या यह सही है कि वहां की जन-संख्या कुछ नहीं है और पिछले साल यह मामला विधान सभा में आया था कि उस गांव के अन्दर मनफूलसिंह राज्यमंत्री का घर है और किसी का मकान नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : जो गांव सेन्सस रिपोर्ट में लिखा गया है वह रेवेन्यू विलेज लिखा गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गांव लिखा गया है लेकिन वहां पर कोई रहने वाला नहीं है। आप गलत उत्तर दे रहे हैं। गांव का नाम नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य का ध्यान सेन्सस रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव की जो जन-संख्या है उसको वे देख लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : या तो ट्रेजरी बेंच का नशा है या भांग पी रखी है उसमें बोल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्यों के शब्दों का आब्जेक्शन लेता हूं। मैंने जो फेक्ट्स दिये हैं वे पब्लिश्ड डाक्युमेन्ट्स के आधार पर दिये हैं। इस पर कोई एतराज हो तो उसको उस रूप में रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी शायद उस गांव में गये हुए हैं तो हम जानकारी करना चाहते हैं कि कोई गांव वीरान होता है लेकिन सेन्सस में उसका नाम है तो वास्तविकता क्या है ? इस बात की जानकारी करना चाहते हैं कि जहां बिजली दी गई है वहां पर आबादी है या और दूसरी आबादी वहां से बहुत दूर है। जहां बिजली नहीं आती है वहां स्थिति क्या है। आप कह सकते हैं कि राज्य मंत्री हैं तो बिजली पहुंचा दी, लेकिन वास्तविकता हमें मिलनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : वास्तविकता यह है कि यह एक रेवेन्यू विलेज है। मैं खुद इस गांव में—जब यह डूब में आया था तो कई विरोधी दल के माननीय सदस्यों के साथ में और विरोधी दल के जितने नेता है उनके साथ में गया हूं, और जाकर मैंने स्वयं ने इस गांव को देखा है और स्थिति यह है कि गवर्नमेंट के रेकार्ड के अनुसार ६० मकानों को कम से कम रिलीफ दिया गया है।

श्री मदनसिंह दाता : वह ढाणी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है...

श्री मजलिस खां : क्या कोई चक एच. बी. में कोई कनेक्शन नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : इस प्रकार ऑफ हैण्ड मैं कैसे जवाब दे सकता हूं ?

श्री मजलिस खां : क्या वह कुम्भाराम जी का चक है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं क्या कह सकता हूं कि कुम्भारामजी के यहां बिजली लगी है या नहीं लगी है, मगर जहां तक उसका सवाल है यह मैं कह सकता हूं कि वह एक रेवेन्यू विलेज है।

कई माननीय सदस्य : ढाणी है।

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट रेकार्ड के अन्दर वह रेवेन्यू विलेज लिखा हुआ है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप मोहल्ला मानें तो हम कब इन्कार कर रहे हैं !

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक इसका सवाल है मैं स्वयं इस गांव के अन्दर गया हूं और मैंने देखा है कि वह रेवेन्यू विलेज है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): कितने घर हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आबादी उसकी १२०० लिखी हुई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर आप कहें तो आपकी बात मान ली जायगी लेकिन जिस जगह पर बिजली का कनेक्शन दिया गया है वहां पर कितने परिवार बसे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : ६० परिवारों को रिलीफ दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय महेन्द्रसिंह।

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री मजलिस खां (कामां) : क्या यह सही है कि एस. बी. ३४ में एक ट्रान्सफारमर पड़ा है जो और किसी के काम में नहीं आ रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह है कौनसा ?

श्री मजलिस खां : क्या यह सही है कि श्री कुम्भाराम जी के चक में एक ट्रान्स-फार्मर पड़ा हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कुम्भारामजी ने बिजली लगाई हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं जिस विलेज के बारे में कह रहा हूं वह एक रेवेन्यू विलेज है।

एक मा. सदस्य : ढाणी है।

श्री हरिदेव जोशी : यह रेवेन्यू विलेज के नाम से दर्ज है। कम से कम जहां तक इसका सवाल है मैं स्वयं वहां गया हूं, विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ गया हूं।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : यदि आप वहां पर गये हैं तो कम से कम यह तो बता दीजिये कि वहां पर ५ परिवार से ज्यादा परिवार बसते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : निश्चित रूप से बसते हैं। ६० परिवारों को तो रिलीफ दी गई है।

श्री केदारनाथ : मनफूलसिंहजी के साथ दूसरों को भी बिजली दी जाती तो कोई बात नहीं थी।

श्री हरिदेव जोशी : यदि माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि मनफूलसिंहजी के कारण उस गांव को बिजली दी है तो मनफूलसिंह जी तो आज मंत्री बने हैं और बिजली सन् ६४-६५ में दी गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जन संख्या दी है, वोटर लिस्ट पेश की है, पंचायत की १० हजार की आबादी है, अमरपुरा में १८ घर नहीं हैं......

श्री उपाध्यक्ष : आोर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

एक मा. सदस्य : आबादी क्या है इस गांव की ?

श्री उपाध्यक्ष : आोर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

ग्राम अयाना के वैद्य के विरुद्ध शिकायतें

७५७. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपलदा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा की पंचायत समिति इटावा के ग्राम अयाना के वैद्य की काफी शिकायतें हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कई अनियमिततायें होने के कारण उक्त वैद्य को सस्पेन्ड कर दिया गया था ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त वैद्य के मामले की जांच हेतु डिप्टी डाइरेक्टर अयाना गये थे ?

(४) क्या यह सही है कि जो शिकायतें की गई थीं वे सब सही पाई जाने पर भी वैद्य को वापस सरकारी ड्यूटी पर उसी औषधालय में ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री, आयुर्वेद (श्री कन्हैयालाल पटेल) : (१) जी हां।

(२) जी हां। शिकायतों के प्राप्त होने पर सस्पेन्ड कर दिया था।

(३) जी हां।

(४) आरोप प्रमाणित नहीं होने से वैद्य को पुनः प्रतिष्ठापित किया गया।

एक माननीय सदस्य : आपकी तारीफ तो बतादें।

आयुर्वेद मंत्री : (श्रीअमृतलाल यादव) जिस वैद्य के खिलाफ शिकायत की गई थी उसकी प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी करने के बाद उसको सस्पेन्ड कर दिया गया था और उसके बाद डिप्टी डाइरेक्टर जैसे बड़े अधिकारी ने जांच की और जांच के बाद शिकायत प्रमाणित नहीं हुई तो उसको रिइन्सटेट करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था इसलिये उसको रिइन्सटेट करके वापिस वहीं पर भेज दिये। इसके बावजूद भी यदि वहां की जनता उससे नाराज है तो उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

श्री महेन्द्रसिंह : मुझे मंत्री जी के जवाब पर ऐतराज है। जो जवाब दिया है वह बिल्कुल गलत है। डिप्टी डाइरेक्टर ने इन्क्वायरी की उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इन्क्वायरी के बाद मैं कोटा

(श्री महेन्द्रसिंह)

में उनसे मिला हूं और मैंने उनसे पूछा कि आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि गांव वाले सही हैं, वाकई अनियमितताएं अधिक हैं उनको देखते हुए उसका सस्पेन्शन होना चाहिये। उस वैद्य की बहुत अधिक शिकायतें हैं। जो महिलाएं वहां पर इलाज के लिये जाती हैं उनके बयान हैं कि वह महिलाओं के गुप्तांग को प्रेस करता है (शेम शेम) यही नहीं, वहां के पटवारी का लड़का बीमार हुआ तो उसको लेकर वह वैद्य जी के पास पहुंचा तो उसने इलाज करने से इन्कार कर दिया। तब उसने तहसीलदार से कहा......

एक माननीय सदस्य : इतना समय ले लेते हैं और हमारे दूसरे प्रश्नों के जवाब मिलते नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरक प्रश्न इतने अधिक पूछे जाते हैं कि दूसरे प्रश्न रह जाते हैं। अब आगे इस पर भाषण नहीं होगा। आपने अपनी बात फरमा दी। मंत्री जी ने फरमा दिया कि उसको वहां पर रखना उचित नहीं होगा तो हटा दिया जायगा।

श्री महेन्द्रसिंह : क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता ? उसकी शिकायतों को देखते हुए क्यों नहीं उसको नौकरी से अलग किया जाता ? सही बातें छिपाई जायेंगी तो अनियमितताएं बढ़ती जायेंगी।

श्री भैरोंसिंह : यह बताया जाय कि किस आधार पर उसको सस्पेन्ड किया गया था ? क्या कोई प्राथमिक जांच हुई थी ?

श्री अमृतलाल यादव : उसके खिलाफ जो शिकायतें हुई थीं उनकी प्राथमिक जांच हुई, सरसरी तौर पर देखा और सस्पेन्ड कर दिया। उसके बाद डिप्टी डाइरेक्टर जैसे सीनियर अधिकारी को जांच करने के लिये भेजा गया। जो आरोप उसके अगेन्स्ट थे वे जांच से प्रूव नहीं हुए इसलिये उसको रीइन्सटेट किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्रारम्भिक जांच भी उसी डिप्टी डाइरेक्टर द्वारा की गई थी ?

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास यह सूचना नहीं है कि प्रारम्भिक जांच किसके द्वारा की गई थी। सस्पेन्शन के बाद जांच डिप्टी डाइरेक्टर ने की।

श्री भैरोंसिंह : सस्पेन्शन के ओर्डर और रिइन्सटेट करने के ओर्डर किसने दिये थे ?

श्री अमृतलाल यादव : डाइरेक्टर ने दिये होंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्नकर्त्ता जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने जो बातें इस वैद्य के बारे में कहीं वे भद्दी हैं और ठेस पहुंचाने वाली हैं। यदि जनता का सेवक अत्याचारी बनता है तो मन्त्री महोदय को यह तो चाहिये कि जनता को सन्तोष दिलाने के लिये उसका स्थानान्तरण करें।

श्री अमृतलाल यादव : यह तो मैं निवेदन कर चुका हूं।

छीपा बड़ौद क्षेत्र में ज्वार की उपज

७५८. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(१) पंचायत समिति छीपा बड़ौद, जिला कोटा में इस वर्ष कितनी संकर ज्वार बोई गई थी ? इस ज्वार की औसत पैदावार क्या रही है ?

(२) क्या सरकार इस ज्वार के बोने से होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिये काश्तकारों को कुछ मुआवजा देने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (१) पंचायत समिति छीपा बड़ौद में संकर ज्वार पिछली खरीफ में १२५ एकड़ में बोयी गई थी इसकी औसत पैदावार ६.७ मन प्रति एकड़ रही।

(२) जी नहीं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सरासर गधे के सर पर पंख लगाना है। इसमें कत्तई सत्यता नहीं है। क्या यह सत्य है कि इस तरह से काश्तकारों को प्रलोभन देकर सरकार ने उनको नुकसान पहुंचाया है ?......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न के रूप में पूछें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि इस तरह से सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने पर काश्तकारों ने संकर ज्वार के बीज बोये और उससे काश्तकारों को नुकसान हुआ ? क्या सरकार काश्तकारों के नुकसान को पूरा करने का इरादा रखती है ?

श्री हरिसिंह : संकर ज्वार के बीज से देसी ज्वार के बीज की बनिस्पत अधिक उपज होनी चाहिये लेकिन यहां पर ६.७ मन की उपज हुई हैं। औसतन २५ मन से ३० मन प्रति एकड़ में उपज होती है लेकिन यहां पर इतनी उपज नहीं हुई है। लेकिन संकर ज्वार से अधिक उपज तभी हो सकती है जब कि इसके अनुकूल परिस्थिति हो। वहां पर कंटिन्युअस रेन्स हुई और खरीफ का सीजन ठीक नहीं होने से पूरी उपज नहीं हो सकी। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि कंटिन्युअस रेन फाल से सीड डेमेज हो जाता है और क्लाइमेटिक कंडीशन्स अनुकूल नहीं होने से अधिक उपज नहीं होती।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि संकर ज्वार बोने से पहले अधिकारियों ने काश्तकारों को पूरी जानकारी नहीं दी इस वजह से कोटा जिले में करीब ४० बैल इस ज्वार को खाने से मर गये ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद पंचायत समिति के प्रधान ने संकर ज्वार से पैदावार कम हुई है इस सम्बन्ध में कृषि विभाग को लिखा है ?

श्री हरिसिंह : मेरे पास कम होने की सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री विजयसिंह मकराना : क्या यह सही है कि चालीस में से ३६ मरे और चार जिन्दा हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! अगला प्रश्न !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय मन्त्री

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

ने उत्तर दिया कि छः मन, सात मन प्रति एकड़ पैदावार हुई है, यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दिया है, वह गलत मानते हैं या सही मानते हैं इसका निर्णय नहीं हो सकता। अगला प्रश्न !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : १६ एकड़ के अन्दर ज्वार मैंने खुद ने बोई थी, बिलकुल ज्वार पैदा नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आईदानसिंह !

विद्युत् विभाग को दी गई धनराशि

७५६. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अकाल सहायता विभाग से विद्युत् विभाग को जिला जालोर के लिये रुपये ४६५ लाख दिये गये हैं ?

(२) अगर हां तो अब तक कितनी धनराशि काम में आ चुकी है ? कृपया कामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) :— (१) जी नहीं। ४-६५ लाख नहीं ५-५० लाख रुपये की स्कीम स्वीकार की गई थी।

(२) जालोर जिले के खर्च का व्यौरा अलग से उपलब्ध नहीं है। कामों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री आईदानसिंह : क्या यह सही है कि जिन नामों की सूची मुझे दी गई है वह अकालग्रस्त थे ?

श्री गंगाराम चौधरी : अकालग्रस्त थे तभी काम करवाया गया था।

श्री आईदानसिंह : राज्य सरकार द्वारा जिन्हें अकाल सहायता दी गई, उन गांवों का नामो निशान इसमें नहीं है—क्या यह भी सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : क्या ?

श्री जयनारायण सालोदिया : सहायता नहीं दी ?

श्री आईदानसिंह : क्या उन गांवों का इस लिस्ट में नाम नहीं है—क्या यह सही है?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम ५ लाख ५० का स्वीकार किया गया, वह पूरा कर दिया गया। इस प्रश्न का इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

श्री आईदानसिंह : यह पांच लाख पचास हजार या चालीस हजार रुपया दे दिया गया तो वह अकालग्रस्त गांवों के लिए दिया गया न कि उन गांवों के लिए जो अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किये गये—क्या यह भी सच है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास यह सूचना नहीं है कि कौन कौन से गांव इसके अन्दर थे। यह पासिबिल हो सकता है कि बीच के अन्दर गांव रहे हों। जो रुपया स्वीकार किया गया वह ५ लाख ५० हजार किया और उस रकम को पूरा खर्च कर दिया।

Page No. 29

श्री ग्राईदानसिंह : क्या यह सही है कि जालौर ग्रौर ग्राहौर के बीच में ग्रकाल था?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रगला प्रश्न ।

श्री हरिदेव जोशी : यह मैं नहीं कह सकता कि किस जगह था, किस जगह नहीं था । यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है । मगर डिपार्टमेंट कन्सर्न ने जो स्कीम स्वीकार की ग्रौर जिसको हैल्थ डिपार्टमेंट ने ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्वीकार किया, उसका हमें जो प्रोग्राम दिया, जो काम उन्होंने दिया उस काम को डिपार्टमेंट ने पूरा कर दिया ।

श्री दिग्विजयसिंह– स्पेसिफिक रूप से उस काम को करना चाहिए जो ग्रकालग्रस्त गांवों के लिए था । सदस्य का पूछना है कि वह काम उन गांवों के ग्रन्दर किया गया या नहीं क्योंकि ग्रकाल राहत कार्यक्रम की स्कीम दी गई वह उन गांवों के लिए तैयार की गई थी ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को थोड़ा भ्रम है । राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस काम के ग्रन्दर ग्रमुक डिपार्टमेंटल एजेंसी के रूप में काम किया । उसने पैसा दिया ग्रौर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लाइन बिछा दी ग्रौर उसका उन्होंने पैसा दिया । It is all.

श्री ग्राईदान सिंह: ग्रापको जालौर के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह काम हुआ है यह जालौर के ग्रलावा चारों तरफ हुग्रा है, जालौर का पश्चिमी एरिया का क्षेत्र है वह इस तरह बचाया जा रहा है जैसे वहां लोग बसते नहीं हों, सड़कों का काम हुग्रा, ग्रकाल का काम हुग्रा वह जालौर पूर्व में हुग्रा ग्रौर काम होते हैं तो वह जालौर पूर्व में होते हैं । ग्राप जालौर के पश्चिमी एरिया को भी ग्रपने हाथ में लीजिए ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ग्राप इसकी जांच कर लीजिये ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को ग्राप यह राय दें कि वह इस प्रश्न को सम्बन्धित विभाग से पूछें तो ज्यादा ग्रच्छा होगा । मैंने निवेदन किया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उस विभाग की एजेंसी के रूप में काम किया है । विभाग ने ग्रमुक काम को पूरा करने के लिए पैसा दिया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसको किया ।

श्री ग्राईदान सिंह : ग्रकाल सहायता विभाग ने पैसा क्यों दिया ?

श्री मदनसिंह दांता : ग्राप इसका जवाब ठीक फर्मायें, काम ठीक ठीक जिस जगह कराना था, सम्बन्धित विभाग ने वैसा नहीं किया । मैं मुख्यमंत्री से ग्रर्ज करूंगा कि सम्बन्धित विभाग ने ग्रकालग्रस्त गांवों के लिए योजना नहीं रखी तो क्या ग्रापका जिस काम से सम्बन्ध है उसमें वैसा कर सकते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, न मुख्य मंत्री का प्रश्न पैदा होता है, न दूसरा प्रश्न पैदा होता है । माननीय सदस्य ने पूछा, ग्रमुक विभाग ने क्या ग्रापको रुपया दिया । मैंने स्वीकार किया, हां दिया । जो स्कीम स्वीकार की गई; उस स्कीम को पूरा कर दिया गया । उसके बाद में यह उस विभाग से पूछने की बात है कि उन्होंने ग्रपना जजमेंट ठीक वहां पर लागू किया ग्रथवा नहीं, या वह काम

(श्री हरदेव जोशी)

ठीक था अथवा नहीं, उस क्षेत्र के लिए यह काम किया गया था या नहीं किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस हद तक जवाबदेह है जो स्कीम उसको दी गई उसको पूरा किया गया या नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दिग्विजय सिंह : एक प्रश्न और। अकाल सहायता कार्य के लिए अकाल सहायता विभाग ने यह पैसा उन गांवों के लिए दिया था जहां अकाल था तो दूसरी योजना विद्युत् विभाग ने स्वीकार करके कैसे कर दी ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कह दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अमुक विभाग ने क्या इतना रुपया दिया। मैंने स्वीकार किया—हां दिया। अब अकालग्रस्त गांव थे या नहीं—इससे इस विभाग का सम्बन्ध नहीं है। यह सम्बन्धित विभाग से पूछिये।

श्री शिवनाथ सिंह : एक सवाल रह गया है, उसको ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा अगला प्रश्न है ७६०, यह अल्प सूचना प्रश्न के रूप में पूछा था, सामान्य तौर पर आया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इससे अगला प्रश्न है ७६०, यह अल्प सूचना प्रश्न के तौर पर मैंने पूछा था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ७६०

अध्यापक का स्थानान्तरण

७६०. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षामन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

१) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के आदेश हैं कि यदि पति और पत्नी दोनों अध्यापक हों तो उनको जहां तक संभव हो सके एक ही जगह पर रखा जावे ताकि उनका गृहस्थ जीवन ठीक प्रकार सामान्य रुप से चल सके ?

२) क्या यह सही है कि श्री मूलाराम वैष्णव राजकीय माध्यमिक पाठशाला शेरगढ़ जिला जोधपुर में अध्यापक तृतीय ग्रेड में तैनात हैं ? कृपया, श्री मूलाराम ने जब से राजकीय सेवा में लिये गये हैं, तब से अब तक किस किस स्थान पर और कौन कौन से पद पर कितने कितने समय के लिए कार्य किया, उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

३) क्या यह सही है कि श्री मूलाराम वैष्णव की धर्मपत्नी श्रीमती शकुन्तला वैष्णव राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या-पाठशाला सोजत सिटी में सहायक अध्यापिका के रुप में कार्य कर रही हैं ? श्रीमती शकुन्तला वैष्णव राजकीय सेवा में कब ली गई थीं ? जब से वे राजकीय सेवा में ली गई हैं, तब से अब तक उन्होंने किस किस स्थान पर कौन कौन से पद पर कितने कितने समय के लिये कार्य किया है ? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

४) क्या यह सही है कि श्री मूलाराम वैष्णव और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शकुन्तला वैष्णव को अक्टूबर, १९६१ से अलग अलग स्थानों पर नियुक्त किया जा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार के जनरल आदेशों के बावजूद ऐसा क्यों किया गया ?

५) क्या यह सही है कि श्री मूलाराम वैष्णव ने अतिरिक्त संचालक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को एक शिकायत पत्र लिखा था जिसमें कुछ शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध दुराचरण के आरोप लगाए थे ? यदि हां, तो वे आरोप क्या थे ? पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

६) क्या यह सही है कि अतिरिक्त संचालक महोदय ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्याः ई०बी०डी० । ई । एस । टी । बी । टी०आर०—११।१२६६२ । एस० पी० एल० । ६५ दिनांक, २।६।६५ द्वारा श्री आर०सी० कल्ला उपसंचालक शिक्षा विभाग जोधपुर—बीकानेर मण्डल जोधपुर को यह लिखा था कि इनका केस सही (जीनाइन) मालूम पड़ता है इस पर शीघ्र कार्यवाही करें। यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई ?

७) क्या यह सही है कि श्री मूलाराम ने दिनांक, १।१२।६५ को विभागीय अत्याचारों से तंग आकर तार द्वारा अपना त्यागपत्र भी विभाग को भेज दिया था ? इनके स्तीफे पर कार्यवाही क्या की गई ? यह सही है कि इनका स्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है ?

८) क्या राज्य सरकार इस सारे मामले में जांच करायेगी कि उक्त अध्यापक को इस प्रकार क्यों परसीक्यूट किया गया है और दोषी अधिकारियों को दण्ड देगी ?

शिक्षामन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) :

(१) जी नहीं।

(२) यह सही है कि श्री मूलाराम तृतीय वेतन श्रृंखला में थे। दि० ५-११-६५ से दो दिन के आकस्मिक अवकाश पर गये थे। उसके पश्चात् वे अपने कार्य पर उपस्थिति नहीं हुए। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां, श्रीमती शकुन्तला वैष्णव १-७-५८ से राज्य सेवा में हैं। ये निम्न प्रकार स्थान पर रही हैं:—

१-७-५८ से मार्च, ६१ तक कन्याशाला पाली।

१-४-६१ से सितम्बर, ६४ तक माध्यमिक शाला सोजत सिटी।

१-१-६५ से ३१-७-६५ तक सोजत रोड।

१—८—६५ से आज तक सोजत सिटी में।

(४) अक्टूबर, ६१ से श्री मूलाराम व उनकी धर्मपत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि श्री मूलाराम ने अपने ही प्रार्थना पत्र पर राज० माध्यमिक शाला रूमाबाद (सोजत के समीप) नियुक्त किये गये और बाद में शिक्षा प्रसार अधिकारी रायपुर पर लगाए गये। रायपुर से उनका स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया।

(श्री शिवचरण माथुर)

(५) श्री मूलाराम वैष्णव का इस प्रसंग का पत्र निदेशालय में प्राप्त हुआ था और इस पत्र को उप निर्देशक, शिक्षा विभाग जोधपुर को श्री वैष्णव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने इस पत्र में भद्दी बातों का प्रयोग किया था। उप निर्देशक को लिखे गये पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं मिली है प्रति।

श्री शिवचरण माथुर : मैं दे देता हूं।

(६) भाग (५) में उल्लिखित पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। कारण यह मामला उप निर्देशक महोदय के कार्य क्षेत्र का है।

(७) १-१२-६५ को मूलाराम ने एक तार अपना इस्तीफा मंजूर करने की प्रार्थना का किया। निश्चित रूप से इस्तीफा देना नहीं बताया गया है।

(८) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न ५ के अन्दर कहा है, उस पत्र की सूची को सदन की मेज पर रख दिया गया है। वह कृपया पढ़ कर सुना दीजिये, वह मुझे मिली नहीं है, वह आपके पास होगी। वह क्या पत्र है, उसकी जानकारी दे दीजिये। इन्होंने एलीगेशन किया है दुराचरण का, वह क्या है?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन कर दूं, ओरिजिनल पत्र है। उसकी कापी नहीं मिली है, उसका फार्वडिंग लैटर है। उसकी कापी मांगी है। मैं भी चाहता हूं कि वह पत्र क्या है, यह देखें। हम जानकारी कर रहे हैं। एडीशनल डाइरक्टर का लैटर यह है—

"श्री मूलाराम सहायक अध्यापक राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, जैसलमेर का पत्र संलग्न है। इस पत्र में इन्होंने भद्दी बातों का प्रयोग किया है। इस विषय में उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय।

उनका केस जेनुआइन मालुम पड़ता है। इस विषय में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।"

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह पत्र आपने एडीशनल डाइरेक्टर का बताया, जो श्री मूलाराम ने पत्र लिखा है, शिकायत की, दुराचरण की वह किस आफिसर के खिलाफ हैं कि मेरी पत्नी से इस प्रकार व्यवहार किया गया। यह शिकायत की, उन्होंने जांच करने के लिए और उन आफिसर के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। उसके खिलाफ एक्शन न लेकर अब कहते हैं कि मूलाराम के खिलाफ एक्शन लिया जाय। यह मामला जरूरी है, मैं लैटर चाहता हूं, जो आपके डिपार्टमेंट को लिखा है जो १-९-६५ का है।

श्री शिवचरण माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया इस फोरवार्डिंग लेटर के साथ वह पत्र होना चाहिये था वह नहीं है, उसको मंगवाने की कोशिश की है। तो इससे मुझे खुद को संतोष नहीं हैं, मैं

(श्री शिवचरण माथुर)

इसकी जांच कर रहा हूँ। जांच में सच बातें सामने आयेंगी, उन पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो पत्र मूलारामजी ने लिखा, जान बूझ कर डिपार्टमेंट उसे छुपा रहा है, उसकी प्रति मेरे पास है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि डायरेक्टर ने खुद ने माना है कि १-१०-६१ से ६५ तक अध्यापक ने कोशिश की कि मुझे और मेरी धर्म पत्नी को एक साथ रखा जाय, पर नहीं रखा जाता। पहली दर्ख्वास्त करते हैं तो १० मील दूर भेज दिया जाता है और दूसरी दर्ख्वास्त करते हैं तो २४ मील दूर भेज दिया जाता है और तीसरी दर्ख्वास्त करते हैं तो १२४ मील दूर भेज दिया जाता है। फिर ७० मील दूर भेज देते हैं, फिर नाराज हुए तो २५७ मील दूर जैसलमेर भेज दिया गया, फिर १३७ मील दूर शेरगढ़ भेज दिया जाता है। वहां से तंग आ कर भूख हड़ताल करते हैं और फिर वहां से तंग आकर स्तीफा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय इस सबसे तंग आ कर उनकी धर्मपत्नी मिलती है सुधीन्द्रकुमार डिप्टी डायरेक्टर से १-२-६४ को और वे कहते हैं कि मेरे बंगले पर आओ। फिर वह रामचन्द्र कल्ला डिप्टी डायरेक्टर से मिलती है १४-९-६४ को तो वे कहते हैं फर्स्ट ओब्लाइज, जिससे लिखित में डिप्टी डाइरेक्टर की शिकायत की है।

फिर तीसरे इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स जैसलमेर में जाते हैं तो टीचर कहते हैं कि देखिये मेरा ट्रान्सफर इतनी दूर कर दिया। हमको एक जगह पर रखना चाहिये, तो उन्होंने कहा बंगले पर आओ फर्स्ट ओब्लाइज। तीसरे इन्सपेक्टर साहब जो जवाब देते हैं वह आप पढ़ ही सकते हैं, मैं पढ़ कर नहीं सुना सकता.........

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : पढ़ कर सुनाया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल: तीनों आफिसर्स के खिलाफ स्पेसिफिक एलीगेशन्स उस टीचर ने लगाये हैं, इससे यह साबित है पर फिर भी डिप्टी डायरेक्टर का एक्शन नहीं होता है तो तंग आकर कहता है कि अगर मुझे और मेरी बीबी को एक जगह सिवाय इसके कि मेरी बीबी को अपनी इज्जत लुटानी पड़े, नहीं रखा जाता तो स्तीफा देता हूं, यह आखिरी लेटर है, तंग आकर उसने वह आखिरी लेटर लिखा, उस पर डायरेक्टर साहब कहते हैं कि भद्दी लेंग्वेज का प्रयोग किया है, इसलिये टीचर के खिलाफ कार्यवाही की जाय। पर साथ ही लिखा है मामला जेन्वाइन मालूम होता है, पर जेन्वाइन होने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं, वे दोनों एक जगह नहीं रह सकते, १७० मील दूर शेरगढ़ में रखा जाता है, उनके लिखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं तो फिर इस्तीफा देना पड़ा। अब भी स्तीफा देने के बाद भी डायरेक्टर नहीं कहते कि वह नौकरी में है या कहां पर हैं, वह घर पर बैठा है, उनको एक जगह नहीं

Page No. 34

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रहने दिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात रख दी ।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात यहां कही, उसमें यदि तथ्य है........

श्री रघुनाथ विश्नोई : और क्या तथ्य चाहिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : डूब कर मर जाना चाहिये, औरतों की इस प्रकार इज्जत लूटी जाय........

श्री शिवचरण माथुर : इस पर जांच करके........

श्री रामचन्द्र : लानत है........

श्री शिवचरण माथुर : मैंने अपने उत्तर में पहले ही निवेदन किया है कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, पूरी जांच करूंगा । मैं माननीय सदस्य का आभारी होऊंगा जो लेटर उनके पास है वह मुझे दें, यदि सही है तो यह बहुत गम्भीर बात है, निश्चित रूप से मैं इसकी जांच करूंगा । मैंने पहले ही कहा कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसकी और जांच करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय बताने की कोशिश करें कि जब शिकायत बहुत पहले पहुंच गई तो आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरे पास फरवरी में शिकायत पहुंची थी ।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास नहीं, आपके विभाग में बहुत पहले पहुंच गई थी तो आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यही तो जांच कर रहा हूं कि विभाग के पास शिकायत पहुंची तो क्यों नहीं कार्यवाही की गई, इसी की जांच कर रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के पत्र पर कार्यवाही होनी चाहिये थी विभाग से, वह क्यों नहीं की गई ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं यही तो जानकारी करना चाहता हूं विभाग से कि आपके पास शिकायत आई तो आपने क्या कार्यवाही की ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर क्वश्चन पोस्टपोन होना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगले सोमवार को रख दीजिये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है और सामान्यतया प्रति-पत्नि को अलग नहीं रखना चाहिये, यह एक मानवीय प्रश्न है । इसको लेकर इतने दिन गुजर चुके हैं और प्रश्नकर्त्ता ने चर्चा की है, उसके समर्थन में मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित किया भी जाय या नहीं किया जाय तो भी इसमें शिक्षा मन्त्री को

Page No. 35

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सामान्यतया जानकारी प्राप्त करनी चाहिये, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी होनी चाहिये, एक सप्ताह से अधिक समय क्यों माननीय शिक्षा मन्त्री व्यतीत करेंगे, यह समझ में नहीं आता। मूल बात है मानवीयता के नाते आपको क्या करना चाहिए, हम एक सभ्य देश के निवासी हैं, इस नाते माननीय शिक्षा मंत्री शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठा सकते, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पेशल सीनियर आफिसर से इसकी जांच करा ली जाय और यह हाउस एड्जोर्न हो उससे पहले हाउस को इन्फोर्म कर दें कि उस एन्क्वायरी का क्या रिजल्ट रहा।

(करतल ध्वनी)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: एक बात मुख्य मंत्रीजी बता दें कि क्या सरकार को इसमें आपत्ति है कि दोनों पति–पत्नी एक साथ रहें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वह कदम तो ले लेना चाहिये था, पर ऐसा नहीं करने का क्या कारण है इसकी और इस सारे मामले की एक सीनियर स्पेशल आफिसर से जांच करा कर हाउस एड्जोर्न हो उससे पहले जांच के परिणामों से सदन को अवगत करा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: एक स्थगित प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इधर की ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों का प्रश्न है और खास तौर से मेरे दल का सम्बन्ध है बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं, पूछे नहीं जाते। मैं देखता हूं कि औसतन २०-२१ प्रश्न पूछे जाते हैं और १२ प्रश्न अनिवार्य रूप से रह जाते हैं। तो अधिक से अधिक माननीय सदस्यों के संतोष के लिये निवेदन करूं कि आप कृपा कर के २४ या २५ ही प्रश्न पूछें तो मेरे खयाल में अधिक लाभदायक होगा और इस व्यवस्था से माननीय सदस्यों को संतोष भी होगा। अगर क्वेश्चन आवर से १५ मिनिट पहले ही क्वेश्चन खत्म हो जाय तो कोई बात नहीं। पर दस-दस, बारह-बारह प्रश्न रह जाते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि उचित समझें तो इस प्रकार की व्यवस्था कर दें।

श्री हरिदेव जोशी: मैं इससे सहमत हूं। क्वेश्चन्स आप अगर इतने रखवा सकें कि क्वेश्चन आवर में ही समाप्त हो जाय। एक मिनिस्टर के १५—१६ क्वेश्चन आते हैं उस तरफ भी देखें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: एक व्यवस्था का प्रश्न है। बहुत नम्रता से निवेदन है कि स्थगित प्रश्नों को क्वेश्चन आवर में चाहे केवल ५ मिनिट ही दें पर अनिवार्य रूपेण दिलाने की व्यवस्था करें तो स्थगित प्रश्न का भी महत्व रहेगा, पूछने का भी महत्व रहेगा और पूछने वाले को भी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

विश्वास और संतोष होगा कि वह प्रश्न आया। यह मेरा निवेदन और है।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायगा। इसके साथ सभी प्रश्न समाप्त किये जाते हैं। केवल एक स्थगित प्रश्न को पूछने के लिये पांच मिनिट का समय दिया जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

स्थगित प्रश्न

(५–३–६८ व १३–३–६८)

इन्डियन एलमोनियम फेबल्स कम्पनी द्वारा चम्बल प्रोजेक्ट को माल की सप्लाई।

४४४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि इन्डियन एलमोनियम केबल्स कम्पनी को चम्बल प्रोजेक्ट पर माल सप्लाई करने के लिये माल (मेटीरियल) व नकद रुपया एडवान्स किया गया है?

(२) अगर हां, तो कब-कब व कितना-कितना रुपया तथा माल (मेटीरियल) एडवान्स किया गया था?

(३) क्या यह सही है कि मेटीरियल के लिये उक्त कम्पनी को इम्पोर्ट लाइसेन्स भी दिया गया था? अगर हां तो कौन से मेटीरियल के लिये कितनी तादाद हेतु लाइसेन्स दिया गया था?

(४) उक्त माल, एडवान्स तथा इम्पोर्ट लाइसेन्स किस माल की सप्लाई के लिए दिया गया था?

(५) उक्त माल की सप्लाई की समय अवधि कितनी थी?

(६) क्या कम्पनी ने सरकार को माल सप्लाई कर दिया है?

(७) क्या कम्पनी ने इम्पोर्ट लाइसेन्स से माल प्राप्त कर लिया है?

राज्य मंत्री, विद्युत (श्री जयकृष्ण शर्मा) (१) जी हां। मंजूरशुदा शर्तों के अनुसार।

(२) बैंक गारन्टी लेकर।

(अ) एलमोनियम छड़ें।
१८५८–९९२ मैट्रिक टन अप्रेल ६५ से जुलाई, ६५ तक में।

(ब) रुपये २१,५८,१३५) दिसम्बर, ६४ में।

(स) स्टील वायर्स की कीमत पेटे २० लाख रुपये अगस्त ६७ में।

(३) जी नहीं। अलबत्ता जैसा प्रश्न सं० २ के उत्तर में उल्लेख है, १८५८-९९२ मैट्रिक टन एलमोनियम छड़ें जो कि प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस द्वारा प्राप्त की गई थी, दी गई।

(४) ३१३० किलोमीटर ए०सी०एस० आर० एलमोनियम कंडक्टर स्टील रीएन-फोर्स्ड पैंथर बना कर सप्लाई करने हेतु।

Page No. 37

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(५) २०० किलोमीटर प्रति माह के हिसाब से सप्लाई सितम्बर, १९६४ से होनी वाली थी किन्तु बाद में वह सितम्बर १९६५ कर दिया गया।

(६) ९५९–३८८ किलोमीटर पैंथर कंडक्टर सप्लाई किया गया है।

(७) प्रश्न के भाग (३) के उत्तर से प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : शरायत के अनुसार कितना माल सप्लाई किया है, कितना माल सप्लाई करना ड्यू हो जाता था ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने जैसा आपको निवेदन किया ९५९ व ३८८ माल सप्लाई किया। उनको सप्लाई करने का था १८,५९.९९२.

श्री कृष्णकुमार गोयल : इतना कम माल सप्लाई क्यों किया गया ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : एक तो इम्पोर्ट लाइसेन्स नहीं मिला दूसरा यह कि जो प्रोग्राम आटोमिक प्रोग्रेस का बनाया गया था उसकी प्रोग्रेस स्लो होने की वजह से विभाग ने राय दी कि धीरे से दे सकते हो।

श्री भैरोंसिंह : जो माल और रकम इनको दी है इस प्रकार की शर्तें जब टेन्डर्स इनवाइट किये गये थे उस समय टेन्डरर्स को अपना इन्टेन्शन डिक्लेअर किया था ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : माल सप्लाई नहीं किया तो एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : जो माल गवर्नमेंट को सप्लाई करना था, इम्पोर्ट लाइसेन्स फोरिन एक्सचेन्ज देना या वह गवर्नमेंट नहीं दे सकी उसके पेटे २१ लाख रुपये की बैंक गारन्टी दी है।

श्री भैरोंसिंह : जो माल सप्लाई नहीं किया उसमें एग्रीमेंट ब्रीच भी हुआ क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें एग्रीमेंट के ब्रीच होने का सवाल नहीं पहले यह गवर्नमेंट की ओर से हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो माल इनसे लेना था क्या वह माल दूसरी लाइन पर काम नहीं आ सकता था, उस कम्पनी से माल लेकर दूसरे पर्पज में काम ला सकते थे ?

श्री हरिदेव जोशी : स्पेसिफिक पर्पज के लिए था और स्पेसिफिक पर्पज के ही काम आ सकता था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पब्लिक प्रोसीक्यूटरों की नियुक्तियां एवं उनकी वेतन शृंखला

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री शिवनाथ सिंह)

(१) राजस्थान में पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एडीशनल पब्लिक प्रोसीक्यूटर व असिस्टेन्ट पब्लिक प्रोसीक्यूटर कहां-कहां व किस-किस कोर्ट में तैनात हैं ? इनकी लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । प्रत्येक की वेतन शृंखला क्या है ?

(२) इन पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स, एडीशनल व असिस्टेन्ट प्रोसीक्यूटर्स की क्या-क्या तनख्वाह है ? क्या यह सही है कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की तनख्वाह में राजस्थान बनने के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है ?

(३) क्या सबको वेतन एक समान दिया जाता है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों होता है ?

(४) क्या राजस्थान सरकार इनके वेतन में जो अन्तर है उसे खत्म कराने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) इनके सिलेक्शन के लिए कोई रूल्स बनाये हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? सरकार ऐसे रूल्स कब तक बनाने का इरादा रखती है ?

(६) इस वक्त जो इनका सिलेक्शन होता है वह किस क्राइटेरिया के तहत होता है ?

(७) इनका जो एपोइंटमेंट होता है वह एक साल के लिए होता है या तीन सालों के लिए या परमानेन्ट बेसिस पर ?

(८) क्या सरकार पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की तनख्वाह या मंहगाई भत्ता बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिसमें प्रत्येक की वेतन शृंखला अंकित है।

(२) तनख्वाह (रिटेनर) सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है। पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की तनख्वाह में राजस्थान बनने के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

(३) जी नहीं। वेतन स्थान का महत्व, बार की स्थिति तथा कार्य भार के अनुसार निश्चित किया जाता है।

(४) वेतन स्थान का महत्व, बार की स्थिति तथा कार्यभार के अनुसार दिया जाता है, इसलिये अन्तर समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी हां, नियुक्ति के नियम बने हुए हैं।

(६) पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स, एडीशनल पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स व असिस्टेन्ट पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धि जिला दण्डनायक वकीलों से प्रार्थनापत्र प्राप्त करते हैं और उनकी (वकीलों की) सिविल एवं क्रिमिनल प्रेक्टिस की योग्यता को ध्यान में रखते हुए जिला सत्र न्यायाधीश की सम्मति के साथ सरकार के पास योग्यता क्रमानुसार अपनी सिफारिश भेजते हैं, जिसके पश्चात सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है।

(७) सर्व प्रथम नियुक्ति ६ माह की परिविक्षाधीन अवधि के लिये की जाती है। फिर जिला दण्डनायक व सत्र न्यायाधीश की सिफारिश पर आगे ज्यादा से ज्यादा एक बार तीन साल तक के लिये बढ़ाई जा

(विधि मंत्री)

सकती है। परमानेन्ट बेसिस पर अब नियुक्ति नहीं की जाती है।

(८) तनख्वाह का मामला विचाराधीन है। अंशकालिक पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स, वगैरह को मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। अतः उनका मंहगाई भत्ता बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों का चालान

७४३. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सही है कि राज्य सरकार ने एक आदेश द्वारा कृषि-उपज मंडियों के व्यापारियों के चालान करने के अधिकार को समाप्त कर दिया है ?

(२) क्या सरकार को नियमों में संशोधन किये बगैर ऐसे अधिकार समाप्त करने का अधिकार है ?

(३) अगर नहीं, तो सरकार ने ऐसा क्यों किया ?

उत्तर

(१) जी नहीं। राज्य सरकार ने यह आदेश दिया था कि विभिन्न कृषि उपज मंडियों से अगला निर्णय होने तक कोई नये चालान सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किये जावें।

(२) सरकार ने मंडी समितियों के कोई अधिकार समाप्त नहीं किये हैं। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में एकत्रित धनराशि

७४४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में राजस्थान से अब तक कुल कितनी धनराशि जमा हुई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि सुरक्षा कोष में धनराशि देने के पश्चात् रसीद दिया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को इस प्रकार की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई कि सुरक्षा कोष में प्राप्त धनराशि के हिसाब में गड़बड़ियां हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इन शिकायतों की जांच कराई ? जांच के फलस्वरूप कौन कौन व्यक्ति व संस्थायें दोषी पाई गईं ?

(३) क्या रक्षा कोष का आडिट करवाया गया ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अक्टूबर, १९६२ से ३० मई, १९६७ तक जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल २,६४,४१,७३८) २८ जमा कराया गया— जिलेवार विवरण की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No. 40

(श्री मुख्य मंत्री)

(२) सुरक्षा कोष में धनराशि प्राप्त करने के लिए रसीद दिया जाना अनिवार्य है। सुरक्षा कोष में प्राप्त धनराशि के हिसाब से संबन्धित कुल ४६ शिकायतें मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुई। जांच के पश्चात् १५ शिकायतें तथ्यहीन पाई गई और ३० शिकायतें विचाराधीन हैं। एक मामले में रकम विलम्ब से जमा कराने पर सम्बन्धित अध्यापक को चेतावनी दी गई।

(३) सुरक्षा कोष का हिसाब राज्य के २६ जिलों के जिलाधीश कार्यालयों एवं मुख्य मंत्री कार्यालय में रखा जाता है। इन कार्यालयों में रखे गये हिसाब का आडिट समय-समय पर होता रहा है। इन सब आडिट रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

बारां क्षेत्र के सहायक रजिस्ट्रार का रिक्त स्थान

७४९. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बारां क्षेत्र के सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बारां की जगह कितने समय से खाली पड़ी हुई है और किन कारणों से ?

(२) इस स्थान की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(१) बारां क्षेत्र के सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का पद दिनांक १७–६–६७ से खाली था। इस पद को निरीक्षकों में से पदोन्नत करके भरना था। क्योंकि उनकी वरिष्ठता विचाराधीन है, यह पद कुछ समय खाली रहा।

(२) इस स्थान पर नियुक्ति करदी गई है।

राज्य में बड़े उद्योगों के लिए प्रयास

७५५. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) केन्द्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो हेवी इन्डस्ट्री लगाई जाती है उसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य में कितनी लगाई गई ?

(२) क्या यह सही है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान को इस बार में बिल्कुल भुलाया गया है ?

(३) यदि हां, तो कारण क्या है ?

(४) क्या राज्य सरकार ने कभी इस बारे में प्रयास किये हैं ?

(५) यदि हां तो, कौन कौन से उद्योग के लिए प्रयास किया गया और किन आधारों पर नामंजूर किये गये ?

उत्तर

(१) केन्द्र द्वारा ३ उद्योग लगाये गये तथा एक लगाया जा रहा है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता

(४) जी हां।

(उद्योग मंत्री)

(५) राज्य सरकार ने निम्न उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की :—

(क) इन्स्ट्रूमेन्टेसन लिमिटेड, कोटा

(ख) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर

(ग) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतड़ी

(घ) मशीन टूल कारपोरेशन लिमिटेड, अजमेर। टेलीफोन इन्डस्ट्री लगाने के लिए प्रयास हो रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

किसानों को अल्पकालीन ऋण

३४९. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कृषि उत्पादन हेतु किसानों को राज्य सरकार ने अल्पकालीन कर्जे दिये हैं ? यदि हां, तो पिछले ५ वर्षों में ये कर्जे प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी धनराशि, बीज व खाद के रुप में दिये गये ? प्रत्येक जिले का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि अल्पकालीन ऋण फसल के बाद वापस वसूल कर लिया जाता है ? यदि हां, तो अब तक ५ वर्षों में दिये गये अल्पकालीन ऋणों की वसूली क्यों नहीं हुई ? प्रत्येक जिले के कारण बतावें।

(३) क्या यह सही है कि अल्पकालीन ऋण पर बाड़ी या ब्याज लगाया जाता है ? और समय पर भुगतान न करने पर पेनल इन्ट्रेस्ट भी लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

कर्जे की सिक्योरिटी

३५०. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री शान्तिलाल जोशी निवासी ग्राम पंचायत मांगलियावास जिला अजमेर ने कोई कर्जा सहकारी विभाग से ले रखा है ? यदि हां, तो कब से व कितना कर्जा ले रखा है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कर्जे की सिक्योरिटी में रखी हुई अपनी तमाम जायदाद श्री शांन्तिलाल जोशी ने अपने भान्जे के नाम रजिस्ट्री कर दी है ? यदि हां, तो सहकारिता के कर्जे की क्या सिक्योरिटी है ?

उत्तर

(१) श्री शान्तिलाल जोशी ने सहकारी विभाग से कोई ऋण नहीं ले रखा हैं परन्तु मांगलियावास ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० से १०००) रु० अल्पकालीन ऋण दिनांक २१–८–६३ से ले रखा है।

(२) श्री शान्तिलाल जोशी ने जो अल्पकालीन ऋण लिया है उसके लिये दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत जमानत है कोई जायदाद की जमानत नहीं है। इसलिए कर्जे की सिक्योरिटी की जायदाद अपने भानजे के नाम रजिस्ट्री करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

लेवी की वसूली एव अनाज की खरीद पर सरकार द्वारा विचार

३५१. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

इस वर्ष फसल रबी के अच्छे व अधिक उत्पादन की आशा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार लेवी कतई नहीं लेने और खरीद सीधी मंडियों से करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) गेहूँ की खरीद राज्य सरकार करेगी परन्तु तत्सम्बन्धी नीति अभी निर्धारित नहीं हुई है ।

तहसील छीपाबड़ोद से चलने वाली बसें

३५२. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील छीपाबड़ोद के सालपुरा से छीपावड़ोद, सारथल, इकलेरा होती हुई मनोहरथाना व सालपुरा से छीपावड़ोद इकलेरा तक कितने परमिट बसों के लिए जारी हैं ?

(२) उपरोक्त बसों के मालिकों द्वारा अपने निर्धारित रास्तों पर १ जनवरी सन् १९६७ से ३० दिसम्बर, १९६७ तक कितनी बार समय-समय पर बसें चलाई गई ? अगर बस मालिकों द्वारा बसें बराबर नहीं चलाई गई तो उन बस मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

१—(क) सालपुरा मनोहर थाना वाया छीपाबड़ोद, सारथल इकलेरा ल्हास मार्ग पर दो बसों के परमिट हैं ।

(ख) सालपुरा मनोहर थाना वाया छीपावड़ोद सारथल इकलेरा हरनावदा मार्ग पर चार यात्री वाहनों के परमिट हैं ।

(ग) सालपुरा से छीपाबड़ोद इकलेरा कोई मार्ग नहीं है ।

२—(क) सालपुरा मनोहर थाना वाया ल्हास होकर चलने वाली दो यात्री वाहनें आर जे—जी २६२ एवं । आर जे—आर ३४५७

जिनमें से आर जे-जी २६२ के मालिक पर सन् १९६७ में न चलने के अपराध को पचास रुपये से संधान किया जा चुका है ।

(ख) इस मार्ग पर चार बसों के सन् १९६७ में न चलने के अपराध में बस नं० आर. जे. ओ. ९२ का अनुज्ञापत्र रद्द किया जा चुका है एवं शेष तीन बसों के अपराध को १२५ रु० प्रत्येक बस संधान किया जा चुका है ।

(ग) यह मार्ग अब बपावर सालपुरा छीपावड़ोद इकलेरा बन गया है और इस पर वाहन संख्या आर. जे. आर १५६७ के न चलने पर ४००) संधान शुल्क लिया जा चुका है ।

आयुर्वेद विभाग से हकीम व वैद्यों की स्थाई नियुक्तियां

३५३. **श्री दुर्गालाल आढ़वार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि आयुर्वेद

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

विभाग में हकीम व वैद्यों का जो सन् १९६३ से पहले के कर्मचारी थे, स्थायी नियुक्तियां दे दी गई हैं ?

(२) कितने वैद्य और हकीम ऐसे हैं जो सन् ६३ से पहले से काम कर रहे हैं पर उन्हें स्थायी नहीं किया गया है ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और ऐसा नहीं करने का क्या कारण है ?

(३) क्या वैद्य और हकीमों के स्थानान्तरण करने के कोई नियम हैं ? यदि नहीं, तो स्थानान्तरण करने में विभाग किस आधार से कार्य करता है ? यदि नियम हों तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(४) आयुर्वेद व यूनानी पद्धति से चलने वाले औषधालयों की कितनी श्रेणियां हैं ? और प्रत्येक श्रेणी के औषधालय में किस-किस योग्यता के हकीम व वैद्य नियुक्त किये जाते हैं ?

(५) हकीम तथा वैद्य की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है और इस योग्यता के अतिरिक्त कितने वैद्य व हकीम नियुक्त किये गये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, ऐसे सभी वैद्य, हकीमों को स्थायी नियुक्तियां दे दी गई हैं।

(२) ऐसा कोई वैद्य, हकीम नहीं हैं जो सन् ६३ से पूर्व कार्यरत हो और अस्थाई हो । अतः सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(३) जी नहीं । सामान्यतया परिवर्तन सरकार द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार ही दिये जाते हैं । पृथक नियम नहीं होने से प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(४) आयुर्वेद व यूनानी पद्धति से चलने वाले औषधालयों की वर्तमान में (अ), (ब) और (स) तीन श्रेणियां हैं । नियमानुसार (ए) एवं (बी) श्रेणी में पदोन्नतियां ही की जाती हैं तथा (सी) श्रेणी में वैद्य ग्रेड III के पद के लिए भिषग्वर (राजस्थान) तथा हकीम पद के लिए तबीबफाजिल न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित हैं ।

इसके अलावा नियुक्तियों में प्राथमिकता भिषगाचार्य (राजस्थान) एवं तत्सम को दी जाती हैं । (बी) व (ए) श्रेणी में वैद्य ग्रेड II व I के पद के लिए सेकन्ड डिविजन भिषगाचार्य व तत्सम व हकीम के लिए कामिल उल त्तिब्बूल जराहत (देहली) एवं तत्सम योग्यता निर्धारित हैं।

(५) राजस्थान आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियम सन् १९६६ (प्रकाशन २८-१२-६६) में हकीम तथा वैद्य के लिए तबीबफाजिल व भिषग्वर योग्यताएं न्यूनतम क्रमशः निर्धारित की गई हैं और नियम के विरुद्ध न्यूनतम योग्यता के अभाव में कोई नियुक्ति नहीं की गई हैं ।

मेड़ता से अजमेर चलने वाली बसों की व्यवस्था

३५४. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गोरधन सोनी)

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व यातायात मन्त्री के आश्वासन के बावजूद पुष्कर में दो बस स्टेन्ड हैं जिससे यात्रियों को बस बदलने में परेशानी होती है ?

(२) क्या यह सही है कि बावजूद भूतपूर्व यातायात मन्त्री के आश्वासन के अब तक मेड़ता से सीधे अजमेर बसें चलाने की व्यवस्था नहीं है जिससे मेड़ता से अजमेर या उससे आगे व उधर से आने वाले यात्रियों को बस बदलने में तकलीफ होती है व आते व जाते वक्त 10 न. पै. नगर-पालिका पुष्कर को देने पड़ते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि मेड़ता एक मंडी व सेशन कोर्ट होने के नाते वहां से बड़ी संख्या में बसों व ट्रकों का आना जाना रहता है ?

उत्तर

(१) पुष्कर में दो बस स्टेण्ड हैं पर सरकार की ओर से एक ही बस स्टेण्ड रखने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(२) मेड़ता से सीधी अजमेर बस चलाने की कार्यवाही प्रादेशिक परिवहन अधिकरण जोधपुर द्वारा चालू है ?

(३) जी हां।

जिला बांसवाड़ा को जिला डूंगरपुर से मिलाने वाली रेल्वे लाइन

३५५. श्री रतनलाल रोत (चौरा-सी-सु): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार जिला बांसवाड़ा को जिला डूंगरपुर से मिलाने के लिये रेल्वे लाइन रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा जोड़ने के प्रस्ताव भारत सरकार से करने का विचार रखती है ताकि इस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके ?

उत्तर

जी हां।

रोडवेज बस दुर्घटनाएं

३५६. श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान रोडवेज विभाग की बसों की गत सात माह में कितनी बार दुर्घटनाएं हुई और उसके कारण कितने यात्री मारे गए और कितने रुपयों का नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या सरकार ने रोडवेज बसों की आए दिन होने वाली बस दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ?

(३) क्या सरकार ने बस दुर्घटना रोकने हेतु कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(४) क्या सरकार ने मृत यात्रियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया है ? यदि हां, तो किस-किस को कितना रुपया दिया ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(यातायात मंत्री)

(२) ऐसी कोई जांच अभी नहीं कराई गई है। अलबत्ता निगम अपने अधिकारियों द्वारा विभागीय जांच हर दुर्घटना के बारे में कराता है।

(३) निगम आवश्यक कार्यवाही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए करता है। निगम ने बसों की रफ्तार निर्धारित कर रखी है व समय समय पर चालकों को दुर्घटनाओं की तरफ सचेत रहने की हिदायतें जारी की हैं।

(४) जी नहीं क्योंकि निगम के विरुद्ध मुआवजा देने का कोई भी फैसला अभी तक नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

रोडवेज की बसें

३५७. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रोडवेज में इस वक्त कुल कितनी बसें हैं? इन बसों में से कितनी ऑन दी रोड हैं और कितनी ऑफ दी रोड हैं? कितनी रिपेयर के लिए पड़ी हैं?

(२) उक्त बसों की तकनीकी मरम्मत मेकर्स के नियमानुसार न होने के क्या-क्या कारण हैं?

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में इस समय ५३७ बसें हैं जिनमें से ३३० बसें ऑन दी रोड हैं। व २०७ बसें ऑफ दी रोड हैं। उक्त २०७ आफ दी रोड बसों में से ४० बसें रिपेयर के लिये हैं।

(२) बसों की मरम्मत नियमानुसार व मेकर्स से स्टेण्डर्ड के अनुसार ही होती है।

बसें फेल होने के कारण

३५८. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): क्या राज्य परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत वर्ष में रोडवेज की किस-किस रूट पर कौन-कौन सी बसें फेल हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इनके फेल होने के मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं?

(३) रोडवेज बसों के फेल होने व कुव्यवस्था की कुल शिकायतें अब तक कितनी आई हैं? सरकार ने इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की?

(४) इन बसों के फेल होने के कारणों को दूर करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) फेल होने के कारण उपरोक्त सूची में अंकित हैं।

(३) १९६७ में बसों के फेल होने की कुल दो शिकायतें आई, जांच के बाद प्रादेशिक यांत्रिक अभियन्तां ने जांच की। लघु यांत्रिक खराबियां साधारणतया रास्ते में हो जाना सम्भावित रहता है। उन सवारियों को यथा स्थान पहुंचा दिया जाता

(राज्य परिवहन मंत्री)

है। यथा शक्ति जांच के बाद भी कुछ आकस्मिक यांत्रिक खराबियों के कारण बस फेल होने पर समुचित व्यवस्था तुरन्त की जाती है।

(४) ब्रेक डाउन पिछले दो माहों में करीब २०० हुये हैं। ब्रेक डाउन आकस्मिक यांत्रिक खराबियां जो टायर बर्स्ट या झटकों से या पाईप लाईन बर्स्ट के कारण होती हैं, उनको शत प्रतिशत किसी प्रकार नहीं रोका जा सकता परन्तु यथा शक्ति जांच की पूरी व्यवस्था की जाती है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट में व्यय हुई धनराशि

३५६. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् ६६-६७ व ६७-६८ में मंत्रियों एवं उपमंत्रियों द्वारा डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट में से कितना-कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(ख) यह रुपया किन-किन को दिया गया है ? कृपया पतेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या इस डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुये हैं ? यदि हां, तो कृपया उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(क) वांछित सूचना संलग्न तालिका परिशिष्ट 'क' में अंकित करदी गई है।

(ख) मन्त्री वार सूची संलग्न तालिका परिशिष्ट (ख) में अंकित करदी गई है।

(ग) जी हां, मुख्य मन्त्री एवं अन्य मन्त्रियों के स्वेच्छानुदान के पृथक-पृथक नियमों की प्रति संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम छीपाबड़ौद में मिडिल स्कूल भवन का निर्माण

३६०. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम छीपाबड़ौद जिला कोटा में छात्राओं के पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल भवन है ? अगर नहीं है तो क्या सरकार वहां पर मिडिल स्कूल भवन बनवाना चाहती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या इस स्कूल भवन को बनवाने के लिए ग्राम पंचायत छीपाबड़ोद में धनराशि जमा है ? अगर हां, तो कितनी ?

(३) क्या कलेक्टर कोटा ने अपने चेरिटी फण्ड में से १०,०००/-या१५,०००/- रु. देने का कहा था ? अगर हां, तो अब तक यह धनराशि किसे दी गई है और नहीं दी गई, तो क्यों ?

उत्तर

(१) ग्राम छीपाबड़ौद में छात्राओं के पढ़ने के लिये राजकीय कोई पृथक भवन नहीं है। कन्याशाला के लिये नये भवन

(शिक्षा मंत्री)

का निर्माण जनता के सहयोग पर निर्धारित है।

(२) इस सम्बन्ध में स्थानीय कार्यालय को कोई सूचना नहीं है।

(३) कलेक्टर कोटा द्वारा चेरिटी फण्ड से १५,००० रु० भवन निर्माण हेतु देने पंचायत समिति की मीटिंग में आश्वासन दिया था। यह राशि किसी को दी गई है अथवा नहीं स्थानीय कार्यालय को कोई सूचना नहीं है।

हरनावदा शाहजी में मिडिल स्कूल

३६१. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबड़ोद जिला कोटा में मिडिल स्कूल है तथा स्कूल चलाने के लिए भवन उपलब्ध है?

(२) इस स्कूल की छात्र संख्या कितनी है?

(३) क्या सरकार इस मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में परिणित करना चाहती है? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी हां, भवन अपर्याप्त है।

(२) ३०५।

(३) अगले वर्ष ऐसे ही अन्य स्कूलों के साथ सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस पर भी विचार किया जायेगा।

प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में परिवर्तन

३६२. श्री नाथूदास (फलासिया–सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम बाधपुरा तहसील फलासिया जिला उदयपुर में जो प्राथमिक शाला है उसे माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने की सरकार की कोई योजना है?

(२) यदि हां, तो क्या अगले सत्र से उक्त प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला बनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) ग्राम बाधपुरा तहसील फलासिया जिला उदयपुर की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने के वास्ते अगले वर्ष विद्यालय निरीक्षक व जिला परिषद उदयपुर से प्रस्ताव मांगे जायेंगे और उन प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा। अभी से अगले वर्ष में खोले जाने वाली शालाओं के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(२) भाग (१) में स्पष्ट है।

शिक्षण संस्थाओं में स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्तियां

३६३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि शिक्षण

(श्री हरजीराम बुरड़क)

संस्थाओं में कोई पार्ट टाइम स्वास्थ्य या चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं? यदि हां, तो लाडनूं क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में किन-किन को कब-कब चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया और उनको कितना-कितना पारिश्रमिक कब-कब दिया गया तथा उनकी योग्यता क्या है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उक्त अधिकारी सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों में से नियुक्त किये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलें, कस्बा लाडनूं

३६४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कस्बा लाडनूं जिला नागौर में कितनी स्कूलें सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं और उनको कितनी-कितनी सहायता सालाना किस पर्सेन्टेज के हिसाब से दी जाती है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इन सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए कोई सर्विस रूल्स बने हुए हैं?

(३) क्या इन सहायता प्राप्त स्कूलों का मैनेजमेन्ट इतना अच्छा है कि वे राज्य सरकार के टेक्निकल स्टाफ के समान ही व्यवस्था कर लेते हैं? अगर नहीं, तो क्या पढ़ाई के स्तर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है?

(४) सहायता प्राप्त स्कूलों के खोलने संबंधी सरकार की क्या नीति है और किन किन शर्तों पर ये स्कूल खोले जाते हैं?

उत्तर

(१) कस्बा लाडनूं में स्कूलों की सूची मय गत वर्ष स्वीकृत राशि एवं मान्य व्यय पर प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

नाम	मान्य व्यय	प्र.श.	स्वीकृत राशि
(१) जौहरी उ. मा.- विद्यालय, लाडनूं			--७८७२ सरकार द्वारा २५-७-६६ से राज्याधीन किया गया।
(२) महावीर उ.मा शाला, लाडनूं	५८३२५	७०	४०८२७
(३) महावीर प्राथमिक शाला लाडनूं	१७३४२	७०	११६७२
(४) जे. वी. उ.मा. वि. लाडनूं	५९८१४	७०	४१८७०
(५) के.वी.प्राथमिक शाला, लाडनूं	२१३४७	७०	१४९४३
(६) राष्ट्रीय विद्यालय लाडनूं	१०१७८	६०	६१०७
(७) बालभारती विद्यालय, लाडनूं	८२५५	५०	४१२८

(२) सहायता प्राप्त संस्थाओं के अलग से सर्विस नियम नहीं हैं। वेतन

Page No. 49

(शिक्षा मंत्री)

शृंखला, अवकाश, महंगाई भत्ता सरकारी नियमानुसार, अनुदान नियम के अन्तर्गत अनुबन्ध के अनुसार दिये जाने का प्रावधान है।

(३) पढ़ाई के स्तर का सम्बन्ध मैनेजमेन्ट से न होकर शिक्षित व योग्य अध्यापकों के चयन तथा पर्याप्त पाठन सामग्री पर निर्भर करता है और अनुदान नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था के लिए आवश्यक है कि वे योग्य और शिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति करें।

(४) सहायता प्राप्त संस्थाओं के खोलने का कार्य सरकार द्वारा नहीं होता है, मान्यता प्राप्त चालू संस्थाओं में से जो नियम २ और ३ का पालन करती हैं उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार अनुदान समिति की सिफारिश उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार विचार करती है।

ट्रन्ड ग्रेज्युएट अध्यापक

३०५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह बात सही है कि राज्य सेवा में बहुत से ट्रेन्ड ग्रेजुएट अध्यापक हैं जिनको अभी तक तृतीय वेतन शृंखला में ही नियुक्त किया हुआ है ?

(२) ऐसे अध्यापकों को द्वितीय वेतन शृंखला में पदोन्नति करते समय प्राथमिकता किस आधार पर दी जाती है ? राज्य सेवा में प्रवेश होने की तिथि के आधार पर अथवा ट्रेन्ड ग्रेज्युएट बनने की तारीख के आधार पर अथवा परीक्षा में प्राप्त नम्बरों या डिवीजन के आधार पर ?

(३) क्या यह सही है कि एस. टी. सी. पास मेट्रीक्यूलेट्स को राज्य सेवा में भर्ती करते समय उनकी योग्यता (मैट्रिक में प्राप्त डिवीजन) के आधार पर ही प्राथमिकता दी जाती है ?

(४) क्या राज्य सेवा में होते हुए ट्रेनिग प्राप्त करने वालों और राज्य सेवा से बाहर रहकर ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों के भर्ती के आधारों में अन्तर रखा जाता है ?

(५) राजस्थान में ऐसे एस. टी. सी. ट्रेन्ड मेट्रीक्यूलेट्स की संख्या क्या-क्या होगी जिनको अभी तक राज्य सेवा में नहीं लिया जा सका है ?

उत्तर

१. यह सत्य है।

२. द्वितीय वेतन शृंखला में पदोन्नति वरिष्ठता और निर्धारित योग्यता के आधार पर दी जाती है। पदोन्नति में मैरिट और वरिष्ठता क्रम योग्यता १:२ का अनुपात होता है। निर्धारित योग्यता के उपरान्त वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाती है।

३. तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती के लिए मैट्रिक और एस० टी० सी० परीक्षा के नम्बरों के प्रतिशत और अन्य योग्यताएं जैसे खेलकूद, स्काउटिंग, वाद-विवाद इत्यादि के नम्बर भी जोड़े जाते

(शिक्षा मंत्री)

हैं। इस तरह इन सारे नम्बरों की जोड़ भर्ती के लिए शुमार की जाती है।

४. राज्य सेवा में नियुक्त अध्यापकों की पदोन्नति ५० प्रतिशत और सीधी भर्ती ५० प्रतिशत होती है। पदोन्नति में योग्यता और वरिष्ठता कम योग्यताएं का १:२ का अनुपात होता है। विभागीय अध्यापकों को पदोन्नति दी जाती है तो नए अध्यापक भर्ती किये जाते हैं।

५. यह बताना संभव नहीं है।

विदेश अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति वालों को भेजना

३६६. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्ष १६६६-६७ में देश के बाहर कितने व्यक्तियों को शिक्षा के लिये भेजा गया है और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कितने हैं ?

(२) क्या सरकार इस वर्ष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को विदेश अध्ययन के लिये भेजने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) शिक्षा विभाग द्वारा देश के बाहर किसी व्यक्ति को नहीं भेजा जाता है परन्तु उच्च अध्ययन के लिये जाने वाले व्यक्तियों को इस विभाग द्वारा अध्ययन ऋण स्वीकृत किया जाता है। वर्ष ६६-६७ में इस विभाग द्वारा ११ व्यक्तियों को अध्ययन ऋण स्वीकृत किया गया था।

(२) भाग (१) में स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

पाली में हायर सेकेन्डरी स्कूलें

३६७. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ऐसी-ऐसी हायर सेकेन्डरी पाठशालायें भी पाली जिले में हैं जिनमें शिक्षकों की संख्या के अनुपात में छात्र अभी तक भी नहीं हो पाये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पाली जिले में सादड़ी, बाली, तखतगढ़ व सुमेरपुर की सैकेण्डरी स्कूलों में छात्रों की संख्या अत्यधिक होते हुए भी उन्हें हायर सैकेण्डरी नहीं बनाया गया है ? अतः सैकड़ों छात्रों (जो दसवीं में उत्तीर्ण होते हैं) को ग्यारहवीं कक्षाओं में प्रवेश हेतु बहुत भटकना पड़ता है ? इन चारों स्थानों की सैकेण्डरी पाठशालाओं को हायर सैकेण्डरी में परिवर्तित करने हेतु क्या जिला निरीक्षक पाठशालायें, पाली ने सुझाव अपने उच्चाधिकारियों को भेजा है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) सुमेरपुर (जिला पाली) की कन्या पाठशाला का भवन चार वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है तो कन्या शिक्षा को प्राथमिकता देने हेतु सरकार इस शाला का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी कब तक पूर्ण करवा देगी ?

Page No. 51

उत्तर

१. यह सही है कि पाली जिले में कुछ उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्र संख्या पर्याप्त नहीं है इस संबंध में समस्त राज्य की समस्त संस्थाओं के बारे में अध्ययन पर उचित सुझाव देने हेतु राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसी शालाओं को बन्द करने पर पास की शालाओं में मिलाने हेतु उचित कार्यवाही की जावेगी। पाली जिले की ऐसी शालाओं के निम्न नाम हैं जहाँ २० से कम प्रति अध्यापक छात्र संख्या है :—

(१) बगडी (२) सेवारी (३) राबी (४) कालू (५) नीमज (६) अबां (७) दूंसरी (८) नाडोक

२. विभाग कई वर्षों से हाई स्कूलों को हायर सैकेण्डरी नहीं कर रहा है क्योंकि शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि स्कूल स्तर पर १२ वर्ष का पाठ्यक्रम हो। राज्य सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

३. राज्य सरकार धनाभाव के कारण भवन निर्माण के लिये जन सहयोग अपेक्षित करती है। गत कई वर्षों से केवल उन्हीं भवन निर्माण कार्यों के लिये ऐसा किया जा रहा है जो पहले से चल रहे हों। सुमेरपुर कन्या शाला के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी शालाएं हैं जहां भवन व्यवस्था ठीक नहीं है परन्तु राज्य सरकार धनाभाव के कारण इनकी पूर्तिके लिये धन-राशि देने में असमर्थ है।

कपूरडी खान बाड़मेर

३६८. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की कपूरडी खान सन् ६५ से बन्द पड़ी है, यदि हां, तो क्यों ?

(२) इसके कारण राज्य सरकार को कितनी हानि हुई है, तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(१) जी हां कपूरडी एवं आलम सरिया का मुलतानी मिट्टी का क्षेत्र का खनन पट्टा पूर्व में श्री रामलाल एण्ड सन्स को ५ वर्ष के लिये ६४०००) रु. सालाना पर संचालक के आदेश संख्या डी एम जी.जे. आवे। एस.सी. ३३६। ६०६। ५४ दिनांक १३-१२-५४ से स्वीकृत किया गया था। खनन पट्टे की अवधि की समाप्ति पर इसी वार्षिक डेडरेन्ट पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक १२-२-६० के द्वारा प्रथम नवीनीकरण आगामी ५ वर्ष के लिए किया गया जो अवधि दिनांक २०-१२ ६४ को समाप्त हुई। इसके बाद द्वितीय नवीनीकरण राज्य सरकार द्वारा ८०,००० रुपये सालाना पर राज्यादेश संख्या एफ ४ (१) (३३) ईन्ड (बी) ६४। २३६० दिनांक २५-३-६५ द्वारा किया गया किन्तु पार्टी को डेडरेन्ट की रकम मंजूर नहीं थी अतएव उसने संविदा संपादन नहीं किया और उसी कारण राज्यादेश संख्या एफ ४ (१) (३३) इन्ड (ब) ६२। ४६६७ दिनांक २६ जुलाई १९६५ के द्वारा खनन पट्टे को निरस्त कर दिया गया। तदुपरान्त इस क्षेत्र को दिनांक

(खनिज मंत्री)

१३-१-६६ एवं १६-६-६६ को नीलाम किया गया किन्तु बोली नहीं आने से रिक्त पड़ा रहा। तदुपरान्त इस क्षेत्र को नीलाम पर न उठाकर प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने हेतु चार हिस्सों में विभाजित किया जाकर राजस्थान राजपत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित दिनांक २७-१०-६६ को कराई गई एवं आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। दिनांक २९-११-६६ को १४ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। प्रायोरिटी बेसिस पर एवं अनुभव के आधार पर तरजीह दी जाकर निदेशालय के पत्र संख्या डी एम जी एफ २ (ए) (५७)जे ओ० । अ५० । ६६-४६३ दिनांक २७-६-६७ द्वारा प्रस्ताव पारित हुए।

कस्बा छीपाबड़ोद में हाइड्रोलिक बिजली की योजना

३६९. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या छीपाबड़ोद तहसील, जिला कोटा के कस्बे छीपाबड़ोद को हाइड्रोलिक बिजली बारां होकर देने की सरकार की योजना है ? अगर हाँ, तो कब तक यह योजना पूरी हो जावेगी ?

(२) क्या सरकार इस तहसील में गांवों में खेती के लिए बिजली देना चाहती है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(३) क्या इसी प्रकार तहसील छबड़ा में भी सप्लाई करने की सरकार की योजना है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। ३१-३-६८ तक पूर्ण होने की आशा है।

(२) जी हां। लाइन खिच जाने के बाद।

(३) जी हां।

पत्रों को विज्ञापन

३७०. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या सार्वजनिक सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा किस-किस पत्र को किस-किस प्रकार का व कितने-कितने मूल्य का विज्ञापन दिया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि विज्ञापन के देने में सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों की अवहेलना की गई है ? यदि हां, तो क्यों और किन-किन मामलों में ?

उत्तर

(१) तालिका की प्रतियां साथ में संलग्न हैं। (तालिका संलग्न है)।

(२) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बिजली की लाईन

३७१. श्री दुर्जनसिंह (रानीवाड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री दुर्जनसिंह)

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने गुजरात से पालनपुर होती हुई भीनमाल वाया रानीवाड़ा बिजली लाने की योजना स्वीकृत की है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जावेगा ?

(२) इस योजना के तहत कौन-कौन से क्षेत्र को बिजली दी जावेगी और कब तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली जिला कृषक समाज, सुमेरपुर द्वारा कुओं को बिजली की मांग

३७२. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली जिला कृषक समाज सुमेरपुर, राजस्थान सरकार से सन् १९६३ से बार बार लिखा पढ़ी (आवेदन पत्रों व तारों द्वारा) निवेदन करता रहा है फिर भी क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुओं को बिजली देने की व्यवस्था अभी तक भी ठीक नहीं की है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं व सुचारु रूप से विद्युत देने की व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

जी नहीं

प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व जागीरों के कर्मचारियों को नियमानुसार सहूलियतें

३७३. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या उद्योग विभाग में भूतपूर्व जागीरों के कर्मचारियों को लिया गया था ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को लिया गया था ?

(२) क्या ऐसे सभी कर्मचारियों को नियमानुसार सभी सहूलियतें प्रदान करदी गई थीं ?

(३) यदि नहीं, तो इनके संबंध में कब तक निर्णय हो जायेगा ?

उत्तर

(१) जी, हां

केवल एक व्यक्ति को।

(२) जी, हां।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

रॉयल्टी की वसूली, सवाई माधोपुर

३७४ श्री अवरणलाल (हिण्डौन-सु.) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर में किस-किस में कितनी-कितनी रकम रॉयल्टी की कब-कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) बकाया वसूली के लिये क्या

(श्री श्रवणलाल)

कार्यवाही की जा रही है और कब तक वसूली हो जावेगी ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) बकाया वसूली की कार्यवाही जो की जा रही है उसकी टिप्पणी सूची बकाया में अंकित करदी गई है।

यह बकाया की रकम ६८–६९ में वसूल हो जाने की आशा है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम मकराना का विद्युतिकरण

३७५. **श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू के ग्राम मकराना का विद्युतिकरण हुए कितना अर्सा हुआ ?

(२) उस गांव में कितने ट्रांसफारमर लगाये गये हैं तथा प्रत्येक से कितने-कितने कनेक्शन लगाये जा चुके हैं ?

(३) ग्राम मकराना में बिजली लेने के लिये कितनी दर्ख्वास्तें अभी तक पेंडिग पड़ी हैं जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा सका है ? प्रत्येक की तारीख दर्ख्वास्त पेश होने की देने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) २ वर्ष

(२) मकराना ग्राम में केवल एक ट्रांसफारमर लगाया गया है। इस ग्राम में अभी तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है।

(३) संलग्न सूची में दिखादी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

तहसील पचपदरा में कुओं पर बिजली

३७६. **श्रीमती मदन कौर (पचपदरा):** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पचपदरा तहसील के आसोतरा एवं बीठूजा गांवों के कितने कुओं पर बिजली उपलब्ध कराई जा चुकी है ?

(२) उक्त दोनों गांवों के कितने काश्तकारों के बिजली लेने हेतु प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित अधिकारियों के पास कब से विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) पचपदरा तहसील के आसोतरा एवं बीठूजा ग्रामों में अभी तक एक भी कुए को बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

(२) आसोतरा ग्राम के २३ एवं बीठूजा ग्राम के १६ प्रार्थनापत्र कुओं पर विद्युत देने हेतु पेंडिग पड़े हुए हैं। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 55

बिजली की लाइनों पर व्यय

३७७. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर सब-डिविजन में बिजली की वर्तमान लाइनों के प्रसार अथवा नई लाइनें लगाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में इस सब-डिवीजन में व्यय के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(२) उक्त राशि से कितने कूपों (वैल्स) में कनेक्शन दिये जाने में विभाग सक्षम हुआ ?

उत्तर

(१) चालू वित्तीय वर्ष में सवाई माधोपुर सब-डिवीजन में वर्तमान लाइनों के प्रसार हेतु ३०,०००/ रु० दिये गये हैं। नई लाइनें डालने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कोई रकम स्वीकृत नहीं हुई है ।

(२) कुओं पर बिजली देने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में सवाई माधोपुर सब-डिवीजन को ४०,०००/- रु० दिये गये हैं जिससे ३१-१-६८ तक २६ कुओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं ।

श्री जयदुर्गा वीवर्स को-आपरेटिव सोसायटी दुर्गापुरा

३७८. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु.) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) श्री जयदुर्गा वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी दुर्गापुरा, जयपुर को कितना ऋण व कितना अनुदान दिया गया है तथा कब दिया गया है ? इसमें से कितना ऋण वसूल हो चुका है ?

(२) क्या यह सहकारी समिति अभी चालू है ? यदि हां, तो कितना माल प्रति माह उत्पादन होता है ?

(३) उक्त सहकारी समिति को जो ऋण दिया गया है साधारण लूम्स के लिये दिया गया है अथवा पावर लूम्स के लिये दिया गया है? यदि पावर लूम्स के लिये दिया गया है तो क्या वे पावर लूम्स चल रहे हैं और इनकी संख्या कितनी है और मासिक उत्पादन कितना है ?

उत्तर

(१) ५९०६२ रु० ऋण व ४६५० रु० अनुदान मार्च ६१ में दिया गया है तथा अभी तक ऋण की कोई वसूली नहीं हुई है ।

(२) जी हाँ । सन् १९६८ में प्रतिमाह औसतन १४३२७ मीटर कपड़ा बनाया गया है ।

(३) उक्त समिति को पावर लूम के लिये ऋण दिया गया है । १५ पावर लूम्स में से १४ चल रहे हैं । मासिक उत्पादन सन् ६७ में औसतन १४३२७ मीटर हुआ है ।

अलवर जिले में फैक्ट्रियां

३७९. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु.) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर जिले में कुल छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां कितनी हैं तथा कौन से उद्योगों

(श्री गंगासहाय)

की हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या सरकार इन फैक्ट्रियों को कच्चे माल का कोटा देती है ? यदि हां, तो कितना-कितना प्रति वर्ष देती है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(१) अलवर जिले में कोई बड़े उद्योग नहीं चल रहे हैं । पंजीकृत लघु उद्योगों की सूची संलग्न है ।

(२) जी हां । इन उद्योगों का कोई वार्षिक कोटा निर्धारित नहीं है । १९६७ में दिये गये कोटे की सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीमेंट चीनी आदि की उत्पादन क्षमता का उपयोग

३८०. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६१ में निम्नलिखित वस्तुओं की उत्पादन क्षमता राजस्थान में क्या थी :—

(१) सीमेन्ट

(२) चीनी

(३) सूती कपड़ा

(४) सूती धागा

(५) बाल बियरिंग

(६) बिजली के मीटर

(७) शीशा और

(८) नमक

(२) क्या यह उत्पादन क्षमता पूरे तौर से उपयोग में आई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) १९६५-६६ की क्या स्थिति रही है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

उद्योगों आदि पर खर्च हुई बिजली

३८१. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) १९५१ में विद्युत (बिजली) राजस्थान में निम्न मदों पर कितनी खर्च हो रही थी—

(१) उद्योग

(२) घरेलू उपयोग

(३) व्यापारिक संस्थान

(४) खेती

(५) सार्वजनिक प्रकाश

(६) सार्वजनिक जल प्रदाय

उक्त मदों पर बिजली के उत्पादन के खर्च का अनुपात क्या था ?

(२) आज इस खर्च की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(१) सन् १९५१ में राजस्थान में विभिन्न मदों पर निम्नलिखित बिजली खर्च हुई:—

	यूनिट	बिजली के उत्पादन का अनुपात
१. उद्योग	१, १४, ३५,०००	२१.३%
२. घरेलू उपयोग	८०,३३,०००	१५.०%
३. व्यापारिक संस्थान	४५,०४,०००	८.३%
४. खेती	१६,०३,०००	२.९%
५. सार्वजनिक प्रकाश	१३,३८,०००	२.४%
६. सार्वजनिक जलप्रदाय	१, १८,९५,०००	२२.१%
	३,८८,०८,००० यूनिट	७३.००%

(२) सन् १९६६—६७ में विभिन्न मदों पर बिजली खर्च का, बिजली उत्पादन का अनुपात निम्नलिखित है:—

	यूनिट	
१. उद्योग	१६,२३,१७,०००	३७.३%
२. घरेलू उपयोग	३,०८,३०,०००	७.०%
३. व्यापारिक संस्थान	३,२४,०६,०००	७.४%
४. खेती	२,८६,४८,०००	६.७%
५. सार्वजनिक प्रकाश	६५,०१,०००	१.४%
६. सार्वजनिक जल प्रदाय	२९०,४९,०००	६.६%
	२८,९७,५१,०००	६६.४%

नसीराबाद में नये उद्योग धन्धे

३८२. **श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नसीराबाद में पिछले २० वर्षों में राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा या छोटा उद्योग धंधा नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार यह महसूस करती है कि राजस्थान के जिन कस्बों एवं शहरों का औद्योगिक उत्थान पिछले २० वर्षों में नहीं हो सका है वहां नये उद्योग धंधों का निर्माण अति आवश्यक है ? यदि हां, तो नसीराबाद में कब तक सरकार नये उद्योगों का निर्माण करेगी ?

उत्तर

(१) आमतौर पर राज्य सरकार अपनी ओर से कोई उद्योग नहीं खोलती है बल्कि उद्योगों के लिए कोई प्राइवेट पार्टी इजाजत चाहती है उसकी स्वीकृति देती है।

(२) राजकीय क्षेत्र में किसी उद्योग को खोलने की योजना होगी उस समय उस स्थान की उपादेयता पर विचार किया जा सकता है।

पंचायत समिति सीमलवाड़ा में कुओं पर बिजली

३८३. **श्रीरतनलाल रोत (चौरासी-सु.)**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में सीमलवाड़ा पंचायत समिति के काश्तकारों ने बिजली कुओं पर लेने के लिए बिजली विभाग में रुपये जमा कराये हैं और इसका अर्सा दो वर्षों का होता है ? यदि हां, तो क्या अधिक अन्न उत्पादन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ऐसे काश्तकारों को बिजली शीघ्र ही दी जा सकेगी ?

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि पंचायत समिति सीमलवाड़ा के क्षेत्र में काफी ग्राम ऐसे हैं जहां कुओं पर बिजली देने की जरूरत है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर इस वर्ष कुओं पर बिजली देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(१२.३५ म० प०)

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : पोलिटेक्निक कालेज के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री भैरोंसिंह, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री प्रेमसिंह सिंघवी से प्राप्त हुई हैं।

इन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं में यह भी बतलाया गया है कि छात्रों की हड़ताल चल रही है और कई स्थानों पर छात्रों की गिरफ्तारियां भी की गयी हैं, कालेज भी बन्द कर दिये गये हैं और विद्यार्थियों के लम्बे अर्से से हड़ताल पर रहने के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक

(श्री उपाध्यक्ष)

महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की कार्यवाही को स्थगित की जा कर विचार किया जाय किन्तु यह उपयुक्त होगा यदि माननीय शिक्षा मन्त्री जी द्वारा स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल तक इस विषय में वक्तव्य दिया जाय।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देना सम्भव नहीं होगा।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था को मैं मान कर चलता हूँ पहले भी इस संबंध में विधान सभा में एक वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय ने दिया था उसके बाद स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। आज भी स्थिति यदि इमीजियेटली एक्शन नहीं लिया तो निश्चित रूप से बिगड़ सकती है और ज्यादा गम्भीर हो सकती है। अतः इस मामले पर आज ही विचार किया जाय चाहे शाम तक मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दे दें।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री): मैं अभी दे देता हूं। पोलिटेक्निक के छात्रों की हड़ताल के संबन्ध में मैंने पहले भी सदन में वक्तव्य दिया था। उसके बाद में ८ मार्च को जब सदन में वित्त मंत्री ने अपने भाषण को पढ़ा उस समय भी सरकार की नीति के बारे में उल्लेख किया गया था। आज की हालत में सरकार जो कुछ कर सकती है इस समस्या को सुलझाने के लिये उस संबंध में काफी कहा गया है। उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि छात्र लोग इससे सन्तुष्ट होकर अपनी अपनी कक्षाओं में जाते। १८ तारीख को होली के बाद पोलिटेक्निक स्कूल खुलने वाले थे जोधपुर का स्कूल खुल भी गया और भी कई जगह खुल गये उसके बाद भी छात्र लगातार नहीं आ रहे हैं। मैं यह मानता हूं जो कुछ भी इस स्थिति में सरकार कर सकती है इस समस्या को सुलझाने के लिये उसमें उदार वृत्ति से कदम उठाया है अब कोई कारण नहीं छात्र कक्षाओं से बाहर रह कर हड़ताल करें।

हम आज भी निवेदन करना चाहते हैं छात्र वर्ग से वे कृपा करके हड़ताल खत्म कर अपनी पढ़ाई आरम्भ करें, परीक्षा के दिन भी नजदीक है। अगर छात्र वापिस आजाते हैं तो हमारी तरफ से कोई इन्कार नहीं। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी छात्रों को हड़ताल तुड़वाने में सहयोग दें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं में जाकर पढ़ सकें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर) : माननीय वित्त मंत्री ने जिस इलाज की घोषणा की थी बजट भाषण के दौरान उनके कारण इसका हल निकल नहीं पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर और जयपुर में मुझे याद है १९६६ में, जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था उसके बाद इन स्कूलों में भरती के लिये रिक्रूटमेन्ट किया गया। विद्यार्थियों के घर घर पर सरकार की ओर से चिट्ठियां गई पोलिटेक्निक में आप एडमिशन लीजिये। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से लोगों के घरों पर चिट्ठियां लिखकर उनको एडमिशन के लिये बाध्य किया उसके कारण करीब २५० विद्यार्थियों ने जयपुर और भरतपुर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की पोलिटेक्निक संस्था में एडमिशन लिया। उसके बाद से वे वहां पढ़ रहे हैं आज आपके सामने यह स्थिति है कि आपने उन इन्स्टीट्युशन्स को बन्द करने का आदेश दिया इसके अलावा वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इस समस्या के बारे में जिस प्रकार का निदान बताया वह सही निदान नहीं उससे यह समस्या हल होने वाली नहीं। इस प्रकार की सहानुभूति से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। आप यदि इस समस्या से चिन्तित हैं तो इस समस्या का हल निकल सकता है। आप विद्यार्थियों के डेपूटेशन से मिल कर उनकी जो सही मांगे हैं उनके प्रति केवल जबानी सहानुभूति प्रगट करने से समस्या का क्या हल निकल सकता है। यह आप उनके साथ बैठकर उनके अभाव अभियोगों को सुनकर उसका हल निकाल सकते हैं। आज स्थिति इतनी ही है कि वे केवल हड़ताल पर हैं और भूख हड़ताल भी उन्होंने शुरू कर दी है। जैसा अखबारों से विदित है वे कुछ दिनों के बाद विधान सभा के सामने प्रदर्शन भी करने वाले हैं। उदयपुर और जोधपुर में भूख हड़ताल हो रही है। कहीं ऐसा न हो और ज्यादा उग्र रूप यह आन्दोलन धारण कर ले उसके पहले ही गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिये।

राजस्थान के युवक इस तरह से हड़ताल करते रहें, भूख हड़ताल पर बैठे रहें, मुकदमे बनते रहें, इससे देश की तरुण शक्ति का अपव्यय होगा और विद्यार्थियों को आंदोलन के लिए मजबूर करने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर होगी और आप मानकर चलें कि विद्यार्थियों का आन्दोलन दबाने से दबने वाला नहीं है। पहले पालीटेक्निक्स का, फिर मेडिकल कालेज का फिर सारे राजस्थान में एकता का नारा लगाकर विद्यार्थियों ने यदि भाग लिया तो राज्य सरकार की जो शक्ति विकास के कामों में लगनी चाहिए वह नहीं लग सकती। आपने इन्टक में कमी कर दी, ठेकेदारों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे इंजीनियरों व डिप्लोमा होल्डर्स को रखें। यह तो कानूनी पहलू है, ठेकेदार रिटायर्ड आदमी भी रख सकता है, पार्ट टाईम रख सकता है, इस तरह से इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। अगर आप सहानुभूति पूर्ण रवैये का वातावरण तैयार करना चाहते हैं तो जितने गिरफ्तार विद्यार्थी हैं, उनको तुरन्त रिहा कर दें, मुकदमें जो विद्यार्थियों के विरूद्ध दर्ज किये गये हैं इनको तुरन्त विथ्ड्रॉ करें। सरकार को अपनी ओर से गुड जेस्चर दिखाना चाहिये। उनके डेप्यूटेशन से बातचीत करें कि आपकी कौनसी समस्या है और सरकार किस प्रकार हल कर सकती है और आपको आश्वासन देना चाहिए कि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं। आपको जितने सहयोग की जरूरत होगी हम अपनी तरफ से देने का प्रयास करेंगे और परीक्षाऐं आ रही हैं उनको स्थगित करने का विचार करें।

(१२.४२ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
समानेत्री पदासीन)

उन्होंने आपको जो रिवाइज्ड डिमांड्स और सजेस्शन्स दिये हैं, आपको मिले होंगे। उस सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करें। विद्यार्थियों को छोड़ दें, मुकदमे वापिस लें, परीक्षाओं को स्थगित करें और अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए उनके रोजगार के बारे में विशेष रूप से विचार करें।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर): सभानेत्री महोदया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने जब पहली बार पालीटेक्निक्स का स्थगन प्रस्ताव आया था, उस समय इस सदन को सूचित किया था उन्होंने एक समिति बिठाई है और वह समिति जो सुझाव इस समस्या के निदान के लिये देगी सरकार उस पर अमल करेगी। मैं समझता हूं कि वे सुझाव हैं जो वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहे हैं। जिन लोगों की समस्या का आप निदान करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि ये जो सुझाव आपने दिए हैं वह उसका हल है, तो आपको उसके बारे में विद्यार्थियों से जो इससे प्रभावित हैं, उनसे बात चीत कर लेनी चाहिए थी कि ये जो सुझाव हैं वे उनकी समस्या का हल कर पायेंगे? मैं समझता हूं कि इंजीनियरों और डिप्लोमा होल्डर्स में इन घोषणाओं से वाजिब भ्रम है। उदाहरण के लिए आपने कहा था।

श्रीमती सभानेत्री : संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर इसमें थोड़ा समय लगेगा तो बहुत समय बच जायगा। वित्तमंत्री ने जो घोषणा की कि वह ए क्लास और बी क्लास ठेकेदारों को मजबूर करेंगे कि वह इंजीनीयर्स, ओवरसीयर्स को नौकरी में रखें। तो जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में दिक्कत है, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह अध्यापकों की शिकायत है, उनसे १५०) वेतन की रसीद ली जाती है।

श्रीमती सभानेत्री : संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर आपको मेरी बात इरिलेवेन्ट मालूम पडती है और आप कह दें तो मैं नहीं कहूं। सरकार केवल कह दे कि हमने अन्तिम निर्णय कर दिया, ऐसा करके सरकार चल नहीं सकती। इससे ज्यादा समस्याएं पैदा होंगी, उसकी भरपूर व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आपकी घोषणाऐं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल है। और फिर इनको कार्यान्वित करने के लिये जीनुइन एफर्ट करने की जरूरत है कि कैसे इनको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और कैसे उसको ठीक रेट्स देने की गारंटी करेंगे। क्या आप यह घोषणा करने को तैयार हैं कि कांट्रेक्टर का बिल होगा उसमें से उनके पास वह इंजीनियर या डिप्लोमा पास ओवरसियर रखेगा उसकी तनख्वाह आप उसके बिल में से काटकर उनको देते रहेंगे। क्या गवर्नमेंट यह गारंटी देगी कि उन लोगों को तनख्वाह बगैर किसी कटौती के लगातार मिलती रहेगी? इसके अलावा, आपने पी. डब्लू. डी. और माईनिंग इंजिनियरिंग के लिये कहा, लेकिन दूसरी तरह के जो लोग हैं, उनके बारे में आपने कोई संतोषजनक बात नहीं की, केवल एक टकराने वाली बात की उससे समस्या का हल नहीं हो सकता।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह यह है कि उनकी मांगों में से एक मांग यह है कि डिप्लोमा करने के बाद उन लड़कों को इन्जीनियरिंग कालेज में प्रवेश के लिये प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। तीन साल का डिप्लोमा कर लेने के बाद उनको इन्जीनियरिंग कालेज के तीसरे साल में प्रवेश

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मिलना चाहिये ताकि वे ग्रेजुएट्स बन सकें। आप इसको बेकारी की बात से जोड़ें वह ठीक नहीं है। कोई इन्जीनियर्स तो बनेंगे ही, इसलिये इस बात को बेकारी की बात से नहीं जोड़ना चाहिये। इस प्रश्न का तालुक एम्प्लायमेंट से नहीं है पर उनकी योग्यता से है। वैसे भी ए० एम० आई० ई० करके वे इन्जीनियर्स बनते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज में यह सुविधा दे रखी है। तो जब दूसरी जगहों पर यह सुविधा है तो यहां उस सुविधा को देने में क्या ऐतराज है? दूसरी यूनिवर्सिटीज में डिप्लोमा करने के बाद उनको थर्ड ईयर में प्रवेश दिया जाता है, तो फिर राजस्थान में ही उनको इससे वंचित क्यों रखा जाता है ? बाद में वह कहीं भी एब्जार्ब हो जायेगा।

श्रीमती सभानेत्री : मैं निवेदन करूंगी कि आपने काफी समय ले लिया है, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो यही निवेदन करना चाहता था कि इन बातों को ठोस रूप दिया जाये, अभी तक ये हवाई बातें ही हैं। उन लोगों के साथ बैठकर आप इस पर विचार करिये। दूसरा उदयपुर और कोटा में आपने उनके खिलाफ मुकदमे चला रखे हैं तो इन तमाम केसेज को आप विथड्रा करिये। आपकी गलतियों की वजह से एजीटेशन्स होते हैं और उसके बाद आप उनका दमन करना चाहते हैं। इस वक्त आप उनकी इस कमजोरी का फायदा ले रहे हैं कि उनके इम्तिहान के दिन हैं, वे ज्यादा दिन स्थिर नहीं रह सकेंगे। यह रूख आपने अपना रखा है, कि इस साल अगर इम्तिहान में नहीं बैठेंगे तो कम से कम आपके लिये एक साल के लिये तो बेरोजगारी का मसला खड़ा नहीं होगा। यह आपका दृष्टिकोण दुरुस्त नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने इस रवैये को बदलें, आप उन विद्यार्थियों को बुलायें, उनके विचार भी सुनिये और किस तरह से इसको कार्य रूप देना है यह तय करिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदया,.........

श्रीमती सभानेत्री : इस पर जितना कहा गया है वह पर्याप्त है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कुछ नये प्रश्न हैं जो मैं शिक्षा मन्त्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने बजट के समय बताया और बजट के पूर्व भी घोषणा की थी कि हम स्कीम्स बना रहे हैं जिससे विद्यार्थियों का असन्तोष खत्म हो जायेगा। मैं शिक्षा मन्त्री से कहना चाहूंगा कि जिस वर्ग से सारे आन्दोलन का सम्बन्ध है और उस आन्दोलन का समाधान जिस प्रकार से होना चाहिये, क्या सरकार ने कभी इस बात पर गम्भीरता से विचार किया कि सारे प्रश्न का उन्मूलन करने के लिये क्या किया जाये। आज राजस्थान के सारे पालिटेक्निक्स के लड़कों ने यूनियन बना रखी है जिसका नाम है अन्तर राजकीय बहु कला विद्यार्थी संस्थान, राजस्थान। उन्होंने १६ मार्च को जोधपुर में एक बैठक करके इस सारे प्रश्न को सोचा और यह तय किया कि सरकार के सारे वायदे जो हैं वे खोटे हैं और यह निर्णय लिया कि हमारे जो सुझाव हैं वे सरकार को भेजे जायें कि सरकार उन पर गम्भीरता

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पूर्वक विचार करे तो आन्दोलन समाप्त हो सकता है और सारे मसले का हल निकल सकता है। मैं शिक्षा मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि जो सुझाव जोधपुर की १६ मार्च की बैठक में विद्यार्थियों ने तय करके आपको भेजे क्या उन पर आपने कभी गम्भीरता से विचार किया? सरकार का उन सुझावों के बारे में क्या रुख है, क्या आपने अपने मत से उन विद्यार्थियों को सूचित किया? राज्य सरकार ने कभी सूचित नहीं किया। इसके साथ उन विद्यार्थियों ने उस बैठक में यह भी निर्णय लिया कि जब तक सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मैं पूछना चाहूंगा कि यह हड़ताल जारी न रहे इसको रोकने के लिये आपने कोई कदम उठाया?

इसके अलावा सभापति महोदया, स्थिति यह है कि सरकार ने ६ मार्च से १८ मार्च तक अपने सारे संस्थान बन्द रखे। अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है सरकार के निकम्मेपन के कारण और सरकार की अकर्मण्यता के कारण कि आपको अब सारे पालिटेक्निक्स इनडेफीनेट पीरियड के लिये बन्द करने पड़ रहे हैं। आपने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि २१ मार्च से लेकर ये पालिटेक्निक इनडेफिनेट पीरियड तक बन्द रहेंगे। जब आप मानते हैं कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, विद्यार्थी वर्ग का सरकार की घोषणाओं से सन्तोष नहीं हो रहा है, और अभी तो स्थिति यह आ गई है कि वे स्वयं सरकार के सामने आकर प्रदर्शन करने वाले हैं, तो आपने उनको सन्तोष दिलाने के लिये क्या किया? खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि १६ मार्च को जो उन लोगों ने जोधपुर में निर्णय लेकर आपके पास भेजे और आपको इन्टीमेट किया कि हम हड़ताल पर रहेंगे, सरकार ने उनके सुझावों पर क्या कदम उठाये?

सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि १९६७–६८ के अन्दर जो आपने पालिटेक्निक्स आरम्भ किये, उस वक्त आपने कहा कि हमारे यहां ओवरसियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स की जरूरत रहेगी और हम उनको नियुक्ति देंगे। आपके आश्वासन पर ३ साल का जो कोर्स था उसको घटाकर इमरजेन्सी कोर्स दो साल का कर दिया गया और उसके अन्दर, जयपुर में ६५ विद्यार्थी, अजमेर में ६० विद्यार्थी, जोधपुर में ६० विद्यार्थी, इस प्रकार से कुल २५० विद्यार्थी इस इमरजेन्सी कोर्स में भर्ती हुए कि उनकी जरूरत रहेगी। उन लोगों ने फर्स्ट ईयर पास करके सेकन्ड ईयर में एडमिशन ले ली, आपके आश्वासन पर ये लोग भर्ती हुए, आज उनके लिये आप क्या कर रहे हैं? और दुख तो यह है कि इमरजेन्सी काल के अन्दर जो नये कालेज आपने खोले थे, उनके लिये सरकार घोषणा कर रही है कि उनको बन्द करेंगे। आपने घोषणा की है कि १९६६–६७ में जयपुर और भरतपुर में जो इमरजेन्सी में पालिटेक्निक खोले गये थे वे बन्द कर देंगे। यह सरकार है या भड़भूजे की दुकान? आपने स्वयं योजना बनाई, प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये कि ओवरसियर को नौकरी देंगे और आज यह स्थिति पैदा हो जाती है कि आपको ये पालिटेक्निक बन्द करने पड़ रहे हैं। तो आप घोषणा करते हैं, उन घोषणाओं पर

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

कोई सन्तोष नहीं कर सकता। कोटा में आपने कहा कि ये लोग अगर सहकारी समिति बना दें तो उनको ठेके देने में प्रिफरेन्स देंगे। आपके पास इसका कोई प्लान है? आपने कहा कि ऐसे लड़कों को कारखाने चलाने के लिये लोन देंगे। इसके लिये भी आपने कोई स्कीम बनाई? एक नरेश कुमार विजयवर्गीय नाम का लड़का कई दिनों तक घूमता रहा उसका अब जाकर कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है।

श्री शिवचरण माथुर : किस में ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोआपरेटिव में। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी घोषणा कागज पर ही न रहे, उसको अमली जामा पहनाइये और इसके लिये विद्यार्थियों के बीच जाकर उनको सन्तोष कराने के लिये कार्यवाही करिये। आपकी जो घोषणाएं हैं उनको कार्यान्वित कराइये। मुझे लगता है कि अगर विद्यार्थी वर्ग, जिनका भविष्य इस वक्त अन्धकारमय दीख रहा है, उनको सन्तोष नहीं दिलाया गया तो यह आगे जाकर क्या रूप धारण कर सकता है इस पर आपको बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): सभापति महोदया, मैं भी कुछ शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

मैं इस सम्बन्ध में कोई विशेष चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन यह पालिटेक्निक की हड़ताल है, यह मेरे ख्याल से ऐसी समस्या का प्रथम और प्रारम्भिक चरण है और आगे जाकर इसका अन्त क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता। मैं तो शिक्षा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं केवल मात्र कि यह समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, अभी इस समस्या को सुलझाना चाहें तो सुलझाई जा सकती है, और खास तौर से मेरे दल और मेरी तो हमेशा यही नीति रही है कि सरकार को हर तरह से हम सहयोग दें इस सम्बन्ध में कि इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकले। फाल्स सेंस आफ प्रेस्टिज, कोई अवास्तविक प्रतिष्ठा का प्रश्न लेकर मंत्री महोदय इतना भी नहीं करें कि विद्यार्थियों को बुला कर बात नहीं करें, तो यह बहुत बुरी बात होगी और मैं उसकी निन्दा किये बिना नहीं रह सकता।

जहां तक उदयपुर का सम्बन्ध है, मैंने इस बात के लिये व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया, मुझे कोई यश नहीं लेना है, कोई क्रेडिट नहीं लेनी है, लेकिन ऐसा प्रश्न है कि विद्यार्थियों के मन के अन्दर यह भाव है कि हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। विश्वासघात इसलिये कि उनको जो आश्वासन दिये थे उनके भविष्य के बारे में वे सारे के सारे धूमिल हो रहे हैं। और इसके साथ-साथ यदि मैं यह कहूं कि पुलिस ने जो आतन्कवाद उदयपुर शहर के अन्दर मचा रखा है, घोड़े खड़े कर रखे हैं पता नहीं क्या-क्या कर रखा है केवल ६० विद्यार्थियों को दबाने के लिये। डंडे भी चलाये, एक आदमी की रीढ की हड्डी तोड़ डाली। वहां के कलेक्टर की आंख पर मामूली सी

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

चोट आई उस पर इतना प्रहार और इतनी निर्दयता के साथ व्यवहार किया गया। आखिर आपको मुकदमे चलाने हैं तो मुकदमे चलाइये मुझे इससे कोई मतलब नहीं लेकिन आप सहानुभूति के साथ, मानवता के नाते उन छात्रों की यूनियन में से ४ या ५ लोगों को अपने पास बुलाकर, बिठाकर इस पर चर्चा करके कोई तो हल निकालें। आज इतने माननीय सदस्य हमारे यहां बैठे हुए हैं, इतनी जटिल समस्या हमारे होनहार नवयुवकों के सामने खड़ी हुई है तो उसका सहानुभूति पूर्वक कोई निर्णय निकालें। तो यह भी आप नहीं करते हैं तो बड़े ही दुख की बात है। यही मुझे निवेदन करना है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय शिक्षामंत्री जी उत्तर देंगे तो अच्छा होगा। काफी कहा जा चुका है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय मन्त्रीजी का उत्तर हमारे माफिक हो तब तो ठीक है। अन्यथा......

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य क्षमा करें। इस पर वाद-विवाद नहीं होगा। स्थगन प्रस्ताव जिन्होंने रखा है वे बोल चुके हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं ज्यादा समय नहीं लेकर एक ही बात कहना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : एक ही आधार है जिस पर मान सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भरतपुर और जयपुर के पोलिटैक्निक बन्द कर दिये जाने से यह समस्या हल नहीं होगी। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इसका मैं विरोध करता हूं।

इसके अलावा विद्यार्थियों के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसके लिये मैं एक ठोस सुझाव देता हूं कि हर पोलिटैक्निक संस्था में या इन्जीनियरिंग कॉलेज में एक एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज खोला जाना चाहिये। इनमें सरकार अपनी तरफ से ऐसी व्यवस्था करके चले कि उनके लिये जहां जहां जगह हो उसकी पूरी निगरानी रक्खे और उनको एम्पलोयमेंट दिलाने में पूरा प्रयत्न करे। अब अगर सरकार उनको एम्पलोयमेंट न दिला सके तो बेरोजगारी का भता तो वह सब को दे नहीं सकेगी पर एक काम करे कि एक समय निर्धारित करे कि अमुक समय में इनको नौकरी में लगा दिया जावेगा, अन्यथा अमुक समय के बाद जब तक वे बेकार रहेंगे तब तक बेकारी का भत्ता जरूर ही देंगे।

श्री आलमअली (फतेहपुर) : एक बात मैं केणो चावूं। आ तो उल्टी बात हुई है। अपढ पढयोडा ने समझावे। शायद मारी बात वें री समझ में दिमाग में बैठ जावे। माननीय सभापतीजी, मने याद आवे महात्मा गांधीजी की बात।

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : ये तो मारवाड़ी में बोल रहे हैं। आप तो इसके हामी हैं, इनको प्रोत्साहन दीजिये।

Page No. 66

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, इस पर वाद-विवाद नहीं हो रहा है ।

श्री शिक्षा मन्त्री ।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति महोदया, आप यह कभी नहीं समझें कि विद्यार्थियों के प्रति हमारा रुख सहानुभूतिपूर्ण नहीं है । मैं निवेदन करूं पिछले महीने जयपुर के इन्जीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों ने हड़ताल की बात सोची । अभी विरोधी पक्ष के नेता कह रहे थे कि हमें उनसे बात करने में संकोच है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है । मैंने उन विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को अपने कक्ष में बुलाया और काफी समझाया । इसके बाद में उन्होंने यह कहा कि हमारे साथ चल कर सबको समझा दीजिये । इस पर मैं स्वयं स्टेच्यू सर्कल पर गया । बालकों से बात की और स्पष्ट निवेदन किया कि आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिये हम तैयार हैं । पर मेरी दृष्टि से, और मैं आज भी मानता हूं कि केवल नौकरी की कल्पना लेकर हम चलें तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

आज तो प्लान में भी रुपया बन्द कर दिया है खर्च करना और अगर वे प्लान भी पूरी तौर से चालू रहतीं तो भी यह नहीं हो पाता । पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता कि सबको नौकरी में खपाया जाय । वे अपने काम भी चालू करें । इसको ध्यान में रखते हुए एक समिति का निर्माण किया था । इससे कुछ सुझाव आये थे जिनके जरिये से हम इस समस्या का समाधान कुछ आंशिक रूप में ही निकाल सकते हैं पूरी तौर से नहीं । पर प्रयत्न जरूर किया था कि जो विद्यार्थी पोलिटैक्निक या कॉलेज में पढ़ने के बाद निकलें उनको खपाया जा सके । इसके लिये, आपको जानकारी होगी कि सरकार ने घोषणा की थी कि जो ठेकेदार हैं वे इन लोगों को लें । फिर ऐसी भी सुविधाएं दीं कि वे बाहर निकल कर क्रियात्मक क्षेत्र में अपनी योग्यता का परिचय दें । नौकरी के पीछे ही न रहें । टैक्निकल स्किल का आदर करना हम शुरू करें इसके लिये वे अपनी कोआपरेटिव सोसायटियां बना कर उद्योग धन्धे चलावें इसकी बात कही गई । जो सुझाव हो सकते थे सरकारी घोषित नीति के तौर पर दिये गये । मैं इसके लिये भी नहीं कहता कि जो सुझाव हमने दिये वे ही पर्याप्त हैं । मैं तो और सुझावों का हर कोने से स्वागत करता हूँ । और आउट आफ दी वे जाकर भी उन विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिये हम पूरी कोशिश करने को तैयार हैं । पर आज की जैसी हालत में कोई समाधान पूरा नहीं उतर सकता । फिर हड़ताल तो इसका समाधान हो ही नहीं सकता ।

आज विद्यार्थियों के पढ़ने का समय है । इम्तिहान सामने आ रहे हैं । हमारी भावना यह कत्तई नहीं है कि इसमें व्यवधान डाला जाय । मैं साफ बता दूं हमने स्पष्ट आदेश दिये थे कि होली की छुट्टियों के बाद पोलिटेक्निक स्कूलों के खुलने का सवाल आया था तो हमने कहा कि खुले रक्खो उनको । वे आवें, उनका स्वागत है, पढ़ने आइये आप । अच्छे विद्यार्थियों की तरह पढ़िये । इसके आधार पर पोलि-

(श्री शिवचरण माथुर)

टक्निक जोधपुर में भी, और भी जगह खुले। पर उदयपुर में नहीं खुले। वहां बन्द रहे। जोधपुर में भी बन्द हो गया। इस पर हमने सोचा कि विद्यार्थी अगर पढ़ने नहीं आते हैं तो फिर खुले रखने से क्या मतलब है। आज विद्यार्थी आने के मूड में नहीं हैं तो खुला रखने से फायदा नहीं है। इसलिये हमने उनको बन्द कर दिया है। पर मैं आज भी कह सकता हूं कि विद्यार्थी अगर आज भी वापिस आना चाहें तो हम उनको आज भी खोलने को तैयार हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मुझे कोई इसमें शर्म भी नहीं है। प्रतिष्ठा का सवाल भी नहीं है। विद्यार्थियों की शिक्षा का काम रोकने का हमारा कत्तई विचार नहीं है। विद्यार्थियों के साथ जिद्द करने का और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने का कोई सवाल नहीं है।

पर कुछ समस्याएं हैं। अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा। भारत सरकार भी इस बारे में चिन्तित है। और शायद एकाध हफ्ते में पार्लियामेंट में भी यह सवाल आवे और भारत सरकार कोई स्टेट-मेंट दे। तो वहां भी इसका जिक्र किया जावेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ यह समस्या है उसको हमें विद्यार्थियों से मिलकर बैठ कर आपस में बात करके सुलझाने में कोई आपत्ति नहीं है।

(१.६ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

उनके साथ बात करके इस समस्या का कोई हल निकले तो हमें खुशी होगी। विद्यार्थियों को चाहिये, हमारी इच्छा है वे वापिस स्कूलों में जावें। अध्ययन चालू करें। अच्छे परिणाम आवें। हम आप बैठकर समस्या का हल खोजने को तैयार हैं।

मैं विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूं सरकार की तरफ से मेरी उनसे यह अपील है कि वे स्कूलों में वापिस जावें। हमने कभी भी दरवाजे बन्द नहीं किये हैं। हम कहना चाहते हैं पोलिटैक्निक स्कूलें उनके लिये खोली गई हैं।

दो साल पहले हम स्वयं विद्यार्थियों को आमन्त्रित करते थे। यह भी हकीकत है। आज हकीकत यह है कि पोलिटैक्निक और इन्जीनियरिंग कॉलेजों के काफी विद्यार्थी बेकार हैं अब उनमें भरती में कमी नहीं करते हैं तो बेकारों की समस्या और बढ़ती है। पर यह टेम्परेरी फेज है। उद्योगों में यह स्लेकनेस और रिसेशन टेम्परेरी है। यह समस्या तो सुलझ जावेगी। पर असली हल तो तभी होगा जब विद्यार्थी यह मान कर कल्पना करके चलें कि उनको सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर नहीं रहना है। अपने हाथ से भी काम करने की बात सोचें तो फिर मैं कोई कारण नहीं मानता कि बेकारी की समस्या क्यों हल नहीं हो सकती।

अभी माननीय सदस्य श्री कृष्णकुमार गोयल ने गणेशकुमार विजयवर्गीय का उल्लेख किया। वे काफी अच्छे उत्साही कर्मठ विद्यार्थी हैं। मेरे पास आये। अपने साथियों की को-आपरेटिव सोसायटी बना

(श्री शिवचरण माथुर)

की बात बताई। मुझे यह जानकर काफी प्रसन्नता हुई। हमने प्रयत्न किये और आज वह सोसायटी उनकी रजिस्टर हो गई है। इस प्रकार से विद्यार्थी आवें और अपना काम शुरू करें। जो मदद होगी हम करने को तैयार हैं और इसी तरह से इस समस्या का हल होने वाला है।

एक यह सवाल भी आया कि एम्प्लोयमेंट ब्यूरो उन संस्थाओं में ही हों। यह व्यवस्था आज भी किन्हीं अंशों में है। इसके जरिये से हम विभिन्न उद्योगों से उनकी एम्प्लोयमेंट पोटेंशियल की जानकारी लेते रहते हैं और उसमें और रोजगार दिलाने में सामन्जस्य स्थापित हो इसकी व्यवस्था आज भी पोलिटेक्निक के डाइरेक्टरेट में है। हम अपने विद्यार्थियों को निकालने से पहले ही यह कोशिश करते हैं कि कहां पर काम की गुंजाइश उनके लिये है। पर हकीकत है यह कि आज इतनी अधिक मात्रा में विद्यार्थी निकल रहे हैं कि उस मात्रा में आज एम्प्लोयमेंट पोटेंन्शियल नहीं है। इसके लिये विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि नौकरियों के अलावा भी वे उद्योगों का काम अपने हाथ में लें।

श्र कृष्णकुमार गोयल : १६ मार्च को सारे राजस्थान के पोलिटेक्निक के विद्यार्थियों ने मीट करके जो रेजोल्यूशन दिया, जो सुझाव दिये उस पर सरकार ने क्या सोचा?

श्री शिवचरण माथुर : मेरे पास भी इसकी कापी कल ही आई है। अलग-अलग विभागों से समन्वय स्थापित करने को हम तैयार हैं। पर हड़ताल पर रहें तब तक तो यह तो समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी वापिस अपने पोलिटेक्निक कालेज में वापिस जायें, अच्छे ढंग से पढ़ें तो बैठ कर कोई न कोई हल निकले तो मैं समझता हूं कि उनके लिए दरवाजे बन्द नहीं हैं हम बैठकर बात कर सकते हैं यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो भावनायें व्यक्त की हैं कि उनके सामने भी कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है और विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन्स के दिन हैं इसलिए हड़ताल समाप्त हो तो इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो है अनएम्प्लायमेन्ट का प्रश्न कि उनको एम्प्लायमेन्ट कैसे दिया जाये। यह आर्थिक प्रश्न है और बैठकर विचार करके तय करने का प्रश्न है लेकिन दूसरा प्रश्न ऐसा है कि जो सब स्टेट्स का प्रश्न नहीं हैं। यह ऐसा प्रश्न है कि जो केवल राजस्थान में है और जिसके साथ एम्प्लायमेन्ट का प्रश्न जुड़ा हुआ नहीं है और वह है एडमीशन का प्रश्न। विद्यार्थी चाहते हैं कि डिप्लोमा के बाद इन्जनियरिंग कालेज में एडमीशन मिल जाये। तीसरी बात यह है कि कुछ केसेज हड़ताल के बारे में हुए उनको वापिस लेने की बात है। जहां तक एडमीशन का सवाल है यदि आप इन्जीनियरिंग कालेज में उनको एडमीशन दे देते हैं तो उससे कोई अनएम्प्लायमेन्ट की समस्या बढ़ नहीं जायेगी। आप अकेले इस प्रान्त में इस प्रकार की स्थिति क्यों कायम रखना चाहते हैं कि डिप्लोमा होल्डर्स को डिग्रीहोल्डर बनने की अपार्चुनिटी नहीं मिले। तो एक तो इस मांग को आप कन्सीड कीजिए और दूसरे

Page No. 69

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनके केसेज वापिस ले लें। अगर आप उनके केसेज को वापिस ले लेते हैं तो हम भी उनसे जाकर कह सकते हैं कि आप हड़ताल न करो। यह दो प्रोबलम्स तो केवल अपने स्टेट की हैं। जो यहां के विद्यार्थियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है दूसरी यूनीवर्सिटीज के मुकाबले में वह एडमीशन का हक आप उनको दीजिए और अपने बच्चों के ऊपर जो केसेज लगा रखे हैं उनको विथ्ड्रा कीजिए और ऐसा वातावरण उत्पन्न कीजिए कि जिससे कि स्थिति ठीक हो।

श्री शिवचरण माथुर : एक बात का उत्तर देना मैं भूल गया था। आपने जिक्र किया था कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको ऐसी सुविधा प्रदान की जाये कि वह डिग्री कोर्सेस में दाखिल हो सकें। मेरे सामने जब समस्या आई तो मैंने इसको सुलझाने के लिए इन्जीनियरिंग कालेज और यूनीवर्सिटी से बात की और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का केरीकुलम बनाने की बात सोच रहे हैं जिससे डिप्लोमा के बाद एक दो साल पढ़ाई करने के बाद में डिग्री दे सकें यह हमारा विचार है और हमने यूनीवर्सिटी को रेफर किया है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी यूनीवर्सिटीज के अन्दर ऐसा है ऐसा हमें बताया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : सब जगह ऐसी स्थिति नहीं है। किसी में है किसी में नहीं है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाये। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे वर्तमान समस्या का हल होने वाला नहीं है। डिग्री करने के बाद फिर वही समस्या सामने आयेगी...

श्री रामानन्द अग्रवाल : एम्प्लायमेन्ट की दूसरी समस्या है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपकी बात से सहमत हूं और यूनीवर्सिटीज को हमने इसके लिए कहा हुआ है कि वह हमें इस सम्बन्ध में राय दे और जो भी उसकी राय आयेगी उस पर विचार करेंगे और मैं मानता हूं कि ऐसी हालत में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम विद्यार्थियों की समस्याओं से चिन्तित नहीं हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी चिंता आपको है उससे कम चिन्ता मुझको नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो केसेज बच्चों के ऊपर चल रहे हैं पालटेक्नीकल कालेज के अन्दर जिसमें पिछली बार के केसेज थे जहां सरकार ने आश्वासन दिया था कि विथ्ड्रा कर लिये जायेंगे। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसमें से एक ही केस को विथ्ड्रा किया है। इस प्रकार से उदयपुर के अन्दर केसेज चल रहे हैं इनको विथ्ड्रा करने के बारे में सरकार क्या कहना चाहती है यह हम जानना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों का ऐसा मामला है जो कि राष्ट्रव्यापी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी राष्ट्र की निधि हैं और हमें इसका उपयोग करना चाहिये और मैं विश्वास करके चलता हूं कि सरकार इसका समुचित उपयोग कर

(श्री रामनारायण चौधरी)

रही है। मैं दूसरे दलों के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात को समझें और मामूली सी बात को लेकर विद्यार्थियों के मामले को आगे न बढ़ायें और ऐसी हवा न बनायें कि अमुक दल ही उनके हितों की रक्षा कर सकता है। सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों की समस्यायें सुलझें। कोई भाषण देने से या स्थगन प्रस्ताव रखने से समस्या का समाधान नहीं होता है।...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अच्छा यह होता कि आप विधान सभा में नहीं आते।

श्री रामनारायण चौधरी : और विरोधी दल के माननीय सदस्यों को विद्यार्थियों से इतनी ही दिलचस्पी थी तो उन्हें विद्यार्थियों को सरकार के पास भेजना चाहिए और सम्बन्धित मंत्री से बात करनी चाहिए...

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : यहां बैठे किस लिये हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन स्थगन प्रस्ताव देकर और हवा बनाने की कोशिश की जाये कि विरोधी दल के मेम्बर ही उनका हित करना चाहते हैं यह गलत बात है। यह गलत हवा बनाई जा रही है। तो विद्यार्थियों को आप नहीं भड़कायें किसी को गलत हथियार न दीजिए, विद्यार्थियों को आप अनुशासन दीजिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो आपके मंत्री उस समय कहां गये। यह स्थगन प्रस्ताव तो आज आया है। पालिटेक्निक कालेजेज बन्द हो रहे हैं, विद्यार्थियों को जेलों में डाला जा रहा है उस समय आपकी सहानुभूति कहां गयी, आपके मंत्री के अक्ल पर क्या पर्दा डल गया था। आपने उस समय क्यों नहीं कहा ? आपने उस समय क्यों नहीं कहा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। विरोधी दल अपना कर्त्तव्य निभायेगा। विरोधी दल का एक-एक सदस्य विद्यार्थियों के हित की रक्षा के लिए हर कदम पर लड़ेगा और जनता के बीच में खड़े हो कर इन विद्यार्थियों पर होने वाले जुल्म की रक्षा करेगा।...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इस मामले को विवादास्पद नहीं बनाया जाये तो ज्यादा उचित होगा।

श्री मदनसिंह दांता : मामला पहले ठीक ढंग से चल रहा था। मंत्री महोदय एग्री कर रहे थे। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि कल रामानन्द जी और हमसे विद्यार्थी मिले। विद्यार्थियों से हमने कहा कि इस समय ऐसा मौका है कि तुम कुछ फेलो और हम कुछ गवर्नमेन्ट को ललायेंगे। लेकिन आप आरोप लगाओ कि हम उनको भड़का रहे हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका राइट काज है। अगर आज राजस्थान के एजूकेशन मंत्री इस सदन के बीच में उनको इन्जीनियरिंग कालेज में एडमीशन देने के सम्बन्ध में आश्वासन देकर इमरजेन्सी के समय विश्वास दिलाया था कि हम हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा एलान कर दें और मैं समझता हूं कि विद्यार्थी भी ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं कि वह कोई आन्दोलन करना ही चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री मदनसिंह दांता : तीसरी प्रोब्लम केसेज के सम्बन्ध में है। मैं मंत्री महोदय का आपके जरिये ध्यान आकर्षित करूंगा कि इससे बड़े-बड़े आन्दोलन हुए हैं। मद्रास के अन्दर लैंग्वेज के प्रश्न को लेकर बड़ा भारी आन्दोलन हुआ, मोटरें उड़ाई गई हैं और सड़कें तोड़ी गई हैं, उनके भी केसेज विथ्ड्रा हुए हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि विद्यार्थी अपना आन्दोलन वापिस ले लें तो सबसे पहले उनके पुराने मुकदमे हटाये जायें ताकि आज उनको सन्तोष हो कि हमारी सरकार हमारे हितों की रक्षा करेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं एक बात कहना भूल गया...

श्री मदनसिंह दांता : यह भूल गए कि इनको गोली से उड़ा दो।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा संख्या जो कि टैक्निकल लाइन में है वो झुन्झुनू जिले में है और वो संस्था पिलानी में है। यह क्या बात है कि वहां कभी हड़ताल नहीं होती उदयपुर में ऐसी क्या बात हो गयी ? वहाँ पर जनसंघ के सदस्य जाते हैं और लड़कों को भड़काते हैं और स्थिति का दुरुपयोग करते हैं।...

श्री देवीदत्त गाड़िया : जनसंघ के सदस्य झुंझुनू में भी जाते हैं। रामनारायण जी इस होश में न रहें कि कांग्रेस जनता का कोई भला कर सकती है। जनसंघ ही राजस्थान की जनता को भुखमरी से और दूसरी बातों से बचा सकती है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज शिक्षा मंत्री जी !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावतः माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक मिनिट में निवेदन करना चाहूंगी आपके जरिये शिक्षा मंत्रीजी से कि जिन विद्यार्थियों पर केसेज चल रहे हैं उनको उठा दिया जाय।

(विपक्ष से हियर, हियर)

श्री रोशनलाल (सालूम्बर): कलेक्टर पर लाठी चलाना ठीक है।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): मेरा इसके बारे में एक सुझाव है शिक्षा मंत्री जी को।

श्री शिवचरण माथुरः माननीय उपाध्यक्ष.........

श्री केदारनाथः वह सुझाव यह है कि आप हैड आफ दी इन्स्टीट्यूशन्स और स्टूडेन्ट्स के नुमायन्दों की एक मीटिंग को प्रेसाइड करें तो मेरा विश्वास है कि समस्या हल हो जायगी और हड़ताल का आन्दोलन समाप्त हो जायगा।

कई माननीय सदस्य (दोनों पक्षों के) : यह ठीक है।

श्री उपाध्यक्षः आपस में बातें न करें माननीय सदस्य !

श्री शिवचरण माथुरः मैंने आपकी भावनाओं को समझा है उस सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट बात सदन के सामने निवेदन करूंगा.........

श्री मदनसिंह दांताः आप ऐलान करें।

श्री उपाध्यक्षः माननीय मदनसिंह !

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इस समस्या के समाधान के बारे

(श्री शिवचरण माथुर)

में कोई भी सुझाव माननीय सदस्य दें और वह समस्या का समाधान करता हो तो उसको मानने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसी भावना से एक नीति यहां पर घोषित की गई थी। मैं समझता हूं कि आप सदन के बाहर बैठकर बात करें तो नीति में किसी प्रकार की कमी महसूस होती है तो सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ घोषित किया गया है उसमें कोई कमी हो तो। आप कहते हैं कि इसका इम्प्लीमेन्टेशन कैसे होगा, यह लागू कैसे होगा, यह बात दूसरी है। लड़कों के बारे में जो योजना बनाई गई है तो उसमें ए क्लास कान्ट्रेक्टर्स को निश्चित रूप से कहा गया है कि वे कान्ट्रेक्टर्स डिप्लोमा होल्डर्स को रखें। इसको लागू करने में अगर कोई कठिनाई होती हो तो हम मिटाने को तैयार हैं। मैं समझता हूं कि उसी प्रकार की भावना से इस प्रश्न को लेना चाहिए।

जहां तक विद्यार्थियों के केसेज़ का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष भी एक हड़ताल हुई थी, और मैंने अपने तौर पर विद्यार्थियों से कहा था कि आप लोग स्ट्राइक को तोड़ दें और मैंने निवेदन किया था मुख्य मंत्रीजी से तो उनके केसेज विथड्रा हुए थे। लेकिन बार बार ला एण्ड आर्डर की समस्या बना दी जाय और विद्यार्थी कानून अपने हाथ में लेने की बात करें तो मैं यह कह सकता हूं कि सारे केसेज़ को मेरिट्स पर तय करने वाली बात कह दूं, मैं अपनी तरफ से घोषणा कर दूं वह पूरी नहीं होगी और उसका मतलब यह होगा कि वायलेन्स से जो बात की जाय और उसको मनवाने के लिए सरकार को बाध्य किया जाय तो यह चीज मैं उचित नहीं मानता हूं। इसलिए इस बारे में घोषणा करना उचित नहीं होगा। इस बारे में केवल यह कहा जा सकता है कि सारे केसेज़ के मेरिट्स पर फैसले किये जा सकते हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है इस समस्या को सुलझाने के लिए, कोई भी हल निकालने को हम लोग तैयार हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इधर और उधर बैठने वाले हम सब इस समस्या को सुलझायें ऐसी बात होनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप ऐसी मीटिंग कन्वीन करना चाहते हैं। डू यू मीन देट? तो कब कर रहे हैं? उसकी डेट एनाउन्स कर दें कि फलां तारीख को कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर: जहां तक प्रिन्सीपल्स की मीटिंग का सवाल है पोलिटेक्निक में रोज़ बात करते हैं और रोज समस्याओं का समाधान करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: विद्यार्थियों को बुला लें।

श्री शिवचरण माथुर: विद्यार्थियों को बुलाकर बात कर लेंगे।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल: कब?

श्री शिवचरण माथुर: कल ही कह दूंगा कि कल बुला लें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें रावतसर हास्पिटल

(श्री उपाध्यक्ष)

को बिजली नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

यह मामला अविलम्बनीय लोक–महत्व का नहीं है। अतः इसको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना सम्भव नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : यह मामला अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है पर उस गांव में एक हास्पिटल है और चार साल हो गये बिजली आये, लेकिन आज तक उस हास्पिटल में बिजली नहीं दी गई है। लोगों में इससे बड़ी निराशा फैल रही है। आप यह व्यवस्था देते हैं यह तो ठीक है, पर इस प्रकार की व्यवस्था देने से पहले इस बात पर गौर करना चाहिए कि हास्पिटल में बिजली नहीं दी जा रही है। हास्पिटल के पास में खम्बा लगा हुआ है और चार साल से इसको अन्धकार में रखा जाय, और यह सरकार उसको उपेक्षा कि दृष्टि में रखे, और हम प्रस्ताव रखें और आप यह व्यवस्था दे रहे हैं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सम्बन्धित मंत्री महोदय से वक्तव्य तो कम से कम दिला दिया जाय, जिससे कि इस इलाके के लोगों को राहत मिले। इस इलाके में वह एक ही हास्पिटल है और इतना बड़ा कस्बा है १०० गांवों के बीच में एक मात्र हास्पिटल है इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुर्नविचार करें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : इस हास्पिटल के मामले में मंत्रीजी की तरफ से स्टेटमेंट होना चाहिए। खास तौर से किसी ने एक हास्पिटल बनाया है। एक व्यक्ति ने दान देकर सारा हास्पिटल बनाया है उस पर राज्य सरकार ने खर्चा नहीं किया है बनवाने में तो बिजली देने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है?

श्री रामनारायण चौधरी : हास्पिटल सब जगह बने हुए हैं और मेरी कान्स्टीटुएन्सी में भी बना हुआ है, मगर इस प्रकार से प्रश्न उठाया जायगा......

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की कान्स्टीटुएन्सी में हैं तो उनको भी मिले। उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि उस गांव में अगर बिजली है और चार साल से खम्बा मौजूद है तो हास्पिटल जैसी जगह को बिजली न मिले यह बड़ी अजीब सी बात है। इस प्रस्ताव से हाउस को स्थगित करने का मकसद नहीं है मकसद केवल ध्यान दिलाने की बात है इतना एनाउन्समेंट हो जाना चाहिए कि इस मुद्दे पर कार्यवाही की जायगी। अगर मंत्री जी नहीं हैं तो जब वे आयें तो उनको आदेश दिया जाय कि वे एनाउन्स करें। इतनी छोटी सी बात को यहां पर लाना पड़े और चार साल से हास्पिटल में बिजली न हो तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी शेमफुल बात है। सुबह एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि एक मिनिस्टर के लिए १२००० रुपये खर्च करके बिजली ले गये और वह कर दिया और हास्पिटल के लिए यह कहना पड़े बड़ी अजीब सी बात है। एक्सीडेन्टली दोनों क्वेश्चन आज आगये जो कि आपकी गवर्नमेंट की नीति का कन्ट्रास्ट है, उपाध्यक्ष महोदय.........

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रामनारायणजी को इस बात से शिकायत हो, रामनारायण जी को इससे नाराजगी हो और वे चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए तो एक बात कह दूं........

श्री दौलतराम सारण : सदन के नेता से मैं अर्ज करूंगा रामनारायण जी को भी जल्दी ही अवसर देने के लिए। ये बहुत बेचैन हैं। सदन के नेता से कहूंगा की वे जल्दी से ही इनको अवसर दें।

श्री रोशनलाल : आपने क्या फायदा उठाया १० वर्ष तक रहे तो।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : फायदा उठाने के लिए बैठे हैं क्या उधर ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस मसले पर सरकार को लिखा जायगा कि एप्रोप्रियेशन बिल के समय अगर माननीय सदस्य इस बात को उठायें तो इसका जवाब सरकार की तरफ से अवश्य ही दिया जाय।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री रामचन्द्र आर्य : उस वक्त तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर अवश्य देंगे। इसका उत्तर मन्त्री महोदय दें ऐसा प्रबन्ध किया जायगा।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × ×

× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × ×
× × × ×
× × × × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आसन अपने पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें......

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × × × × × × ×

× × ×

× ×

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्ताव में सब बातें कही गई हैं।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × × × × × × × × × × × ×

× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : × × × × × × ×

श्री रामचन्द्र आर्य : × × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्ताव आज ही प्रस्तुत हुआ है, वह अभी विचाराधीन है, इससे पहले ही माननीय सदस्य बोलने लग गये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इस पर व्यवस्था दी जायगी, विचार किया जा रहा है। इस तरह से भाषण करना और समय लेना उचित नहीं है इसलिये इस बात को यहीं समाप्त किया जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

(व्यवधान)

× ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

× × ×

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × ×
× × × × ×

× × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । ओर्डर प्लीज । एक्सपन्ज्ड ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × ×
× × × × ×

× × ×

× × × ×

× × ×

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) :
× × × × ×
× × × × ×

श्री शंकरलाल जैतराण : × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर ही माननीय सदस्य बोल रहे हैं । व्यवस्था के दो प्रश्न एक साथ नहीं हो सकते ।

श्री विजयसिंह रावत : × × ×
× × × × ×

श्री रोशनलाल शर्मा : × × ×
× × × × ×

श्री विजयसिंह रावत : × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × ×
× × × × ×

श्री विजयसिंह रावत : × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । आसन की तरफ से इस पर व्यवस्था दी जा रही है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : × × ×
× × × × ×

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में जैसा कि निवेदन किया गया था माननीय सदस्यों को कि इस पर ग्रासन की ग्रोर से व्यवस्था नहीं दी गई है ग्रौर उससे पहले ही माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं जो एक तरह से एक दल पर ग्रारोप था। तो मैं इसलिए उचित समझता हूं कि शुरू से लेकर ग्राखिर तक जो कुछ इसमें चर्चा हुई है वह सब सदन की प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज कर दी जाय।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : × × × × × × ×

श्री विजयसिंह रावत : × × × × × × × ×

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापस में बात नहीं करें।

श्री विजयसिंह रावत : × × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी समय ले लिया है।

श्री विजयसिंह रावत : × × × × × × × ×

(ग्रश्रव्य)

श्री डूंगाराम राजोरिया : × × × × × × × ×

श्री विजयसिंह रावत : × × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : × × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ! ग्रार्डर ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल—ग्रश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा को यहीं समाप्त कर दें।

श्री रोशनलाल : × × × × × × × ×

श्री गिरधारीलाल व्यास : ×

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : × × × × × × × ×

श्री गिरधारीलाल व्यास : × × × × × × × × × × × × × × × × ×

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : × × × × × × × ×

××× ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार निकाले गये।

श्री मदनसिंह दांता : × × ×
× × × × ×

श्री जयनारायण खालोदिया : × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्ड प्लीज ! आर्डर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष—आॅर्डर प्लीज ! लम्बा भाषण नहीं होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बात क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : × ×
× × × × ×

श्री विजयसिंह रावत : × × ×
× × × × ×

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात समझ गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×
× × × × ×

श्री शंकरलाल : × × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : इस मसले पर व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री शंकरलाल : × × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : रूलिंग दे दी है, उसके बाद क्या कहना चाहते हैं ।

श्री शंकरलाल : × × ×
× × × × ×

श्री विजयसिंह रावत : × ×
× × × × ×

श्री शंकरलाल : × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

× × × ×

× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्री शंकरलाल)

× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

श्री रघुनाथ विश्नोई : × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

× × × × ×

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : × × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : फिर विवाद का विषय क्या है। चलने दो।

श्री रामनारायण चौधरी : × ×
× × × × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप आरोप को जाग्रत न करें। व्यवस्था के बारे में कुछ कहना हैं तो दो मिनिट में कह दें।

श्री रामनारायण चौधरी : × ×
× × × × ×

श्री जयनारायण सालोदिया : × ×
× × × × ×

श्री रामनारायण चौधरी : × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

श्री दिग्विजयसिंह : × × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी समय चला गया है।

अभी दो तीन माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई कि कार्यवाही से वही शब्द हटाये जा सकते हैं जो मानहानिकारक हों या अभद्र हों। तो प्रथम तो मानहानिकारक से क्या मतलब लेते हैं? कोई किसी से कहे कि पैसा खा लिया है तो यह उसकी तारीफ की बात है? आर्डर प्लीज! आर्डर! आर्डर प्लीज!

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × × × × × × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपने पूरी व्यवस्था सुनी नहीं। आर्डर प्लीज! पूरी व्यवस्था नहीं सुनी।

श्री रामनारायण चौधरी : × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिये।

श्री रामनारायण चौधरी : × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! व्यवस्था दी जा रही है। प्रश्न यह है कि मानहानि-कारक यहां पर कोई भी बात कही जाती है, ठीक बात कही जाती है तो वह बात तब ही कही जा सकती है जब कि पूर्ण सूचना सूचना हो, एक। या वह व्यक्ति यहां उपस्थित हो, उसको सूचना हो, उसकी जानकारी में हो तो उसका उसी वक्त जवाब दे सकता है। तीसरा प्रश्न है, आसन के आदेश की अवहेलना करके और कोई बात सदन के ऊपर थोप दें और यह चाहें कि उस सबको प्रिन्ट किया जाय, जिसका सम्बन्ध कार्यवाही से नहीं है तो आसन को ऐसा अधिकार है कि जो कार्य सूची में नहीं है, कार्यवाही में नहीं है उसको चाहे तो उसमें रखे, चाहे तो नहीं रखे क्योंकि जो कार्य सूची होती है, उसे सब माननीय सदस्य, माना यह जाता है, पढ़ कर आये हैं, उसके बारे में तैयार हैं और उसके बारे में वह चर्चा कर सकते हैं। उस बात को मान कर चला जाता है। अब अकस्मात विषय आ जाय जो कार्य सूची में नहीं है, जिसका सदन से सम्बन्ध नहीं है, उसके बारे में कभी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर बिना आसन की अनुमति के कोई बात सदन में कही जाती है तो आसन को अधिकार है कि उसको सदन की कार्यवाही में न रखें। इसलिए जो पहले व्यवस्था दी गई थी, मैं समझता हूं, बिल्कुल उचित है। उससे कोई भविष्य में माननीय सदस्यों का चर्चा का अधिकार है उसके अन्दर बाधा उत्पन्न होगी—यह मैं समझता हूं न तो उसकी मन्शा है और न उसका यह इन्टरप्रिटेशन हो सकता है कि इससे भविष्य में राइट आफ डिबेट पर किसी तरह का असर पड़ेगा! होगा तो यह होगा कि माननीय सदस्य बिना पूर्ण सूचना के, बिना आसन की अनुमति के विषय सदन में उठायेंगे नहीं।

× × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अब ज्यादा चर्चा......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × × × × × × ×

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : × × × × × × ×

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × × × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय ले लिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव !

श्री देवीदत्त गाड़िया : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न काफी हो गये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक व्यवस्था दे दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल जोधपुर में जो दस हजार मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है उस पर स्थान प्रस्ताव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया, स्थगन प्रस्ताव, उस पर आज जवाब दिये जाने को था। आज मंत्री महोदय ने यह चाहा है कि इसको किसी अगले दिन ले लिया जाय। २५ तारीख उसके लिए निश्चित कर दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : यह मसला काफी......

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है उस पर व्यवस्था दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह दे दी जायगी। जिस पर आज नहीं दी गई है उस पर कुछ दिन बाद दे दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : यह मसला काफी गम्भीर है। दस हजार मजदूर हड़ताल पर चल रहे हैं। आप मान कर चल रहे हैं कि दस हजार मजदूर जहां हड़ताल पर चलें वहां शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए.........।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी इच्छा क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : मेरी इच्छा यह है कि इसका जवाब आज आ जाय।

श्री रामनारायण : आज नहीं तो कल दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, आज दिया जाय। यह लेबर का मुद्दा है और लेबर मिनिस्टर बीमार नहीं हैं, वह अनुपस्थित भी नहीं है। इस मसले की हमें सूचना मिल सकती है तो सरकार को भी मिल सकती है। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर तैयार हो कर आये और जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी देर में पूछ कर जवाब दे दिया जायगा।

Page No. 82

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव !

श्री जयनारायण सालोदिया !

ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवाई पंचायत समिति या तहसील क्षेत्र फसलों पर, गेहूं जौ की फसलों पर रोली के प्रकोप के कारण जो नुकसान हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैंने यह ध्यान आर्काषित करना चाहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यहां तक जानकारी है, इन सब ध्यान आकर्षण प्रस्तावों का एक तरीका होता है कि सरकार की तरफ से यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव असेम्बली सेक्रेटरिएट को दें ताकि वह सम्बन्धित मन्त्री महोदय को भेजें और सम्बन्धित मंत्री महोदय उन लोगों को भेजें जिन लोगों से वह सम्बन्धित है। मुझे जहां तक जानकारी मिली है, कि माननीय मन्त्री जी को जो आंकड़े दिये गये हैं वह विकास अधिकारी के द्वारा दिये गये हैं। उसके बाद मैं निवाई गया हूं। जो जानकारी और आंकड़े दिये गये हैं वह विकास अधिकारी के द्वारा दिये गये हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि विकास अधिकारी की लापरवाही और उदासीनता के कारण उनको समय पर दवाई नहीं दी है। समय पर यन्त्र नहीं दिये ! आपने उन विकास अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने गलत रिपोर्ट देनी चाही है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि यह गलत रिपोर्ट है और थोड़े से आंकड़े माननीय मंत्री जी के पास भेजे हैं। यह बड़े दुख की बात है। वैसे माननीय मंत्री जी के उत्तर से मालूम पड़ जाएगा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे मालूम हुआ है, उस तहसील के गांवों के हजारों एकड़ गेहूं और जौ की फसल में रोली रोले, दो प्रकार का रोग है, उससे वह प्रभावित हुई है और निश्चित रूप से हजारों क्विटल गल्ले का नुकसान हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब किसान पंचायत समिति में दवा आदि के लिए गये तो उस समय पर कभी तो उत्तर नहीं मिला कभी विकास अधिकारी नहीं मिले और कभी दवाई के इंचार्ज नहीं मिले। इस तरह से लोगों को टहलाया गया। जो दवाई इमरजेन्सी के तौर पर इन गांवों के उस क्षेत्र के लोगों को देने का सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार को देखना चाहिए कि वह सरकारी स्टाफ है। पंचायत समिति और तहसील में पटवारी और ग्राम सेवक इस तरह से सर्विस करें और सर्विस करके वह दवाई पहुंचाते। यह सरकार का कर्त्तव्य है। इसकी पूर्ति होती तो हजारों मन गल्ला, हजारों मन गेहूं का नुकसान नहीं होता। इस तहसील के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था न करने के उपरान्त जो लोग दवाई लेने के लिए पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर आये हैं, उनको समय पर दवाई नहीं मिली। यन्त्र नहीं मिले। यन्त्र इसलिए नहीं मिले क्योंकि पंचायत समिति के पास इनेगिने १०-२० यन्त्र थे और सैकड़ों गांवों में हर एक गांव में सैकड़ों घरों में उनकी फसल पर इस बीमारी का प्रकोप होने के कारण और थोड़ी संख्या में यन्त्र होने के कारण उसमें सरकार द्वारा पक्षपात किया गया। जिनको यन्त्र नहीं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

दिये जाने थे उनको दिये और जिनको दिये जाने थे उनकी फसल को रोग नुकसान करता रहा उनको यन्त्र नहीं दिये गये। एक बात। रोली खत्म करने की दवाई सरकार ने पैसों से बेची है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, वित्तमन्त्री जी ने कहा है कि जब तक प्रचार करना था सबसीडी दे कर, फ्री या आधे पैसे लेकर दवाई बेची है। अब हम उन सारी चीजों के पूरे पैसे लेकर देते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह तो महामारी का प्रकोप था। जिस तरह से जानवरों और आदमियों को महामारी आती है तो सरकार का कर्तव्य महामारी के टाइम पर होता है। सरकार पैसे लेकर इस तरह से उपचार करना चाहे तो वह महामारी फैलेगी और प्रकोप शान्त नहीं होगा और इससे नुकसान होगा उस प्रान्त का।

(२ म० प०)

इस सूरत में मैं इसे लेना चाहता हूँ। यह फसल पर महामारी थी, सरकार ने इसे महामारी के रूप में नहीं लिया और किसानों से पैसे लेकर दवाई बेची और पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर ही बेची जब कि हर गांव में पटवारियों की मार्फत दवाई और यन्त्र भेजने चाहिये थे। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे टाइम में किसानों से पैसे लें, किसानों को परेशान करें और तहसील हैड क्वार्टर पर सारे किसानों को बुलायें तो इससे जाहिर है कि सरकार कृषि के सम्बन्ध में, कृषि की पैदावार के सम्बन्ध में, कृषि में अच्छी फसल हो और कीड़े लग कर कृषि की फसल खराब न हो, उसके सम्बन्ध में सरकार कितनी उदासीनता बरतती है, इससे किसानों के प्रति सरकार की नीयत जाहिर हो जाती है कि वह किसानों के प्रति, कृषि की उपज के प्रति कितनी उदासीन है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री जयनारायण सालोदिया : संक्षेप में हीं कह रहा हूं।

हर गांव के किसानों ने फसलों को दिखाया है, किसी गांव में ७५ प्रतिशत नुकसान है, किसी गाँव में २० प्रतिशत नुकसान है, इस तरह का नुकसान है। मैं मानता हूं कि सब गांवों में इस तरह का नुकसान नहीं है पर अधिकतर निवाई तहसील के गांवों में इस तरह का नुकसान है कि हजारों एकड़ में इस रोग से अनाज को नुकसान हुआ है, इससे हजारों क्विन्टल की कम पैदावार गेहूँ की और जौ की एक तहसील में होगी। इसलिये मैं सरकार को पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की भयंकर बीमारी से पकी पकाई फसल बरबाद हो गई है, गले आई घूंट पर इस प्रकार का प्रहार हुआ है, इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से इस प्रकार की उदासीनता दिखाना, पैसे लेकर किसानों को दवाई देना और वह भी तहसील हैड क्वार्टर पर बुला कर दवाई देना कहां तक उचित है? क्या सरकार इतना भी नहीं कर सकती थी कि ५ रुपये की दवाई किसानों को किश्त के रूप में, सब्सिडी के रूप में दे दे, जिससे कि ५ मन ही नहीं ५ क्विन्टल गल्ला बढ़ सकता है। इससे किसानों को तो फायदा होता हो पर हमारी खाद्य स्थिति में भी इससे ज्यादा अनाज होने से सुधार होता। क्या सरकार का कर्तव्य नहीं था कि ५)

(श्री जयनारायण सालोदिया)

रु० की दवाई किसानों को उधार दे, किसानों के गांवों में दवाई पहुंचा दे, किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में यन्त्र पहुंचा दें । पर जहां तक मेरी जानकारी है ।

(२.२ म० प०)

(श्री केदारनाथ सभापति पदासीन)

कृषि प्रसार अधिकारी पंचायत समिति में हैं, उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी मांगी कि मैं जाकर देख आऊं तो, पर उनको गाड़ी नहीं मिली उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार की बीमारी बहुत भयंकर है, पर उनको गाड़ी नहीं मिली । तो इस प्रकार की उदासीनता कहां तक उचित है ?

दो तीन प्रश्न मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं । क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि जब किसान तहसील हैड क्वार्टर पर बुलाये गये थे तो उनको पता नहीं था कि रुपयों की जरूरत पड़ेगी इसलिये रुपया लेकर नहीं गये थे, उनको मालूम नहीं था कि पैसा देना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा, ऐसी हालत में क्या सरकार का कर्तव्य नहीं था कि किसानों को दवाई मुफ्त में देते । किसान जो पैसा लेकर नहीं गये थे उनको कहा गया कि इतना पैसा जमा कराओ, और सरकार का जिस प्रकार का प्रोसीजर है कि वहां जमा कराओ, स्लिप लेकर आओ, इस तरह से उन किसानों को परेशान किया गया । दवाई तो पर्याप्त मात्रा में थी या नहीं, इसका पता नहीं पर यन्त्र पर्याप्त मात्रा में नहीं थे । मैंने विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास टूटे-फूटे यन्त्र पड़े हैं, यह हमारे काबू की बात नहीं है ।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके यहां रिपोर्ट आती है इस तरह की पंचायत समिति के विकास अधिकारी या तहसीलदार द्वारा दी जाती है, तो निश्चय तौर से वे महसूस करते हैं कि इसमें हमारी कमजोरी मालूम होगी, विधान सभा में हमारी बदनामी होगी, इसलिये कम से कम आंकड़े भेजते हैं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी भी जांच करें कि किस आधार पर आंकड़े भेजे हैं । यह प्रश्न देने के बाद मैं निवाई जाकर आया हूं । पहले १५० आंकड़े लिखे थे और बाद में १५० के स्थान पर ५० किये, पहले कुछ आंकड़े लिखे फिर उनके स्थान पर दूसरे आंकड़े लिख दिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री जयनारायण सालोदिया : इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूं, उन्होंने एक बुनियादी तथ्य हमारे समाने रखा और वह यह है कि जब-जब इस प्रकार का ध्यान आकर्षण सदन

(श्री शोभाराम)

के सामने पेश होता है और सम्बन्धित मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है और जो सूचना विभाग के अधिकारियों से प्राप्त होती है उसमें अन्तर रहता है। यह ठीक है कि जो सूचना हमको मिली निवाई पंचायत समिति के कुछ गांवों की उसके अनुसार, उसके अनुसार ११ गांवों की १५० एकड़ भूमि पर इस बीमारी का असर हुआ, ३५ एकड़ जमीन पर छिड़कने के लिये किसान दवाइयां ले गये। दूसरी तरफ माननीय सदस्य जिनका हमको इतमीनान करना चाहिये, दूसरी बात रखते हैं। अब इसका इलाज क्या ? तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के तीन चार मामले अगर साल भर में हमारे सामने आयें और जांच पर विरोध पाया जाय और एक्शन लेने की बात हो तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि १५ अप्रेल से ३० अप्रेल के बीच में मैं निवाई तहसील में खुद आना चाहता हूं और जिन किसानों के खेत नष्ट हुए हैं वे मौजूद हों और असलियत का पता चले, जैसा कि आप फरमा रहे हैं ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है तो निश्चित तौर से सैकड़ों आदमियों से मिलने के बाद में सही बात का अन्दाजा लगेगा। तो पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १५ से ३० अप्रेल के बीच में मैं वहां आऊंगा। १० रोज पहले माननीय सदस्य हमें मौका दें, हम सबको सूचना देंगे, कृषि प्रसार अधिकारी के बारे में आपने कहा जीप के बारे में, इस प्रकार की जानकारी हमको मिलती है और निश्चित तरीके से अन्तर आता है तो जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उनको कम से कम वार्निंग या दूसरी सजा दी जा सकती है।

दूसरे मामले में प्रक्रिया के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दो प्रकार की व्यवस्था कीटाणु नाशक दवाइयों के प्रयोग के बारे में हैं। एक तो यह कि गांवों में जब भी इस प्रकार की बीमारी का प्रकोप होता है तो पंचायत समिति के अधिकारियों का तहसीलदार का फर्ज होता है कि उसकी सूचना राज्य सरकार को वक्त पर दे और मैं यह भी निवेदन करूं कि वहां यदि शिथिलता हो तो उस निर्वाचन क्षेत्र से कोई माननीय सदस्य मौजूद हों वे कम से कम इस प्रकार की सूचना राज्य सरकार को दें तो हम इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं कि १०—१५ रोज में पूरी जानकारी करके अगर इस नतीजे पर पहुंचें कि वाकई ज्यादा पैमाने पर रोग लगा है और एपेडेमिक बीमारी के रूप में घोषित कर सकते हैं तो जैसे ही घोषित होता है, उस वक्त सरकार की पूरी जिम्मेदारी है अपने पैसों से मुफ्त में किसानों को दवाइयां वितरित करने की उस वक्त पूरी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है और उसमें जितना खर्चा करते हैं उसका ५० या ७५ प्रतिशत भारत सरकार से हमें मिल जाता है। एक तो यह प्रक्रिया है।

दूसरी प्रक्रिया में पैसों से दवाइयां देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां महामारी घोषित नहीं की जाती है, छोटे मोटे रकबे पर जैसी कि हमारी सूचना के मुताबिक हमको खबर मिलती है हम पंचायत समितियों के पास रबी के मौके पर नवम्बर–दिसम्बर के आखिर में हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर दवाइयां पहुंचा

(श्री शोभाराम)

देते हैं, वहां से हर पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर वे दवाइयां वितरित हो जाती हैं, फिर पंचायत समिति का काम आता है।

पंचायत समिति में इस बात के लिये जहां महामारी फैली हुई है वहां इस बारे में जब भी हम जाते हैं हमें चाहिये हम लोगों को किसानों को यह बतावें। जब-जब भी ऐसा मौका हो पंचायत समिति की मीटिंग में हो जहां भी उनसे मिलने का मौका आये इस प्रश्न को किसानों के सामने खुलासा रख देना चाहिये और किसानों को कुछ भी असुविधा हो इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाय। यह प्रश्न टेकनिकल ढंग से जवाब देने का नहीं है। इस बात की मुझे बहुत तकलीफ है कि लोगों की फसलें बरबाद हों और हम देखते ही रह जायं। मैं समझता हूं इस प्रोब्लेम की तरफ समुचितरूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इस बारे में सभी विधान सभा के माननीय सदस्यों से यही अपेक्षा करता हूं। जब भी इस प्रकार की एपेडेमिक उनके क्षेत्र में हो तो कम से कम पर्सनल ढंग से इसको हल करवाने की ओर ध्यान दें तो मैं समझता हूं इसकी व्यवस्था करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री सुवालाल : मैंने ५ तारीख को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव दिया था वह अभी तक नहीं आया।

श्री सभापति : आप इस बारे में डिप्टी स्पीकर साहब के चेम्बर में जाकर बात कर लें।

अनुदान की मांगों पर विचार

श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य-भवन व सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय,

५२ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,५६,४२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४२ मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,७६, २६,००० रु० तक राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८९, १८, ००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

मांग संख्या २७

श्री रघुनाथ विश्नोई (साँचोर) :

(१) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में भवनों एवं सड़कों की ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

(२) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दाता से साँचोर तक १० मील पक्की सड़क बनाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

(३) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होने वाले कामों के सही ढंग से इस्टीमेट्स न तैयार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(४) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के टेन्डर्स निर्धारित समय पर न लिये जाने जाने एवं उचित विज्ञापन न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(५) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कामों के लिये निर्धारित शिड्यूल ऑफ रेट्स समय रहते रिवाइज न करने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(६) मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्लान्ट्स व टूल्स की खरीद एवं किराये के संबंध में बर्ती जाने वाली असमानता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :

७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (छबड़ा से कवाई की अधूरी सड़क पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (छबड़ा की हाई स्कूल बिल्डिंग के अधूरे कमरे को पूरा कराने एवं छीपाबडौद की गर्ल्स स्कूल भवन के निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रू० कम कर दिया जाय (बारा, अटरू, कवाई सालपुरा, छीपाबडौद इक्लेरा की सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (तहसील हैडक्वाटर्स पर डाक बंगलों के निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

११. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक

(श्री चुन्नीलाल)

५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (खण्डार से बालेर जिला सवाई माधोपुर) तक की १४ मील लम्बी सड़क एवं बरवाडा चौथ से कुसतला तक की सड़क की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

१२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रु० कर दिया जाय (सड़क–निर्माण कार्य के सम्बन्ध में बजट में बहुत कम राशि का प्रावधान रखने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

१३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सवाई-माधोपुर से इन्दरगढ सड़क के निर्माण में अर्थ-वर्क सोलिंग–मिट्टी के पेमेन्ट में घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वर्ष ६७–६८ में सवाई माधोपुर सबडिविजन के क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत न किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वर्ष ६८–६९ में खण्डार से बहरांवडा तथा लीसेबों निवाई सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बोंली से निवाई की सड़क १५ साल में भी पूरी न हो सकी, इस पर चर्चा के लिए) ।

१७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कस्बे की मेन मार्केट रोड से तहसील व हायर सैकण्डरी स्कूलों के राजकीय भवनों तक एप्रोच रोड न बनने के चर्चा के लिए) ।

१८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रू० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार की रोकथाम न हो सकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रू० कम कर दिया जाय)५० बेडेड अस्पताल सवाई माधोपुर के भवन निर्माण का ठेका सबसे कम रेट देने वाले ठेकेदार को न दिये जाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ४२

२०. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १०० रू० कम कर दिया जाय (हायर सेकेण्डरी स्कूल सवाई माधोपुर के विज्ञान कक्ष का भवन ठेकेदार द्वारा निकम्मा बनाये

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

जाने के बावजूद विभाग द्वारा पूरा पेमेंट दे देने तथा ठीक प्रमाणित कर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२१. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १०० रु० कम कर दिया जाय (हायर सेकेण्डरी स्कूल सवाई माधोपुर की ६७—६८ में हुई पुताई के सम्बन्ध में झूठे बिल के पेमेन्ट पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७.

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) :

२२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (डेगाना प्राईमरी हैल्थ सेन्टर भवन की पिछले १० वर्ष से मरम्मत न कराने पर चर्चा के लिये)।

२३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (डेगाना तहसील में सड़कों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

२४. मांग संख्या २७. मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पाली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीशासी अभियन्ता का कार्यालय न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पाली से झीतडा होती हुई पीपाड़ तक सड़क न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पाली से खेरवा तक की सड़क के निर्माण न होने के सम्बन्ध चर्चा के लिये)।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) :

२७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (ग्राम चकवाला (तहसील फागी) के पास चाकसु—दूदू रोड (जिला जयपुर) की सड़क की घूम ठीक कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) :

२८. मांग संख्या २७,मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रू० कम कर दिया जाय (जोधपुर से ओसियां की सड़क पर डामर नहीं बिछाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (अकाल राहत काल के अन्तर्गत बनी सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने अधीन न लेने के कारण इन सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

३०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—

Page No. 90

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोलायत से डूंगरगढ़ को सड़क मार्ग से मिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

३२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बीकानेर जिले के गांवों में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिए)।

३३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसीलें नोखा, बीकानेर, कोलायत व लूणकरणसर में निर्माण कार्य कराने में सरकार के सौतेले व्यवहार एवं पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

३४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर से दिल्ली के राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं० ११, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, को सरकार की ढिलाई व लापरवाही के कारण अभी तक पूर्ण नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

३५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर से अनूपगढ वाया छत्रगढ व महत्वपूर्ण बोर्डर रोड्स पूर्ण कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) :

३६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जालोर गुडा व भीनमाल–झाव सड़कों को प्राथमिकता देने के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

३७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर तहसील बाड़मेर जिला में कवास से बाटाडू तक अधूरी ग्रेवल रोड बनी हुई है उसको पूरा करने पर चर्चा के लिए)।

३८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बालोतरा से तीलवाड़ा (पशुमेला) तक डामर सड़क बनाने के बारे में चर्चा के लिए) :

३९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर में सड़कों और भवनों के निर्माण के बारे में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

४०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बालोतरा नगर से मेवानगर (नाकोड़ा) तक

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

दो २ मील अधूरी डामर सड़क को पूरा करने पर चर्चा के लिए)।

४१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सिवाना से समदडी तक अधूरी ग्रेवल रोड को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाल (बाड़मेर जिले में अकाल सहायता से निर्मित अधूरी सड़कें पूरी नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

४३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (करनावास से समदडी (बाड़मेर जिला) तक लूणी नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

४४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (वायतू से सिणधारी वाया नौर (बाडमेर जिला) की सड़क जो अकाल सहायतार्थ बनाई गई थी, उसको पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

४५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिंक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर डिग्री कालेज भवन के इस साल सम्पूर्ण तौर से निर्माण कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

४६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की सड़कों के निर्माण कार्यो की अवहेलना पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

४७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सड़कों के निर्माण में धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

४८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच माही नदी पर पुल निर्माण पर चर्चा के लिये)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०)

४९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील जम्वा रामगढ़ में सड़कों का निर्माण नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

५०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील दौसा में सड़कों के अधूरे काम पूर्ण करवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा—सु०)

५१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर की आसपुर रोड व माण्डव

(श्री महेन्द्रकुमार)

माइन्स से पाडवा रोड पर आवश्यक धन राशि के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद)

५२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि से से १००) रु० कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में मिट्टी की सड़कों पर कंकरीट करवाने हेतु, इस पर चर्चा के लिये) ।

५३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार व घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

५४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीमा-क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के नाम पर धन के दुरुपयोग व घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

५५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लोहार-वाड़ा से पिटाणी पंचायत (जिला अजमेर) तक की कच्ची सड़क पर तुरन्त कंकरीट कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

५६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गोला ग्राम पंचायत (जिला अजमेर) से लेकर जेठाना ग्राम पंचायत की कच्ची सड़क की दुर्दशा के कारण काश्तकारों को भारी असुविधा होती है, इस पर तुरन्त कंकरीट कराने पर चर्चा के लिये) ।

५७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अजमेर से रामसर वाया श्रीनगर व श्रीनगर से नसीराबाद की डामर की सड़क की दुर्दशा के कारण तुरन्त मरम्मत कराने पर चर्चा के लिये) ।

५८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कानपुरा से तिहारी जिला अजमेर की कच्ची सड़क वर्षा से खराब हो गई है और काश्तकार उस पर बैलगाड़ी चलाने में असमर्थ हैं अतः उस पर तुरन्त कंकरीट डलवाने पर चर्चा के लिये) ।

५९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुष्कर घाटी (अजमेर) से लेकर कानस ग्राम तक की डामर की सड़क में गहरे गड्ढों की तुरन्त मरम्मत हेतु चर्चा के लिये) ।

६०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर धौलपुर सड़क के निर्माण पर ०.४४ लाख अतिरिक्त व्यय हो जाने पर भी दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कर्यवाही नहीं हुई, इस पर चर्चा के लिये) ।

६१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीकर उदयपुर सड़क पर एलाइनमेंट को बदलने से ०.१६ लाख अतिरिक्त खर्च केवल

(श्री विजयसिंह)

इंजीनियर की झूठी व भ्रष्ट धांधली से हुआ, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३२

६२. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रकाशन शाखा में होने वाले फिजूल खर्चों को रोकने पर चर्चा के लिये) ।

६३. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री के क्रम में मितव्ययता लाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४२

६४. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुचित सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर लगने वाले धन को बचाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा—सु०)

६५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन)

६६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक कार्यों पर पूंजी का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३२

६७. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मुद्रण कार्य राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय में देरी से होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)

६८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोडाभीम में मंहदीपुर बालाजी की घाटी का निर्माण करके सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

६९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हिन्डौन सब डिविजन में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

७०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण कार्य को अन्य कार्यों से प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

७१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील हिन्डौन में माध्यमिक शाला के भवन की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

Page No. 94

(श्री श्रवणलाल)

७२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाईमाधोपुर के वेयर हाऊस तथा अन्य भवनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर सु.)

७३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सड़कों सम्बन्धी होने वाले व्यय में बढ़ोतरी आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)

७४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (ब्यावर–भीलवाड़ा वाया बदनोर आसीन्द सड़क को डामर कराने तथा आसीन्द–गुलाबपुरा सड़क को मेटल रोड बनवाने के सम्बन्ध में नीति का अनुमोदन) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

७५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण में प्राथमिकता तय करने में सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन) ।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी)

७६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कनवास धूलेट रोड अभी तक नहीं बनाने पर चर्चा के लिये) ।

७७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रामगंज मण्डी ऊंडवा व श्री छत्रपुर सड़कों की मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

७८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मरम्मत के अभाव में सांगोद क्षेत्र की विभिन्न पुलियाओं के खराब हो जाने पर चर्चा के लिये) ।

७९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (रामगंज मन्डी तहसील में मोड़क चेचट व मोड़क–खैराबाद सड़कों की मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

८०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सन् १९६५–६६ में सांगोद क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु acquire की गई भूमि का मुआवजा नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

८१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बारहमासी पी० डब्लू० डी० गैंग पर होने वाली फिजूल खर्ची व मरम्मत प्रणाली की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

८२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक

(श्री जुझार सिंह)

५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा गागरोन की पुलिया व सड़क की पिछले १० वर्षों से मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल,जयपुर)

८३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा दिए जाने वाले ठेकों में पक्षपात व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

८४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर नगर की कुछ चौकड़ियों में सड़कों पर कुछ भी खर्चा न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

८५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा निर्माण कार्य में बरती जाने वाली लापरवाही व धन की अपव्ययता पर चर्चा के लिये)।

८६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

८७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर में गंगापोल द्वार के बाहर कच्ची सड़क पर तारकोल बिछाने तथा पुलिया बनाने पर चर्चा के लिये):

श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर):

८८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खानपुर चुनाव क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत नहीं होने एवं आवश्यक सड़कों के निर्माण न होने पर चर्चा के लिये)।

८९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (खानपुर चुनाव क्षेत्र की रियासत के समय की कच्ची सड़कों की मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण (मंडावा):

९०. मांग संख्या २७. मुख्य शीर्षक ५० – सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनू से राजगढ़ वाया मलसीसर सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

९१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनू से बिसाऊ मुकन्दगढ़ से मंडावा सड़क की मरम्मत करवाने के विषय में चर्चा के लिये)।

९२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (मंडावा से बिसाऊ (जिला झुंझुनू) सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

९३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (टोंक से सवाई माधोपुर वाया उनियारा सड़क व उस पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

९४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (उनियारा से इन्द्रगढ सड़क पर किसी धन-राशि का बजट में प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

९५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ओगलवी ब्रिज पर से नल निकालने से होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिये) ।

९६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला टोंक में सड़क निर्माण के लिए अपर्याप्त धन–राशि के प्रावधान पर चर्चा के लिये) ।

९७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दूनी से आंवा सड़क की मरम्मत न होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

९८. मांग सख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (निवाई बौंली सड़क का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना से काम चालू हुआ था उसे अब तक पूरा न कराने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३२

९९. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री विभाग की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४२

१०० मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००)रुपया कम कर दिया जाय, सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता)

१०१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निर्माण कार्य की दुर्व्यवस्था एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) :

१०२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले की अधूरी सड़कों को पूर्ण कराए जाने तथा नए एपरोच रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

१०३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील पीपलदा मुख्यालय पर डाक बंगले की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा)

१०४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण के पश्चात् उनकी पूर्ण देख-रेख न होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

१०५. मांग २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर किये गये अदूरदर्शिता पूर्ण व्यय एवं अपव्यय पर चर्चा के लिये) ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़)

१०६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुरानी बनी सड़कों को तुरन्त ठीक करने, नदियों में खुर्रे बनाने तथा सड़कों से गांवों को जोड़ने पर चर्चा के लिये) ।

१०७. मांग संख्या २७, शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर किया जाय (पुरानी सड़कों पर डामर न डालने एवं अधूरी सड़कें पूर्ण नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु०)

१०८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बून्दी से लाखेरी तक की अधूरी सड़क पूरी कराने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री बृजवल्लभ वोहरा (दीगोद)

१०९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों एवं भवनों की समय पर मरम्मत न होने के कारण उनकी दुर्गति होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (छापर सु०)

११०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू-जिले में बनी सड़कों के नीचे आई हुई जमीनों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१११. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (फतेपुर से चूरू वाया रामगढ़— रतन नगर सड़क तथा सरदार शहर से चूरू सड़क को पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)

११२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में सड़कों की दुदर्शा तथा अधूरी सड़कों के निर्माण हेतु चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३२.

(श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

११३. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (मुद्रण व्यवस्था में सुधार हेतु, चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

श्री फतेह सिंह (ब्यावर)

११४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टाडगढ़— बरार रोड की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

११५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ब्यावर — काबरा रोड की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

११६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय मार्ग ८ के लिये ब्यावर से १० मील दूर गांव सूरजपुरा के किसानों की कृषि भूमि का मुआवजा न देने पर चर्चा के लिये) ।

हंसराज आर्य (भादरा)

११७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों का कार्य समय पर नहीं होता, सामान अच्छा नहीं लगता तथा जो सड़कें टूट जाती हैं उनकी समय पर मरम्मत नहीं होती इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)

११८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में आडापारा से ग्राम ढढीकर तक घाटी का निर्माण करके सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

११९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर शहर में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

सुवालाल चौधरी (दूदू)

१२०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पडासोली से साखून, मौजवाद से भाग बगरू, व गाडोता से मौजमावाद से भाग बगरू, व गाडोता से मौजमावाद व नरेना से मरवा-कच्ची रोड को पक्की बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१२१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिचून से फुलेरा तथा दूदू से फागी सड़कों पर डामर डलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१२२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण योजना के अन्तर्गत खरीदे जाने वाले बुल्डोजर, पम्पिगसेट को कृषि उपयोग में लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१२३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक

(सुवालाल चौधरी)

५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गत वर्षों में किये गये अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों को पक्की बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

१२४. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राईमरी हेल्थ सेन्टर बिचून का भवन सरकार द्वारा नहीं बनाने से बीमारों को असुविधा पर चर्चा के लिये)।

१२५. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्र में औषधालयों, सफाखाने व शिक्षण संस्थाओं के भवन पर अधिक पैसा खर्च करने के लिये)।

१२६. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १३०) रु० दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों की मद के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में कृषि उपयोगी कुओं का निर्माण सरकार अपने हाथ में ले, इस पर चर्चा के लिये)।

१२७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्कूल भवन, औषधालय भवन इत्यादि निर्माण कार्यों को करवाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

केशरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली)

१२८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुरानी इमारतों की समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण इमारतें टूट रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

१२९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की कच्ची सड़कों को पक्का कराने हेतु जो राशि पंचायत समितियों को स्वीकृत है वह राशि उन्हें नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री रोशन लाल शर्मा (सलूम्बर)

१३०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम दिया जाय (उदयपुर जिले की कई अधूरी सड़कें पूर्ण नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा):

१३१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा की सड़कों की बिगड़ी हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

१३२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराडा में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

देवीलाल पुरासियां (केकड़ी सु.):

१३३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (विविध सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पक्षपात पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये) ।

१३४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों के निर्माण हेतु काम में आने वाले औजार व स्थिर संयत्र पर अनाप शनाप खर्च पर चर्चा के लिये) ।

श्री गंगा सहाय (कठूमर)

१३५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आर्थिक एवं अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कों, सीमान्त क्षेत्र की सडक तथा केन्द्रीय सड़क के निर्माण, उनकी मरम्मत एवं विकास पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३२

१३६. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १०० रु. कम कर दिया जाय (सरकारी मुद्रणालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या २७

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर):

१३७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुम्हेर से सिनसिनी जनूथर से कठूमर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु.)

१३८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ सब डिवीजन की सड़कों पर काम नहीं होने एवं सड़कों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़)

१३९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किशनगढ़ क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूरा कराने पर चर्चा के लिये) ।

१४०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किशनगढ़ से रूपनगर जाने वाली, किशनगढ़ से सरवाड़ जाने वाली अत्यन्त खराब सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री श्रीनिवास (निम्बाहेड़ा)

१४१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा)

१४२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
में सड़कों के निर्माण की उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)

१४३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में सड़कों व पुलियों के निर्माण कार्यों की उपेक्षा व खुले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

१४४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में भारी धांधली, पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

१४५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विधायकपुरी सदस्य आवास गृह एवं धाभाई जी की हवेली के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर)

१४६. मांग संख्या २७,मुख्य शीर्षक५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (बीकानेर, बाडमेर जैसलमेर की सड़कों पर पुलों के निर्माण का कार्य सन्तोषजनक नहीं होने से राष्ट्र धन की हानि हो रही है, इस सम्बन्ध में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन) ।

१४७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (बीकानेर-बाडमेर-जैसलमेर की सड़क के सुधार का कार्य बहुत मन्द गति से चल रहा है इसमें तीव्र गति न लाने के कारण सरकार की इस विषयक नीति का अननुमोदन) ।

१४८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया (जीर्णोद्धार भवन एवं संचार साधन में होने वाली अव्यवस्था तथा अप-व्यय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१४९ मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीमा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में होने वाली अव्यवस्था को रोकने हेतु चर्चा के लिये)

१५०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मूल निर्माण कार्य-भवन पर होने वाले खर्च के अप-व्यय, अव्यवस्था तथा अकर्मण्यता को तुरन्त दूर कराने हेतु चर्चा के लिये).।

१५१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग के स्थापना (Establishment) पर होने वाले अप-व्यय तथा अनियमित व्यय को तुरन्त रोका जाय, इस पर चर्चा के लिये) ।

१५२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से

(श्री गोकुल प्रसाद)

१००) रु० कम कर दिया जाय (हिसार पंजाब–राजस्थान सीमा को बीकानेर से मिलाती हुई राजगढ़ सरदार शहर और डूंगरगढ़ होते हुए सड़क का निर्माण, विभाग की शिथिलता के कारण पूर्ण न होने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

१५३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर-पूंगल सड़क में होने वाले कार्य में अपव्यय तथा कार्य की समाप्ति में विलम्ब हो रहा, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३२

१५४. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री तथा मुद्रण में होने वाले अपव्यय तथा अकर्मण्यता को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

१५५. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नवीन व्यय के अन्तर्गत फिजूल खर्च को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री रामचन्द्र (खण्डेला)

१५६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (सीकर जिले में अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत बनी सड़कें पूरा न कराने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

१५७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़कें बनवाने में फिजूल खर्ची अधिक है, इस पर चर्चा के लिए)।

१५८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीकर जिले में पलसाना से खन्डेला सड़क बनवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

१५९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खंडेला श्री माधोपुर सड़क का काम अधूरा पड़ा है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१६०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीकर जिले में रुघनाथगढ़ मंडावरा, मलकेड़ा आदि जहां खानों से इमारती पत्थर निकलता है सरकार उन स्थानों को सड़कों से जोड़ने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर)

१६१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जैसलमेर

(श्री बालसिंह सौठा)

क्षेत्र में सीमा सड़क के कार्यों में अनियमितताओं व घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठल (पीपलखूंट)

१६२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री हीरा (कुशलगढ़–सु०)

१६३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ से बामनिया तथा ताम्बेसरा एवं दोहद की सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी–सु०)

१६४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर से सरथूना एवं मांडली सड़क के निर्माण कार्य में शिथिलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़)

१६५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नेशनल हाईवे, जो देहली से जयपुर वाया शाहजहांपुर–बहरोड बनी है, उस पर मुकाम बहरोड़ में उक्त सड़क पर रेस्ट हाउस बनाने के लिए धन राशि का बजट में प्रावधान नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

१६६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भवन एवं सड़कों के बनाने में राजनैतिक दृष्टिकोण न अपना कर जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित होने वाले क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१६७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जो भी निर्माण कार्य चालू अथवा अधूरे हैं उनको प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

१६८. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी बहुत अधिक रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री जवाहरमल (सहाड़ा)

१६९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गंगापुर से आमली तक अधूरी सड़क पूरी कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़)

१७०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के

(श्री सांवरमल बासोतिया)

अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बोर्डर रोड्स के निर्माण में हो रही देरी एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

१७१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने पर चर्चा के लिए) ।

१७२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नवलगढ़ से चिराणा सड़क निर्माण में की जा रही देरी पर चर्चा के लिए) ।

१७३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नवलगढ़ से गुढ़ा सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१७४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं से राजगढ़ वाया मलसीसर सड़क निर्माण में हो रही देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३२

१७५. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग में खरीददारी में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा करने के लिए) ।

१७६. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में राजकीय मुद्रण व्यवस्था को बढ़ाने और सक्रिय करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

१७७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सीमान्त क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों में हुए घोटालों एवं ठेकेदारों को दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१७८ मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (दान दाताओं द्वारा सरकार को दी गई इमारतें विभाग द्वारा अपने कब्जे में न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१७९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जिला नागौर में बनायी गई सड़कों के नीचे आई हुई मुआवजे का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (लाडनूं

(श्री हरजीराम)

सुजानगढ सड़क पर गत दो वर्षों में खर्च बताई गई राशि का दुरुपयोग करने तथा वहां पर कोई कार्य न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लाडनूं से निम्बीजोधा सड़क की हालत अत्यन्त खराब हो जाने के बावजूद भी उसकी मरम्मत न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं में राहुगेट से स्टेशन तक बनी हुई सड़क की मरम्मत न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अप्रोच रोड़ बौलुखा (तहसील डीडवाना) पर किये गये ६००० रु० मरम्मत के लिये खर्च बताना, जब कि वहां पहले सड़क नहीं थी, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३२

१८४. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८— लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री क्रय करने में किये गये घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८५. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८— लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य मुद्रणालयों में छपाई के कार्य करने की अक्षमता के कारण शासकीय छपाई कार्य प्राइवेट प्रेसेज को दिया जाता है, इसे रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४२

१८६. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३— सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जसवंतगढ के कालेज के निर्माण के लिये रकम जमा हो जाने के बावजूद भी भवन निर्माण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २७

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) ।

१८७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नोहर साहवा रोड के निर्माण का कार्य चालू किया जावे ताकि श्री गंगानगर का रास्ता सीधा हो सके, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१८८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल क्षेत्र में सड़कों के नीचे वाटर कोर्स पी. डब्लू. विभाग द्वारा बनाये जाने हैं लेकिन विभाग की लापरवाही से वाटर कोर्स की पुलियों का निर्माण ठप्प है, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

१८९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक

(श्री रामचन्द्र आर्य)

५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में १००) रु० कम कर दिया जाय (नोहर रावतसर सड़क के निर्माण कार्य में अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत समिति द्वारा शिकायत होने पर भी जांच न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१९०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नोहर से ऐलनाबाग (हरियाणा) को मिलाने वाली सड़क के विस्तार पर चर्चा के लिये)।

१९१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने पर चर्चा के लिये)।

१९२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर से ललाना तक सड़क पक्की बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१९३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नोहर साहवा रोड से गाँव दलपतपुरा से पांडूसर तक लिंकरोड का निर्माण करवाया जावे, ताकि वहां पर बना हुआ वाटर वर्कस सफल हो सके, इस पर चर्चा के लिये)।

१९४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर भादरा में सड़कों के निर्माण कार्यों पर व्यय होने वाली राशि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१९५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भाखरा एवं राजस्थान नहर क्षेत्र में मंडियों एवं अन्य मंडियों के निर्माण कार्य में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

१९६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भवनों के स्थान पर सड़कों के निर्माण पर अधिक धन व्यय किये जाने पर चर्चा के लिये)।

१९७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गोगामेड़ी व भादरा रेलवे क्रोसिंग फाटक शीघ्र बनाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

१९८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नोहर सिरसा की अधूरी सड़क पूरी कराने से हरियाणा प्रान्त से सीधा सम्पर्क हो जाएगा, इस पर चर्चा के लिए)।

१९९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर की लिंक रोड्स रामसर से जसान व टोपरियां से ढढेला, परलीका से दीपलाना, रामगढ़, बखाली चाईया से गंधेली के निर्माण पर चर्चा के लिए)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

२००. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नोहर से पल्लू व पल्लू से अरजनसर तक सड़क का निर्माण कार्य चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

२०१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रावतसर से सूरतगढ़ वाया मेकेसरी से बडो पल होकर सूरतगढ़ को मिलाया जावे ताकि कास्तकारों को अपनी खेती की उपज का माल मंडियों तक ले जाने में सुविधा हो सके, इस पर चर्चा के लिए) ।

२०२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोहर तक की गोगामेडी से नेठराना तक लिंकरोड पक्की बनवा दी जावे ताकि यह कस्बा नोहर मादरा रोड से मिलाया जा सके, इस पर चर्चा के लिये) ।

२०३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नोहर से सरदारशहर वाया मन्दरपुरा धानसिया से सड़क पक्की बनवाई जावे, ताकि नोहर सरदार शहर जाने का जनता को साधना मिल सकें, इस पर चर्चा के लिए) ।

२०४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मादरा से सिरसा वाया गांधीवडी सड़क जो फेमिन वर्क से बनी हुई है वह पक्की बनाई जावे, इस पर चर्चा के लिये) ।

२०५, मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निर्माण कार्यों पर लगने वाली राशि अपर्याप्त है, इस संबंधी चर्चा के लिए ।)

मांग संख्या ३२

२०६, मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८— लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री में होने वाला खर्चा अधिक है और इस सम्बन्धी सुव्यवस्था न होने के कारण इस विभाग को घाटा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण भवन व पथ इसके बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं उनके द्वारा मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला जालौर सड़कों के हिसाब से सबसे पिछड़ा जिला है। पिछले बीस वर्षों में जो राशि जिलेवार सड़कों के लिए बजट में रखी गई है उन आंकड़ों को देखा जाय तो जिला जालोर के लिये जो सब से पिछड़ा जिला है सब से कम बजट अलोटमेन्ट किया गया है। जैसे आपका गंगानगर का इलाका है जालोर जिला भी ऐसा जिला है जो कृषि उत्पादन के बढ़ाने के हिसाब से सबसे अच्छा जिला है। जब यहां उत्पादन होता है तो यहां से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सारे राजस्थान के लिए अनाज भेजा जाता है वहां का भाव सबसे कम रहता है। इसका खास कारण यह है कि उस इलाके में सड़कों के न होने की वजह से आवागमन के साधन न होने की वजह से, सबसे कम दाम वहां मिलते हैं। वहां गांव इतने दूर दूर हैं चार-पांच रुपये प्रति बोरी के हिसाब से किराया देना पड़ता है इसका कारण यह है कि पिछले बीस वर्षों में किन्हीं-किन्हीं जिलों में तो बहुत ज्यादा सड़कों का विकास हुआ है उस हिसाब से जालोर में नहीं हुआ है। अगर हम प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे रुपयों का अलोटमेंन्ट देखें तो जालोर में सड़कों के हिसाब से १·३१ आता है जो बहुत कम है। इसके अलावा माइलेज के हिसाब से सबसे ज्यादा चित्तौड़ में अलोटमेन्ट आता है और जालोर में सबसे कम आता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह जिला इतना पिछड़ा हुआ है यहां के लोग भी टैक्स देते हैं यहां कृषि उत्पादन भी अच्छा है फिर भी आप इस जिले के लिये सड़कों का प्रावधान नहीं कर सकते। यह जिला ऐसा है जहां आप सब डिवीजन हैडक्वार्टर भी जिले से सड़क से नहीं मिला पाये। सांचोर तहसील का ज्यादातर इलाका ऐसा है जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहां से बोर्डर सबसे नजदीक है। इस हिसाब से भी पाक आक्रमण के बाद सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों के लिये काफी पैसा मिला है उसके लिये मंत्री महोदय को तो धन्यवाद नही दे सकता फिर भी सेन्टर से जो सड़कों के लिये पैसा मिला है उससे इस जिले की सड़कों को भी फायदा मिलेगा।

इसके साथ साथ रानीवाड़ा से सांचोर तक बीस मील का टुकड़ा बना है उसमें भी दस मील का टुकड़ा इतना खराब है कि सैन्ट्रल ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी आये थे उनसे मैंने उसके बारे में बातचीत की थी। भक्तदर्शन जी भी वहां पधारे थे उनसे भी जिक्र किया था रेलवे स्टेशन से दस मील का टुकड़ा बन जाता हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से डिफेन्स वालों को २८ मील की दूरी पर ही स्टेशन मिल जाता है। आबूरोड़ से सांचोर वाली सड़क का निर्माण कर दिया जाता तो राज्य सरकार को खर्च भी कम होता। इसको पहले महत्व नहीं दिया गया इसके कारण आबू रोड़ से इनको कनेक्ट नहीं कर सके। जैसे मेंटल्ड रोड बड़गावा, जैतपुरा मंडार यहां तक सड़क है लेकिन बरसात के दिनों में नदियों में बाढ़ आ जाने से वह रास्ता बन्द सा हो जाता है। अगर इन पर पक्के पुलिया बना दिये जायं सिर्फ दो-ढाई घंटे में आबू रोड पहुंच सकते हैं। मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी यदि इन पर पुलिया बना दिये जायें, इस बारे में आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। इण्टर स्टेट रोड की दृष्टि से भी यह दस मील का टुकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है जिसकी ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया। हालांकि मंत्री महोदय तो इस रोड पर पधारे नहीं उप मंत्री महोदय इस रोड़ पर जरूर पधारे हैं उनको एक रात तो जरूर निद्रा जोर से आई होगी। यदि मंत्री महोदय पधारे होते तो शायद उनको हाथ पैर दबाये बिना नींद ही नहीं आती। इस सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गये हैं जिसमें डिफेन्स की रोड के लिए मेटिरियल वाली गाड़ियां भी नहीं चल पातीं केवल दस मील के टुकड़े के लिये इतनी परेशानी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

होती है।

इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चहूंगा आप गम्भीरता से इसको सोचें और हर हालत में अगले बजट में इसको बनवावे इससे सुरक्षा रोड़ का महत्व और बढ़ जायगा।

इसके अलावा जालोर जिले में फेअर वेदर रोड्स उनको भी अगले बीस सालों में पक्की रोड नहीं बना पायेंगे इस ओर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इन रास्तों में रेती आने के कारण रास्ते भर जाते हैं और गाड़ियां बन्द हो जाती है।

पहले वाले मंत्री श्री हरिश्चन्द्रजी ने भी आश्वासन दिया था कि ऐसी सड़कें साल में कम से कम एक बार विभाग द्वारा साफ कराई जानी चाहिए ताकि इस पर बसें चल सकें। बरसात और आंधी के बाद उनकी सफाई कराने में उनके बस वालों के ५-५ ७-७ हजार लग जाते हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं। और वे परमिट्स वापस जमा करा देते हैं। तो ऐसे जो रेतीले इलाके हैं, साल में कम से कम एक बार आप गैंग लगा कर साफ करा दें तो लोगों को सुविधा हो सकती है, वरना आगे आने वाले ५० वर्षों में भी इन सड़कों के बनाने की योजना नहीं है। क्योंकि आर्थिक संकट है। आवागमन की दृष्टि से ऐसी सड़कें जैसे सांचोरसे भीनमाल, भीनमाल से जाव, सांचोर से भाव, ऐसे रूट्स पर बसें नहीं चल सकतीं, कोई आपकी नई प्रोपोजल होनी चाहिए और सरकार को विचार करना चाहिए। आपको पुर्नविचार करने की आवश्यकता है, वरना ऐसे लोगों को ऐसे इलाकों में निकट भविष्य में सुविधा मिलना मुश्किल है।

जालौर जिला पिछड़ा हुआ जिला है, वहां पुरानी बिल्डिंग्स सरकारी हैं। सांचौर में छात्रावास का भवन है, मंत्री महोदय ने देखा था वहां के जो कुवार्टर्स हैं शफाखाने के, पिछले दो तीन सालों से मरम्मत नहीं हुई है, पैसा नहीं मिलता, तो नतीजा यह होगा कि लाखों रुपए की जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बेकार ढह जायंगी और इसके साथ-साथ पैसा न होने के कारण आप नए भवन नहीं बना सकते। विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजनीयर से कह कर ऐसी बिल्डिंग्स की मरम्मत की जानी चाहिए और इसके साथ-साथ सिरोही में एग्जीक्यूटिव इंजनीयर का आफिस है, वहां बहुत सी बिल्डिंग्स बन गई लेकिन जालौर, जहां संख्या ज्यादा, स्कोप ज्यादा, एलाटमेंट नहीं किया क्योंकि जहां हेडक्वार्टर है वहां ज्यादा पैसा खर्च हुआ है लेकिन जालोर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सांचोर में रेस्ट हाऊस में दो कमरे बने हुए हैं। आप हमेशा आते हैं। आप कहेंगे कि डिफेन्स का डाक बंगला बना दिया है, वह तो सुरक्षा की दृष्टि से है लेकिन चितकवाना सांचोर वहां ४-४ कमरों का रेस्ट हाऊस बनाना चाहिए। वहां सरकारी अधिकारियों के ठहरने की सुविधा नहीं है इसलिए सरकारी अधिकारी नहीं जाना चाहते। एक घंटा ठहरने के बाद भाग जाते हैं गाड़ी लेकर। इसलिए राज्य सरकार ऐसे इलाकों में जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और सांचोर इसमें आपको भवन निर्माण के बारे में योजना के तहत कुछ न कुछ हर साल आपको पैसा देना चाहिए

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और रेस्ट हाउस में कमरे जोड़ने की बात है या फर्नीचर की बात है उस ओर आपको खास करके पिछड़े इलाकों में आपको और ध्यान देना चाहिए। वहां जो उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन है, उसमें ३५,००० पंचायत समिति से दिलवाए और हमने आग्रह किया था कि कुछ पैसा शिक्षा विभाग से मिले परन्तु वह पैसा जो भी समिति ने दिया शायद विभाग ने खर्च नहीं किया है लेकिन उस इलाके में ठेका बड़ा हाई जाता है और यह भवन विभाग के द्वारा ही बनने चाहिए और न कि ठेके से। इससे डबल खर्चा होता है जोधपुर से पट्टियां लानी पड़ती हैं। इससे मुझे अनुभव होता है कि ५० प्रतिशत ठेका ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे इलाकों में धनाभाव के कारण आपको विभागीय मरम्मत करानी चाहिए। ऐसे इलाकों के लिए जो पिछड़े हुए हैं, जहां खर्चा भवन और सड़कों पर ज्यादा बनता है, तो विभागीय काम होने की आवश्यकता है। विशेषकर जालौर और सांचोर में जो फेयर वेदर रूड्स हैं रेतीले इलाकों में मंत्री महोदय उनके लिए कोई तसल्लीबख्श जवाब देंगे।

श्री मेघराज (चूरू) : सभापति महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० के काम में बरती जाने वाली अनियमितताओं के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। विभाग जो भवन बनाता है या सड़के बनवाता है उसमें लोकल रा मटीरियल का ध्यान नहीं रखा जाता जिसकी वजह से सरकार को जितना पैसा लगना चाहिए उससे अधिक लगाना पड़ता है और ठेकेदारों को दिक्कत होती है। कल ही सदन में श्री विजयसिंह रावत ने प्रश्न पूछा था जिसके जवाब में बताया गया, कि वह पाइप लाइन्स डालने का सवाल था, उसमें सही ढंग से योजना को देखते हुए एस्टीमेट नहीं बनाया गया, बाद में कुछ आइटेम्स हटाने पड़े और उसके फलस्वरूप ठेकेदारों को फायदा हुआ। चूरू जिले में वहां जो सफेदी की कली आती है वह लोकली न रख कर नागौरी कली रखी जाती है। मीठा चूना वहां से १०० मील दूर मिलता है लेकिन एस्टीमेट में लिख देते हैं और बाद में अधिकारियों से बदलवाना पड़ता है। मेरा सुझाव है जो एस्टीमेट बनाया जाय उसमें भी लोकल मटीरियल ही दिखाना चाहिए।

और भी आइटम्स हैं—लूणकरणसर और सूरतगढ़ की सड़क में चांदी की क्यूरी की बलास्ट थी दूसरे स्थान की बलास्ट बदल दी गई। अधिकारियों को मालूम था कि इतनी बलास्ट इस क्योरी में नहीं मिल सकेगी। मगर अर्थ वर्क के बाद बलास्ट की क्यूरी बदली गई। इससे करीब ६० रु० १०० क्यूबिक फीट पर सड़क में ठेकेदारों को अधिक मिला है।

टेण्डर्स का प्रकाशन नहीं किया जाता है और कभी-कभी एक दो का कहीं अखबारों में छापा भी जाता है तो उन तारीखों पर टेण्डर नहीं लिए जाते हैं और ठेका लेने वाले लोगों को टेन्डर देने के लिए जो आते हैं, उनको हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। एक टेन्डर के लिए हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है, एक-एक टेन्डर के लिए ५-५,७-७ बार आना पड़ता है और टेन्डर्स नहीं लिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस्टीमेट्स सैंक्शंन होकर नहीं आए, फाइनन्शल सैंक्शन नहीं आई है। अगर सैंक्शन नहीं है, एस्टीमेट मन्जूर नहीं

(श्री मेघराज)

है तो टेन्डर प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता होती है और जब भी उसकी मर्जी हो जाती है, अवसर देखकर टेन्डर्स लिए जाते हैं जिनके रेट्स हाई होते हैं ।

तीसरा मेरा सुझाव है कि शिड्ल आफ रेट्स जो हैं वह वरसों तक रिवाइज नहीं होता है, भाव नीचे आ जाते हैं, नतीजा यह होता है कि सरकार के जो ऐस्टीमेट्स हैं । उनसे टेन्डर उंचे जाते हैं । अधिक खर्च लगता है और उनके रेट्स हाई जाने से सरकार के मूल्यों में टेन्डर मन्ज़ूर करने में दिक्कत आती है ।

टेन्डर पचास-पचास परसेन्ट एबोव लिए जाते हैं । और समय पर शेड्ल रिवाइज किया जावे तो इतने टेन्डर ऊपर नहीं आवें ।

चौथा मेरा सुझाव यह है कि टूल्स और प्लान्ट्स जो खरीद किए जाते हैं उनमें किसी फर्म की आइडेन्टिटी तस्दीक नहीं की जाती । मनमाने ढंग से कोटेशन लेकर लाखों की खरीद कर ली जाती है । न तो नो ड्यू सर्टीफिकेट सेलसटेक्स का न इन्कम टैक्स का उनसे मांगा जाता है और लाखों का मामला नकली फर्मों से ले लिया जाता है । हर साल इससे सरकार को लाखों का घाटा होता है ।

टूल्स और प्लान्ट्स किराये पर देते है तो इसमें भी किराये में समान रेट नहीं है । उसी कम्पनी की दूसरी चीज है रोलर है उसके भाव प्रतिदिन ४५ रु० है और प्रोजेक्ट एरिया में ६० रु० कर रखा है । जिन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना होता है नान प्रोजेक्ट एरिया में फालतू बताकर किराये दे दिया जाता है ।

इन टूल्स और प्लान्ट्स के हायर-परचेज पर दिये जाने के नियम हैं । उन नियमों की पाबन्दी नहीं की जाती । पिछले बजट सैशन पर सदन में माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने यह सवाल उठाया था जीपों के बारे में । जवाब दिया गया था कि कामों की वेल्यू पर टूल व प्लान्ट्स खानापूर्ति करके उनसे कीमत दस प्रतिशत जमा करा कर दिये गये थे । जो गलत है । यह खानापूर्ति किस तरह से होती है इसके लिए एक अधिकारी की दूसरे अधिकारी के नाम जो चिट्ठी लिखी गई है, को मैं पढ़ देना चाहता हूं ।

No. 2056 Immediate
Dated 20.7.67

From :
The Executive Engineer,
B&R. Project Division I,
Bikaner.

To,
The Superintending Engineer,
B&R Project Circle (East),
Bikaner.

Sub : Transfer of Security Deposit.

The work of providing 3/4" thick Bitumen in Mile 36/0 to 43/750' of National Highway No. 11 was allotted in favour of Shri Om Prakash.

Contractor vide Chief Engineer, B&R, Rajasthan, Jaipur No. 5-67 (96) (36)/D-4602/Sec. II dated 23.12.1965. The work was completed on 10.2.1967 and sanction in the date of completion of the said work was accorded vide your office letter No. F. 2 (a) 26-w/PE/66/9209 dated 5.7.1967 without any compensation for delay. The final bill for the work has also been passed on 13.7.1967 and a sum of Rs. 10,528/-is lying Security Deposite in the credit account of the Contractor. The refund of Security Deposit becomes due on 10.8.1967.

M/s Ganrajya Shramik Theka Sahkari Samity, Ltd., Bikaner was issued one T. M. B. Truck Chassis and one Willys Jeep on hire purchase basis under the orders of the Addl. Chief Engineer, Projects, Bikaner. Since the Society did not remit any amount towards the 10% cost of the said vehicles, when these were allotted to them, whereas the recovery is to be immediately affected and the recoveries being affected from their running bills is also not enough as the progress of the Society is not good, they have submitted an application from Shri Laxami Narain Swami who is the power of attorney-holder and financiar of Shri Om Prakash, Contractor requesting this office to transfer the Security Deposit amount for the work stated in para I above to be transferred in the credit of the said Society. Copy of the application from Shri Laxami Narain Swami is submitted herewith for your kind perusal.

Though the refund will become due on 10.8.67, but as the recovery is to be affected immediately, I am passing transfer entry order, ordering for the refund of Rs. 10,528/-from the security deposit account of Shri Om Prakash contractor for the work of providing 3/4" thick bitumen carpet in mile 36/0 to 43/750' of N. H. W. No. 11, and crediting the amount towards the cost of one jeep issued to M/s. Ganrajya Shramik Theka Sahkari Samiti Ltd. Bikaner, in anticipation of your kind approval and request that the action taken may kindly be approved.

The work has been satisfactorily completed and there are no dues outstanding against Shri Om Prakash, contractor for this work.

Favour of early approval is requested.

Sd./

Executive Engineer,

B&R, Project Division No. I,

Bikaner.

तो १०।७।६७ को सिक्योरिटी की मियाद खतम होती थी उससे पहले दूसरी पार्टी ही जिसके जीप की अमाउन्ट जमा करना था उसके एवज में जमा कर दिया बिना उससे सैंक्शन लिए इसको रेगुलेराइज करने के लिए । जिस ठेकेदार की रकम दी गई उसने ओब्जेक्शन किया है कि मेरे को पूछा भी नहीं पहले ही बिल पास कर दिया और सिक्योरिटी का पैसा लेकर दस परसेन्ट रकम काट कर दूसरे के खाते में जमा कर दी गई ।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह जी ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : सभापति महोदय, मैं पी. डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर का ध्यान कोटा जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस जिले के साथ जिस तरह सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वैसा और नहीं होगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : करोड़ों रुपया लगाया है वहां तो इन्डस्ट्रीज में ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पर सड़कों पर नहीं लगाया । जो स्टेट टाइम पर फेअर वेदर रोड थीं उन पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और दिन-दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है । सरकार से पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि ये पंचायत समिति के अन्डर में हैं । पंचायत समिति से बात करते हैं तो राज्य सरकार के पास भेज देती है । इस तरह से टालने से लाखों की सरकारी प्रोपरटी है सड़के हैं, बिल्डिगें हैं । डर है वे कहीं नष्ट न हो जावें ।

छीपा बडौद तहसील जिसमें ५६ हजार की आबादी है वहां पर सरकार की ओर से एक भी डाक बंगला नहीं है । वहां अधिकारीगण या अन्य यात्री आते हैं तो बड़ी असुविधा होती है । तो वहां एक डाक बंगले की तो व्यवस्था होनी चाहिये ।

दूसरी तरफ छीपा बडौद सालपुरा से रेल्वे का कनेक्शन है । तहसील हेड क्वार्टर तक ११ मील की सड़क है । इसकी हालत इतनी खराब है कि डिलिवरी रोड के नाम से यह मशहूर है । अगर जच्चा मोटर में बैठकर उधर से निकले तो अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं होगी ।

छीपा बडौद से सालपुरा आते समय पांच मील के बीच में एक पालसी लासी गांव मावशिया के पास है । वहां बीच में एक चालीस फीट लम्बी पुलिया की दीवार जो बहुत पुरानी थी, धराशायी हो गई है । अब ट्रैफिक वहां से निकलता है तो एक्सीडेन्ट का डर बना रहता है ।

तो माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें कि उस पुलिया पर जल्दी से कार्य शुरू कराया जाये । दूसरे मैं निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ को मिलाने के लिए इकलेरा के पास एक नदी पर पुल है वह पुल इस कदर नीचे है कि बरसात में एक-एक महीने तक ट्रेफिक रुक जाता है इसलिए इस पुलिया को भी ऊंचा कराना आवश्यक है । दूसरी तरफ छबड़ा सब डिविजनल हैड-क्वार्टर है वहां पर पी०डब्ल्यू०डी० की तरफ से करीब ४ साल पहले स्कूल भवन के लिए एक कमरा बनाने का काम शुरू हुआ था

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

वह काम न जाने किस वजह से रुक गया, पता नहीं या तो वह इनकी निगाह में नहीं है या पता नहीं क्या कारण है वह काम अधूरा पड़ा है। इस तरह से राज्य का पैसा बरबाद हो रहा है और ५-७ हजार रुपया व्यर्थ लगा है और लड़कों को भी पढ़ने में असुविधा है।

एक और निवेदन करूंगा कि छीपा बड़ौद से इकलेरा और सालपुरा तक जो सड़क है उस सड़क के लिए जैसा कि सरकार का नियम है कि सड़क से ३० फुट तक कोई मकान या किसी तरह की अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो मैं मंत्री महोदय के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि हमारे यहां छीपा बड़ौद के अन्दर के मवासा के अन्दर इकलेरा के अन्दर मुश्किल से सड़क से २ फुट भी जगह खाली नहीं है। वहां पर दो गाड़ियां भी एक साथ पास नहीं हो सकती हैं। इस तरह से वहां का जन जीवन खतरे में है तो पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब इस तरफ विशेष ध्यान दें।

इसी तरह से कबाई से छवड़ा जाने के लिए ८ मील का टुकड़ा है इस पर पांच साल से काम चालू है मगर मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख है कि आज तक वह सड़क पूरी नहीं हुई है। अभी जो काम चल रहा है वह सड़क का काम कुछ हद तक चल रहा है लेकिन पुलिया के निर्माण की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर सड़क बन गयी और पुलिया नहीं बनी तो जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

माननीय सभापति जी पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर फैले भ्रष्टाचार के विषय में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। कोटा के अन्दर एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर है मिस्टर सी० पी० एल० सोरल मोटा मन्डी के तो इन्होंने शापिंग सेन्टर में नाला बनाने का ठेका दिया हुआ है। ठेके की रेट ४० पैसा प्रति कातला के हिसाब से है जिसके बजाय इन्होंने कांट-छांट करके ९९ पैसा कर दिया है। इस तरह से सरकार को ५०००० रुपये का ज्यादा पेमेन्ट करना पड़ेगा जिसमें से २०,००० रुपये का ओवर पेमेन्ट तो हो चुका है। इससे साबित होता है कि संबंधित आफिसर कुछ गलत नीति पर है और इन्होंने कुछ कमाया है। इसी तरह से अगर माननीय मंत्री जी जांच करेंगे तो मालूम होगा कि कोटा हवाई अड्डे पर २ इंच के कातले लगाने के थे तो मुश्किल से डेढ़ इंच के कातले लगाये हुए हैं। इसी तरह से ३ – ४ इंच की मोटाई के कातलों की रेट जो कि ५५ पैसा के हिसाब से मन्जूर हुई थी उसको भी कांट छांट कर १.१४ के हिसाब से किया गया। इसी तरह से सरकार को करीब १।। लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा और इसमें इन्होंने कितना लिया यह तो आप ही अन्दाजा लगा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर जांच करे।

इसके अलावा झालावाड़ जिला जो कि मेरी कान्स्टीटुएन्सी के पास है उस ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। मनोहरथाना से चांचोड़ा पर ५२ से काम चल रहा है और यह ९ मील की सड़क है और यह सड़क राज-

(श्री प्रेमसिंह सिचवी)

स्थान को आगरा–बम्बई रोड पर पहुंचाती है । राजस्थान से मध्यप्रदेश को मिलाने के लिए यह ९ मील का टुकड़ा ही है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ५–७ साल से काम चलता रहा है लेकिन यह सड़क पूरी नहीं हो पाई है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें ।

इसी तरह से कोटा डिस्ट्रिक्ट के सड़कों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही हैं तो माननीय मंत्री महोदय अपना इस ओर ध्यान दें ।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल–स्वतंत्र पार्टी

श्री चुन्नीलाल (खण्डार सु०) : माननीय सभापति महोदय, मेरे भी कुछ कटौती के प्रस्ताव हैं । उपाध्यक्ष महोदय, खण्डार तहसील मध्य भारत की सीमा से मिली हुई है । उस तहसील के किनारे–किनारे होकर चम्बल नदी बहती है उसके कटाव से सारी खण्डार तहसील को बड़ा नुकसान हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर मध्यभारत की सीमा से हमारे राजस्थान की सीमा मिलती है इसलिए इस सीमा के निकट किसी भी किस्म की रोड की व्यवस्था नहीं है और इस कारण से इस क्षेत्र में डकैतों का भी बहुत डर रहता है । दो–तीन वर्ष पहले भी डकैतिया हुई थीं । रोड नहीं होने से डकैतों को ढूंढने के लिए हमारे यहां की पुलिस भी नहीं पहुंच सकती है इतना बैकवर्ड इलाका है । तो खण्डार से १६ मील का टुकड़ा है और ८४ गांव उस एरिया में आते हैं और उस क्षेत्र के नागरिकों को आने जाने में बड़ी मुश्किल होती है । तो उस इलाके में रोड के संबंध में व्यवस्था होनी चाहिए । कुछ दिनों पहले ६०–६१ में खण्डार से ६ मील का टुकड़ा मैरावडा का लगता है उसके लिए बजट में पहले प्रावधान था लेकिन उसको भी अब हटा दिया गया है । तो सभापति महोदय जिला हैडक्वार्टर सवाई माधोपुर से खण्डार २४ मील पड़ता है । २४ मील से आगे का जो टुकड़ा है २० साल में एक मील भी उस पर काम नहीं किया गया है । उसके बीच में बनास नदी पड़ती है । यह दो हिस्सों में बांटती है ।

(२.४८ म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस खण्डार तहसील की तरफ सरकार का ध्यान विशेष होना चाहिए और जैसा कि स्टेट के टाइम पर कुछ होता था लेकिन अब दो तीन बार से कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होने से उस तहसील को बिलकुल नहीं संभाला जाता है । इसलिए उन कामों को पूरा कराया जाये । कुछ दिनों पहले फरवरी ६७ में नालों का काम जारी किया था तो उस समय वहां पर गड्डे ही करवा दिये और चुनाव सम्पन्न होने के बाद उन गड्डों में भी मिट्टी नहीं डाली । इसलिए इस पक्षपात से काम नहीं होना चाहिए और समानता का अधिकार उस क्षेत्र को भी मिलना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ !

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी आम बजट पर चर्चा हुई थी उस समय मैंने एक मुद्दा राज्य सरकार के सामने रखा था कि राज्य सरकार के बजट घाटे का प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको यदि नियन्त्रण कर दिया जाय तो यह घाटे का बजट सरप्लस में परिवर्तित हो सकता है और उसमें नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई नई योजना लगाने की जरूरत नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ भी आता है वह ठीक ढंग से राज्यकोष में आ जाय और राज्यकोष से जो कुछ भी व्यय होता है वह ठीक ढंग से उतने का उतना लगाया जाय। बस इतनी सी सावधानी की जरूरत है। लेकिन मुझे एक फिरका याद आता है —

क्या कहूं किस से कहूं, होश में आये तो कहूं।

कई मानीय सदस्य : वाह, वाह !

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अभी तो ये मदहोश हैं, होश में आये तों कहूं।

क्या कहूं किससे हूं सुनने वाला हो तो कहूं,

अभी तो मदहोश हैं होश में आये तो कहूं।

मेरा यह मुद्दा था कि निश्चित रूप से जो राजकीय सम्पदा है वह खुले रूप से लुटाई जाती है और एक पैसा राज्य सरकार में आता नहीं है। मैंने उस समय जंगल का उदाहरण दिया था कि हमारे सवाई साधोपुर में एक करोड़ के जागीर के जंगल बगैर राज्यकोष में एक पैसा आये कटवा दिये गये। यह राज्य सरकार का नियन्त्रण है।

इसी प्रकार से खनिज सम्पदा का भी मामला है। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो राजकीय सम्पदा है उसकी कीमत राज्यकोष में आने की बात है लेकिन उन मांगों पर बहस हो चुकी है। अब प्रश्न यह उठता है कि राज्यकोष से क्षेत्रों के विकास कार्य पर किये जाने का प्रश्न खड़ा होता है तो उतना पैसा वहां दरअसल नहीं लग पाता है। इसलिए मैंने कुछ मुद्दे यहां कटौती—प्रस्ताव के रूप में रखे हैं।

एक उदाहरण देकर इस बात का प्रयास करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि दरअसल किस प्रकार से जो कुछ भी कर के द्वारा गरीब लोगों से जो टैक्स के रूप में धनराशी वसूल होती है उसका व्यय जब किया जाता है विकास कार्यों में तो किस प्रकार से उसमें से २० या २५ पर्सेन्ट प्राइवेट पाकेट्स में राज्यकोष का पैसा चला जाता है। अभी हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो कुल १९,३०० किलो मीटर सड़के राजस्थान में पहले से ही थी। उसके पश्चात् तीन पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है तो हम इस सड़क निर्माण का कार्य कुल ३०, ५९६ किलोमीटर बनाकर प्रगति कर चुके हैं। इसमें वह सड़क भी शामिल है जो कि कच्ची सड़के हैं। पक्की सड़क और डामर सड़क की कोई अधिक प्रगति पहले से नहीं कर सके हैं। सीमेंट की सड़क ४० किलोमीटर तृतीय पंचवर्षीय तक हम बना सके हैं। इस प्रकार डामर सड़क ११५१० किलोमीटर बना सके हैं, पक्की सड़क कुल ५७४१। यह हमनें ६६ तक प्रगति की है। २ वर्ष तक हमारा सड़क की प्रोग्रेस का मामला बिल्कुल नगण्य है। मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमाव बजट में तो

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

सड़कों का बिल्कुल ढेर हो गया है' और बहुत कम प्रावधान इसके लिए रखा गया है। सड़कें कृषि उपज को मन्डियों तक पहुचाने की दृष्टि से और दूसरे कामों को बढ़ावा देने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं यह मानकर चलता हूं कि यह नहीं समझना चाहिये कि केवल आवागमन को ही सुगम बनाती हैं, लेकिन इस प्रकार भी आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं कि जिन इलाकों में सड़कें नहीं हैं वहां के गरीब किसानों का धान और दूसरी चीजें सस्ते दामों पर बिकती हैं इसलिए कि वहां पर ट्रान्सपोर्ट की अधिक व्यवस्था नहीं है। सड़कें केवल आवागमन की दृष्टि से नहीं बल्कि दूसरे मायने में भी किसानों के लिए बहुत बड़ी लाभदायक और आर्थिक लाभ पहुचाने का उद्देश्य पूरा करती हैं।

लेकिन, उपाध्यक्ष, महोदय, हमने बजट को देखा है तो बजट के देखने से यह पता लगता है कि जहां हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ९६० करोड़ रुपये इन सड़कों क निर्माण—कार्य में खर्च किया है हमने, लेकिन अब धीरे-धीरे प्रतिवर्ष इस कार्य मे उदासीनता बरती जा रही है और बहुत कम सड़क निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है।

अब मेरे क्षेत्र की बात कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे यहां पर दो सड़कें कट की गई हैं। नवाब साहब के पास यह नया महकमा है। पहले बजट प्रस्तुत किया था तो अकाल था। आप सवाई माधोपुर कई बार गये हैं। यही नहीं आप उसके अन्दर के भागों में भी गये हैं। आपने वहां की स्थिति देखी है। खंडार तक आप पहुचे हैं और खंडार के आगे सड़क के ६ मील के टुकड़े का प्रावधान प्रतिवर्ष होता है, लेकिन आश्चर्य और खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रावधान रखने को तो रखदिया लेकिन १ मील सड़क आगे नहीं बढ़ी है प्रावधान रखने को तो रख दिया, लेकिन किन्हीं राजनैतिक कारणों से जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने बता दिया कि दरअसल कारण यह था कि ५७ के बाद वहां से कांग्रेस हार रही है इसलिए सड़क नहीं बनने दी। इस प्रकार हर बात में राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो बहुत बुरी बात है। यह कोई एक पार्टी की बात नहीं है राज्यकोष केवल उन्हीं से नहीं आता है जो कि कांग्रेस के मतदाता है। सब का पैसा है। सब पर समान रूप में खर्च होना चाहिये। नवाब साहब से बात की तो निष्पक्षता और आदर्श की दुहाई बार बार देते हैं कि जहां तक मैं हूं बिल्कुल बड़ी निष्पक्षता से काम करूंगा, लेकिन परिणाम में क्या देखा कि खंडार से बहरांवड़ा तक सड़क और बौली से निवाई तक की सड़क को बार बार छोड़ दिया जाता हैं। १५ वर्ष गुजर गये लेकिन पता नहीं। पैसा लग गया सब कुछ हो गया मैं मानता हूं कि ४-५ मील का काम बीच में रह गया। निवाई से शुरू कर दिया और इधर बौली से शुरू कर दिया गया और बीच में छोड़ दिया।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी पार्टी का समय काफी है।

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी का समय नहीं है। दस मिनिट आपके सचेतक ने लिखकर

(श्री उपाध्यक्ष)

दिये हैं-उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : दूसरों का कम कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरों पर कोई अनुशासन नहीं है । यह मैं मानता हूँ ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : बीच में उनको छोड़ दिया गया । पैसा लग गया, लेकिन सड़क पूरी नहीं हुई । उस बौली से निवाई की सड़क को कट कर दिया गया ।

दूसरी बात यह हे कि बजट में प्रावधान किया गया है एक जिला अस्पताल का । जिला अस्पताल का प्रावधान रखा तो पहले स्थान के नाम से अटक गया और स्थान के नाम पर अटकने के बाद स्थान तय हो गया तो उसके बाद अब मामला आ रहा है टेन्डर्स का । टेन्डर्स में भी बड़ी पेचीदगी डाली गई । टेन्डर्स आये हैं तो जो कम से कम रेट का हो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है । स्वीकार किस को किया जाता है ? वहां पर सवाई माधोपुर से इन्द्रगढ़ वाली सड़क पर २० मील का एक टुकड़ा है । उस २० मील के टुकड़े के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि सवाई माधोपुर से इन्द्रगढ़ की जो सड़क बन रही है उसमें भी बड़े-बड़े घोटाले हैं । वह एक ऐसे ठेकेदार के पाले पड़ी है कि उससे ५ वर्ष में भी १६ मील का टुकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है । ७ वर्ष पूरे हो गये । काम पूरा नहीं किया । अर्थ वर्क चला तो अर्थ वर्क में ५० पर्सेन्ट एक्सेसिव पेमेंट ले लिया । उसने बिल में ज्यादा लगा दिया बाद में वह वापिस वसूल हुआ । वहां पर गिट्टी का काम चल रहा है तो साढ़े चार इन्च का एग्रीमेंट है लेकिन गिट्टी ढाई इंच की कूटी जा रही है और दो इंच हजम हो रही है । साढ़े चार इंच की गिट्टी का पैसा दिया जा रहा है । इधर सड़क आगे बढ़ रही है उधर गिट्टी सब उखड़ रही है । गिट्टी के काम में इन्दरगढ़ वाली सड़क पर ओवरसियर को सस्पेन्ड कर दिया गया है । क्योंकि ठेकेदार से मिलकर ओवर पेमेन्ट दिलाया ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी).

जिला अस्पताल का काम उसी ठेकेदार को फिर से दिया जा रहा है ।

(३ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कर ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : भू मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से सोच-समझकर निर्णय लें । ऐसे ठेकेदार को ठेका दिया जा रहा है जिसका रवैया इस तरह का रहा है ।········

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : वह ठेकेदार···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण समाप्त करें ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय······

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

Page No. 119

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मुझे दूसरे सदस्य गण समय दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे सदस्यगण कोई सहयोग नहीं देंगे और शाम के वक्त हर रोज झगड़ा होता है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ऐसे ठेकेदारों को अस्पताल का काम·······

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। वक्त समाप्त हुआ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हम कभी तो खड़े होते हैं······

श्री उपाध्यक्ष : यह आपकी आन्तरिक व्यवस्था का प्रश्न हैं। आर्डर प्लीज़।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं बहुत दिनों में तो बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ·····

श्री जगन्नाथ पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनटों में निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ···खैर आपकी आज्ञा मानकर बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) **:** उपाध्यक्षजी, मेरी पार्टी ने मेरा नाम नहीं दिया था, लेकिन दो ही मिनट में अपनी बात कहना चाहती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सबको समान अवसर दिया जाना चाहिए। हमको सबसे कम समय बोलने का चान्स दिया जाता है। यहां तक होता है कि पूरे सत्र में······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह आपकी बात तथ्यों से परे है। आपके दल का जो समय है वह पूरा दिया जाता है, एक दो मिनट ज्यादा ही होंगे। अब आपकी आन्तरिक व्यवस्था ऐसी है कि आपकी पार्टी के सदस्य ही आपसे सहयोग न करें तो आसन के पास उसका कोई उपाय नहीं है। आपके सचेतक की तरफ से बार-बार इस बात के लिये रिक्वेस्ट आती है कि हमारे माननीय सदस्यों के लिए जितना समय निर्धारित किया जाता है उससे एक मिनिट भी ज्यादा न दिया जाय। मुझे अफसोस है कि मैं कभी नहीं चाहता कि माननीय सदस्य भाषण समाप्त नहीं करें तो आसन को इसके लिये बाध्य होना पड़े, यह मैं कभी नहीं चाहता। राइट आफ डिबेट इन्वेल्युएबल राइट है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पड़ता है, तो माननीय सदस्य मेरी भावना को तो इस मायने में समझें।

श्रीमती गौरी पूनिया।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना)**:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो ही मिनिट में अपनी बात कहना चाहूँगी। वैसे मैंने बहुत सी बातें सदन में कही लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका मुझे अफसोस है मेरा कटौती प्रस्ताव जो है उसमें यह है कि सड़कों की डेगाना क्षेत्र में बड़ी ही दयनीय स्थिति है, लेकिन उन सबके बारे में न कहकर केवल एक ही सड़क के टुकड़े का जिक्र करूंगी, क्योंकि उसके बारे

(श्रीमती गौरी पूनिया)

में मैं पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब से मिली थी और उन्होंने मुझे यह कहा कि मैं सड़क ऐसे नहीं बनाता हूं। मैं तो मौके पर जाता हूँ और देखकर सड़कें बनाता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही आधार रहा तो न तो मौके पर पहुंच सकेंगे और नहीं इस तरह से वह सड़क बनने वाली है।

सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे क्षेत्र में पधारे थे और वे बड़े दुखी हुए जब उन्होंने वहां की सड़कों को देखा। उन्होंने मुझे एश्योरेन्स दिया कि इस तरह की सड़कों की स्थिति है तो कहती क्यों नहीं हैं ? मैंने उनको बताया कि कहने पर यह उत्तर मिलता है। अतः इस मौके पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि रेगा से सांजू सड़क बनानी बड़ी जरूरी है। ये गांव ऐसे हैं कि जहां घुटने घुटने तक रेत है और पैदल चलना मुश्किल होता है। यहां पर पत्थर पास में ही निकलता है। किसान चाहते हैं कि पत्थरों के मकान बनायें क्योंकि वहां के किसान अच्छे खाते पीते हैं लेकिन वे मकान सड़क के न होने से नहीं बना सकते हैं। इस सड़क के लिए (रेगा से सांजू के लिए) मैंने बजट देखा है कि उसमें एक भी पैसा नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि रेगा से सांजू इतनी आवश्यक सड़क है कि इसे बनाना जरूरी है। हम डामर की रोड नहीं मांगते आपसे सिर्फ कच्ची सड़क ही बना दें उसमें भी आप आनाकानी करते हैं।

दूसरा मेरा कटौती-प्रस्ताव डेगाना प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के बारे में है। १० साल पहले राज्य सरकार ने इसको अपने चार्ज में लिया था लेकिन इस पर मरम्मत का एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। इस तरफ हर वर्ष ध्यान आकर्षित किया जाता है, पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है। मैं आपके द्वारा कहना चाहूँगी कि इस तरह से हम कोई बात सदन में करते हैं तो मन्त्री महोदय को उस पर ध्यान देना चाहिए।

अब मैं डिप्टी मिनिस्टर महोदय से कहूँगी कि आपको यह रेगा से सांजू की सड़क बनानी है क्योंकि माननीय मंत्रीजी ने तो मना कर दिया है। आप अगर असमर्थ हैं तो मेरा यह मैसेज माननीय मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगन्नाथ !

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्यों के बाबत आपकी मार्फत निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि टोडारायसिंह क्षेत्र के अन्दर जो सड़कें तहसील देवली और टोडारायसिंह को क्रास करती हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे एक तहसील से दूसरी तहसील में जाती हैं...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ये आया राम हैं या गया राम हैं ?

श्री जगन्नाथ : मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं।

श्री नत्थीसिंह : ये गया राम भी हैं और आया राम भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ : मैं भी डिस्टर्ब करना काफी जानता हूं।

(श्री जगन्नाथ)

उपाध्यक्ष जी, यह रोड टोडा से रायसिंह को जाती है तो इसके दरम्यान में कोई डामर नहीं है, और सड़क बहुत खराब हो रही है। उसके बीच में नाला जाता है साधारण नानेट गांवों के बीच में वर्षा के दिनों ट्रेफिक रुकता है। उस पर पुलिया थोड़े पैसों में ही बन जाती है तो उसके बाबत मैं निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरी बात मालपुरा से टोडा रोड जाती है वहां टोडी से टोडा तक ९ मील के एरिया में डामर नहीं है। बीच में नाला है तो उससे आने जाने में वर्षा के दिनों में काफी रुकावट हो जाती है। उस पर पुल बनाने के लिए मैं आपकी मार्फत निर्माण मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरी बात...

श्री रामकिशन : चौथी बात है।

श्री जगन्नाथ : आप झमेले में न आयें। उस वक्त मैंने स्कूल पा लिया था जब कि आप पैदा नहीं हुए थे।

श्री नत्थीसिंह : फिर भी मंत्री महोदय नहीं सुनते हैं।

श्री जगन्नाथ : आप मुझसे मत लड़िये। मैं उपाध्यक्ष महादय, निर्माण मंत्री महोदय को आपके द्वारा चेतावनी देता हूं कि जो टोरडी से टोडा के दरम्यान की सड़क है उस पर डामर नहीं है और उस पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं तो वहां पर महरबानी करके डामर लगवाने की कोशिश करें।

तीसरी बात, मैं भूल जाता हूं ! (श्री नत्थीसिंह के बोलने पर) वकील साहब मैं भी ऐसे ही करूंगा। मैं फोरन जवाब दे देता हूं।

टोडा से देवली जो रोड जाती है वह बीच में उसमें काम हुआ है वह १११ मील के अन्दाजन का टुकड़ा है वह टोडा से मालपुरा को जो सड़क जाती है क्रास करती है कोटा से जो देवली सड़क जाती है उसको उसकी तरफ निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने के लिए निवेदन करता हूं।

और एक टोडा से रोड राजनद होती हुई मालपुरा जाती है। उसका एक टुकड़ा देवली रोड को क्रास करता है। वह जगह जगह से टूटी हुई है। वह बहुत जरूरी है। उसकी तरफ मैं निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान दिलाता हूं।

बहुत से एक दो मील के टुकड़े पड़े उन पर गौर करने की जरूरत है कि इन को ठीक कराया जाय।

इसके ऊपर रोलरफेरने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके द्वारा निर्माण मन्त्री से निवेदन करूंगा।

एक अर्ज और है। मालपुरा डिविजन और टोडा डिविजन में ६६-६७ में रकम मंजूर हुई निर्माण कार्य के लिए उसमें से २० हजार रुपये सवाई माधोपुर में निर्माण कार्य के लिए लगाये गये हैं तो मैं निवेदन

(श्री जगन्नाथ)

करना चाहता हूं कि उन २०,०००) रू० को टोडा और मालपुरा में लगाने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल ५ मिनिट में ही निवेदन कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, १० साल से मैं बराबर बजट देखता आया हूं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को चुनौती देता हूँ कि १० साल में पाली तहसील में कोई सड़क निर्माण की गई हो तो बतावें। मैंने कई बार कहा है कि पाली से खैरवां १० मील की दूरी पर हैं। इस गांव की तरफ आने जाने का रास्ता बरसात में बिल्कुल खराब हो जाता है। अभी जब बाढ़ आई थी तब हम लोग अकाल सहायता और बाढ़ नियन्त्रण मन्त्री जी वहां तक नहीं जा सके। मैंने कई बार कहा है कि आप पूरी सड़क को एक साथ नहीं बना सकें तो एक-एक, दो-दो मील करके पूरा कर दीजिए। यह सड़क इतनी आवश्यक है कि आसपास के जितने गांव हैं उनमें काफी काश्तकार हैं और वे गांव में आने जाने में तकलीफ उठाते हैं। मारवाड़ जंक्शन से आनेवाले यात्री तकलीफ उठाते हैं। लेकिन १० साल तक बार बार कहने पर भी नहीं बनाई गई। मैं पुर जोर अपील करता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है इसलिए पाली खेरवा तक की सड़क तुरन्त बनाई जाय। यदि धन राशि की कमी है तो आप एक-एक, दो-दो माइल बनाकर पूरा करिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने यहां पर कहा था कि अधिशासी अभियन्ता का दफ्तर जिले के हैड क्वार्टर पर रहेगा। लेकिन पाली जिले के एग्जीक्यूटिव इन्जीनयर का दफ्तर जोधपुर में है। मैं चाहता हूं कि इसका दफ्तर पाली में हो। पाली जिले में हमें काफी काम करना होता है। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने कहा था कि उसका हैड क्वार्टर पाली में ही होगा लेकिन पाली का दुर्भाग्य है कि कार्यालय जोधपुर में है, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर जोधपुर से वहां जाते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो मकान पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा बनाये जाते हैं उनके डवलपेमेन्ट चार्जेज म्युनिसिपेलिटि को नहीं देना चाहते सारे मकान म्युनिसिपेलिटी की जमीन पर बनते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के रिप्रजेन्टेटिव जो कमेटी के मेम्बर हैं उनके सामने यह निर्माण हुआ था कि जो मकान नगरपालिका की जमीन पर बनाते हैं उसका डेवलपमेन्ट चार्जेज देंगे। पाली में २० क्वार्टर्स बनाये गये लेकिन उस जमीन के चार्जेज १ रु. २५ पै. प्रति वर्ग गज के हिसाब से देने चाहिये थे वे आज तक नगरपालिका को नहीं दिये गये। नगर पालिका को आपको हाऊस टैक्स भी देना, चाहिये, पी. डब्ल्यू. डी. की इमारतें बनती हैं, उन इमारतों में बिजली पानी पहुंचाने का काम नगर पालिका का होता है लेकिन नगरपालिका अपनी जमीन की डेवलपमेन्ट की कीमत मांगती है तो वर्षों तक नहीं देते हैं और कहते हैं कि यह तो हमारा काम है, गवर्नमेन्ट बिजनेस है। पी. डब्ल्यू. डी. को मालूम होना चाहिये कि नगरपालिका के नियमों में लिखा हुआ है कि जब कोई इमारत बनावे तो नगर-पालिका को पहले सूचना देनी चाहिये

(श्री मूलचन्द डागा)

लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. वाले इमारत खड़ी करते हैं तो उसकी सूचना तक नगरपालिका को नहीं देते। एकबात मैं और कह देना चाहता हूं कि आपका विभाग जितनी धन-राशि कलेक्टर के बंगले की मरम्मत के लिये लगा देती है उतनी दूसरे अफसरों के बंगलों पर नहीं लगाती। दूसरों के बंगलों पर कम धन राशि लगती में, जुडिशियल ओफीसरों के बंगलों पर भी उतनी ही राशि लगानी चाहिये जितनी कलेक्टर वगैरह पर लगती। गवर्नमेन्ट के बंगलों का हाउस टैक्स भी म्युनिसिपेलिटी को पी. डब्ल्यू. विभाग से देना चाहिये, गवर्नमेंट के बंगले बनाये हैं जिनमें ओफिसर लोग रहते हैं, नगरपालिका की तरफ से हर तरह की सुविधा दी जाती है और उसके बदले में हाउस टैक्स हर नागरिक देता है लेकिन आपके ओफीसर जो सिविल लाइन्स में रहते हैं उनका हाउस टैक्स कौन देगा? यह बड़ा प्रश्न है, सोचा जाय तो यह पैसा नगरपालिका को फौरन देना चाहिये। यदि नगरपालिका बिजली पानी की सुविधा बंद करदे तो क्या हाल होगा?

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानिया।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान जयपुर जिले के निर्माण विभाग के कार्य की ओर दिलाऊं। जयपुर जिले में सड़कों और भवनों का जो कार्य हो रहा है उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जयपुर हमारे राजस्थान प्रान्त का केन्द्र-स्थान है और इस नाते सारे राजस्थान के लोग जयपुर में आते हैं। जयपुर जिले की सीमा के अंदर घुसने पर इस बात की खुशी होती है कि हम राजस्थान की राजधानी की ओर जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ज्यों ही मोटर राजस्थान के अंदर जयपुर जिले में आती है और एक दम वहां की सड़कों पर लोगों की नजर पड़ती है, राज्य के मंत्री जिस जिले में रहते हैं,.........

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिये समय की सीमा ७ मिनट है। भूमिका में ज्यादा समय लेंगे तो तथ्य की बात नहीं कह सकेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : सवा तीन बजे हैं और १० मिनट का समय मुझे दिया गया है.....

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज। यह आपकी इन्टरनल व्यवस्था है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री लादूराम सुलानियां : पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने २ मिनट मेरे लिये छोड़े हैं फिर भी मैं सीमित समय का ध्यान जरूर रखूंगा लेकिन कम समय में मेरी बात पूरी नहीं कह सकूंगा। जयपुर जिले की जो सड़कें हैं और उनकी जो हालत है उस ओर पिछले २० वर्षों में भी निर्माण मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया है। मुझे यह कहना पड़ेगा कि इस साल सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं वे इस ओर ध्यान दें तो मैं कुछ सुझाव उनके सामने रखना चाहूंगा जो निम्न प्रकार है :—

मैं यह कहना चाहूंगा कि दूदू से फागी जाने वाली जो रोड है वह चाकसू और

(श्री लादूराम सुलानिया)

कोटखावदा तक जाती है और सांभर-दूदू-कोटखावदा से मिलती है। यह बहुत बड़ी सड़क है परन्तु दुर्दशा यह है कि इस पर कहीं पर डामर नहीं है, कहीं पर पुलिया नहीं और इस पर काफी घूम है। यदि आप इसके घूम का निरीक्षण करें तो आपको विश्वास हो सकता है कि इस सड़क के साथ सौतेला व्यवहार रहा है। गांव चकवाड़ा के पूर्व में एक घूम है उस पर पचासों एक्सीडेन्ट हुए हैं, एक बालक भी मरा है। इस घूम को निकालने में ज्यादा से ज्यादा पी. डब्ल्यू. डी. को २०००) खर्च करने पड़ेंगे लेकिन आपने केवल २०००) रु. खर्च नहीं कर के जनता को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाया है। मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार के घूम नहीं निकलवाये जायेंगे तो एक्सीडेन्ट्स होते ही रहेंगे और एक्सीडेन्ट्स से लोगों को बहुत भारी नुक्सान उठाना पड़ेगा।

इसके अलावा मैं और सुझाव देना चाहूंगा, जो नई रोड प्रस्तावित हैं सरकार के सामने, और जो नई रोड बनाने की योजना है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। वहां एक रोड है–नियेड़ा-मन्दवास-कुड़ली घटीवाली पचेवर होती हुई पचेवर मिलाई जाय। इससे सुविधा बढ़ेगी और आवागमन के साधन के लिए रोड होगी। दूसरी है मन्दवास, मन्डावरी होती हुई पीरली से मिलाई जाय। इसके अलावा रेनवाल गुन्दी-लदाना होती हुई। इसके अलावा एक है बोराज से बन्धे होती हुई फुलेरा जाने वाली रोड। एक है रेनवाल, पीपला होती हुई भाकरोटा जाने वाली जिसको चाकसू से निमोडीया तक मिलाने का काम है, चाकसू से छीगुनीया मिलाने वाली है। इस प्रकार की रोड कई बनी हुई हैं जो आज से नहीं दस-पन्द्रह साल से है और सरकार और जनता का श्रमदान के रूप में रुपया लगा हुआ है लेकिन आज तक उनके ऊपर कंकर नहीं बिछाये गये हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये सड़कें हैं इनको मद्दे नजर रखते हुए इन पर पूरा पूरा गौर फर्मायें।

कुछ मुद्दे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे हैं जो ठेकेदारों से सम्बन्धित हैं (समय-समाप्ति सूचक घंटी) वैसे तो कई ऐसे मामले और हैं लेकिन उनकी ओर ध्यान न दिला कर मैं विशेष ध्यान इस पर दिलाऊंगा कि ठेकेदार और पी. डब्ल्यू. डी. का दफ्तर है, इनमें मिली भगत होने के कारण राजस्थान के धन का दुरुपयोग होता है। वह ऐसे कि कोई ठेका ठेकेदार को मिलता है उसमें से पी. डब्ल्यू. डी.के अधिकारी, छोटे से लेकर बड़े तक, इन्जीनियर से लेकर जमादार तक रिश्वत खाते हैं। यह एक सही बात है, इसका सबूत माननीय मंत्री जी ध्यान देकर देखें और इसकी जांच करायें तो ठेकेदारों का जो कच्चा रिकार्ड है, कच्चा चिट्ठा है उसके अन्दर तफसील इसकी होती है, उसमें एन्ट्री चढ़ी हुई होती है कि किस सेक्शन के लिए किस इन्जीनियर के नाम, किस ओवरसियर के नाम, किस जमादार के नाम कितना दिया गया। इस प्रकार की उसमें एन्ट्री मिलेंगी। हम इन्जीनियर को जैसे पांच सौ रुपये की तनख्वाह देते हैं तो वह ठेकेदार से भी पांच सौ लेता है, ओवरसियर को गवर्नमेंट डेढ़ सौ रुपये देती है तो

(श्री लादूराम सुलानिया)

उसको ठेकेदार भी डेढ़ सौ रुपया देता है, इसी तरह से जमादार को साठ रुपया देते हैं तो किसी ठेकेदार ने उसको साठ रुपये नहीं दिये तो वह खदार नहीं खोदने देता है। ऐसी स्थिति में पी. डब्ल्यू. डी. से मिलने वाली रकम का पच्चीस पर्सेन्ट पी.डब्ल्यू.डी. के आदमियों को नहीं दे तब तक उसके ठेके का पेमेन्ट नहीं हो सकता है। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अभी–अभी करीबन दो महीने पहले जयपुर के एक ठेकेदार का बहुत बड़ा रिकार्ड पकड़ा गया है। उसकी जांच चल रही है। उस जांच में अब तक यह बात सामने आई है कि कई इन्जीनियर के नाम वहां पर रुपया रिश्वत देने की एन्ट्री मिली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि सुनेगा कौन, कोई नहीं सुनेगा। मेरा निवेदन है कि सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो भी सुनना पड़ेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार राजस्थान की जनता के साथ होता रहा, इस प्रकार का व्यवहार हमारे राजस्थान की दो करोड़ जनता के साथ करती रही तो बर्दाश्त अब वह भी नहीं करेगी। वह दिन दूर नहीं है जब .....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन के सम्माननीय सदस्य हैं, यह अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपको आसन ग्रहण करने के लिए बार-बार घण्टी बजाऊं और आप स्थान ग्रहण न करें। यह बच्चों वाली बात है, इसलिए मैं उचित नहीं समझता। इसमें सहयोग दें और बोलने का टाइम तो और कभी मिल जायगा।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं आपके सामने इसकी मिसाल बताना चाहूंगा। जयपुर शहर में सवाई मानसिंह स्टेडियम बना है। उसके अन्दर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस समय यहां बड़े-बड़े इन्जीनियर और उच्च अधिकारी आये और उसका गेट बनाने के लिए ठेकेदारों को आमंत्रित किया लेकिन उनमें से एक भी गेट नहीं बना सका। एक गरीब ठेकेदार ने उस गेट को बनाया। उसको यह आश्वासन दिया गया कि आपको इसकी एक्स्ट्रा रेट देंगे और एक्स्ट्रा रेट देकर हम आपके साथ न्याय करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के अधिवेशन के पहले गेट बनकर तैयार हो गया लेकिन उस ठेकेदार का आज तक भी क्लेम पास नहीं हुआ है, वह ठेकेदार अपने क्लेम को पास कराने के लिए तीन-तीन साल तक भटकता फिर रहा है। यह बड़े शर्म की बात है, उपाध्यक्ष महोदय।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों के साथ अन्याय करते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : इस प्रकार से हमारे राजस्थान .....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : राजस्थान की जनता को दुःख होता है .....

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हुआ । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के रवैय्ये के जरिये मुझे अपना भाषण खत्म करने के लिए बाध्य करते हैं, यह आसन का......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानिया : मुझे समय मिला हुआ है !......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं आपकी आज्ञा मानकर यह कहना चाहूंगा, मेरी बात थोड़ी बहुत बाकी है, आसन चाहता है कि मैं यह बात नहीं बताऊं तो मैं मजबूर होकर प्रार्थना करना चाहूंगा कि इनका जो रवैय्या हैं, इनकी जो रिश्वतखोरी है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानिया : इसको मिटाने के लिये कोई विशेष काम होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ! थोड़ा नियमों का पालन करें । नियम भी महत्व रखते हैं इस सदन में ।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियमों का पालन करता हूँ और आसन का आदेश मानता हूँ...

श्री उपाध्यक्ष : आसन का आदेश मानते हैं यह सदन के सामने है ।

श्री लादूराम सुलानिया : इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है, मैं वैसे आसन के प्रति श्रद्धा रखता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी श्रद्धा रखता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ ।

श्री लादूराम सुलानिया : थोड़ा आप हमारा भी ध्यान रखें । इस प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा दो तीन मिनिट के अन्दर......

श्री उपाध्यक्ष : आप कल और ले लीजिये समय ।

श्री लादूराम सुलानिया : निर्माण विभाग पर कल नहीं बोल सकता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा नहीं लगता है, माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह दांता : आसन का आदेश ऐसे मान रहे हैं कि पंचों का कहना सिर माथे लेकिन पनाला यहीं गिरेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ! समय सीमा १५ मिनट ।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग और इससे सम्बन्धित मांगों पर मैं आज विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा, उसका कारण यह है

(श्री रामकिशन)

कि राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है उसके कारण और सरकार की योजनाओं के गलत परिणामों के फलस्वरूप जो कुछ सार्वजनिक निर्माण को करना चाहिए था, वह नवाब साहब कहिये या मेंसवाडा कहिये वह नहीं कर सकेंगे। आज स्थिति यह है कि उनकी कोई व्यक्तिगत सामर्थ्य का सवाल नहीं है, न व्यक्तिगत सामर्थ्य की अपेक्षा है क्योंकि राजस्थान को इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बीहड़ जंगल बना दिया है, इस बीहड़ जंगल मे कोई आशा लेकर चलें—यह सम्भव नहीं है क्योंकि जिस तरह की हालत राजस्थान में है और जो वित्तीय स्थिति है, उसको सुधारने के लिए जब तक सरकार बहुत बड़ा प्रयत्न नहीं करती तब तक नहीं कह सकते कि राजस्थान में सड़कें बननी चाहिए वे क्यों नहीं बनीं, तब तक यह नहीं कह सकते जो मरम्मत करने का लक्ष्य रखा गया था वह पूरा क्यों नहीं हुआ।

सबसे पहल मैं जो राजस्थान सरकार के बारे में सोचता हूं, राजस्थान के निर्माण की संभावनाओं, राजस्थान के विकास की संभावनाओ पर विचार करते हैं, उस समय हमने एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया था, राजस्थान का तैयार किया था नक्शा सड़कों के बारे में, जिसमें नहरों के बारे में, बिजली के बारे में। उसमें यह संभावना प्रकट की थी, हमारे राज्य में आवागमन के साधन हों क्योंकि जब उत्पादन होता है अनाज का, काटन का, दूसरी चीजों का तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए कितने साधन चाहिये। इसके लिए कितनी क्षमता राजस्थान में पैदा करनी है। इसके लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखें तो पता लगेगा ६१ से ७१ तक हमें राजस्थान की सड़कों की मद में ७१ करोड़ का नियोजन करना था जिसमें से २६ करोड़ केन्द्रीय सरकार को देना था और ४५ करोड़ की राज्य सरकार को व्यवस्था करनी थी। यह सारी व्यवस्था इस खयाल से की थी कि राजस्थान कैनाल बनने के बाद और चम्बल योजना पूरी होने के बाद हमारे राज्य में इतना उत्पादन बढ़ेगा, इतना मंडियों में जाएगा, इतना स्टेट में उपयोग किया जाएगा। तो नवाब साहब, मैं निवेदन करूंगा कि ७१ करोड़ के नियोजन का अनुमान लगाया था। अब सोचिये, ७१ करोड़ का नियोजन करना था १९७१ तक और अब ६८-६९ चल रहा है। तो आप के इन सालों में कितना नियोजन हुआ है। आप का कोई आधार है, आपका विकास का दिमाग है, आप का कोई कार्यक्रम है तो आपको अपने विभाग पर हावी होना चाहिए था। मुख्यमन्त्री महोदय से कहना चाहिए, आप ने जो सर्वेक्षण कराया और जिन सम्भावनाओं का उसमें जिक्र किया है उनको पूरा करना है। लेकिन राजस्थान में अकाल पड़ गये। पिछले दो साल तीन साल में, वैसे अकाल तब तक पड़ेगा जब तक कांग्रेस सरकार राजस्थान में रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब सरकार बदलेगी तो उसके बदलने के बाद अकाल खत्म होंगे उत्पादन बढ़ेगा। यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि गौरीजी से कह दिया कि सड़क देखेंगे तब उसको ठीक करवा देंगे। आप सड़क देखने लगे तो राजस्थान में ३० लाख किलोमीटर सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं।

(श्री रामकिशन)

जितनी सड़के हैं वास्तव में उनको मन्त्री जी और उपमन्त्री जी देख नहीं सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप का जवाब अनुचित है, आपका जवाब वाजिब था। मन्त्री को सजग होना चाहिए। मन्त्री सजग है लेकिन हर जगह कैसे जायेंगे। और जाकर गड्ढों को देखेंगे तब उनको आप ठीक करवायेंगे। राजस्थान की सारी सड़कों की यात्रा पूरी आप से नहीं होगी। विनोबा जी ने आज से १२ साल पहले अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी। लेकिन वह ७० हजार किलोमीटर चल पाये हैं तो आप कब तक पहुंच जायेंगे। आप मन्त्री हैं फिर भी पुराने नवाब, कहीं किसी ने समझा दिया कि कार में जाने से गड्ढे नहीं देखे जा सकते और कहीं आप ने पैदल चलना शुरू कर दिया तो कैसे कल्याण होगा। होगा ऐसे-आशा रखें, विश्वास रखें और जो आवश्यक राजमार्ग हैं, आवश्यक जिला मार्ग हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करें। उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि राजस्थान में योजनाओं का प्रावधान हर साल बढ़ता गया। पहली पंचवर्षीय योजना में ५४ करोड़ रुपया रखा गया। दूसरी में एक अरब रखा गया और दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में २ अरब १२ करोड़ रुपया रखा गया है लेकिन पी० डब्ल्यू०डी० की सड़कों की हालत का सवाल है, सड़कों के निर्माण का सवाल है, अब योजना की रकम तो दुगनी हो गई। महंगाई का हिसाब लगाकर निर्माण की रकम दुगनी हो जानी चाहिए। यह मेरा हिसाब है।लेकिन हुआ क्या? उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, प्रशासन व्यय बढ़ता गया है। एक इंजीनियर की जगह १५ इंजीनियर बना दिये गये हैं। बना कैसे दिये गये? किस योजना के आधार पर बना दिये गये? किसी मन्त्री का लड़का हुआ, रिश्तेदार हुआ, उसके लिए जगह करनी पड़ेगी। इस तरह सड़क तो बनी नहीं लेकिन विभाग का खर्चा डबल हो गया। हम देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में...

श्री शंकरलाल : किस मन्त्री का लड़का? उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वेग चार्ज हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत आरोप है। झूंट बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी मन्त्री का लड़का नहीं है। यह गलत आरोप है।

श्री शंकरलाल : वेग चार्ज नहीं होने चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : ये नाम लिवाने में दिलचस्पी रखते हैं।

श्री रामकिशन : ये सारी बातें कहने की, किसने किस-किस तरीके से कैसे क्या किया ,किस तरीके से होता है, मेरी आदत नहीं है।

श्री शंकरलाल : आप नाम कहें तो पता लगे।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेसियों की अनियंत्रित भीड़ है। इसको रोका करिये। न तो यह मर्यादा रखते हैं, न तथ्यों की जानकारी रखते हैं, न नियमों का खयाल करते हैं। बीच बीच में बोलते हैं।

Page No. 129

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, गलत बात रखी गई है ।

श्री रामकिशन : पहली पंचवर्षीय योजना के समय में राजस्थान में सड़कों की लम्बाई थी १८३०० किलोमीटर । दूसरी योजना में व्यय बढ़ता गया लेकिन दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम ३१०६६ और ३०५८६ किलोमीटर सड़क बना पाये । उसका नतीजा क्या हुआ । सड़कों का प्रावधान किया गया योजना में वह सड़कें तो तैयार नहीं की गईं दूसरी जो गैर जरूरी चीजें थी उनका खर्चा करते गये । ट्रांसपोर्ट के साधन विकसित करने चाहिये थे । वह नहीं कर पाये । एक चीज और देखेंगे । इस सरकार को देखना चाहिए कि हर विभाग में एक योजना के बाद दूसरी योजना में प्रगति कुछ न कुछ हुई है या नहीं । लेकिन राजस्थान में मेरे ख्याल से, उलटी स्थिति नजर आती है, योजना के हिसाब से बात करें तो सारे हिन्दुस्तान की सड़कों और खर्चे के सम्बन्ध में विचार नहीं करेंगे । पहली पंचवर्षीय योजना में ४२१२ किलोमीटर सड़क बनी । दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४१८२ किलोमीटर रह गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३८९३ किलोमीटर का निर्माण हो सका । नतीजा क्या हुआ । व्यय तो बढ़ गया लेकिन वह प्रशासनिक व्यय है । चीफ इंजीनियर फिर उनके नीचे सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर का व्यय पांच गुना, सात गुना, बढ़ता चला जा रहा है । इस तरह जो पैसा खर्च होना चाहिए सड़क निर्माण पर, सड़कों के सुधारने पर, वह प्रशासनिक व्यय में खर्च होता गया । उसका नतीजा यह हुआ है कि आज राजस्थान के और जिलों की बात नहीं कहता हूं भरतपुर जिले की मिसाल देना चाहता हूं जब राजस्थान का निर्माण हुआ भरतपुर जिले में नागपुर योजना के टारगेट पूरे हो चुके थे । जो नागपुर ने हिन्दुस्तान के टेक्निशियनों ने टारगेट जनसंख्या के हिसाब से माइलेज रखा था वह पूरा हो चुका था । आज केवल दो जिले ऐसे हैं, झालावाड़-अजमेर, अजमेर और भरतपुर दूसरी तरह की स्टेट थीं । झालावाड़ इसलिए कि स्वर्गीय महाराज, झालावाड़ पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर हो गये, इसलिए उन्होंने ध्यान दे लिया । अन्यथा जो लक्ष्य पूरा करना था उसको पूरा नहीं कर पाये हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस मामले पर दुबारा विचार करे । क्योंकि हमारी क्षमता है, राजस्थान का दुर्भाग्य है कि अकाल से हमें जब छुटकारा मिलेगा जब उत्पादन बढ़ेगा, तब हम उसे मंडी में कैसे ला पायेंगे । इस बात का हमें विचार करना होगा । उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना है । आज राजस्थान में हमें सड़कें बनाने की आवश्यकता है । लेकिन भवनों की जरूरत नहीं है । अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, वह कह रहे थे कि सांचौर में आफिसर्स के ठहरने के लिए दो कमरे बना दिये जायें । उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी कोई मुल्क बनता है, किसी देश का निर्माण होता है तो अफसरों के लिए डाक बंगले नहीं बनाये जाते हैं । वहां के लिए फर्नीचर नहीं खरीदा जाता है । मुल्क के निर्माण के समय दूसरी कार्यवाही होती है । राजस्थान राज्य है, जहां इतने मकान बने हुए हैं, भूतपूर्व नरेशों के मकान खाली पड़े हुए हैं । तो इसके लिए एक नया पैसा भी खर्च न करें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां कोई मकान नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : नहीं पड़े हैं, कहां पड़े हैं ?

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि १० साल तक जब तक राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक न हो, अधिक से अधिक सिंचित क्षेत्र न हों गांव—गांव में बिजली नहीं आजाये, तब तक राजस्थान सरकार यह फैसला करले कि प्रशासनिक कामों के लिए कोई मकान नहीं बनवायेंगे । कोई जरूरत नहीं है । राजस्थान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां भू० पू० नरेशों के मकान नहीं हों । अगर आपको अस्पताल के लिए मकान की आवश्यकता हो तो मैं मान सकता हूं । उसकी मंजूरी दे सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, सेक्रेटेरियट में प्रशासनिक भवन बना रहे हैं, उसका प्रावधान किया गया है । क्या जरूरत है । लेकिन मुख्यमन्त्री ने अपनी कुर्सी रखने के लिए ३५ मिनिस्टरों की भीड़ इकट्ठी करली हैं । इनके लिए कोई अलग कमरों की जरूरत नहीं है । क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है । इन सबको एक बाड़े में बन्द कर दो । लोगों के पास कोई काम ही नहीं है । भेंसवाड़ा साहब खुद कह रहे थे .....

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : मैंने नहीं कहा है ।

श्री रामकिशन : वह कह रहे थे.....

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : मैंने नहीं कहा । मेरे पास बहुत काम है ।

श्री रामकिशन : क्या कह रहे थे सुनो तो सही । हमारे पास कोई काम नहीं । उपमन्त्री कहते हैं हमारे पास......

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : मेरे पास काम है, बहुत काम है ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, कोई काम नहीं है । तो मुख्यमन्त्री ने कुर्सी को सलामत रखने के लिए इनको शामिल कर रखा है । मैं एक सुझाव देता हूं कि अलवर—धौलपुर के बीच में एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग पड़ी है, नवाबों का बनवाया हुआ महल है । धौलपुर से थोड़ी दूर । बहुत ही बढ़िया जगह है । इन सारे मन्त्रियों को वहां बन्द कर दिया जाये । और, जब जरूरत पड़े तब मुखाड़िया जी बुला लें । यहां कोई इनको काम नहीं हैं । अगर काम होता उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : उसी में आप को बन्द कर रखा था ?

श्री रामकिशन : बन्द करने का मतलब जेल नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्हें छोड़ दीजिए, ये तो खुद ही भेंस—वाड़ा हैं ।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन कर रहा था कि इन चीजों में पैसा खर्च नहीं किया जाये । अब देखते हैं कि दो करोड़ इक्कीस लाख का भवनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है । राजस्थान में एक ओर पानी की कमी है, पीने का पानी नहीं मिलता है । मुल्क की सड़कों से इसे जोड़ा नहीं, भरतपुर के अस्पतालों में मरीजों को दवाई नहीं मिलती हैं ।

(श्री रामकिशन)

मेरी खुद की समझ में नहीं आता कि २ करोड़ २१ लाख का प्रवधान क्यों किया, शिक्षण संस्थाओं के लिये २०–२५ लाख रखें, प्राथमिक शालाएं बनें तो समझ में आ सकता है। पर राजस्थान सरकार यूनिवर्सिटी के लिये पैसे दे देती है। यहां का वाइस चान्सलर समझता है कि यहां की यूनिवर्सिटी में चार पांच लाख रुपये की लागत का एक सुन्दर होद बने, स्नानागर बने, उसके लिये देती है।

जिन्होंने रूसी क्रान्ति का इतिहास पढ़ा होगा, मैं कोई रूस का समर्थक नहीं, कम्युनिस्टों की थ्योरी का तो समर्थक हो ही नहीं सकता, पर रूस का किस तरह से निर्माण किया गया, यह बताना चाहता हूँ। वहां पहली सात साला योजना में और दूसरी सात साला योजना में, इन दो सात सात साला योजनाओं तक तो उन्होंने यही कहा कि कोई भवन नहीं बनायेंगे, प्रशासनिक कार्यों के लिये भवनों की अभी हमें पहले जरूरत नहीं, छप्पर के नीचे कर सकते हैं, वहां उन्होंने जो निर्माण के लिये देश की आर्थिक स्थिति से सुरक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक काम थे, उन कामों को पहले किया।

हमने लक्ष्य रखा था कि जहां खाने हैं, वहां तक यातायात की सुविधा के लिये सड़कें बना देंगे, पर आज हम देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में खानें हैं, वहां कोई सड़कें नहीं हैं। खानों का सबसे बड़ा क्षेत्र है धौलपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। सार्वजनिक निर्माण मंत्री इन क्षेत्रों में चले जायें और देखें कि रोयल्टी का कितना पैसा लेते हैं, वहां रोड टैक्स कितना मिलता है, जितना वहां ले रहे हैं, वह देखने के बाद चाहे आप कितने ही मुलायम हों, आपका सिर शर्म से झुक जायगा, उन सड़कों पर गाड़ी जा नहीं सकती, एक जीप नहीं निकल सकती। तृतीय पंच वर्षीय योजना में लक्ष्य रखा था सड़कें खानों तक पहुंचाने का, पर तृतीय पंच वर्षीय योजना समाप्त हो गई और खानों तक सड़कें नहीं पहुंचीं।

इस सम्बन्ध में दो तीन सुझाव देना चाहूंगा। जहां जहां खनिज क्षेत्र हैं, वहां वहां सड़कों को प्राथमिकता दें, जो क्षेत्र डाकुओं से पीड़ित हैं, जिन क्षेत्रों में डाकुओं द्वारा इन्सानों को कत्ल किया जाता है, आप एक मनुष्य की कीमत कम मत आंकिये, एक मनुष्य की कीमत बहुत है, सड़कों के आवागमन के अभाव की वजह से उन क्षेत्रों में डाकुओं का राज्य है, डाकू उन क्षेत्रों में पंचायतें करते हैं और लोगों को खुल्लमखुल्ला कहते हैं कि यहां हमारा राज है, वहां सुखाड़ियाजी का राज नहीं डाकू कहते हैं, यहां हमारा राज्य है, वहां पर आपकी पुलिस पहुंच नहीं सकती, जैसी आपकी पुलिस है, उस पर मैं नहीं कहना चाहता, आप खुद जानते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के लिये सड़कें बनाइये। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो डाकू पीड़ित क्षेत्र हैं वहां सड़कें बनाइये, चाहे वे भीलवाड़ा में हों, चाहे बांसवाड़ा में हों, चाहे कोटा में हों।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई और बाढ़ के बाद थोड़ा पैसा दिया, बाढ़ आई

(श्री रामकिशन)

इनकी गलती से फिर भी धन्यवाद दे दूं कि पैसा दिया। आज की तारीख तक ११ लाख रुपया वहां दिया गया और वहां के इंजीनियरों को लिखा कि बाढ़ पीडित क्षेत्रों में इन्तजाम करो और सड़कें बनाओ पर जो पैसा दिया है वह बाढ़ पीडित क्षेत्रों की सडकों पर नहीं राजनैतिक क्षेत्रों की सड़कों पर लग रहा है।

यहां कमीशन की बात होती है, पी० डब्लू० डी० में कमीशन है, यह निश्चित बात है। आप नहीं मानेंगे तो भी है, उसे न तो आप रोक सकते हैं न मैं रोक सकता हूं न और कोई। इसके लिए मैं कहूँगा कि निर्माण मन्त्रीजी आप एक परिपत्र निकाल दो कि कमीशन की नई दर मत बढाओ, जो है वही रखो, २० परसेंट ही रखो, वे अगर कहें कि नहीं साहब महंगाई भी तो बढी है इसलिए कमीशन की दर भी बढनी ही चाहिए तो आप उनसे कहना कि नियोजन भी तो बढ़ा है। मैं बताऊं आपको कि कुम्हेर वाली सड़क टूटी हुई पड़ी है, ६-६ फीट पानी उस पर पड़ा है। मैंने पूछा कि इस सड़क को क्यों नहीं बनाते तो ठेकेदार ने कहा कि कमीशन की जो बढ़ी हुई रेट मांगते हैं उतनी हम नहीं दे सकते। अब नवाब साहब से कहें कि उनकी कमीशन की रेट बढ़ा दो। अभी हम नवाब साहब के घर पर कुछ ईंटें रख कर आये हैं, क्योंकि सदन में तो ईंटें ला नहीं सकते, लाते तो कहीं झगड़ा खड़ा हो जाता। ईंटों की जीप आई है, नेशनल हाई वे में ईंटें लगा रहे हैं और कच्ची ईंटें लगा रहे हैं। हमने कहा था कि अच्छा इन्जीनियर भेजो तो आपने कहा था कि आपके भरतपुर का अच्छा इंजीनियर भेज देंगे। आपके पैसे में घपला नहीं हो जाय, इसीलिये ईंटें आपके यहां रखी हैं। अब आप जायेंगे तो रद्दोबदल कर देंगे।

हमारे यहां बड़ी अजीब स्थिति है...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कितना समय था ?

श्री उपाध्यक्ष : १५ मिनट। आज समय कम था, उसी अनुपात में हर दल का समय कम हो गया, संसोपा का १५ से २० मिनिट तक है।

श्री रामकिशन : हमारे क्षेत्र की बात रख देता हूँ। आज सीमावर्ती सड़कों पर, खरीद फरोक्त पर नहीं बोलूंगा।

आज भरतपुर की बड़ी अजीब स्थिति है, ठेकेदार काम करने जाता है पर एक इन्जीनियर ने सड़क पर लट्ठे गाड़ दिये और कहा कि यह सड़क मेरे पीछे होकर जाती है और मेरे बच्चों पर धूल पड़ती है। इन्जीनियर कहता है कि लट्ठों को उखाड़ नहीं सकते। मैं इंजीनियर को सजा देने को नहीं कहता पर कम से कम उन लट्ठों को तो निर्माण मंत्रीजी उखड़वा दें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे बहुत से मामले रखने थे और हट्स के बारे में कहना था। अन्त में मैं दोनों, मंत्री और उपमंत्री से निवे-दन करूंगा कि यह टेक्निकल मामला है, मैं तो टेक्निकल नहीं हूँ, मैं भी आपकी

(श्री रामकिशन)

ही तरह ना समझ हूँ, आपको शायद इसमें कुछ समझ हो सकती है पर मैं तो नासमझ हूँ, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपको जो रकम दी जा रही है वह बहुत कम है, कमी का कारण बता दूं कि कमजोर मंत्री हैं, यह समझकर कम देते हैं, सुखाड़ियाजी को जो धमकी देता है उसका काम करते हैं, इसलिए आप धमकी देना सीखो। एक तो बना दिया नवाब साहब को और दूसरा ठाकुर साहब को, दोनों लड़ते रहते हैं, मिलकर रहो......

श्री माधोसिंह : हम कभी नहीं लड़ते, आप गलत कहते हैं।

श्री रामकिशन : और धमकी देकर अपनी ग्रान्ट बढ़ाओ। फिर भी अगर नहीं दे तो सड़कों की हालत सुधरने वाली नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज थोड़ा समय बढ़ाया जाय।

एक माननीय सदस्य : फिर हमको भी देना पड़ेगा।

श्री रामकिशन : फिर तो अधूरे भाषण तो कम से कम पूरे कराये जायं।

श्री रणजीतसिंह (श्रोसियां) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान की उस भूमि की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहां बिलकुल रेतीला इलाका है, दूसरे कोई साधन नहीं हैं और किसी प्रकार का साधन नहीं होने के कारण वह इलाका पिछड़ा रह गया है और भविष्य में भी अगर यही स्थिति रही तो पिछड़ा ही रहेगा। मेरा निवेदन है कि जो इलाका पिछड़ गया, वहां यदि कोई काम नहीं होगा, यातायात के साधन नहीं बनेंगे तो वह इलाका किसी तरह आगे नहीं बढ़ सकेगा। जो इलाके आगे बढ़ गये हैं, वे तो पहले से ही आगे हैं, वहीं पर आप और काम करायेंगे तो वे और भी आगे बढ़ेंगे और जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां पर कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पर अगर आप यातायात के साधन नहीं बनायेंगे, उन पिछड़े हुए इलाकों को आगे बढ़ाने के लिये किसी प्रकार के काम वहां नहीं चलायेंगे तो वे पिछड़े के पिछड़े ही रह जायेंगे। तो मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। राजस्थान का पवित्र स्थान हिस्टोरिकल जगह है वह है ओसियां, ओसियां एक ऐसी जगह है जो गुप्त काल से पहले ही आदरणीय स्थान था। पर कुछ कारणों से वह उजड़ गया। उसमें पता नहीं पुराने ग्रंथों के हिसाब से किसकी गलती थी पर आज भी वह बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह है। जिसको देखने के लिए बाहर के टूरिस्ट्स आते हैं पर उस इलाके तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि वहां यातायात का, सड़कों का साधन नहीं है। जब जोधपुर स्टेट थी, उस वक्त वहां एक कच्ची सी सड़क बनी थी, जो आज से ३०-३५ साल पहले बनी थी, वह वैसी ही है। पहली पंचवर्षीय योजना चली गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना चली गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना भी चली गई और आज हम चौथी पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं, पर उस इलाके की तरफ सरकार का ध्यान कभी गया ही

(श्री रणजीतसिंह)

नहीं। इसलिये वह इलाका जैसा पहले था वैसा ही रह गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना यह है कि उस हिस्टोरिकल इलाके की तरफ भी थोड़ा ध्यान देकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें, वहां सड़क बना दी जाय ताकि वहां पर्यटक आ जा सकें।

टूरिस्ट्स जायेंगे तो उस जगह का एक महत्व बन जायेगा, कागजों में जरूर उसका महत्व है। ज्योंही टूरिस्ट्स जोधपुर पहुंचते हैं वहां से किसी गाड़ी को ओसियां चलने के लिये कहते हैं तो सड़क की हालत से लोग जाने को तैयार नहीं होते। अगर आपके पास पैसा है तब तो आप उसको पूरा करवा दीजिये। जो डिफेन्स-रोड्स थीं जो बन रही थीं जोधपुर ओसियां और पाली के लिये उसको डिफेन्स वाले बहुत काम में ले रहे हैं। उनको ट्रेनिंग लेनी होती है तो भी उसी सड़क के ऊपर से गुजरते हैं जो थोड़ी-बहुत वह कच्ची बनी हुई थी वह बिल्कुल बरबाद हो रही है। अगर सरकार के पास पैसा कम है तो उसको डिफेन्स रोड मान लिया जाये तो इसमें माइलेज भी कम पड़ेगा और मिलिटरी को साधन उपलब्ध हो जायेगा। अगर इसके लिये सरकार के पास पैसा नहीं है तो जितने भी निर्माण विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं उन पर जितना पैसा खर्च होता है उसमें कटौती कर दी जाय ताकि वह पैसा तो बचे। बजट में पैसा रखते हैं लेकिन मरम्मत के नाम पर खर्च होता नहीं। जितने भी ओवरसियर्स और इंजीनियर्स हैं उनका इस रोड़ के नाम से जो खर्च होता है वे केवल टी. ए. डी. ए. बनाने में रहते हैं यह इस रोड के लिये फिजूल पैसा लग रहा है। डामर नहीं करने के कारण यह भी है कि वे चाहते हैं कि ग्रेवल रोड ही रहे ताकि ग्रेवल के नाम से उनको पैसा मिलता रहे। कभी-कभी ठेकेदार द्वारा ग्रेवल पड़ा हुआ मिलता है जो तीन-तीन साल पड़ा रहता है लेकिन कोई काम वह नहीं आता। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य कर्मचारी जो इस रोड के लिये हैं उनके पदों को खत्म किया जाय ताकि पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो।

अभी-अभी मूलचन्दजी डागा फरमा रहे थे इस विभाग में जितने भी राज्य कर्मचारी लगे हुए हैं डिवीजन सबडिवीजन सब के हैड क्वार्टर जोधपुर में लगे रहते हैं। कोई भी आदमी समय पर इलाके में जाकर काम नहीं संभालते। केवल टूर करने के नाम पर टी. ए., डी.ए.बनाने में लगे हुए हैं। जोधपुर का तो वहां रहे लेकिन पाली और नागौर का भी वहां रख रखा है इनके ऊपर वाहियात खर्चा क्यों हो रहा है। आखिर यह सरकार के देखने की बात है जैसा वह चाहेगी वैसा होगा।

आप अगर इन रोड्स पर पैसा नहीं लगा सकते तो कम से कम इसके लिए सरकारी मशीनरी है उसको तो कम कर दिया जाय। जितने विहिकल्स हैं जो खाली घूमते रहते हैं साग सब्जियों के लिए चलती है उनको तो ले लिया जाय।इससे भी काफी राहत मिल सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि ओसियां की तरफ एक ही कच्ची सड़क है उसको पक्की कर दी जाय। फेमीन

(श्री रणजीतसिंह)

के दिनों में जो रोड्स बनी थी आज उसको रिपेयर करने की भी व्यवस्था नहीं है । पी० डबल्यू० डी० उसको लेते नहीं वे कहते हैं कि रेवेन्यू वाले करायेंगे इस तरह से इनका मालिक कोई नहीं रह गया । इन सड़कों पर १.४ पैसा लगने से ही ये पूरी हो सकती है । नहीं तो यह होगा कि डेजर्ट इलाके में जो ग्रेवल लगा हुआ है वह निकल जायगा सारा मार्ग बेकार हो गया इसलिए इस काम को महत्व दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दालिया ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : (नोखा-सु) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव बीकानेर जिले की सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में है ।

उपाध्यक्ष महोदद, मैं सरकार का ध्यान बीकानेर जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं बीकानेर जिला सीमावर्ती जिला है इसके पड़ौस में पश्चिमी पाकिस्तान पड़ता है लेकिन यहां की सड़कों का बड़ा बुरा हाल है । इन सड़कों पर कमर कमर तक गड्ढे पड़े हुए है नेशनल हाई वे रोड की दशा भी बहुत खराब है जो इतनी महत्व की रोड है इसको भी राज्य सरकार पूरा नहीं करवा सकी । नेशनल हाई वे रोड बीकानेर-डूंगरगढ़-देहली जाती है जो महत्वपूर्ण रोड है इस रोड की चिंता राज्य सरकार को होनी चाहिए लेकिन वह पूरा नहीं कर सकी यह बड़े शर्म की बात है ।

मैं मेंसवाड़ा के उप मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बीकानेर से अनूपगढ़ और सूरतगढ़ जाने वाली जो सड़क है यह सीमा सड़क है इस सीमा सड़क को भी सरकार आज तक पूरी करने में असफल रही है इस तरह से जो बीकानेर जिले के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया चला आ रहा है इसको बीकानेर की जनता और राजस्थान की जनता बरदाश्त नहीं करेगी । अगर इसी तरह इस इलाके की जनता के साथ व्यवहार किया गया तो ज्यादा दिन तक इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है ।

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं बीकानेर जिले में पी० डबल्यू० डी० विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराये गये हैं उसमें कोई भी काम पूरा नहीं कराया गया ये मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं । जितने भी काम पन्द्रह बीस सालों में करवाये हैं वे सारे के सारे कार्य अधूरे पड़े हैं वे आजतक पूरे नहीं हो सके । अतः मेरा यह निवेदन है कि जो इस प्रकार से अधूरे काम रह गए है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करदें ।

चौथा मेरा यह निवेदन है कि एक जिले से दूसरे जिले को मिलाने के लिए भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है । बीकानेर से गंगानर इस जिले को भी सड़क से जोड़ नहीं सके । गंगानगर बीकानेर जिले का ऐसा सीमावर्ती जिला है, जो बहुत उपज देता है अगर यहां से बीकानेर तक सड़क बना दी जाय तो गंगानगर से खाद्य सामग्री बीकानेर, नागौर जयपुर तक सुविधा जनक रीति से पहुंचाया जा सकता है ।

(४ म. प.)

परंतु यह सरकार महत्वपूर्ण सड़कों को बनवाने में असफल रही है । मैं नहीं कहता, राजस्थान का इतिहास कहता है, बोर्डर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

के जितने जिले हैं तमाम जिलों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। छठा आइटेम है कि नोखा तहसील से डूंगरगढ़ तहसील, एक तहसील के हेडक्वार्टर को दूसरी तहसील के हेडक्वार्टर से जोड़ने में असफल रही है। उनकी नीति में सौतेला व्यवहार रहा है, पक्षपातपूर्ण नीति है। अगर सीमा के जितने जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जो हमारे पाकिस्तान के पास पड़नेवाले हैं, हमारे देश के जो जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, आज तक कोई सड़क का काम नहीं हुआ। बार्डर रोड्स को आज तक सरकार पूरा कराने में असफल रही है। इसकी नीति से साफ जाहिर होता है कि देश से गद्दारी कर रहे हैं और देश की जनता के साथ और मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं नहीं कहता यह आपके आंकड़े कहते हैं।

सातवां है नोखा से कोलायत की सड़क। कोलायत राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। कोलायत तक आज तक नोखा से सड़क नहीं जुड़ी। पंचायत समिति और जिला परिषदों की बारबार रिपोर्ट के बावजूद भी इस सड़क की ओर आजतक ध्यान नहीं दिया। मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है भैंसवाड़ा साहब तो नींद में हैं लेकिन लोहारू साहब को अच्छा आदमी मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : ये लोहारू साहब और भैंसवाड़ा साहब कौनसी बला आ गई सदन में ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बीकानेर से जयपुर जो सड़क है उस पर नापासर से जेतासर तक के रूट पूरा किया जाय तो करीब ३० मील की रोड अच्छी हो जाती है और समय की बचत होगी। लूणकरणसर से विजयनगर की सड़क के लिए मुझे निवेदन करना है कि विजयनगर बहुत ही बड़ी मंडी है जिसको हर तरह से अच्छी माना जाता है। वहां गेहूं वगैरह खाद्य सामाग्री ले जाने पड़ते हैं लेकिन अंधी सरकार आज तक उसको देख नहीं सकी।

श्री अमीनुद्दीन : हाई हाई।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बीकानेर से जयपुर की जो सड़क है बिल्कुल छोटी है। संकड़ी है इसको चौड़ी कराया जाय जिससे आने जाने में बसों को सुविधा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : चेतावनी की घंटी सुनी है ?

श्री चुनीलाल इन्दलिया : अभी मेरा समय है। जो बोर्डर पर रहने वाले लोग हैं, उनको आशा थी कि देश के स्वतंत्र होने के बाद ये सड़कें पूरी होंगी लेकिन अब हम निराश हो गए हैं, यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है। इस सरकार में जनता का विश्वास नहीं रहा। इसलिए आप समय पर संभल जाइए नहीं तो आपके साथ वही होगा जो इतिहास में हुआ है। मैं मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि आप किस होश में सो रहे हो। ये लोग मजाक और मखौल समझते हैं। अगर ये नहीं चेते तो जैसे राजाओं और अंग्रेजों की व्यवस्था थी इन लोगों की भी वही हालत होने वाली है। इसलिए मैं दोनों मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समय रहते ही चेतें, देश की जनता करवट लेना चाहती है और आपसे अगर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

यह काम नहीं संभला तो देश की जनता और हम सब माफी देने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको समय पर चेतना चाहिए जो निर्माण कार्य अधूरे हैं उनको जल्दी पूरा करायें, वर्ना आपको जनता माफ करने वाली नहीं हैं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल): हमारे क्षेत्र को उपमंत्री तो जानते ही हैं। उपमंत्री बनने के बाद कई बार वहां पहुंचे हैं लेकिन आगे न जाकर जालोर से लेकर बाड़मेर तक १०० मील और भीनमाल से लेकर बालोतरा तक करीब ५० मील बीच में कोई भी सड़क का टुकड़ा हो तो राज्य सरकार बताए। कुछ मीलों में निर्माण किया है और वह भी इस टूटी हालत मे है कि शायद उस पर बस न चलकर साइड में गाड़ियाँ चलती हैं। पूरी की पूरी सड़क बोर्डर में मिल जाती है। अभी जैसे हमारे वित्तमंत्री ने एवरेज लिया था, एवरेज १०० मील के १४ मील कर दिया वह तो ऐसे एवरेज हुआ जैसे एक आदमी तीन बच्चों को लेकर नदी के किनारे पहुँचा और पानी देखा घुटने के नीचे है और तीनों डूब मरे, मुझे डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं है। उस दृष्टि से उदय-पुर और जालोर के एवरेज को लें, जालोर को देखेंगे तो १४ मील होता है या नहीं। सड़क निर्माण कार्य मेरे खयाल से योजनाबद्ध नहीं है। योजना से सरकार ने छुट्टी ले रखी है। मैने राज्य सरकार से प्रश्न किया था कि जो २० साल की योजना सरकार ने बनाई थी उसमें जालोर जिले में कौनसी योजनायें हैं तो जवाब मिला, इस योजना पर प्रस्ताव किया था, अभी वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है और इसके लिए आगे के सवालों में कोई प्रश्न नहीं उठता। तो मेरे खयाल से २० साल की योजना नाम की थी और योजनाबद्ध कार्य सड़कों पर नहीं हो रहा है।

जालोर से गुढा तक सड़क है। यहां निर्माण कार्य कराया है। यहां पर एक गोले में आयुर्वेद का अस्पताल है और पशु चिकित्सालय, उसमें आगे सामला में पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, पुलिस स्टेशन है, प्राइमरी हैल्थ सेंटर है, लेकिन दवाइयों के लिए आना चाहें तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि आने जाने की सुविधा नहीं है। पंचायत समिति का हेडक्वार्टर है जो तार, फोन और सड़क से मिला हुआ नहीं है। आगे आप जानते हैं इतना फरटाइल एरिया-है नजर आएगा जिसमें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने भी माना है और ट्यूब वेल प्रोजेक्ट बनाने का विचार रखती है। हमने अंडर ग्राऊंड वाटर बोर्ड से लिखा पढ़ी की उन्होंने कहा मशीनरी नहीं पहुंच सकती.

श्री माधोसिंह: तिलाड़ा भूल गए।

श्री आईदानसिंह: १५० कुओं पर ६० इन्जन लगे, हम टैक्स देते हैं तो हमारे हिस्से में भी कुछ आना चाहिए।

श्री माधोसिंह: आप नाम लेना भूल गए, इसलिए मैंने याद दिलाया।

श्री आईदान सिंह : तिलाड़ा, हरमू में ६० इंजन लगे वहां मार्च से जून तक कम पैदावार होती है बाद में हजारों मन ज्वार पैदा करते हैं, सड़क के अभाव में करीब ५ रुपए बोरी खर्च करके ले जाते हैं और २० रुपया फी ड्रम का देकर तेल लाना पड़ता है।

तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम प्रावधान तो रखा हुआ है पिछले साल था। पर पैसा लगा नहीं। अब इतना ही निवेदन करूंगा कि इस सड़क को हाथ में लेकर पूरा करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) उपाध्यक्ष

श्री कल्याणमल : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: फिर आप दोनों साथ ही बोल लीजिये। कांग्रेस के ही हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मांग संख्या २७ पर मैंने ६ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं।

बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर समवर्ती जिले हैं और सामरिक दृष्टि से इनका विशेष महत्व है। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तभी भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों को यह महसूस हो जाना चाहिये था क्योंकि पाकिस्तान के सम्बन्ध अच्छे कभी नहीं रहे और इस दृष्टि से इस क्षेत्र का विशेष तौर से विकास करना था। पर सन् ६६ तक वहां सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन जिलों में इस बीच जो भी सड़कों का काम हुआ वह नगण्य सा है। सबसे कम माइलेज सड़कों का इस क्षेत्र में बमुकाबले अन्य जिलों के निर्माण हुआ।

बाड़मेर में प्रति सौ वर्ग किलोमीटर पर ४.८० किलो मीटर, जैसलमेर में २.३० किलो मीटर, और बीकानेर में ३.८३ किलो मीटर। दूसरे जितने भी जिले हैं उनमें इन तीन जिलों से अधिक ही बनी हैं।

तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सीमावर्ती और सामरिक महत्व का समझ कर भी ध्यान नहीं दिया। ये तो पक्षपात का दृष्टिकोण अपनाते हैं। जो अविकसित है वह अविकसित ही रहे, और जो विकसित है वह और विकसित किया जाय यह इन के दिमाग में बात रहती है। इस में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पर जब पाकिस्तान का हमला हुआ तब राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की आंखें खुलीं।

इसके बाद में वहां सड़कों के निर्माण का कुछ कार्य आरम्भ हुआ। पर इसे दो सालों से भी अधिक हो गया अभी तक जो सड़कें भी हाथ में ली गईं वे भी पूरा नहीं हो पाई हैं। यह हाल है। फण्ड्स केन्द्रीय सरकार से नहीं मिलने के कारण काम रुक गया। पर जो पाकिस्तान के युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण सड़कों की आवश्यकता समझी गई उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। गडरा से मुनाबा सड़क पर दो तीन महिने पहले ही कार्य शुरु हुआ है और जिस रफ्तार से वह चल रहा है, उसकी उस रफ्तार को देखते हुए उसमें भी अभी १२ महिने का समय लग सकता है। इसी मुनाबा

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

क्षेत्र में हमारी पाकिस्तान से सड़क नहीं होने से बुरी तरह हार हुई थी। अभी ग्रेवल तक भी नहीं हुई है। डामर का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसे तुरन्त और तत्परता के साथ पूरा किया जाय।

दूसरी सड़क है बाड़मेर से छोटीमना। यह भी महत्वपूर्ण सड़क है पर इसका कार्य भी गतिशील नहीं है।

बाड़मेर से जैसलमेर–इसका काम भी गति पर नहीं है। इनकी आज की प्रगति देखते हुए एक साल से पहले पूरी होने की सम्भावना नहीं है। इन सड़कों के निर्माण में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिये। मन्त्री महोदय वहां पधारे थे, मैं उनके साथ चला। उन्होंने वहां काम करने वाले इन्जीनियरों को इन्स्ट्रक्शन दिये। सुपरिन्टेण्डेन्ट इन्जीनियर का आफिस जोधपुर से बाड़मेर में लाने का आदेश दिया हालांकि वह जोधपुर में ही रहना चाहता था। असिस्टेन्ट इन्जीनियरों के आफिस गडरा, छोटीमना और शिव में स्थापित करने के भी आदेश दिये। आर्न दी स्पाट आदेश दिये। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गडरा छोटीमना, शिव में इन्स्ट्रक्शन्स दिये असिस्टेन्ट इन्जीनियर इनका पालन नहीं कर रहे हैं। इस काम को तो युद्धस्तर पर करना चाहिए और पूरी सख्ती के साथ करना चाहिए; पर यह अफसर लापरवाह हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करते। यहां तक कि उनके बड़े से बड़े आफिसर चीफ इन्जीनियर विशेष तौर से बी आर माथुर दो साल हुए इन कामों का इन्सपेक्शन करने खुद कभी बोर्डर पर नहीं गये। जब कि एक चीफ इन्जीनियर को इतने महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों पर खुद कई बार जाकर खड़े रहकर देखने की जरूरत थी। इतना बड़ा अधिकारी लापरवाह रहे और इधर ध्यान न दे तो यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसको अच्छी स्थिति नहीं कह सकता।

सड़कों के बारे में जो ली जा रही हैं वे अपर्याप्त हैं, मैं तो यह कहना चाहता हूं सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा देना चाहिये जो सामरिक दृष्टि से भी अत्यन्त आवश्यक हैं।

एक बाड़मेर से लेकर चोहटन तक सड़क है। फिर चोहटन से लेकर बाकासर तक की सड़क का क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है। पर यहां पर अभी तक ग्रेवल रोड भी नहीं बन पाई है। इस रोड को डिफेन्स रोड में शामिल करें महत्वपूर्ण समझ कर।

दूसरी स्थिति सामने आती है जोधपुर से बाड़मेर टोड की

(४. १५ म. प.)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल सभापति, पदासीन)

जोधपुर बाड़मेर के बीच बाढ़ आई थी इस साल इसके कारण जोधपुर बाड़मेर रोड १।। महिने बन्द रही। उस समय अगर युद्ध हो जाता तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। सरकार पहले नहीं सावधान होती। फिर इससे परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। तो मेरा यह कहना था और

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मेरा अभी तक यह कहना है कि इस के बीच में पड़ने वाली पुलिया सिणधारी एवं बालोतरा को बनाना बहुत आवश्यक है और जल्दी से जल्दी इसका काम हाथ में लेना चाहिए ।

जोधपुर से बाड़मेर तक सड़क बन सकती है सीधी भी जिसमें पुल नहीं बनाना पड़े। इसमें लूणी नदी बचाई जा सकती है। पचपद्रा कवास बाड़मेर तक सड़क ले जाई जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने चाहिये।

तीसरी सड़क जोधपुर से गुजरात बोर्डर तक जाने वाली है जिससे मिलिटरी फोर्सेज भी जल्दी से उस रास्ते को तै कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि जोधपुर सिन्दरी से गांधव सांचोर होते हुए गुजरात जाने की रोड की व्यवस्था की जावे। बाड़मेर से सांचोर होकर जाने का भी रास्ता है, इससेजावें तो पचास साठ मील का ज्यादा रास्ता पड़ता है। तो यह किसी तरह सुविधाजनक नहीं हो सकता। इसलिए मैं विशेष तौर से इन सड़कों के निर्माण का काम हाथ में लेने की मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं ।

फिर जैसलमेर क्षेत्र में भी सड़कों का निर्माण करना चाहिये। उन का काम बन्द कर दिया गया। पोकरण में नाचना, जैसलमेर से मंयाजनगर, जैसलमेर से मुरार, नाचना से भाखोला, नाचना से बाला ये सामरिक महत्व की सड़कें हैं। इनको आप ड्राप कर रहे हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का ध्यान आकर्षित करिये और बजट उनसे लीजिये। यह राजस्थान की सुरक्षा और सुविधा का ही सवाल नहीं है, सारे देश की सुरक्षा का सवाल इसमें निहित है। इसमें केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी है। इन सड़कों के बारे में भी विशेष ध्यान देना चाहिए ।

अब अकाल में जो सड़कें हमारे क्षेत्र में बनीं वे अच्छी तादाद में बनीं। पैसे का काफी दुरुपयोग होने पर भी कुछ बनीं। इन पर पी० डबल्यू० डी० विभाग का अधिकार नहीं है। इसलिए रिपेयर के अभाव में ये जल्दी ही समाप्त हो जावेंगीं। कहीं दो-दो मील का टुकड़ा बनने से भी रह गया है।

इसी प्रकार बाड़मेर से कवास बाटाड़, कानोक इसमें भी तीन चार मील का टुकड़ा बीच में बाकी है। कहने का मतलब यह है कि १॥। करोड़ रुपया आपने अकाल का इन सड़कों पर खर्च किया है। इतना खर्च करके भी और रिपेयर इनका नहीं करते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। इनको पी० डब्लू० डी० के अधिकार में देकर रिपेयर करावें।

जब यह सड़कें बनाई गई यह सोचकर बनाई कि बीस साल योजना में उन सड़कों को लिया और १॥। करोड़ रुपया खर्चा हुआ और दो वर्ष में सड़कें बिलकुल साफ हो जायेंगी क्योंकि वह रेगिस्तान का इलाका है, टीबे हैं और धोरे हैं और मैं समझता हूं गर्मियों के दिनों में ही वह समाप्त हो जायेंगी इसलिए इस चीज की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुख होता है पी. डब्लू. डी. विभाग जो कि पब्लिकवर्क्स डिपार्टमेन्ट है अपना कर्त्तव्य और जिम्मेदारी के साथ काम करे तो देश की बड़ी सेवा कर सकता है । इस डिपार्टमेन्ट के लिए भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे सदस्यों ने कहा कि बड़ा ही करप्शन है । मुझे देखकर अफसोस होता है कि उनका फिक्स कमीशन मुकर्रर है । ओवरसीयर का २ परसेन्ट, असिस्टेन्ट इन्जीनियर का २ परसेन्ट, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का २ परसेन्ट और आफिस का ११.२ परसेन्ट और यह परसेन्टेज भी बढ़ाने की कोशिश की जारही है । यह हमारी गवर्नमेन्ट के लिए कलंक है । हम देखते हैं कि यह हमारे सामने होता है तो कांग्रेस सरकार को कोशिश करना चाहिए, पूरी शक्ति लगानी चाहिए, मंत्री मण्डल को पूरी शक्ति लगानी चाहिए कि इसको रोका जाये और यह जो दो-दो परसेन्ट लेते हैं और इस प्रकार करीब १० परसेन्ट कान्ट्रेक्टर से आता है, कहीं १२ परसेन्ट और कहीं १५ परसेन्ट भी लेते हैं तो यह कान्ट्रेक्टर अपनी जेब से नहीं देता है । १० परसेन्ट तो उसको देना पड़ता है और १० परसेन्ट उसका लाभ होता है तो यह नुकसान २० परसेन्ट होता है । यह देश की सम्पत्ति का विनाश होता है और यह कान्ट्रेक्टर से मिल कर पी० डब्लू० डी० करती है तो इस संबंध में आपको ठोस कदम उठाना चाहिए । कांग्रेस सरकार को सख्त कदम उठाकर दिखाना चाहिए कि हम वास्तव में जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, प्रान्त के लिए कुछ कर रहे हैं ।

मुझे भवन के बारे में भी कुछ कहना है । मैंने जैसा पहले कहा था कि जो हालत सड़कों की है वही हमारे क्षेत्र में भवनों की है । पशुधन के बारे में अगर सबसे ज्यादा स्कोप है तो वह बाड़मेर जिले में है । बीकानेर में भी इतना स्कोप नहीं है जितना बाड़मेर में है । परन्तु उस पशुधन के होते हुए भी उसके विकास के लिए बहुत ही कम कर रहे हैं । तो इस प्रकार हम कुछ दिलचस्पी लेते नहीं हैं, किसी तरीके से हम प्रगति नहीं करना चाहते हैं । पशुधन के संबंध में मैं कहना चाहता था कि पशुओं के लिए कोई चिकित्सालय हमारे यहां नहीं है । एक भी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में चिकित्सालय की बिल्डिंग नहीं बनी है । बहुत से इलाकों में बनीं है। लेकिन हमारे वहां कोई प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल एवं हायर सैकेन्डरी स्कूल के लिए प्रावधान रखा नहीं है । हमने जितने भी पैसों का प्रावधान देखा है वह उदयपुर में और दूसरे डिवीजन में देखा है। लेकिन जो अविकसित क्षेत्र हैं उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । इन्ही शब्दों के साथ में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सभापति: श्री भैरोंसिह ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के पिछले सत्र में भी सीमावर्ती सड़कों के संबंध में काफी विचार हुआ था और इस सदन से यह आशा थी कि अगली बार जब विधान सभा में सीमावर्ती सड़कों के संबंध में विचार होगा तो हमारी सरकार बधाई लेने के योग्य बन जायेगी । लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि बधाई देना तो दूर रहा कड़े से कड़े शब्दों में भी

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार की निन्दा की जाये तो वह भी अपर्याप्त होगा ।

सभापति महोदय हमारे देश की कुछ स्थिति ऐसी बन गयी कि सीमा के ऊपर जिस समय संकट खड़ा होगा उसी समय हम सावधान होंगे । उसी समय इस बात की चिन्ता होगी कि हमें सड़कों का निर्माण करवाना है । हमें लोगों को शस्त्र देने हैं, हमें पीने के पानी का प्रबंध करना है और सामरिक दृष्टि से बाकी की तैयारियां पूरी करनी हैं । लेकिन ज्योंहि युद्ध की हवा धीरे धीरे शांत होती है हमारी सरकार की गतिविधियां भी उसी के अनुसार शांत होती हैं मुझे याद है जिस समय १९६२ में चीन का आक्रमण हुआ उस समय एक बार राजस्थान की सरकर और भारत सरकार इन दोनों ने मिलकर इसकी आवश्यकता को महसूस किया कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण कराया जाये । लेकिन चूंकि वह युद्ध नेफा और लद्दाख के क्षेत्र में था और राजस्थान उससे बहुत दूर पड़ता था इसलिए चिन्ता व्यक्त करने के बाद भी हमने इसका ख्याल नहीं किया कि पाकिस्तान से हमारा युद्ध १९६५ में हो सकता है । उस समय कुछ योजनायें बनीं, कुछ उसमें एडवाइज़र्स ने राय दी, राजस्थान की सरकार ने भी प्रपोज़ल्स भेजे और भारत सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दी लेकिन उसके उपरान्त भी जितना काम होना चाहिए था उसमें थोड़ा सा भी काम नहीं हो पाया और इसी बीच कच्छ के क्षेत्र में पाकिस्तान ने आक्रमण किया । उस समय हमारी सरकार को फिर चिन्ता हुई कि हमें रोड्स का काम अपने हाथ में लेना चाहिए और १९६५ के सितम्बर में जब राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान से हमारा संघर्ष आया हम पाकिस्तानियों का मुकाबला सड़कों के अभाव में नहीं कर सके । राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग पर पाकिस्तान घुसपैठ करने में सफल हो गया और राजस्थान का नाम जिस प्रकार का शौर्य की दृष्टि से इतिहास में लिया जाता था उस नाम को भी कलंक लग गया । तो हमारी सरकार और भारत सरकार दोनों को इस बात की चिंता हुई कि अब हमें सड़कों के निर्माण के कार्य को तीव्र गति देनी चाहिए । जिस समय शुरू शुरू में यह योजना बनाई थी ६५ के अक्टूबर में उस समय युद्ध लगभग समाप्त हो गया था । उस समय सारी रोड्स के लिए २९ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया और किस प्रकार की कौन कौनसी रोड्स ली जायेंगी वह भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया । उसके बाद रकम ज्योंही स्वीकृत हुई काम आरम्भ करने का सवाल आया सबसे पहला संघर्ष इस बात का आया कि यह राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाये या भारत सरकार अपनी एजेन्सी के माध्यम से काम करावेगी । यह खुशी की बात है कि उस समय राजस्थान सरकार ने इस दायित्व को अपने हाथ में लिया और एक अलग आर्गेनाजेशन बनाया । कुछ काम चालू हुए, कुछ मशीनरी की दिक्कत आई, कुछ फण्ड्स में दिक्कतें आई । लेकिन मोटे रूप से कहें कि आरम्भ से लेकर पिछले वर्ष तक भारत सरकार ने जो फण्ड्स एलाट किये थे वह भी हमने खर्च कर दिये और उसके उपरान्त भी ६० लाख रुपये

(श्री भैरोंसिंह)

का काम अधिक कराया । रोड्स का निर्माण भी हुआ लेकिन उसकी मशीनरी के परचेजेज़ को लेकर, रोड्स के टेन्डर्स को लेकर कई घपले हुए हैं उसकी न तो हमारी भारत सरकार को ही चिन्ता है और न राजस्थान सरकार को है । हमने चिंता व्यक्त की लेकिन चुनाव का वर्ष था, राजस्थान की कांग्रेस को रुपयों की आवश्यकता थी और रुपया ठेकेदारों से मिल सकता था । मशीनरी देकर मशीनरी के एवज में चुनावों में चन्दा लिया जा सकता था । वह सारे अराष्ट्रीय काम उस समय की कांग्रेस की हुकूमत ने किया जो कि समय आने पर ही मालुम होगा कि कितने फण्ड्स का दुरुपयोग किया गया । लेकिन मैं समझता हूं कि चुनाव का वर्ष निकल गया । मैं सोचता था कि चुनाव के वर्ष के बाद इस काम में प्रगति होगी लेकिन पिछले दिनों जब मैंने सदन में चर्चा उठाई और वित्त मंत्रीजी पर मैंने आरोप लगाया कि इस साल भी जो भारत सरकार से धन राशि मिली थी उस धन राशि में से ८६ लाख रुपये आपने लैप्स कर दिये, वास्तव में यह ८६ लाख रुपये नहीं थे बल्कि कुल मिलाकर आपने १ करोड़ २५ लाख रुपये लैप्स कराये । इसके उत्तर में राजस्थान की हुकुमत यह कहना चाहती है कि भारत सरकार से मशीनरी मांगी थी लेकिन वह मशीनरी नहीं मिली इसलिये ये रुपये लेप्स हो गये । भारत सरकार से लोक सभा में आज से ४ दिन पहले प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार से राजस्थान सरकार ने कितनी मशीनरी की मांग की थी और उसमें से कितनी मांग पूरी की गई ? इसके उत्तर में उस विभाग के डिप्टी मिनिस्टर ने श्री पाटोदिया को कहा कि राजस्थान सरकार ने जो मशीनरी मांगी थी वह सारी उसको उपलब्ध करादी । मंत्रीजी की इस बात का अनुमान लगाकर चलें कि भारत सरकार ने बोर्डर रोड्स के लिये मशीनरी नहीं दी तो भी मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस समय ६५–६६ में काम आरम्भ किया गया था उस समय से लेकर मार्च सन् ६७ तक काम करते रहे उस समय भी मशीनरी नहीं थी । रात दिन काम करके भारत सरकार ने जो फण्ड्स एलोट किये थे वे सब खर्च कर दिये । वे ही खर्च नही किये बल्कि थोड़े समय तक जिस गति से काम किया वह बिना मशीनरी के कर दिया लेकिन गत वर्ष राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से मिला हुआ एक करोड़ से अधिक रुपया लैप्स कर दिया जब कि राजस्थान सरकार के पास मशीनरी आइडल पड़ी है । राजस्थान केनाल के पास मशीनरी पड़ी है । कोई मशीनरी आवश्यक नहीं थी जिसकी आड़ में निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता था । भारत सरकार ने हाई और लो प्रायोरिटी का निर्माण किया, आज आपका रोड पर अर्थ वर्क हो गया, ग्रेवल डाल दी, सोलिंग का काम कर दिया लेकिन उसका पक्का करने का सवाल आया, डाम्बर डालने ग्रेवल डालने या सोलिंग का प्रश्न आता है तो वहां पर सारी मशीनरी किस जगह खड़ी हो गई जिसके कारण आप रोड्स को गति नहीं दे सके । मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के निर्माण मंत्री के लिये इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती । एक तरफ पाकिस्तान के सारे सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा हुआ है वह सीमावर्ती इलाके

(श्री भैरोंसिंह)

के लोगों को फौजी शिक्षा दे रहा है और उन लोगों को शस्त्र बांट कर हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है और इधर हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी भारत सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा मशीनरी नहीं मिली। भारत सरकार ने बोर्डर रोड्स के लिये जो फंड्स एलोट किये थे उसमें से इनको सवा करोड़ रुपये लैप्स करने पड़े हैं।

यह बात इतनी ही नहीं है सभापति महोदय, पिछली बार मैंने इस सदन में प्रश्न पूछा था कि रोड्स के संबंध में कितनी मशीनरी खरीदी गई और वह किन-किन कांट्रेक्टर्स को दी गई। आज मंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि भारत सरकार ने ८ करोड़ की धन राशि को घटाकर ३.५ करोड़ कर दिया इस लिये रोड्स का काम बंद कर दिया। उस समय जो ठेकेदार मशीनरी पर काबिज थे वही ठेकेदार हैं जिनको आज कांट्रेक्ट मिला है। तीन कांट्रेक्टर्स को ही नया काम दिया है बाकी वही ठेकेदार हैं जिनको मशीनरी दी थी। जिनसे आपने काम लिया था उन्हीं का काम बंद कर दिया। अगर सरकार कोशिश करती तो वही मशीनरी दूसरी तरफ काम आ सकती थी और सड़कों का निर्माण होता और भारत सरकार की रकम लैप्स नहीं होती। लेकिन सभापतिजी इस विभाग के मंत्री नवाबसाहब और चीफ इंजीनियर ने कोई ध्यान नहीं दिया। चीफ इंजीनियर के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि जहां पर नवाबसाहब दौरे पर जाते हैं वहीं पर वह चीफ इंजीनियर कैंप लाग कर बैठ जाय यह हाल आज मंत्री जी का और चीफ इंजीनियर का है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि ईमानदारी से सड़क निर्माण का काम करते तो रकम लैप्स नहीं होती।

दूसरा प्रश्न सभापति महोदय, आपको मालूम है, सदन को मालूम है कि कई रोड्स ऐसी हैं जिन पर पहले अर्थ वर्क कराया गया है। मैंने उस समय भी कहा था कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के इलाके में केवल अर्थ वर्क से सन्तोष नहीं हो सकता। उन पर ग्रेवल डाला जाय और उसके दो पड़त डाली जायं तो भी उन सड़कों को रिटेन करना मुश्किल होगा। मुझे याद है उस समय स्वीकार किया गया था कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले में जहां अर्थ वर्क हुआ है वहां पर चाहे ग्रेवल डालें, चाहे किनारों पर ग्रेवल डालदें चाहे दो-दो फुट इसके डालदें लेकिन जिस समय आंधी आयेगी उस समय न ग्रेवल रहने वाला है और न अर्थ वर्क। जो कुछ मैंने जानकारी की उसके आधार पर कह रहा हूं। रामदेवरा, नाचना, माड़वा रोड है उस पर अर्थ वर्क करके, सोलिंग करके ग्रेवल डाला है इसके लिये १४ लाख का कांट्रेक्ट दिया गया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस रोड पर मरम्मत का काम करवाया जाय, यदि दुबारा मरम्मत करवाई जाय तो कोई ठेकेदार ऐसा नहीं होगा जो यह नहीं कहे कि पहला काम तो गया, पहले काम को वापिस करने के लिये १० लाख रुपये और चाहिये। चाहे वह रुपया भारत सरकार का हो चाहे राजस्थान सरकार का हो, १० लाख रुपया बेकार गया है। नाचना-बावला रोड को मैं स्वयं देख कर आया था, मैं स्वयं बावला हो गया था इस सदन को यह सुन कर

(श्री भैरोंसिंह)

ताज्जुब होगा कि उस स्थान पर मुझको सड़क देखने को नहीं मिली, यह नहीं कहा जा सकता कि वहां पर कभी कोई रोड थी। अर्थ वर्क था वहां ऐसा लगता है कि कोई रोड को उठा कर ले गया हो। नवाब-साहब या तो उसको उठा कर लोहारू ले गये होंगे या अपने बंगले में ले गये होंगे। जब वहां पर आंधियां चलती हैं उस समय वहां पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री स्वयं खड़े हो जायं तो उनको भी पता नहीं लगेगा, पता नहीं टिक सकेंगे या नहीं। ऐसे स्थान पर अर्थ वर्क कराने में नाचना-बावला रोड पर ९ लाख ६८ हजार रुपये खर्च हुऐ। इसी तरह से नोंवुल जुगारो रोड पर ५ लाख रुपये बेकार गये। इसी तरह जेसलमेर, सम और सम से मुराव सड़क पर अर्थ वर्क बेकार गया। इस पर जो ग्रेवल डाली गई वह भी बेकार गई। इसी तरह से जेसलमेर से खूड़ तक पहाड़ी इलाका आता है यहां तक तो पता चल जायगा कि मिट्टी डाली गई है लेकिन आगे पता नहीं लगेगा वहां पर कोई नहीं कह सकता कि यहां पर अर्थ वर्क हुआ होगा। इसमें ५ लाख रुपये भारत सरकार के बेकार चले गये और भारत सरकार को ५ लाख रु. का घाटा हुआ।

इसी प्रकार सभापति महोदय, बीकानेर डिविजन में सूरतगढ़ रायसिंहनगर सड़क पर अर्थ वर्क कराया गया जो बेकार गया। बीकानेर से पूंगल तक की सड़क पर ७ लाख रुपये अर्थ वर्क में बेकार चले गये। पूंगल से भीकमपुरा तक की सड़क पर ५ मील में जो काम कराया वह आधी सड़क खत्म हो गई। इसी तरह भीकमपुरा से रणजीतपुरा तक की सड़क पर ५ लाख रुपये बेकार गये। टोटल में यदि पूछना चाहें तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कोई जांच करले, राजस्थान सरकार का हो चाहे भारत सरकार का हो दोनों को मिला कर ७५ लाख रुपयों का राजस्थान में नुकसान हुआ है। आज आपके दिमाग में आ सकता है कि भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया और भारत सरकार राजस्थान सरकार की शिकायत कर सकती है लेकिन जनता जानती हैं और भारत सरकार और राजस्थान सरकार को रोती है कि उन्होंने ७५ लाख रुपये मिट्टी में उड़ा दिये। जब हम कहते हैं तो सरकार कहती है कि भारत सरकार पैसे नहीं देती। लेकिन भारत सरकार रोड्स के लिये जो पैसा देती है उससे इंजीनियर्स के बंगले बनाये जाते हैं और मन्त्री जी कहते हैं कि टोटल एक्स-पेन्डिचर है उसमें से इन्सपेक्शन बंगले और गेंग हट्स बन सकते है। आज हिन्दुस्तान में ही नहीं मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि डेवलप्ड कंट्रीज का दौरा करके देखें तो यहां पर जो गेंग हट्स हैं वैसी किसी देश में नहीं है। इनमें इतनेचिकने फर्श हैं कि यदि उन पर गिरजाय तो पंसलिया टूट जांय वहां की लैट्रीन का वातावरण,वहां के बैड रूम, ड्राइंग रूम का वातावरण और इनकी हालत देखें तो उससे आप सुखाड़िया जी के बंगले का मुकाबला कर लीजिये, राजस्थान के निर्माण मन्त्री के बंगले से उसका मुकाबला कर लिजिये। हो सकता है कि निर्माण मन्त्री इस विभाग के मन्त्री हैं इसलिए इनके बंगले में थोड़ी चमचमाहट आ गई हो, इनके बंगले में फिलसन आ गई हो। लेकिन उन बंगलों की अकोमोडेशन देखें, उन बंगलों का फर्निशिंग देखें तो जिस प्रकार के बंगले बनाये हैं उनको देख कर-मुझे शर्म आती है कि हमारी सुरक्षा सड़कों

(श्री भैरोंसिंह)

का पैसा बंगलों में खर्च हो जाय। क्या दुश्मन वहां तक आकर उनके अन्दर आराम करेगा? वहां का वातावरण, जिस प्रकार की लेट्रिन बनाई है, जैसे फर्निश किया है वह क्या दुश्मन के लिऐ आराम के लिए तैयार करना चाहते हैं। जो पैसा रोड्स में नहीं लगाना चाहिए वह पैसा रोड्स में नहीं लगाया आपका कहना है कि एक दो तीन मिलाकर गैंग हट्स बनाये हैं। आपने जिस तरह के गैंग हट बनाये हैं वह मैंने एक-एक देखे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान की सीमा पर जो गैंग हट बने हैं उनमें मजदूर नहीं रहते हैं, वह खाली पड़े हुए हैं। खाली पड़े हुए हैं, कभी कोई इन्जीनियर साहब आते हैं तो उसमें एक-दो दिन ठहर जाते हैं। उनके दो दिन ठहरने के लिए तो और भी स्थान मिल सकता था। आज अमर्जेन्सी है उसके अन्दर आपका कहना है कि मित-व्ययता के अन्दर काम होना चाहिए। लेकिन यह मितव्ययता का विषय नहीं है,सवाल यह है कि जो पैसा आ रहा है उसको खर्च कैसे किया जाय। आज मन्त्री जी जब जवाब देंगे तब बतायेंगे कि क्या जितना काम बना है, वह सारा का सारा टेन्डर से बनवाया गया है, क्या वह पी० डब्ल्यू० डी० के कान्ट्रेक्टर्स की मार्फत बनाया है? इसका जवाब तो गवर्नमेंट के पास नहीं। इसका जवाब नहीं हो सकता। क्योंकि जो लिस्ट सरकार ने दी है, उस लिस्ट में भवन की कीमत बीस हजार बताई है। मैंने इनके आंकड़ों को देख कर अच्छे-अच्छे इन्जीनियर्स से बात की हैं। उनका कहना है कि वह मकान ८० हजार रुपये के हैं, कोई एक लाख रुपये का है लेकिन आपकी लिस्ट में बीस हजार रुपये का बताया है। मैं राज-स्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि साठ हजार रुपया कहां से आया...

श्री रणजीतसिंह : ठेकेदारों से चन्दा वसूल किया है।

श्री भैरोंसिंह : ठेकेदारों से वसूल किया है, तो चन्दा कहां से आयेगा। बिल्कुल ठीक है, वह चन्दे से वसूल हो गया। लेकिन ठेकेदार चतुराई में मन्त्री से भी आगे हैं, ठेकेदार मन्त्री जी से भी आगे हैं। मन्त्री महोदय की अक्ल काम नहीं करती है। कोई जेब से रकम निकाल कर दे दी, यह मानकर चलें तो कोई अपनी जेब से निकाल कर पैसा दे दे- ऐसी स्थिति नहीं है। उसने सड़कों से पैसा लिया है और पैसा लेकर बंगलों में लगा दिया है। बंगलों में पैसा लगा कर सरकार के ऊपर कृपा कर दी और उधर रोड्स में घोटाला कर दिया। सभापति महोदय, आज मन्त्री महोदय कह रहे थे, हमने जो मशीनरी दी, कुछ दिन पहले कह रहे थे, उसकी पूरी कीमत वसूल कर ली। अभी-अभी चुरू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक लेटर प्रस्तुत किया, उस समय जवाब दिया गया था. कह रहे थे कि दस पर्सेन्ट मनी सबका जमा हो गया था, सीक्योरिटी सबकी ले ली थी। तमाशा क्या हुआ, ठेकेदार को थोड़े काम के लिए काफी मात्रा में मशीनरी दे दी इसलिए मशीनरी की रकम वसूल नहीं हुई। उसके बाद यह विधान सभा में झगड़ा हुआ तो दूसरे ठेकेदारों की रकम में से काट कर उसमें जमा करा दी। गाय के ऊपर भैंस और भैंस के ऊपर गाय, नवाब साहब ऊपर और भैंसवाड़ा नीचे और भैंसवाड़ा ऊपर और नवाब साहब नीचे- यह दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं— यह मेरी समझ में

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं आता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, नवाब साहब, आपसे खास तौर से इसलिए कि कई बार लोग ऐसी बात कर जाते हैं कि बोर्डर रोड्स का काम इसलिए पूरा हुआ क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग नवाब साहब के पास है। हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन इस प्रकार की लोगों में चर्चा होती है। वह सही नहीं है लेकिन चर्चा जरूर है। तो आपको बहुत सावधानी के साथ इन सब बातों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब यदि आप व्यवस्था नहीं करते हैं तो मैं आपको यह कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आपकी सड़कों का इन्तजार करने वाला नहीं है। सभापति महोदय, इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया, उसके पहिले कई दफा मैंने इस विधान सभा में सवाल पूछे कि बोर्डर रोड्स क्यों नहीं बनाई जाती हैं। कहने लगे कि वहां मशीनरी नहीं पहुंचती हैं, वहां पत्थर नहीं जा सकते, वहां मजदूर नहीं मिल सकते। लेकिन अभी पिछले दिनों में मैंने सारे बोर्डर पिलर को देखा तो पाकिस्तान ने एक दो महिने में, जिस समय हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया था, उस समय एक बुलडोजर से सालागढ़ से जज्जेवाली चौकी, जहां कि पाकिस्तान ने कब्जा किया था, एक सीधा रास्ता बना दिया, जिस रास्ते पर आज हमारी गाड़िया चलती हैं। आज बदकिस्मत ऐसी हो गई है कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने सड़कों का निर्माण करके अपनी तमाम व्यवस्था करी है, लेकिन आज हमारी सड़कें ऐसी पड़ी हैं कि आज कोई जाना चाहे जेसलमेर से तनोट, तनोट से जैसलमेर या तनोट से शाहगढ़ तो हमारी रोड्स को बनाने का काम हाथ में लिया था उनको अधूरा छोड़ दिया गया है और इसलिए जो साधारण गति ट्रान्सपोर्ट की थी वह भी बंद हो गई है, उन रोड्स पर गाड़ी नहीं जा सकतीं, टीबों का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसी तरह से जो टीबे आते हैं उनकी रोकथाम करने की व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उस सारे सीमा क्षेत्र में, जहां कहते हैं मिट्टी है, जहां के लिए कहते हैं कि पीने का पानी नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है, वहां पाकिस्तान ने सारा काम कर लिया है। लेकिन सारे राजस्थान का निकम्मापन इकट्ठा होकर इस राज्य सरकार में आ गया है और इस राज्य सरकार का निकम्मापन इकट्ठा होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग में, किसी तरह से आ गया है।

(४५.४ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)

मैं इसके अलावा यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रोड्स के मामले जिस प्रकार की स्थिति को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आज यह सारी गति क्यों रुकी। मैंने गजट नोटिफिकेशन निकाले और निकालकर उन्हें देखा कि भारत सरकार ने जो फंड्स दिये थे वह खर्च क्यों नहीं हो पाये। एक अगस्त २४, १९६७ को राजस्थान की सरकार ने टेण्डर इन्वाइट किये सात रोड्स के, उस गजट में प्रकाशित टेण्डर जिन लोगों को देने थे उन लोगों ने टेण्डर दे दिये। उसके बाद तीन तीन महीने तक टेन्डर हमारे मंत्री

[redacted]

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय के बीच और फाइनेन्स डिपार्टमेंट के बीच में घूमते रहे। अब भारत सरकार को दोष लगाना चाहते हैं तो बस सरकार से कोई पूछे कि एमर्जेन्सी के मामले के अन्दर यदि टेन्डर की सेंक्शन तीन तीन महीने तक नहीं हो, तो यह अपराध भारत सरकार का है या यह अपराध राजस्थान सरकार का है। मैं इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री से व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूंगा, वह तारीख बतलायें कि किस किस टेन्डर की सेंक्शन के लिए आपके पास कब कब कागजात आये और कब कब वह टेन्डर सेंक्शन किये गये। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान के अन्दर चीफ इन्जीनियर, पी० डबल्यू० डी० राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर एडीशनल सेकेटरी के रूप में काम करते है, तो उस समय सेक्रेटेरियेट का सेक्रेट्री होने के नाते रेड टेपिज्म है वह अपने आप खत्म हो जाता है। अब यह कहें कि चीफ इंजीनियर, एडीशनल सेक्रेटरी के रूप में एक मामला मंत्री महोदय के पास रखते हैं तो मंत्री महोदय ने कौनसी टेक्निकल एजूकेशन ली है, कौनसा मिनिस्टर को रोड कन्स्ट्रक्शन का काम आता है, तो जो सारे टेक्निकल आफिसर के आधार पर उनके पास एक टेन्डर आता है उसमें वह नुक्ता चीनी करने की तैयारी करते हैं। हो सकता है कि फाइनेन्सियल एलोकेशन के आधार फाइनेन्सियल मैटर पर फाइनेन्स डिपार्टमेंट की ओपिनियन लेनी पड़े। लेकिन दो तीन महीने उसको इसके लिऐ रोकना मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए डिले इसलिये नहीं हुई कि भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया, यह डिले इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास मशीनरी नहीं थी–इसका मोटा कारण यह था कि हमारा विभाग बिल्कुल इन्एफीसियेन्ट साबित हुआ है। इस कारण रोड्स का कन्स्ट्रक्शन नहीं हुआ। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन रोड्स के अन्दर भी चालाकी से काम लिया जाता है। लोग कहते हैं कि जिन रोड्स से इनको आमदनी हो सकती है वह सारी की सारी रोड्स देते हैं ठेकेदारों को, जिन रोड्स के अन्दर कोई आमदनी का जरिया नहीं हैं, जैसा कि माननीय सदस्य कमीशन की बात कहते हैं, जहां कमीशन का कम पर्सेन्टेज आया, जहां ठेकेदार को अधिक मुनाफा नही हो सकता उस प्रकार की रोड्स को राजस्थान सरकार डिपार्टमेंट से करवाती है, और जहां कमीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाय, जहां जहां पर खाने पीने के साधन उपलब्ध हों वह रोड्स कान्ट्रेक्टर को दे देते हैं। इस प्रकार तथ्य मंत्री महोदय बतायेंगे, आपने इन बोर्डर रोड्स के अन्दर से जो डिपार्टमेंटल करवायी हैं, उनका पर्सेन्टेज जो कान्ट्रेक्टर से कारवायी हैं उससे कहीं ड्योढ़ा है, कहीं सवाया है, कहीं दुगुना है, इस खर्च में डिपार्टमेंट से करवाया है, जब कि ठेकेदार से आप सस्ता काम करवाना चाहते हैं। कोई काम सरकार करे तो कीमत दुगुनी लगती है, इसका मतलब यह है कि यह डिपार्टमेंट बिल्कुल इन्एफीसियेन्ट है।

मैं एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। सभापति महोदया राजस्थान में शहर का प्रश्न और रोड्स के प्रश्न पर जब किसी शहर की रोड्स के सम्बन्ध में इस सरकार से कहा जाता है तो मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि यह

(श्री भैरोंसिंह)

हमारे विभाग में नहीं है। अब यह विभाग में आता नहीं है। नगर पालिका और नगर परिषद के पास पैसा होता नहीं है उसका परिणाम यह होता है कि सड़कों का निर्माण होता नहीं है।

बीकानेर, जोधपुर और बाकी के क्षेत्रों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं जयपुर नगर के बारे में कुछ विचार रखना चाहता हूं। जयपुर नगर परिषद की इतनी इनकम नहीं है कि वह राजधानी की सड़कों का निर्माण कराये। नगर परिषद् जितना टैक्स लगा सकती थी वह उसने लगा दिया। टैक्स की दृष्टि से हम उस प्वाइंट पर पहुंच गये हैं कि हम जयपुर शहर से किसी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं कर सकते और उस आमदनी से हमारा जो इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा है वह पूरा नहीं होता। राजस्थान का पी० डब्ल्यू० डी० रोड्स को अपने अन्तर्गत लेता नहीं। तो क्या मैं यह मानकर चलूं कि जयपुर की सड़कें टूटी फूटी सड़कें हैं। गलियों में टूटी फूटी सडकें हैं। वह सुधरने वाली नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा जयपुर शहर के बारे में कि सरकार द्वारा रोड्स बनाने की दृष्टि से मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जयपुर के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि उनको जययुर से चिन्ता हो सकती है। यह सही है लेकिन जयपुर की सड़कें केवल एक नगर की नहीं है। राजस्थान की राजधानी की हैं। लेकिन सिर्फ असेम्बली से सिविल लाइन्स में मन्त्री महोदय जायें सिर्फ इसी लिए तीन चार रोड्स पर डामर डालते जायें। और मन्त्री लोग जिस रास्ते से सेक्रेटरिएट जाते हैं, उन रोड्स पर डामर डालने की व्यवस्था करदें। तो उससे मसला हल नहीं होता है। जयपुर नगर की सड़कों और गलियों की यह हालत है कि वह टूट फूट गई हैं और उन पर पिछले १० सालों से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। यह जयपुर शहर के साथ; सरकार का सौतेला व्यवहार साफ नजर आता है। सभापति महोदय, आज के ५ वर्ष पहले जयपुर में बाढ़ आयी थी और जिस समय बाढ़ आयी तो सरकार ने उदारता बताई कि हम नाली की लाइनिंग करा देंगे। नाली को कवर करा देंगे और पानी का रास्ता निकाल देंगे। इस तरह १३।१४ लाख की स्कीम बनाई थी। उसके अन्दर से जो तत्काल खर्च होगया। ४।५ लाख रुपया वह भी बांध में खर्च होगया। बाकी जितना छुटपुट काम था वह बंद हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कल नारी के नाके में आप लोग गये थे वहां के लोगों की हालत आपने देखी। क्या आपने महसूस नहीं किया कि यहां रोड्स की आवश्यकता नहीं है क्या। आपने महसूस नहीं किया है कि इन गन्दी बस्तियों में लोग कैसे रहते हैं। आपको उनकी चिन्ता नहीं है। चिन्ता इस बात की है कि किस प्रकार हम विधान सभा के अन्दर फण्ड्स ले लें। फण्ड्स का दुरुपयोग भी कर लें फिर भी आलोचना नहीं हो और बजट प्राविजन जिस प्रकार रखा है उस प्रकार पास हो जाए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पी० डब्ल्यू० डी० में बहुत बड़ा स्कैंडल चलता है। यह मैं सदन के सामने रखता हूँ। आज जो लोग कहते हैं कि कमीशन बंधा हुआ है। इस कमीशन के बांधने का

(श्री भैरोंसिंह)

रीजन क्या है ? कारण क्या है ? मैटीरियल खराब लगाया जाएगा, आम बात है। कम लगाया जाएगा, यह आम बात है। लेकिन सबसे बड़ा करप्शन उस जगह आता है जब कंट्रेक्टर के बिल्स पास होते हैं। बिल्स पास होने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर ऊपर जिस लेविल तक मामला जाता है, उस सारे लेविल तक उस मामले में से कैसे पैसा काटा जाए। उसके लिए धमकी देते हैं इस बात की कि तुमने आकर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन काम नहीं किया। स्पेसिफिकेशन के अनुसार मैटीरियल नहीं लगाया। जितना मैटीरियल लगाना चाहिए था उतना नहीं लगाया। यदि इसकी जांच करना चाहें तो पी० डब्ल्यू० डी० के आफिसर जांच नहीं कर सकते। विधान सभा के कुछ सदस्यों की एक समिति बना दी जाये जो इस बात की जांच कर ले कि असि० इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, जो वास्तव में काम का सुपरवीजन करते हैं, ओरिजिनल रिपोर्ट क्या दी हैं ? और उसके अनुसार जितनी कटौती होनी चाहिए वह आगे जाकर जितनी कटौती होनी चाहिए, कटौती नहीं होती है। बल्कि जितनी रकम वह क्लेम करता है उतनी रकम सारी की सारी मिल जाती है। अगर करप्शन को रोकना है तो इस बात की व्यवस्था करनी होगी जो कंट्रेक्टर्स के बिल आते हैं उसके पेमेंट में डिले न की जाए। वहां डिले के नाम पर पैसा मारा जाता है। झूठा और गलत सड़क का सार्टिफिकेट दिया जाकर रुपया डकारा जाता है। उस मर्ज को हमें रोकना पड़ेगा। वह मर्ज हम नहीं रोक पायेंगे। क्योंकि कमीशन मंहगाई के हिसाब से बढ़ेगा और खर्च के हिसाब बढ़ेगा। लोगों में लग्जरी की आदत पड़ जाएगी उसके अनुसार बढ़ेगा। मैं निवेदन करूंगा सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको दूसरी पंचवर्षीय योजना का बहुत बड़ा हिस्सा मिला था वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में कम हुआ। (समय समाप्ति सूचक घंटी) उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना का जो ईयर प्लान चल रहा है उसके अन्दर पैसा मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा। पैसा खर्च करने के बाद उसका पूरा उपयोग नहीं होता है। जन-मानस में पी० डब्ल्यू० डी० की कार्यवाही के प्रति एक भयंकर असंतोष है। मन्त्री महोदय. उस असन्तोष को रोक नहीं पायेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमन्त्री ने जिन्हें यह विभाग दिये हैं उसके जो मन्त्री और उपमन्त्री हैं, माननीय सभापति महोदय, हम आपस में बात कर सकते हैं। हम कांग्रेस के लोगों से मिल सकते हैं। हंसी मजाक हम में चल सकता है। लेकिन इसके मन्त्री और उपमन्त्री में कुत्ते और बिल्ली जैसा वैर है।

श्री माधोसिंह : गलत बात है।

श्री भैरोंसिह : छत्तीस के आंकड़े की तरह हैं। तीन एक तरफ और छः एक तरफ। मुझे जानकारी नहीं है। मन्त्री महोदय यही कहेंगे लेकिन मंत्री महोदय यह कोशिश करते हैं कि इंजीनियर्स, डिप्टी मिनिस्टर से नहीं मिलें और डिप्टी मिनिस्टर यह कोशिश करते हैं तो सारे एम० एल० एज० मिनिस्टर से नाराज हो जायें।

श्री माधोसिंह : गलत बात है।

श्री भैरोंसिह : और यह दोनों संघर्ष

(श्री भैरों सिंह)

करते हैं । आप दोनों नहीं करें । मुझे आप से सार्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है । मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हमारी हाँ में हां करें । लेकिन आपका मन बोल रहा है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो हाथ हिलाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : हाथ हिलायें, या पैर हिलायें, सिर हिलायें या शरीर हिलायें । इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ।

श्री श्रवणलाल : आंख से इशारा कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन मन नहीं हिलना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम पूर्ण तया असंतोष जनक स्थिति में चल रहा है । उसके कारण जिस बात को लेकर मैंने बात रखी है, बोर्डर रोड्स का मसला है उसमें राजस्थान की सरकार में भयंकर रूप से गलत फहमी है । भारत सरकार और राज्य सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण राजस्थान और भारत की जनता के लाखों रुपयों को पानी में बहाया है । उस सब मसले पर जांच होने की आवश्यकता है । मैं रोड्स के मामले में कहना चाहूँगा कि जिन रोड्स के मामले में घोटाले हुए हैं कण्ट्रेक्टर्स को रुपया देकर मशीनरी देकर के बैठे गये । टेण्डर्स में डिले हुई है । रकम लैप्स हुई है । जिस तरह के मकान और भवन और गैंग हट बनाये गये है और जो रोड्स हवा में उड़ गई हैं, जिनमें जितने धन का दुरुपयोग हुआ है उसकी जांच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिए । तब जाकर पता लगेगा......... (विराम) ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जी हां क्या पता लगेगा । मैं सुन रहा था ।

श्री भैरोंसिंह : कमीशन नियुक्त कर दिया गया तो आप रहने वाले नहीं है ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप होंगे, उसमें तब ।

श्री भैरोंसिंह : उसके मेम्बर आप हुए तो ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : खुदा ऐसा न करे ।

श्री खेतसिंह : वह मुश्किल है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं, वह मुश्किल है । नवाब सा० हमारी तरफ थे तब कहते थे उधर जाने वाले हैं । डिफेक्ट हो गये और उधर चले गये तब कहते हैं खुदा ऐसा न करे । तो खुदा तो करेगा ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : नमूना पेश कर देंगे आप ।

श्री भैरोंसिंह ; आप समझते हैं जैसे पी०डब्ल्यू०डी० के काम के कट्रेक्टर होते हैं । जो एक समय के पहले टूट नहीं सकते । मैं आपको बता दूं कि यह पी०डब्ल्यू०डी० का कट्रेक्टर नहीं है जिसको लेकर हाई कोर्ट से स्टे ले आयें । यह जनता का कण्ट्रेक्ट है । जिसको दबाये हुए हैं और

(श्री भैरोंसिंह)

उसने दबा लिया तो राजस्थान के अन्दर आप का कब्रिस्तान ही होगा।

श्रीमती सभानेत्री—माननीय शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मैंने इस मांग के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी राज्य के लिए सड़कों का निर्माण बहुत आवश्यक है और इस विकास के युग के अन्दर एक जगह से दूसरी जगह चाहे वह सीमावर्ती इलाका हो, दूसरा इलाका हो उसके अन्दर इनका निर्माण होना चाहिए। सभापति महोदया, यह तो कई माननीय सदस्यों ने सड़क निर्माण के बारे में बहुत कुछ कहा है। आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय, का ध्यान इन तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सड़क का निर्माण होता है और उन सड़कों के निर्माण के द्वारा जब कई जगह हमें काश्तकारों की जमीन को अवाप्त करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है तो सभापति महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दस-दस साल से उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है? हम सड़कों का निर्माण एक तरफ करें......

श्री दौलतराम सारण: कई जगह कब्जा कर लिया आज तक नहीं दिया पैसा।

श्री शंकरलाल : और यह कह रहे हैं कि लोगों के अन्दर विकास की भावना जागृत करें। विकास होगा लेकिन अजीब तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर से जयपुर की तरफ सड़क आती है, जोधपुर से लेकर गड़रिया और जैतारण निर्वाचन क्षेत्र तक सड़क आती है, उसका आज से दस साल पहले निर्माण हुआ......

श्रीमती सभानेत्री : सदन की मंशा है कि समय बढ़ा दिया जाये ?

श्री दौलतराम सारण : सदन थक चुका है।

श्री रामकिशन : कितना ?

श्रीमती सभानेत्री : कोई समय निश्चित नहीं किया, जो भी वक्त होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप की मंशा है जैसे चलें।

श्री विजयसिंह : जैसी आप की मंशा हो वैसा करें।

श्री शंकरलाल : इस सड़क निर्माण में जिन जिन काश्तकारों की भूमि १० वर्ष पूर्व ली.........

(५ म० प०)

उसका मुआवजा नहीं चुका सके और जब इस बात का पता लगाया तो ज्ञात हुआ जोधपुर में लैंड एक्वीजिशन आफिसर है, उन लैंड एक्वीजीशन आफिसर ने—भूमि अवाप्ति अधिकारी को उन कागजों का पता तक नहीं लगने दिया। जब उनसे पूछा गया तो वे यह कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। इतना ही नहीं सभापति महोदया, एक तरफ मुआवजा नहीं देते और दूसरी तरफ उनसे लगान की वसूली का तकाजा करते हैं, उनको नोटिस देते हैं। जो भूमि सड़क निर्माण कार्य में ले ली गई है उसका मुआवजा तो दूर रहा, वे तो

(श्री शंकरलाल)

उस भूमि का लगान लेने को नोटिस दे रहे हैं। मैं नहीं समझता पी० डबल्यू० डी० इस तथ्य की ओर क्यों नहीं देखती कितनी ही जगह ऐसी है, जहां किसानों को भयंकर असन्तोष है। कोई बात नहीं कि आप उनकी जमीन निर्माण कार्य में न लें, आप अपनी जमीन ले सकते हैं लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया और उल्टे उनसे लगान वसूल करने का तकाजा किया। इसीलिए सभापति महोदया, उदाहरण के रूप में कहा है। राजस्थान के कई इलाकों में शिकायत है। दूसरे मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय के समक्ष जो गांवों में ठेकेदार की मारफत सड़क निर्माण का कार्य होता है, जिनमें मजदूरों से काम लिया जाता है मैं समझता हूं कि यह विभाग की जिम्मेदारी है कि उसकी मजदूरी के साथ ठेकेदार का न्याय किया जाता है या नहीं, उनको समय पर मजदूरी दी जाती है या नहीं, उनसे बराबर कितने घंटे काम लिया जाता है। सभापति महोदया, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज उदाहरण के रूप में ब्यावर से बर का सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है और यह डिफेंस रोड कही जाती है। १८ लाख की स्वीकृति है जो भारत सरकार द्वारा खर्च की जा रही है, सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी बराबर नहीं दी जाती है, निर्धारित समय से ज्यादा काम लिया जाता है। मैंने स्वयं ने मन्त्री महोदय को लिखा है कि इसकी जांच करावें लेकिन खेद है कि अभी तक कोई जांच नहीं हुई। सभापति महोदया, लाखों रुपया खर्च करते हैं लेकिन उन मजदूरों के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके विकास के लिये कोई बात नहीं कही जाती। दूसरों को मजदूरों के विकास की बात कहेंगे, लेकिन स्वयं का कोई पता ही नहीं है। मजदूरों की भावना की कोई कद्र नहीं है। उनसे कहे कि काम मत करो तो वे बेचारे कहते हैं कि काम नहीं करें तो क्या करें, इसलिए सभापति महोदया, काम करना पड़ता है पेट के लिये लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि उनको वही सुविधायें होनी चाहिये जो दूसरों को होती हैं चाहे वे ठेकेदार के नाम पर काम करें और चाहे सरकार के नाम काम करें। उनका शोषण न हो। सभापति महोदया, जो १८ लाख की स्वीकृति है, उसके अन्दर भारत सरकार का प्रावधान है कि जितनी लागत लगे उसका २ परसेन्ट वहां के मजदूरों के हित के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिये उनकी चिकित्सा के लिए खर्च किया जाय। किन्तु खेद है कि वह २ परसेन्ट अभी तक सरकार के पास पड़ा है। एक भी पैसा मजदूरों को नहीं दिया। मैंने निवेदन किया, मंत्री महोदय को लिखा, कई बार विनय की कि उनका पैसा जो भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य व. चिकित्सा के लिये दिया गया है, उस पैसे को आप वहां के इलाके के अन्दर खर्च करें, वहां का जो हास्पिटल है उसके अन्दर डोनेशन कर दीजिये जहां मजदूरों के पैसे का उपयोग हो सके। सभापति महोदया, मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज कितने अरसे से वहां सड़क बन रही है, उसका प्लान बार-बार चैन्ज किया जाता है। कभी इधर सड़क बनाते हैं तो कभी उधर सड़क बनाते हैं। हो सकता है

(श्री शंकरलाल)

यह ठेकेदार का काम हो और उसमें उसी का पैसा खर्च हो रहा हो, लेकिन उसमें विलम्ब तो हो रहा है, उसमें देरी हो रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी महत्वपूर्ण सड़क जो भारत सरकार बना रही है और जिसका डिफेन्स के रूप में निर्माण किया जा रहा है वहां के मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह पता नहीं किया जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। सभापति महोदया, उसके साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक विभाग इस सड़क के आस-पास के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की कटाई करता है। सदन में यह कई बार सवाल भी आया था, उन वृक्षों की कटाई यह विभाग कैसे करता हैं ? वह उन वृक्षों को काट कर कहां ले जाता है, क्या करता है आदि बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदया, मैंने देखा है सड़क से काफी दूर वृक्ष लगे हुये थे, उनको काटने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन इस नाम से काटे जाते हैं कि सड़क बनाई जा रही है। पी० डब्ल्यू० डी० उन वृक्षों का दुरूपयोग करती है, उनको चुपचाप बेचती है, उसके अन्दर घोटाले होते है और सरकार की आमदनी को इस प्रकार घटाया जाता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि वहां सड़कों पर लगे दरख्तों को कटवाने की आवश्यकता ही नहीं थी। सभापति महोदया, दूसरा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर से जैतारण और जयपुर व नीमाज के पास सभापति महोदया, उस सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं जिनकी सालाना १५-२० हजार की आमदनी होती है। पी० डब्ल्यू० डी० ने उनको समाप्त कर दिया, वह उनकी सम्पत्ति नहीं है। मैंने कई बार पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित किया कि वह भूमि सरकार की है, पी० डबल्यू० डी० की नहीं है लेकिन उन वृक्षों की आमदनी भूतपूर्व जागीरदार ले रहे है। भूतपूर्व जागीरदार उनका फायदा उठा रहे हैं। सरकार मालूम नहीं क्यों नहीं ध्यान देती है, मुझे आश्चर्य होता है। सभापति महोदया मैं एक और निवेदन करूंगा कि सड़कों का जहां निर्माण हो चाहे वह सड़क किसी के माध्यम से बनाई जाय और किसी वक्त बनाई जाय, उनको अधूरी न छोड़ी जाय, उनको पूरी बनाई जाय चाहे वे सड़क टूटी-फूटी हो, उनकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। सभापति महोदया, आपको आश्चर्य होगा व्यावर से लाम्बिया की सड़क सन् १९६१ के अन्दर बनी थी— आज उसको कितना साल हो गया— ७ साल हो गये। आज तक वह अधूरी पड़ी हुई है। ७ साल तक सड़क अधूरी पड़ी रहती है। व्यावर से भावड़ा रोड़ है वहां पर केवल ५ मील सड़क बन पाई है सभापति महोदया, मेरा निवेदन करना यह है कि इन सड़कों को पहले पूरा करवाया जाय। नई सड़कें हाथ में ले सकते हैं लेकिन पुरानी को नहीं छोड़ें। एक तरफ एक काम शुरू कर दिया और दूसरी तरफ दूसरा कार्य शुरू कर दिया इससे कोई विकास नहीं होगा। जो सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं जिनके लिए पहले पैसा खर्च कर दिया गया है अगर उनको समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो जो कच्चा रास्ता रह जाता है उससे वापिस उस सड़क की दुर्दशा हो जाती है। इससे तो अच्छा यह

(श्री शंकरलाल)

होता कि उन सडकों का काम चालू ही नहीं किया जाता। सभापति महोदया, मैं एक और निवेदन करूंगा फेमिन की सड़कों के बारे में। फेमिन होता है जब काम शुरू हो जाता है और फिर बाद में बन्द कर कर दिया जाता है। कई बार पी० डब्ल्यू० डी० को और रेवेन्यू की ऐजेन्सी को लिखा गया लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पी० डब्ल्यू० डी० ऐसे समझता है कि जैसे यह सड़कें ऐजेन्टों ने बनाई हैं और उस समय के लिए ही बनाई गई हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। फेमिन की सड़कें हैं, फेमिन के लिए बनाई गई हैं और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई वे किन्तु सभापति महोदया मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जनता के पैसे से बनाई गई हैं, यह उनका फर्ज है कि वे उनको पूरा करें। उदाहरण के तौर पर बताऊं पाली से सुमेरपुर तक जो सड़क बनी है, जेतपुरा से खोड़ तक जो सड़क जाती है वे सड़कें फेमिन में बनी हैं, पहले कच्चे रास्ते थे तो कच्चे रास्तों में किसान अपनी बैलगाडी अच्छी तरह से ले जा सकते थे, मोटरें भी जा सकती थीं पर फेमीन में हजारों रुपया उन सड़कों पर खर्च हुआ और आज वे सड़कें इस तरह से दांत निकाल रही हैं, अच्छा होता कि इससे तो वे सड़कें ही नहीं बनतीं। पी० डब्ल्यू० डी० से कहते हैं तो वे कहते हैं कि यह सड़कें तो फेमिन से बनीं हैं।

जैतावरण से देवरिया की सड़क केवल चार मील का टुकड़ा है, सभापति महोदया मैं आपकी मार्फत सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस सड़क का दो मील का टुकड़ा अधूरा पड़ा हुआ है, उस तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार की एक नीति मैं जानना चाहूँगा कि फेमिन में बनी सडकों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है। सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि जो सडकें फेमीन में मजदूरों को राहत देने के लिए बनाई जाती हैं, पर अधूरी रह जाती हैं तो सरकार को पहले उन सड़कों को हाथ में लेकर पूरा करवाना चाहिये।

सभापति महोदया, मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र जैतारण में काफी ऐसा इलाका है जो पहाड़ी इलाका है। रायपुर के इलाके में पहाड़ी क्षेत्र है। पहले पह इलाका अजमेर में था तो ब्रिटिश इलाका था, बाद में यह इलाका राजस्थान में आया। वहां पर वही सड़कें बनी हुई हैं जो अंग्रेजों के जमाने में बनी थीं, राजस्थान में आने के बाद उस इलाके में कोई सड़क नहीं बनी है। यह ऐसा इलाका है कि वहां डकैतियां होती हैं, कत्ल होते हैं पर वहा पहुंचने का जरिया नहीं है। उस इलाके की उपेक्षा की जा रही है, वहां सड़कों का कोई काम नहीं होता है।

इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इन अधूरी रोड्स को पहले हाथ में ले और जहां पहाड़ी इलाका है, जहां डकैतियां होती हैं, कत्ल होते हैं उन पहाड़ी इलाकों में सड़के नहीं हैं, वहां पर सड़कें बनाई जांय कई जगह सड़कों पर ऐसे खतरनाक मोड़ हैं कि एक्सी-

(श्री शंकर लाल)

डेन्ट्स होते रहते हैं, मामूली खर्च से उन मोड़ों को ठीक किया जा सकता है इसलिए उन मोड़ों को ठीक करवा करके ऐक्सीडेन्ट्स बचाये जायं, दरवाजे के ऊपर मोड़ है, वहां आये दिन एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं, थोड़े से खर्च से एक्सीडेन्ट्स को बचाया जा सकता है, उन मोड़ों को ठीक कराया जाय। नीमाज के पास वृक्षों का मामला मैंने रखा वहां मामूली सा मोड़ है, वहां एक्सीडेन्ट्स होते हैं, उस मोड़ को ठीक कराया जाय। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे कामों की ओर सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिये, ऐसे काम में, ऐसे मदों में पहले खर्च करे उसके बाद में दूसरे काम हाथ में ले।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री लादूराम सुलानियां : सभापति महोदया, अभी हमारी पार्टी का समय बाकी है.........

श्रीमती सभानेत्री : श्री नाथूराम।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदया, हमारी पार्टी का अभी बहुत समय बाकी है.........

श्रीमती सभानेत्री : मुझे सब मालूम है, मेरे पास सब के टाइम का रेकार्ड है, मैं बता दूंगी कि कितना समय बाकी है।

श्री विजयसिंह ; बताने की आवश्यकता नहीं है, समय बंटा हुआ है.........

श्रीमती सभानेत्री : मुझे बिलकुल पता है।

श्री विजयसिंह : आप रिमार्क पास करें कि बता दूंगी, हमारे पास भी पूरा रेकार्ड है कि किस-किस पार्टी ने कितना कितना समय लिया है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप आसन की प्रतिष्ठा का खयाल रखें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हमारी पार्टी ने कितना समय लिया है, यह भी हमें पता है, हमारे पास सब लिखा हुआ है।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज। श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम : (बागीडोरा) सभापति महोदया, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग के सम्बन्ध में है, उसके बारे में बोलना चाहता हूं इस पर व्यय के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं, जो व्यय किया जा रहा है ६८—६९ में उसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। बजट में १९६६—६७ में कुल २८०५ लाख रखा था, १०५१ लाख खर्चा हुआ, ६७—६८ में ३२६५ लाख कुल रखा गया था, उसमें से ११४० लाख रुपया खर्च हुआ। इसी तरह इस वर्ष ६८—६९ में कुल रकम ३२५६ लाख रुपया रखा गया इसमें १०३८ लाख रु० खर्चा है। पंचायत समिति बागीदुरा मूखियां गढ़ी में कोई प्रोविजन नही रखा गया है। जबकि हम इस वर्ष इस मद में १०३८ लाख रुपया खर्च कर रहे हैं मेरे

(श्री नाथूराम)

क्षेत्र बागीडोरा, भूखियां गढ़ी में जहां कि लाखों की तादाद में आदिवासी रहते हैं, जो शिड्यूल एरिया घोषित किया हुआ है, उसमें १०० रुपया भी इस बजट में नहीं रखा गया है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष जहां भयंकर अकाल था और दो तीन साल में लाखों रुपया खर्च हुआ तो खाली मिट्टी और पत्थर डाल दिये, जो वर्षा में बह गये, जो लम्बी सड़कें बनी हैं, उन पर कोई पुलिया नहीं बनी है इस तरह से तमाम पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। गत वर्ष भी मैंने इस पर प्रकाश डाला था, इस वर्ष भी मेरी मांग है कि गत वर्ष जो लाखों रुपया खर्च हुआ उसमें जाह जाह हजारों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। आपके पी. डब्ल्यू .डी. के जो कर्मचारी काम कराते हैं वे अनेक प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, घोटाले करते हैं। गत वर्ष गढ़ी पंचायत समिति में धमेन्द्र कुमार और गौरीलाल ओवरसियर के बारे में मैंने शिकायत की थी, उनके सम्बन्ध में आपने कोई जांच नहीं की, जो गरीब आदिवासी सड़कों पर मजदूरी करते थे उनका पेट काट कर, हजारों रुपया आपके अधिकारियों ने हजम किया, डिपार्टमेंट ने इस सम्बन्ध में शिकायत करने पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। मैं कहता हूं आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो वह पी.डब्ल्यू.डी. में है, जहां गरीब लोग सड़कों पर मजदूरी करने जाते हैं और दिन भर कस कर मेहनत करते हैं, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा ये अधिकारी बीच में ही खा जाते हैं और इस तरह से इन गरीबों का पेट काटते हैं, हम शिकायतें करते हैं पर मन्त्री महोदय उनको सजा देने के बजाय अपने उन अधिकारियों की रक्षा करते हैं। जो लोग गरीबों का पेट काट कर उनकी मजदूरी का पैसा खा जाते हैं वे राष्ट्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लाखों रुपया जो राजस्थान सरकार की तरफ से पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा खर्च होता है उसमें लाखों का घोटाला होता है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से एक कमीशन बैठाया जाना चाहिए और इसकी पूरी जांच कराई जानी चाहिए और जांच से जो दोषी पाये जाये उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये। इसलिए मेरी मांग है कि पी०डब्लू०डी० के द्वारा जो लाखों रुपया खर्च हुआ है, उसमें घोटाले हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिये।

डूंगरपुर—बांसवाड़ा माही नदी गुजरात की ओर बहती है, वहां वर्षा में रास्ते कट ऑफ हो जाते हैं। १९६३ में माही नदी पर पुल बनाने के लिये ५५ लाख रुपया मंजूर हुआ था पर चार साल में एक भी पैसा उस पर खर्च नहीं किया गया। कहा जाता है कि कडाना डेम की वजह से पुल कहां बनायें, डूंगरपुर से माही, बांसवाड़ा से माही, गलियाकोट के पास सड़कें जहां मिलती हैं, वह सड़कें कम्प्लीट हैं, दोनों तरफ सड़कें हैं, इस पुल की सर्वे भी पूरी हो गई पर अब वहां पर यह पुल न बनाकर इससे दस मील ऊपर माही पर पुल बनाया जा रहा है। बागीडोरा, गढ़ी तहसील और गलियाकोट के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब जहां पुल बनाने जा रहे हैं वहां एक तरफ वह पुल आ जाता है। हमें बताते हैं कि

(श्री नाथूराम)

वहां नदी भरी रहेगी इसलिये पुल नहीं बनाया जा सकता । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों को सुविधा के लिये पुल बनाया जा रहा है या केवल पुल बनाना है इसलिये पुल बनाया जा रहा है। हमारे उस एरियाको राष्ट्रपति ने शिड्यूल एरिया घोषित किया है,शिड्यूल एरिया के लोगों की भलाई के लिये यदि कानून में पूर्तियां नहीं हों तो उन लोगो की भलाई के लिये सेन्टर के कानून को भी चेंज कर दिया जा सकता है। सरकार को हानि भी हो और शिड्यूल एरिया के लोगों का उससे हित होता हो तो उसको चेंज किया जा सकता है। इस पुल के लिये पहले जहां सर्वे हुए हैं वहां इस पुल को बनाने से शिड्यूल एरिया के लोगों को बहुत अधिक लाभ है और अब जहां यह पुल बनाने जा रहे हैं उससे उन लोगों को नुकसान है क्योंकि अब पुल दूसरी ओर बनाया जा रहा है। नई जगह पुल बनाने से पहले जितनी सड़कें बागीडोरा, गढ़ी तहसील गलियाकोट की बनाई गई हैं और लाखों रुपया उन पर खर्च हुआ है वह फालतू जायगा और जो अब ऊपर पुल बनाना चाहते हैं वहां पर दोनों ओर नई सड़कें बनानी पड़ेंगी, इससे यह लाखों रुपयों का खर्चा होगा और पहले सड़कों पर लाखों खर्च किया गया है, जो सड़कें बनी हुई हैं, वह सब लाखों रुपया व्यर्थ जायगा। जहां पहले पुल का सर्वे हुआ उस जगह पुल बनाया जाय तो ज्यादा सड़कें नहीं बनानी पड़ेंगी और यदि उस जगह पुल नहीं बना कर उस जगह से दस मील ऊपर पुल बनाया जाएगा तो पुल पर जितना खर्चा आयेगा उतना सड़कों पर खर्चा बढ जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां पर पहले सर्वे हुआ है, उसी जगह माही पर पुल बनाना चाहिये।

गलियाकोट तीर्थ स्थान है वहां पर सारे हिन्दुस्तान से लोग आते हैं, हिन्दुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी वहां पर आते हैं, यहां पर अगर माही का पुल न बनाया गया तो यात्रियों को आने जाने में बड़ी असुविधा होगी।

आज राजस्थान में सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, नदियों पर पुल नहीं बनाये जाते हैं, बांसवाडा से गलियाकोट बस चलती है, वह सड़क भी कच्ची बनी हुई है, इस वजह से गर्मियों में बसें रास्ते में पड़ी रह जाती हैं और यात्रियों को बड़ी भारी असुविधा होती है......

(५.२० म० प०)

(श्रीपूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

गढ़ी से गलियाकोट १० मील का टुकड़ा है, गढ़ी हाई स्कूल में सैकड़ों लड़के परीक्षाएं देने जाते हैं, बाहर के यात्री भी कारें लेकर आते हैं पर गलिया कोट पहुंचने के लिये उनकी गाड़ियां नहीं जा सकती, ऐसी वह सड़क खराब है।

मैंने माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन किया इस साल के बजट में इसके लिये पांच रुपया भी नहीं रखा गया। जब कि आपका लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन आप थोड़े से टुकड़े के लिये पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। रिलीफ की जहां भी सड़कें बनी हैं वहां धन का दुरुपयोग हुआ फिर भी आपको छोटी-छोटी पुलियाओं के लिये प्रोवीजन रखना है। इससे आपने जो लाखों

Page No. 159

(श्री नाथूराम)

रुपया खर्च किया है उसका फायदा हो सकेगा ।

जहां—जहां से आपने सड़कें निकाली हैं उसके लिये हमने राय दी सहयोग दिया खेतों के बीच से सड़कें निकाली गई लेकिन जिन लोगों के खेतों के बीच से सड़कें गई हैं उन लोगों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया । पी० डब्लू० डी० विभाग की तरफ से जांच नहीं हो रही है उस जगह का किसान जो एक फसल या दो फसल जमीन पर पैदावार करता है उसके यहां से सड़क निकल गई, सड़कें यदि सीधी निकली हैं तो पैसा भी कम खर्च होता है लेकिन मोड़ से निकालते हैं तो ज्यादा खर्च होता है । अभी तक उन गरीब किसानों को मुआवजा नहीं मिला । सड़कें जो बनती हैं उसके लिये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बननी चाहिये सड़कों की जांच होनी चाहिये मुआवजा जिनको नहीं मिला उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलवाने की मेरी मांग है ।

बांसवाड़ा जिला में कई जगह कुछ मील का टुकड़ा बिना पूरा किये छोड़ दिया इसलिये जो टुकड़ा अधूरा है उसको पूरा करवाने के लिये मेरी मांग है । पंचायत समिति मूखिया है जिससे लगता हुआ गुजरात का बोर्डर है उसके दक्षिण हिस्से में कुछ भी सड़कें नहीं हैं । उस तहसील की ४० हजार की जनसंख्या है बागीडोरा तहसील पर जाने के लिये वहां अनास का पुल है वह कम्पलीट नहीं हुआ है । इसलिये मेरी यह मांग है कि वह आदिवासी इलाका है वहां के आवागमन के रास्तों को सुधारने के लिये बजट में प्रोवीजन रखें यही मेरी मांग है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम राजोरिया ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनको प्रस्तुत करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में जो सुनते आ रहे हैं कि इस विभाग में घोटाले है रिश्वतखोरी के काम होते हैं इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों और मैंने भी कई बार सरकार का ध्यान लाने की कशिश की है लेकिन इस बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । कई बार ऐसे सुझाव दिये हैं कि ये घोटाले कर्मचारी ठेकेदारों से मिल कर करते हैं । तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार श्रमिक सहकारी समितियों को ठेके क्यों नहीं देती ? जबकि सरकार सहकारिता को बढ़ावा देना चाहती है । राजस्थान के मजदूर को मजदूरी देनी है तो । लेकिन यह सब कुछ नहीं होता ठेकेदार लोग अधिकारियों से मिल करके अपना परसेन्टेज देकर उनसे ठेका ले लेते हैं जितने भी ठेके होते हैं उन सब में अधिकारियों का परसेन्टेज चलता है । अगर इससे सरकार को बचना है तो मेरा सुझाव है जो इन्जीनीयर बेकार हैं जिनको सरकार नौकरी नहीं दे रही है वित्त मन्त्री जी ने भाषण में कहा था कि उनको ठेकेदारों के यहां रखेंगे । मेरा निवेदन है कि उन इन्जीनियरों को ठेकेदारों के बजाय श्रमिक सहकारी समितियां जो हैं उनके अन्दर लगाया जाय

Page No. 160

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

जो ठेकेदारों को काम दिया जाता है वह उनको न देकर श्रमिक सेवा सहकारी समितियों को देना चाहिये। इससे श्रमिक व इन्जिनियर दोनों को रोजगार मिलेगा। सरकार का पैसा भी बचेगा काम भी अच्छा होगा। ठेकेदारों से जो मुनाफा अधिकारी खाते हैं वह बच जायगा, इस तरह से श्रम समितियां पनपेंगी, भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जायगा। इसके अलावा आज क्या होता है ठेकेदार मजदूरों का पैसा खा जाते हैं मजदूरों का कोई संघ नहीं होता जो कि केस करके पैसा वसूल कर। अगर ठेकेदार को ठेके में मुनाफा नहीं होता, मजदूरी के पैसे रोक लेते हैं। मजदूरों के साथ यह भी अन्याय होता है। श्रम सहकारी समितियों को ठेका देने से वह भी रुक जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे इलाके की सड़कों के बारे में निवेदन करूं जमवा रामगढ़ और दौसा एरिया इन इलाकों के बारे में मैं कहता आया हूँ कि यहां कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। अगर सरकार कुछ करना चाहे तो मेरा सुझाव है। दौसा इलाके में कुछ सड़कें अधूरी पड़ी हैं अतः मेरा निवेदन है कि दौसा की सड़कों की तरफ भी सरकार ध्यान दे।

आन्धी से बोरदा तक सड़क बनाई जावे यह छोटा सा टुकड़ा है। इस रास्ते से जयपुर से सवाई माधोपुर सर्विस गाड़ियां चलती हैं। बरसात में आवागमन के रास्ते रुक जाते हैं इसलिये इस टुकड़े को बनवाया जाना चाहिये।

एक रोड़ नायला से बूझ और खवा होता हुआ नफटी घाटी रोड से मिलाया जाय उसके बारे में सदन से कई बार कह चुका हूं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो नायला बूझ और खवे का रोड है इसको शीघ्र बनाया जाय। आंधी गांव में गन्ने की पैदावार इतनी होती है, लगान आपको बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए जिस जगह से आप इतनी लगान वसूल करते हैं वहां की जनता को सुविधा मिलनी चाहिए।

दौसा से कुंडलगढ़ की सड़क पर वहां पर करीब ५ बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान कभी नहीं गया है, भैसरा, झिडोली कई पंचायतें इस बीच में पड़ती हैं, आपको इस टुकड़ी की ओर ध्यान देना चाहिए।

दिल्ली का जो नेशनल हाई वे है जयपुर से निकला लालडूंगरी होकर निकला है वह वैसो की वैसी पड़ी है और उससे क्या होता है कि शहर से जितनी ट्रकें है, शहर और बस्तियों से होकर आती हैं और सड़कें खराब हो रही हैं, खड्डा है मोती कटला से बाहर तो जो सड़क आपने नेशनल हाई वे दिल्ली की सीधी निकाली है उस सड़क को इस साल में पूरा किया जाय ताकि उन बस्तियों को होकर न आएं कई ट्रकों की दुर्घटनायें हुई हैं अगर बच्चे नीचे आ गए हैं। सरकार की तरफ से ध्यान देना चाहिए।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला डूंगरपुर से आसपुर, साबला, डूंगरपुर से सतुना, डूंगरपुर से साग-

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

वाड़ा, सागवाड़ा से सबला, ये सड़कें लगभग १५ साल से बन रही हैं लेकिन अभी भी सड़क अधूरी पड़ी है और उन सड़कों पर जहां नाले पड़ते हैं उन नालों पर अभी तक पुलिया नहीं बन रही है। इससे बरसात के दिनों में बसें तीन दिन रुक जाती हैं और सवारियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। पता नहीं कि विभाग के अधिकारियों की ढिलाई है, १५ साल से काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। जहां पर सड़कों का मुड़ाव वहां आवश्यक नहीं है, जहां आवश्यक होता है वहां काम नहीं किया जाता है। डूंगरपुर एक पिछड़ा हुआ जिला है और आदिवासी एरिया है, वहां पर सड़कों की कमी है और उन सड़कों के लिए निगरानी बराबर नहीं होती है इसलिए आप से प्रार्थना है कि उन सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर जल्दी से जल्दी उनको पूरा कराया जाय। साथ ही साथ डूंगरपुर से मांडव माइन्स जो बहुत बड़ी खान है उस खान से पारवा जो सड़क जाती है वह कच्ची है। उसके आस-पास १५-२० गांव पड़ते हैं। उन गांवों में आने जाने के लिये १५ मील और जाना पड़ता है, तब उनको सर्विस मिलती है। तो कच्ची सड़क को माइन्स से मांडव रोड तक मिलाने के लिए उस सड़क का सर्वे कराया जाय और जल्दी से जल्दी चालू कराने के लिये दे दिया जाय। इसके साथ अकाल राहत कार्यों में डूंगरपुर जिले में आदिवासी एरिया में कई सड़कें बन रही हैं जिस पर हजारों रुपए खर्च हुए हैं लेकिन उन सड़कों में जहां-जहां अधूरे काम पड़े हैं उन्हें अभी तक नहीं कराया जा रहा है इसलिए वे सड़कें बेकार होने वाली हैं। इसके साथ-साथ उन सड़कों पर जहां जहां नाले पड़ते हैं कम से कम विभाग की तरफ से छोटी पुलिया बनाई जाय तो सड़कों पर जो हजारों रुपया अकाल में खर्च किया है, वह बेकार नहीं जायगा, सड़कें बराबर बनी रहेंगी।

इसके अलावा डूंगरपुर से पीपलदा और पीपलदा से खेमपुर धावड़ी अच्छी सड़क है और उधर एरिया में कई गांव पड़ते हैं, उनमें आवागमन की दृष्टि से तकलीफ उठानी पड़ती है। उस सड़क पर काम कराया जाय और जहां पर पुलिया नहीं बनी हैं वहां पुलयिा बनाई जायं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आवागमन की दृष्टि से सुविधा मिल सके और तकलीफ दूर हो। मेरा खास तौर से आपके द्वारा निवेदन है कि अकाल राहत द्वारा जितनी कच्ची सड़कें बनी हैं, वहां छोटी छोटी पुलिया बना देंगे तो वे सड़कें सुरक्षित रहेंगी और लोगों को सुविधा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह। (अनुपस्थित) श्री विजयसिंह रावत। आप कृपया समय की सीमा में रहें।

श्री विजयसिंह रावत : (नसीराबाद) मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री का मेरे क्षेत्र के अन्दर जीतनी भी कच्ची सड़कें बनी हैं उनकी ओर, ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे क्षेत्र के अन्दर जितनी सड़कें पिछले आम चुनावों में बनाई गई हैं और वह पैसा जितना बरबाद किया गया है, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन जितना धन उन सड़कों पर खर्च किया गया है, उनकी

Page No. 162

(श्री विजयसिंह रावत)

हालत बारिश होने के बाद खराब हुई है और उसके कारण वहां के काश्तकार जो अपना अनाज गाड़ियों द्वारा घर पर नहीं ले जा सकते जो मिट्टी डाली गई वह टूट-टूट कर जगह-जगह नाले बन गये तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा इन सड़कों के आसपास कंकर जो कन्क्रीट करने के लिये रा मेटीरियल इकट्ठा किया गया है उसमें कम से कम डामर नहीं कराए तो रा मेटीरियल उस पर लगा दिया जाय, कन्क्रीट कर दिया जाय जिससे बरसात में खराब न हो और किसान को असुविधा न हो।

लोरवाड़ा से मटियानी सड़क अकाल राहत कार्य में बनी, उसकी बुरी हालत है, दोनों तरफ कान्क्रीट पड़ा है जगह-जगह। मैं चाहूंगा कि कम से कम कान्क्रीट को उस पर लगा दिया जाय ताकि वह सड़क काफी वर्षों तक चल सके और वहां के किसानों पर किसी प्रकार की तकलीफ न हो। गोला से जेठाना सड़क भी खराब है। जेठाना से डामर की सड़क आती है। इसको भी कान्क्रीट द्वारा कच्ची सड़क बनाई जाय। अजमेर से रामसर वाया श्री नगर होकर नसीराबाद के लिए मुझे दुख से कहना पड़ता है कि श्रीनगर-से नसीराबाद सड़क के बीच में बालू रेत के टीबे बन गये हैं, ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक लगभग ५ महीने से जाम है। जहां तक मुझे याद है और जानकारी है मैंने निर्माण मंत्री को डी० ओ० लिखा था कि ट्रैफिक जाम है, इस पर जो ठेका दिया गया वहां के इंजीनियर ने मिलकर ठेकेदार से मिलकर टेंडर इन्वाइट नहीं किया, ठेके को कैंसिल किया उसके बाद अपनी योजनानुसार दूसरे ढंग से बनवाना शुरू किया है। वहां की ट्रैफिक को खोलने के लिये जिस ढंग से आप बनाना चाहते हैं, काम को जल्दी से जल्दी किया जाय जिससे किशनगढ़-नसीराबाद बीच में आता है वह क्लीयर हो जाय। टूट-फूट ज्यादा है, जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा किसी गर्भवती स्त्री को अस्पताल ले जाना हो और उस सड़क से ले जाना पड़े तो अस्पताल में पहुंचने से पहले ही रास्ते में डिलीवरी हो जायगी। इस हालत को देखते हुए मैं चाहूंगा कि मरम्मत के लिए जो पैसा आता है, उस पैसे को यहां लगाया जाय और सड़क का ठीक कराया जाय।

दूसरी सड़क कानुपुरा से तैयार की है इसमें तीन-तीन, चार-चार और पांच पांच फुट के गड्ढे हो गये हैं।

पुष्कर घाटी से कनास तक की सड़क है। बीच में तरेर पड़ गई है। इसको ठीक करावें।

अजमेर जिले में मरम्मत के नाम के पैसों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने विभाग के कार्य में लिया है अक्टूबर ६७ से दिसम्बर तक ६० हजार का पेमेंट मरम्मत के नाम का विभाग ने अपने काम लिया है। उसकी जांच की जानी चाहिये। इससे सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी और हालत और भी खराब हुई, बड़ी दुर्दशा हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : दुर्दशा का मतलब खराब है।

श्री विजयसिंह रावत : इस विभाग में, नवाब साहब मानें या न मानें इतना भ्रष्टा-

(श्री विजयसिंह रावत)

चार फैला हुआ है जितना किसी विभाग में नहीं है। पिछले दिनों कहा था धौलपुर उदयपुर, सीकर तथा अन्य सड़कों के बारे में पी. एस. सी. की रिपोर्ट में भी जिक्र आया है। मैं कहूँगा कि इंजीनियर और कन्ट्राक्टरों में मिलीभगत है। इसके प्रति जागरूक रहकर कोई रास्ता निकालें जिससे राजस्थान में जो कच्ची सड़कें हैं उन पर कन्क्रीट तो करवा दें डामर न करा सकें तो। इससे गाडियां चलाने वाले किसानों को असुविधा न हो और धन का दुरुपयोग न हो इतना ही कहकर अपने कटमोशन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में अधिक एरिया पहाड़ी है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात सड़कों पर पुलियाओं के नहीं बनने से है। मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार ने काम बहुत किया है और रोड के लिये भी काम किया है। लेकिन गर्मियों में तो काम चल जाता है पर बरसात के दिनों में पुलियों के न होने से न गाड़ी आ जा सकती है न घोड़ा ही आ जा सकता है। ऐसी जगहें हैं।

उदयपुर में सराड़ा–खेरवाड़ा–गोगुन्दा घांटोल ऐसे एरिया हैं जहां सड़कों में सरकार का काफी रुपया लगा है। पर लोगों को पुलियोंके अभाव में उसका फायदा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए।

मेरा क्षेत्र गोगुन्दा–कोटड़ी के लिए पहले भी मन्त्री महोदय से निवेदन किया था और मुझे इस बात की तो खुशी है कि वहां सड़कें बनी हैं पर पुलिया नहीं होने से बरसात में कठिनाइयां आती हैं और घूम कर चक्कर खाकर सीरियासल होकर मारवाड़ होकर आना पड़ता है। हमारा जिला उदयपुर पड़ता है। गरीब आदमी हैं गांवों में वे अगर किसी काम से उदयपुर जाना आना चाहें तो बरसात में नहीं आ जा सकते आसानी से।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आगादी से कोटड़ी जाने वाली सड़क पर मैपुर के पास एक नदी है उस पर पुलिया बंधवा दी जाय। इसके वाद तो गाड़ी आ जा सकती है और बरसात में भी रुकावट नहीं होगी और हमारे कोटड़ी से आने जाने वाले लोग आगादी होकर सीधे आ सकते हैं।

आगे गोगुन्दा से कोटड़ी राणकपुर एक सड़क है। राणकपुर एक बड़ा तीर्थ स्थान है। इस पर रोड बन जाने से मारवाड़ आने का रास्ता खुल जावेगा। और इधर कोटडी आगादी से उदयपुर का सीधा रास्ता हो सकता है। राणकपुर का काम चल रहा है पर इतना धीमा है कि लगता है बरसों में पूरा होगा। फिर राणकपुर सड़क के लिये सरकार ने चालीस हजार रुपये रखा है। इसमें कमी रहेगी। और रुपया इसमें लगाना चाहिये। इस एरिया में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। उनको आने जाने की दिक्कतें रहती हैं। ये सड़कें हो जाने से उनको सुविधा हो सकेगी और इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इन सड़कों की तरफ ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इस एरिया को ठीक करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम आगरी

श्री दौलतराम आगरी : (देसूरी-सु.) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने की अनुमति दी, इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

बाली से देसूरी २४ मील के एरिया में सड़क डामर की है बाली उपजिलाधीश का हैडक्वार्टर है देसूरी पर तहसील हैडक्वाटर है। रास्ते में पुलिया नहीं बनने से बरसात में चार चार दिन रास्ता बन्द हो जाता है। डाक भी नहीं आ जा सकती। तो मन्त्री महोदय से निवेदन करुंगा कि उस सड़क पर जल्दी से जल्दी पुल बनाने की व्यवस्था करें।

इसके अलावा बूसी से नाडौल बूसी से देवली तक ११ मील का टुकड़ा बन गया है। पर उसमें अब गढ़े पड़ गये हैं। साइकिल सवार भी आ जा नहीं सकता उस सड़क को जल्दी से जल्दी ग्रेवल रोड बनावें। फिर डामर रोड करें। व साथ में देवली से नाडौल तक सड़क का निर्माण करावें।

इसके आलावा उपाध्यक्ष महोदय, राणी से पाली बस रूट है। कच्चे रास्ते की वजह से बरसात में आवागमन रुक जाता है। वह सड़क वाया चाचोड़ी होकर पाली जाती है उसको तैयार करें।

और उपमन्त्री जी का चाचोरी फार्म भी उस पर है। मुझे आश्वासन भी दिया था उसे बनाने कराने का।

श्री माधोसिंह भंसवाड़ा : मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया। आपने मांग की थी।

श्री दौलतराम आगरी : वह तेतीस मील का टुकड़ा है। मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे उसको बनावें।

इसके अलावा फुलाद से देसूरी ३३ मील का टुकड़ा है फिलहाल जो पंचायत समिति और जिला परिषद् द्वारा मांग की जाती है वह केवल ६ मील की फुलाद से जोजावर तक अभी बनी है। तहसील हैड क्वार्टर से जोडने के लिये २७ मील का टुकडा हाथ में लेकर तैयार करें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर लाल

श्री शंकरलाल (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे भी बोलने की इजाजत दी। अर्ज यह है कि वैसे देखा जाये आजादी के बाद हमारी सरकार ने सार्वजनिक निर्माण किये हैं और हो रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्क यह है कि जो काम हो रहे हैं उन कामों की ओर मन्त्री महोदय का दृष्टिकोण होना चाहिए कि कौन सा काम कितना हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना पानी में बह गया है या उसका यूटीलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस विषय के ऊपर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वैसे तो यह ठीक बात है कि हमें क्षेत्रीय भावना को लेकर नहीं चलना चाहिए, कि मेरे क्षेत्र में यह होना चाहिये, अमुक क्षेत्र में ज्यादा काम हो गए और हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ जिस तरह से जो काम होते हैं बजट के अनुसार ही होने चाहिए। यह तो राजस्थान आजादी के पहले टाइफाइड का बीमार था और जब अच्छा हुआ है तो भूख लगी है। उस भूख को कांग्रेस ने ही मिटाई है और कांग्रेस ही मिटायेगी। अब सवाल

(श्री शंकरलाल)

हमारे सामने यह आ जाता है कि जो बजट हमारा पेश होता है और जो बजट हम पेश करते हैं उसमें इक्विल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए कि किस जिले में कितना पैसा मिलना चाहिए, किस में कितना खर्च करना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चित्तौड़ जिले की उपेक्षा की गई है। चित्तौड़ का क्षेत्रफल सड़कों के लिहाज से देखा जाये तो बहुत ही लम्बा है और ऐसा क्षेत्र है कि यह जिला दूसरे जिलों से जुड़ा हुआ नहीं है जब कि पहली पंचवर्षीय योजना में ऐसा प्रावधान था कि हर तहसील के जिलाहैड क्वार्टर से जोड़ दिया जायेगा। तो मैं अर्ज करूं कि चित्तौड़ से बड़ी सादड़ी अगर हम सीधे जाते हैं तो ४५ मील का फासला है लेकिन वर्षा के मौसम में मावली होकर जाना पड़ता है। बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी सन् ५२ में सड़क बनी है और अभी तक उसकी पुलियायें नहीं बनी हैं तो बरसात के दिनों में कोई आदमी छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी पेश के ऊपर आता है तो वह मावली नीमच होकर आता है। डूंगला से मंगलवाड़ ८ मील का टुकड़ा है वह अभी तक पड़ा हुआ है। अगर यह टुकड़ा बन जाता है तो काफी सहूलियत मिल जाती है। इसी तरह से बिनोता से जलोदा ६ मील का टुकड़ा है और इसको बना दिया जाता है तो बड़ी सादड़ी का संबंध इससे हो सकता है और छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी पर पुलिया बन जाती है तो यह सारी रोड कम्प्लीट हो जाती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सादड़ी सोना काण्ड वाली ही है ?

श्री शंकर लाल (छोटीसादड़ी) — प्रतापगढ़ की पुलिया इन्कम्पलीट पड़ी है, निम्बाहेड़ा से छोटी सादड़ी की पड़ी हुई है, निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़ की इनकम्पलीट पड़ी हैं चित्तौड़ से कपासन इनकम्पलीट पड़ी है और चित्तौड़ से लाडपुरा की इन-कम्पलीट हैं, कपासन से मादसोड़ा इनकम्प-लीट पड़ी हैं. कपासन से राशमी, राशमी से गंगरार और आकोला से फतहनगर और मंगलवाड़ चौराह से निम्बाहेड़ा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में काम हुआ था यदि आज उनका निरीक्षण करें तो उसमें तीन-तीन और चार-चार फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। फतहनगर ऐसी मन्डी है कि जहां हजारों गाड़ियां आती हैं। एक रोज मैं अपने क्षेत्र में गया था जीप लेकर तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वहां जीप फंस गई थी। इस प्रकार की हालत उस सड़क की है तो कम से कम मैं यह निवेदन करूंगा कि बड़ी सादड़ी से इस जिले को जोड़ने के लिए जो बिनोता से जलोदा का ६ मील का टुकड़ा है, मंगल-वाड़ के चौराहे से निम्बाहेड़ा और मंगल-वाड़ से डूंगला इनकम्पलीट है इसको कम्प-लीट करा दें। दूसरे कपासन से मादसोड़ा वाली सड़क में भी थोड़ा पैसा और खर्च हो जायगा तो आपका जो पहले का पैसा खर्च हो गया है उसका पूरा उपयोग होने लग जायगा।

इसके अलावा दूसरी और अर्ज करूंगा कि जितने भी अकाल राहत कार्य शुरू हुए हैं उनमें मिट्टी डलवा दी वह पानी में बह जायेगी इसलिए जितना काम शुरू हुआ है उसको पूरा करा दो तो अच्छा रहेगा और

(श्री शंकरलाल)

मन्त्री महोदय का ध्यान उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आकर्षित करना चाहूंगा कि रोड्स के मामले में चित्तौड़ जिले की उपेक्षा नहीं करें। हम चित्तौड़ जिले वाले ऐसे हैं कि जो ७ कांग्रेसी आये हैं इसलिए खुदा के नाम पर हमारे जिले को भी थोड़ा और दो।

श्री उपाध्यक्ष : ६ बजे मन्त्री महोदय का उत्तर शुरू होगा। श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसको कि भारत सरकार ने भी बैकवर्ड घोषित किया है। आज तक २० वर्ष के बाद वहां पर जो काम होने चाहिए थे वह नहीं के बराबर हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो सड़कें ली गई थीं उनको अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि उनके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है। इसी के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां टोडा भीम से घाटी पड़ती है मेंहदीपुर के बालाजी के लिए उस रूट को बनाने में सरकार का लाखों रूपया खर्च हो गया लेकिन आज तक वह घाटी पूरी नहीं हो पाई है और उसके कारण से वहां पर जो डाइरेक्ट रूट से मिलने वाली थी उस रूट पर अभी तक कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। इसी के साथ-साथ सवाई माधोपुर के अन्दर हिन्डोन तहसील के अन्दर घमान कोलेट थी उसमें पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने उस पर काम किया और उस काम के साथ ही साथ मिट्टी डालना शुरू किया और जिस समय मिट्टी डाली जा रही थी उस समय तो इतनी जल्दी की गई थी कि वहां के काश्तकारों की फसलें जो खड़ी हुई थीं उस खड़ी फसल के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक उन किसानों को न तो मुआवजा दिया गया और उस सड़क को देखा जाय तो सिवाय मिट्टी के २० वर्ष गुजर जाने के बाद भी कान्क्रीट या मिट्टी भी नहीं पटकी है। हिन्डोन से कोटरी जाने वाली सड़क है इसी डिपार्टमेंट को वहां से लाखों रूपया रायल्टी का वसूल होता है। पत्थर की खानों के लिए वह सड़क गई है। माननीय मन्त्री महोदय भी कुछ समय पहले निरीक्षण करके आये हैं। वह सड़क ऐसी है कि जिससे लाखों रूपये की आमदनी इस सड़क से होती है लेकिन सड़क की हालत को देखा जाय तो यह महसूस होता है कि जो सड़क लाखों रूपये की आमदनी हर साल इस सरकार को देती है तो उसकी हालत इस प्रकार की है कि ५-५ और ६-६ फुट के गड्ढे उस सड़क में मिलेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ हिन्डोन से भरतपुर जाने वाली जो कि एक जिले से दूसरे जिले को मिलाती है उसको देखा जाये तो उसकी हालत इस प्रकार से है कि कोई रोड पर चलना चाहे या अपनी गाड़ी या बस ले जाना चाहे तो जा नहीं सकता। जितनी भी बसेस हैं वह रोड पर नहीं चलकर उसके आसपास या बाजू वाली पटरी पर वह चलती हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, आज इन सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो गयी है कि सरकार आंखें मूंदकर सोई है। सड़कों के बनाने के बारे में हमेशा लाखों

(श्री श्रवणलाल)

रुपया खर्च करती है लेकिन आज भी सड़कों को देखा जाये वह क्षेत्र जो कि एक डकैत एरिया है जहां महिने, दो महिने में १० डकैतियां पड़ जाती हैं अगर उन सड़कों को इस प्रकार से रखा गया तो वहां पर डकैतियों की भी संख्या ज्यादा बढ़ती चली जायेगी...

(६ म. प.)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सड़कों पर जहां पर कि डकैतों के मसले बहुत ही गम्भीर रूप से आये दिन बने रहते हैं जल्दी से जल्दी और इमीजियेटली जिस प्रकार से भी सहूलियत हो वर्क करवाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ जो सड़कें जिला परिषद के द्वारा या पंचायत समितियों के द्वारा या पहले जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे उनके द्वारा बनाई गई थीं उनकी हालत बड़ी ही खस्ता हो रही है। मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि जो सड़कें इतने लाखों रुपयों के खर्च होने पर बनी हैं उन पर मिट्टी और गिट्टी नहीं डलवाने से वे बरबाद हो रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनकी सम्हाल नहीं की तो सड़कें लाखों रुपयों की लागत से बनी हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने की बनी हैं उनकी हालत खराब हो जायगी इतनी कि उनकी पूरी की मरम्मत करवानी पड़ेगी या उनको दुबारा बनवाना पड़ेगा जिसमें लाखों रुपया इनवेस्ट करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़कें पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने की बनी हुई हैं उन पर थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण सड़कें ठीक हो सकती हैं और आने-जाने के साधन बड़े सुगम हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ-साथ हमारे यहां जो हिन्डोन के अन्दर जो स्टेशन से शहर के लिए रोड आती है वह पी० डब्ल्यू० डी० की रोड़ है। वहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्राफिक इतना अधिक चलता है ट्रकों और बसों का जिसके कारण एक्सीडेन्ट होते हैं। इसलिए आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इतना लम्बा एरिया नहीं है और सिर्फ दो मील का टुकड़ा है अगर उसको सही ढंग से कुछ और चौड़ी कर दी जाय तो यह जो एक्सीडेन्ट्स होते हैं वे नहीं होंगे।

इसके साथ-साथ मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि ये सड़कें जिस प्रकार से खराब हो रही हैं और उन पर आज तक २० साल के बाद भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है उन पर थोड़ा ध्यान देकर पूरा करवाने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय !

श्री लालचन्द वैद (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनिट का समय चाहता हूं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय !

श्री उपाध्यक्ष : श्री लाभचन्द बेंद !

श्री लाभचन्द बेंद (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा नवाब साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि रतनगढ़ से सालासर की सड़क जो अधूरी पड़ी हुई है उसको पूरी करवा दी जाय तो बहुत अच्छा रहेगा । उससे दो काम होंगे । एक तो यह है कि सालासर जो तीर्थ स्थान है जहां पर आसाम से लोग चल कर आते हैं उनको वहां जाने में सुगमता होगी, और जयपुर से जाने वाले, सरदारशहर और सुजानगढ़ वालों को सबको उससे आराम मिलेगा ।

दूसरी बात यह है कि चूरू जिले के अन्दर जाने वाली जो सड़क बनी हुई है वह अधूरी पड़ी हुई है उस पर डामर बिछा दी जाय तो बहुत अच्छा रहेगा ।

यह कहकर मैं इसको समाप्त करता हूं ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार के समस्त विभाग नुकसान में रन कर रहे हैं वहां राजस्थान का पी० डब्ल्यू० डी० का विभाग ही ऐसा है जो कि जितना खर्च करता है उससे अधिक पैदा करता है । राजस्थान में दो करोड रुपये नई सड़कें बनाने के लिए हैं और लगभग डेढ़ करोड़ रुपया सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार के बजट में निश्चित है । मैं इस पर निवेदन करूंगा कि रोड टैक्स से लगभग दो करोड़ रुपया राजस्थान को वापिस टैक्स के रूप में मिल जाता है इसलिए पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि आप राजस्थान की अधिक से अधिक आय को सड़कों पर खर्च करें जिससे कि रोड टैक्स के आधार पर अधिक से अधिक राज्य कोष में मिल सके ।

दूसरा, जो राजस्थान सरकार की गलत नीतियां हैं मैं उनका विरोध करता हूं । यह पी० डब्ल्यू० डी० का सड़कों का जो बजट है वह सारे राजस्थान में इक्वली डिस्ट्रिब्यूट नहीं किया जाता है, और राजनैतिक आधार पर पोलीटिकल आधार पर कार्य किया जाता है । जब कि हिन्दुस्तान और राजस्थान में डेमोक्रेसी है तो आप निश्चित मान कर चलिये कि राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर जो आज शासन में बैठे हुए हैं वे अपोजिशन में आजायेंगे और जो आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं वे शासन में आ जायेंगे । इसलिए शासनारूढ़ दल का सदस्य जीतकर आता है वहां तो आप काम करवाते हैं और जहां शासनारूढ़ दल का सदस्य पिट जाता है उस क्षेत्र की आप उपेक्षा करते हैं । यह बुरी हालत है । प्रजातन्त्र के अन्दर यह एक प्रकार से गलत तरीका है । वह लोकतन्त्र के लिए खतरा है । इसलिए माननीय मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि आपको क्षेत्रवार, कान्स्टीट्एन्सीवाइज, निर्वाचन-क्षेत्र के हिसाब से सारी धनराशि का बंटवारा करना चाहिए । यह एक स्वस्थ परम्परा होगी जो परमावश्यक है ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

अब झालावाड़ जिले के बारे में मंत्री-महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पिछले डेढ़ साल के अन्दर झालावाड़ जिले में पी० डब्लू०डी० मिनिस्टर साहब यह बतला दें कि कितना रुपया खर्च हुआ है। जो पैसा मन्जूर था बजट के अन्दर उस पैसे को दूसरी जगह लगाया है। यह एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है और शासन के लिए कलंक की बात है।

मैं जिस चुनाव क्षेत्र से चुनकर आया हूं मनोहरथाने से चांचौड़ा रोड़ पर सन् ५८ से करीब ९ मील का टुकड़ा है बन रहा है और १६ साल के अन्दर भी वह ९ मील का टुकड़ा पूरा नहीं हुआ है तो यह किसी शासन के लिए कलंक की और शर्म की बात है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, मैं अदब से श्रीमान् पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर साहब को झालावाड़ जिले की ओर विशेष तवज्जह देने के लिए प्रार्थना करता हूं। दरबार झालावाड़ के साथ आप वहां गये हैं जब कि वे पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर थे। आपके और उनके जो पुराने सम्बन्ध हैं उस दृष्टि से उनको सम्पूर्ण करने का ऐलान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणमल।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष में बजट के अन्दर जो सड़कों का प्रावधान रखा गया है उसके लिए मैं यह अर्ज करूंगा कि बारबार पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर महोदय का ध्यान जहाजपुर तहसील की ओर दिलाया गया जहाजपुर तहसील एक पहाड़ी और पिछड़ा हुआ इलाका है। जहाजपुर तहसील में कुल १२ मील के अलावा कोई रोड़ नहीं होने के कारण वहां की तीन लाख जनता को अपना अनाज मंडियों में पहुचाने का कोई साधन नहीं है। अगर वहां रास्ता नहीं है तो, माननीय उपाध्यक्ष, किसानों को मंडियों तक अपना अनाज पहुंचाने में ५० प्रतिशत खर्चा होता है। उपाध्यक्ष महोदय; आज किसान वहां से अनाज मंडी तक लेकर आये तो कम से कम तीन दिन उनके खर्च होते हैं तो इस पर उनका खर्चा विशेष हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष, वह एक गिरी हुई तहसील है जिसके लिए मंत्री महोदय का ध्यान दिलाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि शक्करगढ़ जहाजपुर से १४ मील दूर है। अकाल राहत कार्यो में वहां पर मिट्टी डालीगई है और अर्थ वर्क हो चुका है तो थोड़े से पैसों में उस सड़क की समस्या पूरी हो सकती है।

दूसरा, टोडा से शक्करगढ़ तक का चार मील का टुकड़ा है। वह अगर चार मील का टुकड़ा बन जाता है तो कोटा—बूंदी, अजमेर रोड़ से उसका सम्बन्ध हो जाता है।

इसलिये उनके अलावा एक और सावर का ६—७ मील का टुकड़ा है। वहां अकाल के द्वारा काम हो चुका है। इस रोड़ को बनाने से जयपुर, अजमेर यानि केकड़ी की जो रोड़ है वह बन जाती है। समस्या तो काफी है, पहाड़ी इलाका है—लम्बा चौड़ा क्षेत्र है। विशेष रुप से निवेदन करूंगा कि इस तरफ ध्यान देवें और उस रोड को बनाने की कौशिश करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा

(श्री कल्याणमल)

हुआ है। कोई साधन अनाज वगैरह लाने ले जाने के नहीं हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने का साधन नहीं है। उसको खाट में उठाकर ले जाना पड़ता है, जैसे मुर्दे को उठाकर ले जाते हैं। साधनों की वजह से कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ को पार करना पड़ता है इसलिये विशेष निवेदन न करके मैं पी०डब्ल्यू०डी० मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाते हुये यह मेरा जो कट मोशन है— —

श्री रावतराम (छापर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट अर्ज करना चाहता हूं— माननीय सदस्यों ने यही कहा कि सड़क नहीं है, फलां नहीं है, सड़क टूटी हुई है तो सबका सारांश यह है कि मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि १८४ कान्सीट्यूएन्सी हैं और सब जगह के लोग हैं इसलिये सब जगह छोटी छोटी रोड्स बना दी जायं और सबको लिन्क कर दी जाय। हालांकि हमारा कहना भैंस के आगे बीन बजाना है।

(माननीय सदस्यों द्वारा हंसी)

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा : छोटी चिड़िया बोलती है।

एक माननीय सदस्य : यह तो लाडला नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय,।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस साल दो सो कट मोशन्स आये पिछले साल ११७ थे। इस साल ६४ माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स भेजे। इसका मतलब यह है कि कितना अहम मसला है और कितने माननीय सदस्य इस मसले को दिलचस्पी से लेकर चलते हैं। लेकिन दूसरी चीजजो गौर से देखने की है वह यह है कि इन छोटी रोड्स पर बोलने वाले २७ माननीय सदस्य हैं किन्तु बोर्डर रोड पर दो माननीय सदस्य बोले हैं। इसका मतलब है कि कितने इतमिनान से बोर्डर रोड्स का काम चल रहा है।

इस दफा जो है वह कन्सर्न व्यक्ति नहीं है। जितना कन्सर्न है—ताल्लुक रखते हैं वह सब आम रोड्ससे रखते हैं और वह इसलिये है कि वे समझते हैं कि मंत्री जी कुछ कह जायं तो वे कुछ न कुछ करेंगे, उनका ऐसा विश्वास है इसलिए इन रोड्स पर जोर दिया गया है और कट मोशन्स दिये गये हैं मैं सारे मजमून में न जाते हुये जिन महानुभावों ने कुछ कहने का कष्ट किया है उनका जवाब देता जाऊं तो उन तमाम, मसलों को जिनका ताल्लुक सबसे ज्यादा है श्री विश्नोई ने फरमाया है अपनी सड़कों के बारे में कि जालौर जिले में सबसे कम सड़कें हैं इसलिये ज्यादा सड़कों की तरफ तवज्जुह की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हम यह देख रहे हैं कि किन किन जगह सड़कों की जरूरत ज्यादा है और किन किन जगह ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हम यह अन्दाज नहीं लगा सकेंगे निर्माण का कार्य करना थोड़ा मुश्किल है। हम सबसे पहले मिसिंग लिन्क्स का काम हाथ में लेंगे जिससे दो सड़कों की टुकड़ी जुड़ जाय दूसरे छोटी टुकड़िया जो खास सड़कों

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

के करीब वाली हैं उन सड़कों से मिलाया जाय जैसा मैंने आपसे अर्ज किया है इस हिसाब से यह काम किया जायगा और पूरा होने के बाद यह तवज्जह दी जायगी कि किन-किन जिलों में सड़कों की कमी है और किन-किन जिलों में ज्यादा है। आपने फरमाया रानीवाड़ा रोड़ के लिये। यह मैं मानता हूं कि यह टुकड़ी बड़ी जरूरी है। इसको बनानी है। इसको बनाने की पूरी कौशिश की जायगी ताकि हम डिफेन्स रोड से मिला सकें। इस सिलसिले में मैंने सेन्टर को लिखा है और अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भी किया तब भी हम इस तरफ पूरी तवज्जह देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तवज्जह इस साल देंगे या अगले साल ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह सब फन्ड्स पर है। आपने जो बिल्डिंग के मुतालिक कहा। इनकों डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर मेन्टेन करते हैं। उनके रेन्ट से जो फन्ड मिलता है जितना फण्ड मिलता है वही खर्च हो सकता है उससे ज्यादा खर्च करने का अधिकार नहीं है। दूसरा श्री मेघराज जी ने फरमाया है कि इनका काम बिना टेन्डर के मुताबिक और बिना रेट्स के हो रहा है। उन्होंने जिक्र किया है कि गलत तरीके पर टेन्डर लिये गये हैं और गलत तरीके पर टेन्डर छोड़े गए हैं। इस सम्बन्ध में वे मुझे लिख कर देंगे तो मैं इस ओर भी तवज्जह दूंगा और जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी। श्री सिंघवी ने छबड़ा में कलवर्ट्स और डाक बंगलों आदि की मांग रखी और उसके अन्दर सोरल साहब एक्स०ई०एन० का जिक्र किया है। आपने इस सम्बन्ध में किस एक्स०ई०एन० को लिख कर भेजा है अगर वह आप मुझे लिखेंगे तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगा। सड़कों के बारे में आपने कहा कोटा जिले में सड़कें काबिले गौर हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उससे भी ज्यादा खराब हालत कई जिलों में है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही नहीं है कि आपके विभाग के चीफ इंजीनियर और सौरल साहब के विरुद्ध एन्टीकरप्शन विभाग ने लिखकर भेजा है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : पहले आप सुन लें, जैसा आपने कहा कि चीफ इंजीनियर के बारे में शिकायत है तो आप लिखकर भेजें तो वह ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है मंत्री कितना ही चाहे, दूसरों को भी हक होता है जवाब देने का,इसलिये आप इसमें मदद करेंगे तो कुछ न कुछ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम भी तवज्जह रखेंगे, आप हमेशा रखते ही हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कर सकेंगे, ऐसी आशा है। श्री चुन्नीलाल जी ने जो खन्डार से आये हैं उन्होंने सवाई माधोपुर से पाली की खन्डार की सड़कों के बारे में बताया। वे अब बहुत अच्छी हैं, उनकी मरम्मत हो गई है बल्कि वहां पर एक फेरी का इन्तजाम भी कर दिया गया है।

श्री हरिवल्लभ : नवाब साहब, जिसका जवाब तलब...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

और तकरीर करने के साथ-साथ शेर भी पढ़ा लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि वे मेरा जवाब सुनने के लिये यहां पर मौजूद नहीं........

श्री विजयसिंह रावत : हम पहुंचा देंगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : लेकिन आप समझने के काबिल नहीं हैं। फिर भी मैं सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि आप मदहोश हैं। मैंने यहां बैठे-बैठे लिखा कि 'होश में आये तो पीना ही क्या, हाय जालिम तू भी पीता देखता' (करतल ध्वनि) मैंने यहां बैठे ही लिख दिया।

अब श्रीमती पूनियाजी ने फरमाया, क्योंकि आप सदस्या हैं आपका कहना बजा है। उनसे मैं कसूर की माफी जरूर मागूंगा और कोशिश करूंगा कि उनकी सड़क की तरफ खास तवज्जह दी जाय।

श्री जगन्नाथ जी साहब का कहना है, वह अपने जिले की सड़कों के मुत्तल्लिक सोचते हैं, आप मुझे फरमायेंगे, आप मेरे दोस्त हैं हो सका तो मैं उनकी खातिर कर सकूंगा।

श्री मूलचन्द जी डागा ने बहुत कुछ खयाल का इजहार किया और जो हाउस टैक्स के मुतल्लिक सवाल है गवर्नमेंट बिल्डिंग पर लेंगे न लेंगे या नगर पालिका के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि कुछ परसेन्टेज देना चाहिये। इसके मुतल्लिक मैं यहां एग्जामिन करा लूंगा डिपार्टमेंट से और जवाब आपको दे दिया जायगा।

श्री लादूराम जी सुलानिया ने अपने जिले की सड़क का जिक्र किया और घूम के बारे में कहा कि इससे नुकसान होता है। घूम के बारे में देख लिया जायगा। मैंने नोटिस इसलिये बनाये हैं कि उन पर अमल हो सके। करेप्शन के मुतल्लिक आपने कहा और मैंने बार-बार कहा कि यही हो सकता है कि आप स्पेसिफिकली लिख कर भेजें ताकि मैं आगे कार्यवाही कर सकूं। महज कहने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आप गैर जिम्मेदाराना बात कहेंगे तो मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूं कि ऐसी बात करूं.......

श्री रामचन्द्र आर्य : कई दफा शिकायतें भेजी गई हैं........

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : मन्त्री जी की जानकारी के लिये कह दूं।

श्री उपाध्यक्षः पहले इनकी बात तो सुन लें।

श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा : आप हमको गैर जिम्मेदार मानते हैं क्या?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जवाब की बात कहता हूं। मैंने यह कहा कि जिम्मेदारी से कोई बात कहें तो जिम्मेदारी से उस पर कुछ किया जा सकता है।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी): मैं एक मिनिट में निवेदन कर देता हूं। मेरा कहना यह है कि आप हाउस में यह कर बात टालना चाहते हैं कि यदि

(श्री लादूराम मुलानिया)

लिख कर शिकायत भेजेंगे तो उन पर कार्यवाही होगी। मैं निवेदन कर दूं कि लिखित में जो दिया जायेगा उसकी इन्क्वायरी होगी लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से यहां बात कहते हैं उसमें वजन होता है। यहां पर विधान सभा में हम जो कुछ भी बात कहते हैं उस पर कार्यवाही होनी चाहिये वरना हमारे यहां आने से और कहने से फायदा ही क्या। यहां की सारी प्रोसिडिंग्ज पर ध्यान रख कर कार्य करना आपका फर्ज है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो बात जांच के लिये है उसकी पड़ताल कर लेंगे मैंने लिख लिया है लेकिन जहां तक एक्शन लेने का सवाल है, मेरे नोट्स के आधार पर ही कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि शिकायत करने वाला ही मामले में पार्टी बन सकता है, मैं तो पार्टी बन नहीं सकता इसलिये किसी शिकायत करने वाले को मिलना चाहिये।

मुझे खुशी है कि रामकिशन जी तशरीफ ले आये हैं क्योंकि एक मिसरा है कि जब शहद से काम चले तो जहर की जरूरत क्यों हो। आप प्रेम से बोलते हैं उसका कद्रदान हूं लेकिन उसमें जितनी मलामतें हैं उनको मैं ही समझता हूं क्योंकि उर्दू जबान बृज भाषा से निकली है। आपकी बात को मैं ही समझता हूं। तमाम राज्य का जितना रुपया भरतपुर जिले में खर्च होता है उतना दूसरी जगह नहीं होता, चाहे रोड्स के रूप में हो चाहे फ्लड्स के रूप में हो। आप हमको इल्जाम देते हैं कि आप काम नहीं करते लेकिन जो हम कर सकते थे शुरू किया। मरम्मत हो रही है........

श्री भैरोंसिंह : किसकी हो रही है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: सड़क की।

श्री भैरोंसिंह : रामकिशन जी की तो नहीं न ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : रामकिशन जी का तो मैं बहुत आदर करता हूं, कद्र करता हूं इनकी खसूसियत की, आपने फरमाया कि हजूर और पुरनूर कह कर काम करते हैं......

श्री रामकिशन : मैंने आपके लिये नहीं कहा, मैंने कहा कि आपके इंजीनियर बड़े तेज हैं वे हुजूर पुरनूर कह कर काम निकाल लेते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: किसी तरह से आपने फरमाया तो। हजूर और पुरनूर तो हम रहेंगे ही। मंत्रीगिरी के पद से कोई ताल्लुक नहीं है वह अपनी जगह पर है पर खैर मंत्री सोने में सुहागा। आपने जो सम्भलने की बात कही तो संभलने की यह बात है कि हम बहुत संभले हुए हैं। यदि संभले हुए नहीं होते तो इस पोजीशन में नहीं होते जिसमें आज हैं। बहुत संभले हुए हैं, बहुत पक्के हैं और बहुत अटल हैं, अपनी जगह पर कायम हैं और रहेंगे। आप भी देख कर खुश होंगे कि हम किस जमे-जमाये तौर पर काम कर रहे हैं ...

श्री रामकिशन : मैंने जो बात कही उसका जावाब दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी बात है कि जितनी बातों की आपने सूचना दी है उनका एक मिनिट में जवाब देता अच्छा नहीं लगता हूं न आप कहते अच्छे लगते हैं इसलिये आपस में बैठ कर बात करें। आप मुझे समझा दें मैं अपको समझा दूं। ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं सकें। आखिर शरीफ इन्सान हैं। लेकिन आपने जो रूस का हवाला दिया उसकी मैं कतई तारीफ करने वाला नहीं हूं। आपने तारीफ की...

श्री रामकिशन : मैंने यह कहा था कि मैं रूस के सिस्टम का समर्थक नहीं हूं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह बहुत अच्छी बात है मैं बहुत खुश हुआ।

श्री रामकिशन : दूसरी बात सुनिये रोड्स पर ज्यादा खर्चा करें बिल्डिंग्ज पर नहीं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं समझ गया। हमारे आपके भेद भाव नहीं होना चाहिये।

आपस में समझ लेंगे, बात-चीत कर लेंगे। रोड्स के मुतल्लिक फंड्स के मुताबिक जो कुछ हो सकेगा कोशिश करेंगे सही रोड्स पर लगेगा। आपने कहा कि फालतू लग रहा है मुझे बतावें कि फालतू कहां खर्च हुआ। यह भी खत्म।

श्री रामकिशन : अब भैरोंसिंहजी को खत्म करें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : श्री रणजीतसिंह (ओसियां) ने बेकवर्ड इलाके का जिक्र किया। मेरे खयाल से बेकवर्ड इलाके के लिये बात करेंगे। बेकवर्डनेस के लिये जो भी खिदमत करें थोड़ी है जहां तक वादे का ताल्लुक है लेकिन जब अमल में आजायगा तभी है।

श्री चुन्नीलाल जी ने अपने एरिया के मुतल्लिक फर्माया, और बहुत सा फर्माया। यह मेरे साथ में बीकानेर में रहे हैं और कोलायत में तशरीफ भी ले गये हैं। मेरे ख्याल में उस इलाके में काफी काम हो रहा है और सुफल होगा तो और भी होता रहेगा। इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वहां काफी काम चल रहा है।

श्री आईदानसिंह जी ने अपनी सड़कों के मुतल्लिक कुछ कहा।

एक माननीय सदस्य : वह नहीं हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : वह नहीं हैं तो मैं उनको सुना दूंगा बाद में।

श्री आईदानसिंह : यह आपके ध्यान को डाईवर्ट कर रहे हैं। मैं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी शक्ल तो उनके कागज पर नहीं लिखी है, नाम लिखा है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : पीछे से फर्माया इसलिये अर्ज किया। मैं शक्ल भी जानता हूं।

श्री विजयसिंह रावत : आपका ध्यान मेंसवाड़ा की तरफ चला गया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उनकी तरफ

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

मेरा ध्यान हर वक्त रहता है। मेरे डिप्टी हैं मजाक नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : डिप्टी हैं या डबल हैं।

एक माननीय सदस्य : मनाकर दें पीछे से छेड़-छाड़ नहीं करें।

श्री विजयसिंह : आपका ध्यान इधर-उधर चला जायगा तो मैंसवाड़ी बिगड़ जायगी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : वृद्धिचन्द्र साहब ने जो तकरीर की, उनकी बहुत सी बातें ऐसी जिम्मेदाराना हैं कि जिनको मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ नोट किया है और उसमें कोई कमी है किसी चीज में तो उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी, और उसमें ताकत, उसमें फैलाव और लायेंगे। बाड़मेर मेरे साथ जाने का इत्तिफाक हुआ तो मेरी उनसे गुफ्तगू होती। अब मै जानकारी लेकर देना चाहता हूं। वैसे हैड क्वार्टर का उन्होंने जिक्र किया कि वहां नहीं गया है तो वहां अब चला गया है, एक्स. ई. एन. वहां मौजूद है। वह पहले नहीं पहुंच सका बीमारी की वजह से, अब जरूर पहुंचा है। यह बड़ा जरूरी है कि मौके पर इन्जीनियर हों ताकि काम सही तरीके से चल सके। जो थोड़ा काम है, उसका फर्ज है, उसको पूरी तरह तौर पर कराये और उसमें नुक्स वाली बात न रहने दे। एक करप्शन के मुतल्लिक आपने फर्माया। उसमें भी वही जवाब है। मैं बहुत आभारी हूं, अगर आप कोई केस ऐसा निकलवा कर दे दें जिसमें कारगुजारी हो सके। हर साल केस आते हैं, करप्शन करप्शन के, लेकिन इस सदन के इतने सदस्यों के अन्दर से कोई मेरी मदद करें तो मैं समझूंगा कि सही मायने के अन्दर मदद इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की हो रही है वरना उसकी हद करप्शन कहने की भाषण की ही रहेगी तो उसमें कोई आने-जाने वाली बात नहीं है…

श्री विजयसिंह (मकराना) : इससे ताल्लुक तो नहीं है, कोई तो इस जाम में मेरे साथ हो।

श्री खेतसिंह : अब भैरोंसिह का जवाब दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अब भैरोंसिह जी आये। मैं बताना चाहता हूं……

श्री रामकिशन : इन्हें भी खत्म करें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : खत्म करता हूं।

इसमें शक नहीं है, श्री भैरोंसिह साहब की तकरीर बहुत जोरदार थी, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी पुरअसर होनी चाहिए उतनी नहीं थी क्योंकि मैं उसका आदी हो चुका हूं। आपने बहुत सी बातें फर्मायीं और यह बहुत सी बातें आपने पहले भी फरमायीं थी। मैं जानता हूँ आपको चिन्ता भी बहुत है। लेकिन मैं एक जगह कतई एग्री नहीं करता हूं, जैसा आपने कहा कि राजस्थान में पाकिस्तान के हमले से **कलंक का टीका लगा। कलंक का टीका** किस बात पर लग सकता है?

श्री भैरोंसिह : आप नहीं मान सकते। राजस्थान के लोग जानते हैं।

Page No. 176

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हर्गिज नहीं मान सकता। आपके राजस्थान की सीमा पर ही लोग जमे बैठे रहे, दूसरे नहीं बैठे हैं। आपको यह मानना पड़ेगा नहीं-नहीं, आपको मानना पड़ेगा, आपकी सीमाओं से, आपके देहातों से आपके शहरों से कोई भाग कर पीछे नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : नवाब साहब आप नहीं-नहीं कहते हैं। लेकिन सड़कों के अभाव में ही पाकिस्तान घुसपैठ करने में सफल हो गया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसमें कहां **कलंक का टीका** लग गया।

श्री भैरोंसिंह : और क्या **कलंक का टीका होता** है। उसे नहीं मानेंगे जो इतिहास में है। वैसे मैं जानता हूं कि आप नहीं मानेंगे, हम मानेंगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप मानें या न मानें। मैं भी हकदार हूं, लोयल भी हूँ।

श्री भैरोंसिंह : दुर्भाग्य से हममें और आप में यही फर्क है। उस चीज को आप **कलंक का टीका नहीं** मानते कि दुश्मन हमारे क्षेत्र के अन्दर आकर जम जाय, पाकिस्तान के लोग हमारे क्षेत्र में आ कर जम जायं, यह कलंक का टीका नहीं है तो और क्या है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जरूरी नहीं है कि हर जगह आप ही बढ़ते चले जायं और दूसरा बिल्कुल आगे न बढ़ पाय। मैदाने जंग में कोई भी बढ़ सकता है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या हम यह मान कर चलें, उपाध्यक्ष महोदय, कि पाकिस्तान आगे बढे...

श्री अमीनुद्दीन अहमद : लड़ाई का फैसला इस तरह से नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : सार्वजनिक निर्माण मंत्री का यह कहना है सदन में कि हम चूंकि आगे बढ़ गये थे इसलिए पाकिस्तान भी बढ़े। यह कहने का मतलब है।

(शोर गुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत सीरिअस है।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : क्या चीज ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने जो शब्द कहे हैं उन शब्दों को वह वापिस लें क्योंकि राजस्थान की जनता का इस प्रकार के शब्द कह कर राजस्थान सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने मोरेल डाउन किया है। मैं जानता हूं कि आपका भाइ पाकिस्तान के अन्दर फौज में कमाण्डर है, आप इस प्रकार की बात कह कर राजस्थान की मिलीट्री को हतोत्साहित करना चाहते हैं और पाकिस्तान के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय भैरोंसिंह !

Page No. 177

श्री भैरोंसिंह : कमाण्डर वाली बात से तो हमें लेना देना नहीं है । प्रश्न यह है कि नवाब साहब ने जैसा भाषण में कहा वह आपत्तिजनक है । उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता कि अपनी तरफ के बढ़ जायं और दूसरी तरफ पाकिस्तान न घुसे । इसका मतलब यह है, भले ही आपने भोलेपन में कहा, किसी तरह से कहा हो, लेकिन जो कुछ कहा है उसका अर्थ यह निकलता है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मंत्री महोदय तो केवल......

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्पष्टीकरण करें, उसके बजाय मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण करना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय को करना चाहिए ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं कहना चाहता हूं, आपने जैसा फर्माया कि हमारा रुपया लेप्स हो रहा है, उसका जवाब देना मुझे जरूरी है, हमारा रुपया लेप्स होने की......

श्री भैरोंसिंह : पहले उसका स्पष्टीकरण कर दीजिये, अपनी पहली बात का स्पष्टीकरण कर दीजिये कि जो कहा था उसके पीछे क्या भावना थी ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसके पीछे यह भावना थी कि मैदाने जंग में जब लड़ाई कहीं होती है तो जरूरी नहीं होता, एक तरफ बढ़ावा होता चला जाय । बढ़ावा घटावा होता रहता है लड़ाई के अन्दर ।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं कहा था ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यही कहा था ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही कहा था । इस तरह से बात को मोड़ नहीं सकते ।

श्री भैरोंसिंह : मोड़ने का सवाल नहीं है । यों नाराज होने से और आप आंख दिखायें इससे मैं बैठने वाला नहीं हूं । नवाब साहब आंख दिखायें, आप उछलें इससे मैं नहीं बैठूंगा । प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि मेरा चार्ज यह है कि रोड्स के अभाव में पाकिस्तान घुसपैठ करने में सफल हो गया, यह कलंक की बात हमारे लिए है । यह कलंक की बात मानें या नहीं मानें लेकिन राजस्थान की जनता को इस कलंक पर सोचना पड़ेगा । यह तथ्य है, यह ऐतिहासिक तथ्य बन गया है । उसके जवाब में आपने कहा कि यह नहीं हो सकता कि एक तरफ हम बढ़ जायं और दूसरी तरफ से वह बढ़ कर नहीं आये । इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान बढ़ जाय इस पर आपत्ति नहीं है ।

श्री रोशनलाल : यह बात नहीं कही ।

श्री भैरोंसिंह : यही कहा है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह नहीं कहा ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह (मकराना) : कैसे कहते हैं । बिल्कुल गलत है, बकवास है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप कैसे कहते हैं ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया ; उपाध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्टीकरण हो जाय......

श्री उपाध्यक्ष : यह बात नहीं है। आप स्थान ग्रहण करें। (शोरगुल) आसन अपने पैरों पर खड़ा है।

श्री लादूराम सुलानिया : ऐसी बकवास यह नहीं कर सकते, यह कलंक का टीका नहीं है तो क्या है। इन शब्दों को प्रोसीडिंग्स से निकलवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है, वह पूरे सदन ने सुनी है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि लड़ाई के दौरान में कोई जरूरी नहीं होता है कि एक पक्ष जीते। यह सम्भव है कि दूसरा पक्ष आगे बढ़ सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम नहीं बढ़े और वह बहुत बढ़ जाय। न मतलब यह था। मैं अर्ज कर रहा हूं इस बात को यहीं समाप्त कर दिया जाय।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह बिल्कुल सही है, जैसा आपने इन्टरप्रिटेशन खत्म कर दिया। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं इस सदन को मुझे अपने पर इस देश का होने के नाते नाज है। मैं यह चाहूंगा कि कभी एक इंच जमीन........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : जानते हैं। सब जानते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : एक इंच जमीन कहीं नहीं जाने पाये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सबको यकीन है।

अब जब हम आते हैं बोर्डर रोड्स में कि हमारे जो बोर्डर रोड्स के काम चलते हैं, उन बोर्डर रोड्स के काम चलाने में कमी रही तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं। एक दफा कोई काम बन्द हो जाता है तो उसको फिर शुरू करने में टाइम लगता हैं। ३ करोड़ पर हमारा काम सेंटर से बन्द करवाया गया, ८ करोड़ की मन्जूरी सितम्बर में आई, जो काम हमारा चल रहा था उसमें बाधा आई। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो हर काम बोर्डर रोड्स पर करना पड़ता है, वह सेन्टर की मन्जूरी से करना पड़ता है, जिनको सेन्टर बन्द करता है, उन कामों को हमें बन्द करना पड़ता है, जिनको वे शुरू करने का कहते है, उन कामों को हमें शुरू करना पड़ता है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो जो रुपया लेप्स हुआ उसमें सेन्टर का दोष है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : न सेन्टर का दोष है, न हमारा दोष है, हालात का दोष है।

श्री भैरोंसिंह : हालात का क्या दोष है, आपकी जिम्मेदारी है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एक मशीनरी आसाम से लानी पड़ती है, एक मशीनरी बंगाल से लानी पड़ती है, एक मशीनरी पंजाब से

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

लानी पड़ती है, एक कलकत्ता से लानी पड़ती है, वह मशीनरी एक मिनिट में नहीं आ सकती, यह कोई मजाक नहीं है कि एक मिनिट में हवाई जहाज से ले आई जाय। आखिर इतनी दूर से मशीनरी हमें लानी पड़ती है, कोई खराब हो तो इसकी मरम्मत करनी पड़ती है, एक मिनिट में सारी मशीनरी हवाई जहाज से लाकर राजस्थान में रख दें, यह कोई मजाक नहीं है......

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में आपके प्रोजेक्ट के पास मशीनरी थी, फिर आप क्यों नहीं काम पूरा करवा सके ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : वह दूसरी तरह की मशीनरी थी, यह दूसरी तरह की मशीनरी है। आज इतना रुपया खर्च हो गया, ६०—७० लाख खर्च नहीं हो सका तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे यह कह दें कि हम तो नहीं देंगे, सेन्टर की छूट है कि आप जितना चाहें अगले साल खर्च कर दें। बेकार खर्च करें तो कल कहेंगे कि बेकार खर्च कर दिया, दुगुना इसमें खर्च कर दिया, यह कैसे हो सकता है, आखिर काम तो काम की रीति से होगा, जो काम हमने किया है उसकी कद्र करनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : कद्र इस बात की होती कि जैसे पिछले वर्ष जितना रुपया दिया गया था, उससे ६० लाख ज्यादा खर्च हुआ, मशिनरी नहीं थी। नया प्रोजेक्ट खोला था, नया ओर्गेनाइजेशन खोला था, तब भी सारा खर्चा कर दिया पर अब की बार तो सारी मशिनरी थी, सारा प्रोजेक्ट जमा हुआ था, सारा ओर्गेनाइजेशन जमा हुआ था फिर भी आप पूरा खर्च नहीं कर सके और फिर भारत सरकार पर इल्जाम लगाते हैं......

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तो आप चाहते हैं कि मैं उन पर इल्जाम लगाऊं, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। जहां तक हमारी बात है मैं यह यकीन दिला कर चलना चाहता हूँ कि आप कोई इस तरह की बात बतायेंगे कि इस तरह से काम में हानि हुई है, या हो रही है तो मेरे बस की बात होगी वहां तक हानि नहीं पहुँचने दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपके पास तीन चार महिने कागज पड़े रहे और इजाजत देर से दी......

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह आपको गलत मालूम है कि मेरे पास महीनों कागज पड़े रहे, यह बात आप दिल से निकाल दीजिये कि मेरे पास कागज महिनों पड़े रहे।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर बताइये......

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप बताइये...

श्री भैरोंसिंह : अगस्त में टेन्डर इन्वाइट किये और नवम्बर तक आपने टेन्डर डिस्पोज ऑफ नहीं किये...

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह नहीं है। गलत बात है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर क्या बात है आप बताइये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप बताइये, आप यह कह रहे हैं तो आप बताइये।

Page No. 180

श्री भैरोंसिंह : अगस्त में टेन्डर इन्वाइट किये, ३ टेन्डर नवम्बर में डिस्पोज ऑफ किये और दो टेन्डर २७ अक्टूबर को डिस्पोज ऑफ किये। इस तरह से २ टेन्डर्स में दो महिने का समय लगा और ३ में तीन महिने का समय लगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अब कहिये ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं मानता ही कब हूं कि इतना समय लगा, कोई मजाक थोड़े ही है कि मान लूं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : मशीनों का आपने कहा, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। आप तो खुद मिलिटरी में रहे हुए हैं। बोर्डर रोड्स कों बनाने का आर्डर मिलता है तो बोर्डर का ओपरेशन एरिया है, आप जानते हैं कि ओपरेशन 'एरिया में जो काम आर्डिनरी तरीके से १२ वर्ष में बनता है वह ओपरेशन एरिया में १२ महिने में बनना है। लेकिन आप बोर्डर रोड्स का काम टाइम पर नहीं करके आपने ६०—७० लाख रुपया वापिस भारत सरकार को दिया। ऑपरेशन एरिया के काम के लिये आपकी वह दलील है कि मशीनें आपको आसाम से बंगाल से पंजाब से लानी पड़ी। ऑपरेशन एरिया में हर हालत सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर काम करना चाहिये......

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मगर यहां मिलीटरी रूल नहीं है, यहां मिलिटरी रूल के आधार पर काम हो नहीं रहा है, यहां डेमोक्रेसी है।

श्री विजयसिंह रावत : ओपरेशन एरिया में गवर्नमेंट का कर्तव्य था कि समय पर सारा काम पूरा हो।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपकी जानकारी में यह ओपरेशन एरिया हो सकता है, पर हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कितना अमाउन्ट लेप्स हुआ ?

(विराम)

मैं यह जानना चाहूँगा कि वित्त मन्त्री जी ने बताया था कि १ करोड़ से ज्यादा लेप्स हुआ और निर्माण मन्त्रीजी कहते हैं कि ६०—७० लाख लेप्स हुआ तो सही कौन हैं, निर्माण मन्त्री जी कहते हैं वह सही है या वित्त मन्त्री जी ने जो कहा वह सही है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह ३१ मार्च के बाद बता दूंगा, पहली अप्रेल को पता चल जायगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर चाहूँगा कि यह दो कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हुए उनमें सही कौनसा स्टेटमेंट है......

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह ३१ मार्च के बाद पता चल जायगा।

श्री भैरोंसिंह : यह मजाक नहीं है कि शेर पढ़ कर हाउस में इस तरह के सीरियस मामले को मजाक में टाल दिया जाय...

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपकी तरफ से शुरूआत हुई, आपकी तरफ से पहले शेर

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

पढ़ा गया।

देखिये आप अब हंस रहे हैं, पहले भी हंस चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी हंसी बन्द करता हूं। वित्त मन्त्रीजी ने जब बजट पर भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि १ करोड़ से अधिक रुपया बोर्डर रोड्स का लेप्स हुआ है, आज निर्माण मन्त्री जी कह रहे हैं कि ६०—७० लाख ही लेप्स हुआ तो मैं यह जानना चाहूँगा कि सही फीगर्स कौनसे हैं, जो वित्त मन्त्री जी ने फीगर्स बताये वे सही हैं या अब निर्माण मन्त्री जी बता रहे हैं वे सही हैं। हाउस में ये दो कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिये गये हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तो अन्दाज की बात है, ६०—७०—८०—९०......

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर बजट की बातें रखते हुए मैंने निवेदन किया था तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी तकरीर में कहा था कि करीब ८० लाख रुपया बोर्डर रोड्स का लेप्स हुआ है, तो मैंने कहा कि एक करोड़ के करीब लेप्स है......

श्री भैरोंसिंह : आपने एक करोड़ से ज्यादा बताया।

श्री मथुरादास माथुर : यह मैंने कहा था लेकिन १४५ लाख का इस वक्त लेप्स है।

श्री भैरोंसिंह : फिर तो निर्माण मंत्री जी को सदन में खड़े होकर माफी मांगनी चाहिये कि उन्होंने सदन को गलत फीगर्स दिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : एक्च्युअल फीगर्स देता तो माफी मांगता, मैंने तो कहा था कि अन्दाज इतना लेप्स हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, डिमाण्ड पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो अन्दाज से काम नहीं चलता, निर्माण मन्त्रीजी को जब यह पता नहीं कि कितना लेप्स हुआ तो वे क्या बोर्डर रोड्स का निर्माण करवायेंगे, वे शेर पढ़ कर सदन को गुमराह करना चाहें, इससे काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह : पहले इसका जवाब दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरा अगर गलत स्टेटमेंट था तो वित्त मन्त्री जी ने दुरुस्त कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब हुआ कि वे दुरुस्त नहीं करें तब तक आप गलत कहते रहें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, ६०—७० लाख की आवाज उधर से आ रही थी, इसलिये मैंने अन्दाजन कहा...

श्री भैरोंसिंह : एक्च्युअल अमाउन्ट कितना लेप्स हुआ है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसके लिये आप टाइम देंगे तो बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण मन्त्री जी यह नहीं बता सके कि कितना लेप्स हुआ है, निर्माण मन्त्री जी को यह तक मालूम नहीं कि बोर्डर रोड्स जैसी महत्वपूर्ण सड़कों का कितना रुपया लेप्स हुआ है, इससे बढ़ कर दुर्भाग्य की बात राजस्थान के लिये और नहीं हो सकती।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : लेप्स हुआ कहां है, अब होगा।

श्री भैरोंसिंह : तो वित्त मन्त्री जी कह रहे हैं, वह गलत है ?

(विराम)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक बोर्डर रोड्स के बारे में निर्माण मन्त्री जी जवाब नहीं देंगे तब तक हम उन्हें नहीं बोलने देंगे। या तो आप स्पष्ट बताइये कि कितना लेप्स हुआ हैं, यह कोई पांच, दस या १००—२०० का मामला नहीं है, एक करोड़ से ऊपर का अन्तर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गाड़िया जी, स्थान ग्रहण करें।

इसमें ऐसा कि वित्त मन्त्री जी ने करीब एक करोड़ के लेप्स का कहा......

श्री देवीदत्त गाड़िया : १३९ लाख का कहा।

श्री उपाध्यक्ष : निर्माण मन्त्री जी ने अन्दाज से बताय ६०—७०—८० । कितना लेप्स हुआ कितना लेप्स नहीं हुआ, यह तो ३१ मार्च को ही सही स्थिति मालूम होगी।

श्री भैरोंसिंह : एस्टीमेट्स में सही चीज आनी चाहिये, एस्टीमेट्स वित्त मंत्री जी ने १ करोड़ ४७ लाख बताये, आप ६०—७०—८०—९० लाख कह रहे हैं...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चूंकि अभी तक फाइनल अकाउन्ट बना नहीं है अभी ठेकेदारों के बिल चुकाने हैं उसके बाद में सही स्थिति बता सकते हैं कि कितना लेप्स हुआ। निर्माण मंत्रीजी ने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा है अभी वे सही फीगर्स बता भी नहीं सकते। अगर फाइनेन्स अकाउन्ट गलत बन जाता तो कह सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : आपने बजट एस्टीमेट्स देखे हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह मैंने भी देखा है यह दोनों देख लिये है। जब तक पूरा हिसाब किताब नहीं होजाता है तब तक सही बात नहीं बतायी जा सकती।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर यह बजट एस्टीमेट्स हमको दिये जाते हैं इस पर रिलाइ नहीं कर सकते केवल घोखा देने के लिये यह किया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोर्डर रोडस के बारे में जो फीगर्स यहां बताये गये हैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

साठ सत्तर लाख और डेढ करोड़ के करीब इसमें डिफरेन्स है । यह डिफरेन्स जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने बताया बजट पेपर्स जो सरकुलेट किये गये हैं उसके अन्दर रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में सात करोड़ का खर्चा बताया गया है उसके हिसाब से १.५ का लेप्स होगा यह बजट पेपर्स जो सरकुलेट किया गया है उससे मालूम देता है जो आपके सामने है । इसमें जानकारी का फर्क हो सकता है इसमें मुगालता देने की बात नहीं है । इसके साथ साथ मैं यह भी स्पष्ट कर दूं पिछले साल ६ करोड़ और कुछ लाख बोर्डर रोड्स पर खर्चा किया गया है उसके कम्पेरिजन में इस वर्ष सात करोड़ के ऊपर या करीब करीब इतना खर्च होगा । लास्ट ईयर ६ करोड़ के करीब रुपया केवल मशीनरी पर खर्च होगया इस साल सात करोड़ रुपया रोड्स के कन्स्ट्रक्शन पर खर्च हुआ है । जो मशीनरी बाहर से आने को थी विभाग द्वारा प्रयत्न करने पर भी आसाम, बंगाल वगैरा से अब तक नहीं पहुंची है । इस बीच यह भी कोशिश की गई थी राजस्थान नहर पर काम आने वाली अर्थ मूविंग मशीनरी है, चूंकि उसके लिये प्रोवीजन कम होगया अत: उसको लाई जाकर काम में लाया जाय । लेकिन अब राजस्थान नहर के लिये पर्याप्त धन मिलने की संभावना है अर्थ मूविंग मशीनरी को इस काम के लिये लाना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

एक्चुअल माइलेज के पोइन्ट आफ व्यूसे एक्सपेन्डीचर को देखते हैं तो पिछले वर्ष से ज्यादा होना चाहिये । वह भी ८.१० लाख का होजाता । लेकिन पहले सेक्शन काम नहीं होने के कारण बीच में जो गेप हुआ उसके अन्दर सेट बेक हुआ । मैं समझता हूं नेक्स्ट ईयर से हम इसकी प्रोग्रेस काफी तेज कर सकेंगे । इसमें शक नहीं है कि बोर्डर रोड्स और ड्रिंकिंग वाटर जो इन जगहों की प्रीलिमिनरी आवश्यकतायें हैं इनकी ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है । यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले पाक एग्रेशन के समय जो कुछ हालात हुए उसके कारण सभी को चिन्ता होना स्वाभाविक है । मैं माननीय सदस्यों की भावना को एप्रीसियेट करता हूं, हम इसके लिये पूरी तेजी के साथ प्रयत्न करेंगे जो भी पैसा हमें इसके लीये मिलता है उसको रिफन्ड करने का हमारा कतई इरादा नहीं है । जिन हार्ड सरकम्सटान्सेज में हमारे इन्जीनियर उस जगह काम कर रहे हैं जो स्टाफ हमारा काम कर रहा है मैंने वहां जाकर देखा है और आप से भी निवेदन करता हूं कि आप भी जा ें और देखें कि कितने हार्ड सरकम्सटान्सेज में हमारा इन्जीनियरिंग का स्टाफ काम कर रहा हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अब आप जरा सम्हल कर बोलिएगा ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अब सम्हल कर ही बोलूंगा । मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी मुस्कराहट मुझे दिखाई दी और अब मुझे पूरा इत्मीनान हो गया । अब हमारा झगड़ा खत्म हो गया । यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, मानी हुई बात है कि हमारी दोनों की नीतियां बहुत अच्छी हैं ।

(श्री. अमीनुद्दीन अहमद)

जितनी अच्छी नीति आपकी है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी भी उतनी ही अच्छी नीति है।

श्री गोपाल प्रसाद शर्मा : आप दोनों की गुफ्तगू हो और हम चुप रहें ? कुछ वे कहते हैं, कुछ आप कहते हैं, आप दोनों की गुफ्तगू हो रही है और हम यहां किस लिए बैठे हैं ? उनकी मुस्कान आपने देख ली, यह क्या बात है ? यहां सदन में सही बात कहने के लिए, राजस्थान के निर्माण के लिये हम कह रहे हैं, और यह कोई आपका जवाब है ? यह क्या मजाक है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : नीतियों का तालुक जवाब से है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं।

आपने एतराज किया कि गैंग हट्स बनी हुई, उसके बारे में आपने कहा। तो मुझे कहना है कि ये गैंग हट्स जो हैं वे गवर्नमेंट आफ इंडिया से बनी हैं, उन्हीं के पास शुदा नक्शों के अनुसार बनी हैं। मेरे खयाल से और भी लोग इनका फायदा उठा सकते हैं, वहां से सड़कें गुजरती हैं, वहां से जीपें चलेंगी, आफिसर लोग आयेंगे जायेंगे। इनका जो स्टैंडर्ड है वह गवर्नमेंट आफ इडिन्या से मन्जूर शुदा है।

श्री भैरोंसिह : मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप विधान सभा के किसी भी माननीय सदस्य, जिन पर आपका विश्वास हो, को वहां भेजकर उनसे रिपोर्ट करवाइये कि ये गैंग हट्स किसी मिनिस्टर के बंगले से कम नहीं हैं। मिनिस्टर्स के बंगले इन गैंग हट्स के मुकाबले कहीं नही टिकते।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने दोनों देखे हैं।

श्री भैरोंसिह : मुख्य मंत्री के बंगले से यह गैंग हट्स कहीं ऊंचे पड़ते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने मुख्य मन्त्री का बंगला भी देखा है और ये गैंग हट्स भी देखे हैं। दोनों में बहुत फर्क है।

श्री भैरोंसिह : अच्छा कौन सा है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मुख्य मंत्री का बंगला।

श्री हरिदेव जोशी : और बोलो।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं यह कह रहा था कि वहां से आफिसर्स भी आयेंगे जायेंगे, जीपें जायेंगी और ये गैंग हट्स उनके भी काम आ सकती हैं, सड़कों को मेन्टेन रखना पड़ेगा। जैसे जैसलमेर में कोई बहुत बड़ा अड्डा बनाया जाता है तो वहां पर जीपें चलेंगी और आफिसर आयेंगे। तो यह जो रुपया लगाया है वह मन्जूरी से लगाया है। आपने एक बात और भी देखी होगी कि वहां पर टांकें भी बना रखे हैं, इसके अलावा और भी टांकें बनायेंगे। तो पी० डब्लू० डी० को बुरा-भला कहते हैं वह तो सही है, लेकिन इतने कुएं बनाए है, वहां पर पानी मुहय्या किया है पब्लिक को, उनको देखने वाले मौजूद हैं, कहीं तो

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

आप पी. डब्ल्लू. डी. की तारीफ भी किया करिये कि अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पी. डब्ल्लू. डी. के लिए तो यह ही बहुत है कि आप जैसा मन्त्री पी. डब्ल्यू. डी. को मिल गया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मंत्री तो आते–जाते रहते हैं। मुझ से पहले जो थे वह क्या कम थे ?

श्री रामकिसन : यह जो आप कह रहे हैं कि पहले वाले क्या कम थे, तो यह क्या शक्ल सूरत के लिहाज से या काम के लिहाज से ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हर लिहाज से।

अब माननीय भैरोंसिंह जी ने जो कुछ कहा, मैं उनसे मिलता–जुलता रहता हूँ, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जितना भी मुमकिन होगा हम करेंगे। पुलों का निर्माण भी जरूरी है, सड़कों के लिये थोड़ा रुपया है, लेकिन जितना हो सकेगा हम करेंगे। यह सब पैसा राजस्थान का है, इस विधान सभा का है, और हम सही तरीके से ही खर्च करेंगे। आपकी राय हर वक्त हमारे सामने रहेगी यह आप यकीन जानकर चलें।

(७ म० प०)

श्री विजयसिंह रावत : आपके सामने सदस्यों ने मांगों पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं, कई मुद्दे उठाए हैं, मैंने भी एक प्रश्न उठाया था कि हमारे क्षेत्र में कान्क्रीट पड़ा हुआ है और बरबाद हो रहा है, पैसा लगाया है आपने सड़कें बनाने के लिए, तो उस पर आपने कोई प्रकाश नहीं डाला और केवल यह कहा कि नवाब साहब उस पर ध्यान देंगे। आप स्पष्ट रूप से उत्तर दें, इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना रा मेटीरियल इकट्ठा कर रक्खा है, यूटीलाइजेशन कैसे होगा ?

श्री लादूराम मुलानिया : उन्होंने कहा जहां घूमें हैं, देख लेंगे। आपकी नजर से घूम निकल जायगी। आपके देखने से घूम निकलने की नहीं हैं। आप कैसे निकालेंगे ? चकबाड़े की घूमें ३–४ बच्चे मर गये हैं। उसको निकलवा दें।

श्री आईदानसिंह : मैंने कहा था कि राजस्थान में जितकी सड़कें बनी हैं. योजनाबद्ध नहीं बनी हैं। मंत्री महोदय से जवाब नहीं बन रहा है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जिनको जवाब नहीं दिया गया है, उन सबको जवाब भेज दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : थोड़ी देर के लिये अगर उपमंत्री को अनुमति दी जाय बोलने की तो अच्छा रहेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : लिखित में जवाब कब तक आ जायेंगे और बोर्डर्स की सड़कें जो बरसों से पड़ी हुई हैं उनके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया। बीकानेर से छतरगढ के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। आपने बार–बार मुस्करा दिया, अदब से कह दिया और आप जवाब न दें ......। आप हंसी जानते हैं काम नही जानते हैं।

(शोरगुल)

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

हरियाना, पंजाब और बीकानेर से मिलने वाली सड़क कब तैयार होगी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जब पैसा आयगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पैसा है, काम नहीं करते। मुख्य मन्त्री भी वहां गए थे, सड़क पाकिस्तान की सीमा पर है। आप बनाना नहीं चाहते हैं हरियाना, पंजाब और बीकानेर की सड़क को नहीं मिलायेंगे। मैंने जो बातें कहीं थीं एक का भी जवाब नहीं दिया और भैरोंसिह और आप दोनों वादविवाद में पड़ गए जैसे कोई नाटक हो रहा है। आप बताइये बोर्डर पर क्या करना चाहते हैं ? आपने कह दिया बीकानेर से आपके पुराने ताल्लुकात हैं, इस तरह से हम चुन करने वाले मानते हैं कि ताल्लुकात होंगे लेकिन राजघराने से आपके ताल्लुकात हैं, जनता से नहीं। कितने दिनों में वह सड़क बना देंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हमारे पास टारगेट डेट्स मौजूद हैं बोर्डर रोड्स के लिए, हमारी पूरी कोशिश है कि उन टारगेट्स तारीखों के अन्दर पूरी हो जायं। इससे ज्यादा और क्या कोशिश की जा सकती है।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने कहा रा मटीरियल वहां पड़ा हुआ है और जो माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात रखते हैं, अगर आप नाटककर टालना चाहें, तो हम नहीं मानेंगे। जिन्होंने डिबेट में भाग लिया है और जिनको उत्तर नहीं मिला है उनको लिखित में उत्तर भेजेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कह दिया कि लिखित में उत्तर भेज दिए जायेंगे।

श्री विजयसिंह रावत : इस सदन का एक मिनट मूल्यवान् है, मंत्री अगर सदस्यों...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते... आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत : आपको हरेक सदस्य को सुनना पड़ेगा और लिखित में उत्तर देना पड़ेगा। नाटक और शेर कहने के लिए सदन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कह दिया कि सब कटौती प्रस्तावों के जवाब दिए जायेंगे।

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह रावत : मांगें पास करवाना चाहते हैं, तकरीर दे दी...

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल जाट : आपने चित्तौड़गढ़ जिले की उपेक्षा की है, आप आश्वासन देंगे कि जो राशि रखी गई है उनसे आप इन्कम्पलीट सड़कें बना देंगे ?

श्री आईदानसिंह : राजस्थान में जितना सड़कों का काम हो रहा है, वह योजनाबद्ध नहीं हो रहा है।

Page No. 187

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सब कटौती प्रस्तावों का जवाब भेजा जायगा ।

श्री विजयसिंह रावत : कटौती प्रस्ताव इसलिए देते हैं कि मांगें मंजूर करने से पहले हम चाहेंगे कि मंत्री महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजयसिंह रावत : हमें सख्त एतराज है (अश्रव्य)

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजयसिंह रावत : हम आसन से प्रोटेक्शन चाहेंगे । मंत्री इस तरह से बैठकर चुपचाप मजाक के तौर पर समय नष्ट करना चाहते हैं । जैसे सीरियल वाइज है वैसे लें...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री डूंगाराम : सीरियल वाइज...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानिया : हम चाहते थे...

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानिया : नियोजित ढंग से काम नहीं हो रहा है । हम जो बात कहें आप उसका उत्तर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन आपकी बात तब सुनेगा जब नियमानुसार काम करेंगे । स्थान ग्रहण करें । आसन अपने पैरों पर है, आप कोई चीज सुनते नहीं । कल व्यवस्था दी गई कि डिबेट का मतलब होता है दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात रख लें । उसके बाद मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, यह डिबेट के अन्दर कभी नहीं होता है । माननीय सदस्यों को करीब १५–२० का समय दिया गया । आप किसी मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकते कि जो आपने मांग की है वह उसे मन्जूर करे ही ।

श्री विजयसिंह रावत : सरकार को चाहिए तो वह एक दिन में एक मांग रखे, लेकिन एक-एक दिन में ४–४,५–५ मांगें विधान सभा में रखी जायं, बजट सेशन साल में एक बार होता है उसके बाद भी मंत्री उत्तर नहीं देना चाहें, आखिर क्या करना चाहते हैं ? सुखाड़ियाजी आप तय कर लें, आप उत्तर नहीं दिलाना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप पहली बार विधान सभा में आए हैं ।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने हाऊस आफ कामन्स देखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं । समय पर काम पूरा होना चाहिये । बहुत से माननीय सदस्य बराबर नियमों की और आसन के आदेशों की

(श्री उपाध्यक्ष)

अवहेलना करते हैं और आखिर में मजबूर होकर यह करना पड़ेगा कि मैं अब जो माननीय सदस्य बोलेंगे नाम से सम्बोधित करूंगा और बाद में उसका क्या हो सकता है नेसेसरी कान्सीक्वेन्सेज, उनको रियलाइज करना चाहिये ।

काफी समय ले लिया गया। काफी सदस्य बोलना चाहते थे, उनको समय दिया, उत्तर भी दिये। जानकारी चाही वह दी । जो पक्ष जैसी जानकनरी दे सकता था उस हिसाब से उसी तरह से दी । आप शायद उससे खुश नहीं हों यह अलग बात है । पर पार्लियामेन्टरी सिस्टम में अगर नियमों के अनुसार काम नहीं करेंगे तो सदन चल नहीं सकता । आपके लिए भी यह शोभा की बात नहीं होगी । हमारे लिए भी नहीं होगा । कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह : यह आपत्ति केवल इस बात की थी कि माननीय मन्त्री महोदय ने कई सदस्यो के तो नाम ले लिए। उनकी मुस्कराहट से भी वे खुश हो गए, कइयो की मुस्कराहट से वे खुश हो गये। कइयों के बारे में आवाजें भी दीं और कइयों के नाम ही लेना भूल गये । यह डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने किया यह आपत्ति जनक है ।

श्री हरिदेव जोशी : यह बात तो सही है । यह मन्जूर कर लेना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस मामले को यहीं समाप्त करिये।

श्रीमती गौरी पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, ११ बजे से अब सात बजने वाले हैं। आखिर समय की सीमा तो होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य तो जा भी सकते हैं । आसन की ओर देखिये ।

मांगों पर मतदान ।

श्री भैरोंसिंह : यहां पर तो रात के ११ बजे तक भी बैठक हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य, ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़क (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय ५२ सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२५६४-२०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

मांग स्वीकार की जाय । हां पक्ष जीता ?

श्री विजयसिंह रावत : ना पक्ष जीता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हाउस आफ कामन्स लागू कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिविजन क्लेम करते हैं ।

श्री लादूराम सुलानिया : जी हां ।

(डिविजन घंटी बजी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : आप यह मान लें। आप विधान सभा की बात करते हैं, यह हाउस आफ कामन्स की करते हैं।

श्री रामकिशन : हाउस आफ कामन्स ही नहीं देखा है। यू. एन. ओ. देखा जहां वीटो का अधिकार होता है। वहां बहुमत से ही फैसला हो यह जरूरी नहीं है। वीटो से भी होता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनको मुगालता है कि उनको वीटो का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य-भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय ५२-सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,५६,४२,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८९,१८,०००) रुपये तक की राशी प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही ७.१७ शनिवार दिनांक २३-३-६८ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्तगित हुई।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ की सूची)

प्रतिलिपि प्रस्ताव जो ग्राम पंचायत खारिया धन्नीराम की बैठक दिनांक १५-४ ६७ में सर्वसम्मति से पारित हुआ।

प्रस्ताव संख्या ७	निर्णय :—
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर ० खारिया कनीराम एवं उसके ० अधीनस्थ ग्राम न्यापा व ० स्थानापा में सिंचाई हेतु ० विद्युत् लगवाने पर विचार ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०	श्री मुलेसिंह उप सरपंच ने सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि अपनी पंचायत के पास ही के गांव शोमासर में बिजली की लाईन लग चुकी है। खंभे रोप दिये गये हैं व तार भी लगा दिये गये हैं।

सोमासर अपने पंचायत्त हैडक्वार्टर स्वास्थिा कनीराम से करीबन २ . २।। मील दूर तथा खारीया कनीराम से न्यापा शामिल व स्योनाय्या; ३ मील दूर है इसलिये अपने पंचायत क्षेत्र खारिया कनीराम के अधीनस्थ दोनों गांवों के लिए भी बिजली उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जावे तो ठीक ही है।

इस पर श्री कानाराम सरपंच ने बताया कि पंचायत क्षेत्र के ग्राम खारिया कनीराम ने इस समय लगभग ३ कुओं ग्राम न्यापा में १० कुओं तथा ग्राम रथानरा में कुआ है। जो चालू कृषि योग्य है। इसके अलावा बहुत से ग्रामवासी विद्युत आ जावे तो सभी कुएं चालू हो सकते हैं।

इस पर उपरोक्त प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए श्री लादू पंच ने बताया कि हमारे पंचायत क्षेत्र में लगातार ३ साल से अकाल पड़ रहा है। अनाज की बहुत कमी है किसानों के पास यहां पर अच्छी उपजाऊ जमीन भी है। लेकिन सिंचाई का कोई साधन नहीं होने के कारण जमीन का सही उपयोग नहीं हो रहा है अगर सिंचाई के साधन हो तो यही जमीन हरी भरी लहलाते खेतों में बदल सकती है ? तथा यहां से अनाज की पूर्ति के अलावा भी अनाज का उत्पादन हो सकता है। क्योंकि यहां का पानी मीठा है। जमीन उपजाऊ है। जिससे फी एकड़ लगभग ३५ से ४० मन अनाज उत्पन्न हो सकता

है । विद्युत आने से लोगों को काम मिल जायेगा । तथा अच्छी मजदूरी से रोजगार वृद्धि में जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा । एवं अकाल के कुचक्र से भी बचाव हो सकेगा ।

अतः वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पंचायत हैडक्वाटर खारिया कनीराम व उसके अधीनस्थ सभी ग्रामों में बिजली लगवाने हेतु सदस्यों ने एक मत से फैसला किया एवं निर्णय हुआ कि उसके लिए श्रीमान मुख्य अभियन्ता, सिंचाई व विद्युत् जयपुर राजस्थान व श्री सदानन्द वामन विश्वेश्वरकर सलाहकार विद्युत विभाग जयपुर एवं श्रीमान जिलाधीश महोदय चुरु को निवेदन किया जावे इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी संलग्न भेजी जाये । उपरोक्त निर्णय सर्व सम्मति से हुआ है ।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव उस प्रस्ताव की सही प्रतिलिपि है जो ग्राम पंचायत खारिया कनीराम पोस्ट खारिया वाया सूजानगढ़ जि० चुरु की बैठक १५-४-६७ में सर्व सम्मति से पारित हुआ एवं जो कार्यवाही रजिस्टर के पेज १५-१६ पर अंकित है ।

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ की सूची)

Under the Famine Relief Work an amount of Rs. 5.40 lacs was sanctioned for the following works :—

1. 33 kv Ahora Jalore line.	4.00 lacs.
2. Steip—up & Stop Dowin Sub—station and Construction of 11 kv line to cater the following pumping load :—	1.40 lacs.
	5.40 lacs.

(a) Leta
(b) Un (Ud)
(c) Tikhi.
(d) Guda Balotan.
(e) Sonapura
(f) Nawa Kheda
(g) Paharpura.
(h) Rawatra.
(i) Bagara.
(j) Mithri.

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या ७६० की सूची)

१६–२–५० से ३१–७–५८	प्राथमिक शाला कोशेलाव
१–८–५० से ३०–४–५१	,, चोहटन
१–५–५१ से ३१–१२–५४ तक	माध्यमिक शाला बाड़मेर
१–१–५५ से ३०–६–५५ तक	,, मारवाड जं०
१–७–५५ से ३०–४–५६ तक	एस० टी० सी० प्रशिक्षण उदयपुर
१–५–५६ से ३०–४–५७ तक	राज० प्राथमिक शाला, सुमेरपुर व पाली
१–१०–५७ से १९५८ तक	माध्यमिक शाला देसूरी
१९५९ से ३०–९–६० तक	पाली
१–१०–६० से ३०–९–६१ तक	उ० वि० सोजत सिटी
१–१०–६१ से १८–१२–६१ तक	माध्यमिक शाला राणावास
१९–१२–६१ से ७–८–६२ तक	शि० प्र० श्र० रायपुर
८–८–६२ से ४–९–६२ तक	छुट्टीपर
५–९–६२ से २४–८–६३ तक	शि० प्र० श्र० जायल
सितम्बर ६३ से १–३–६४ तक	उ० वि० तख्तगढ़
२–३–६४ से २०–३–६५ तक	राज० उ० वि० जैसलमेर
२१–८–६५ से ४–११–६५ तक	माध्यमिक शाला शेरगढ़
५–११–६५ से	अनुपस्थित है।

———

परिशिष्ट ४

(समय भाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्टेट लेवल को-ग्रारडोनेशन कमेटी की बैठकें

७६१. **श्री मेघराज पंवार (चुरू)**—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इन्डस्ट्रीज के प्रोगाम के सिलसिले में स्टेट लेवल को-ग्रोरडीनेशन कमेटी का गठन कब हुआ ग्रौर ग्रब तक इस कमेटी की कुल कितनी ग्रौर कब कब मीटिंगें हुई तथा ग्राखरी मीटिंग कब हुई ?

(२) इस कमेटी में कौन-कौन सदस्य है ? ग्रौर साथ ही मीटिंग वार सदस्यों की उपस्थिति बतलाने की कृपा करें ?

(३) मीटिंगों में क्या-क्या एजेन्डे रखे गये ग्रौर उन पर क्या क्या निर्णय लिये गये ? उन निर्णयों में से किनने कार्यान्वित किये गये ग्रौर कितने लैप्स हुए ? मीटिंग वार बतलाने की कृपा करें।

(सरकार द्वारा स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई।)

कृषि उपज मंडी समितियों के कर्मचारियों ग्रादि के वेतन का भुगतान

७६२. **श्री रामचन्द्र ग्रार्य (नोहर)**—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही हैं कि कृषि उपज मण्डी समितियों के सचिवों को एक साल से वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां तो कौन-कौन सी समितियों के सचिवों का वेतन रुका हुग्रा है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्रलवर, दौसा व किशनगढ़ कृषि उपज मण्डी समितियों के कर्मचारियों को जुलाई, १९६६ से ग्राज तक वेतन नहीं दिया है ? यदि हां तो क्यों ? ग्रौर यदि नहीं, तो वेनन कब, कौन सी तारीखों में दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि इस प्रकार की ग्रव्यवस्था हर कृषि उपज मण्डी समितियों के कर्मचारियों के साथ है ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ जिलों में ही कृषि उपज मण्डी समिति कायम की है ? यदि हां, तो कौन-कौन जिलों में समिति कायम हुई है ग्रौर समितिवार कुल कितने कर्मचारी हैं ?

(५) क्या यह सही है कि मण्डी समितियों के सचिवों व ग्रन्य कर्मचारियों को वेतन सरकार देती है ? यदि हां, तो कुल माहवारी कितना खर्चा है ? यदि नहीं, तो उन्हें वेतन कौन देता है ?

उत्तर

१—जी नहीं।

२—यह सवाल नहीं है।

३—जी नहीं।

(श्री कृषि मंत्री)

४–केवल जैसलमेर जिले को छोड़ते हुए शेष समस्त जिलों में मण्डी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं।

५–जी नहीं, मण्डी समिति कर्मचारियों को वेतन सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति अपने फन्ड में से देती है।

झालावाड़ जिले के वैद्यों के पेंशन आदि के मामले

७६३. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) ––क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६४ में आयुर्वेद विभाग जिला झालावाड़ में कितने वैद्यों का स्थान रिक्त हुआ है? इनमें कितने सेवा से अवकाश लेने के कारण व कितने स्वर्गवास होने के कारण रिक्त हुये? ये वैद्य कौन-कौन हैं?

(२) क्या यह सही है कि इनकी पैन्शन व फैमली पैन्शन ग्रेच्युटी आदि अब तक इन्हें मिली। यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

१–सन् १९६४ में आयुर्वेद विभाग झालावाड़ जिले में एक ही वैद्य श्री रघुनाथ शर्मा का दिनांक १५-१२-६४ को स्वर्गवास होने के कारण स्थान रिक्त हुआ है। सेवा निवृत्ति के कारण किसी भी वैद्य का उक्त जिले में स्थान रिक्त नहीं हुआ है।

(२) जी हां, स्वर्गीय वैद्य श्री रघुनन्दन शर्मा को अब तक पैन्शन, फैमली पैन्शन व ग्रेच्यूटी नहीं मिल सकी है। इसका कारण यह है कि वैद्य रघुनन्दन शर्मा की प्रथम नियुक्ति अधिक आयु में होने एवं मृत्यु पूर्व लम्बे अवकाश में रहने कारण उनकी आयु शैथिल्य की स्वीकृति प्रदान करने एवं अवकाश के नियम में समय लगा।

अब वैद्य रघुनन्दन शर्मा के परिवारिक पेन्शन के पत्रादि इस कार्यालय पत्रांक एफ २ (पेन्शन) ६८।१२७०-७२ दिनांक ५।२।४८ के द्वारा अन्तिम निर्णयार्थ महा लेखाकार कार्यालय राज०, जयपुर को प्रेषित किये जा चुके हैं।

ग्राम गुढावेरसल वास उग्रास में बिजली

७६४. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू)—क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील दूदू में ग्राम गुढावैरसल व उग्रास में बिजली के खम्बे लगाये जाकर तार आदि लग चुके हैं? अगर हां तो कितने समय में लगे हुए हैं?

(२) ग्राम गुढावैरसल व उग्रास के कितने कुओं पर बिजली लेने के फार्म भरे हैं? क्या जो फार्म भरकर किसानों ने मांग की है वह पूर्ण हो चुकी है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(३) उक्त ग्रामों में बिजली के खम्बे कब लगे थे?

उत्तर

(१) तहसील दूदू के ग्राम गुढा वैरसल

(श्री विद्युत् मंत्री)

व उगरिया वास में बिजली की ११ के. जी. की लाईन ता० २८-३-६७ को लगादी गई थी।

(२) ग्राम गुढा वैंरसल में २५ व ग्राम उगरियावास में १८ कूपकों को कुओं पर बिजली लगाने की मांग है। जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है क्योंकि गुढा वैंरसल के दि० १९-३-६८ को ही रकम जमा कराई है और ग्राम उगरियावास के कृषकों ने अभी तक रकम जमा नहीं कराई।

(३) ता० २८-३-६७ को ११ के. वी. लाईन लगाई थी।

डिग्री कालेज बूंदी का भवन

७६५. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बूंदी के डिग्री कालेज के उद्घाटन के कितने सालों के बाद इस के भवन का काम शुरु किया गया ?

(२) क्या इस कालेज के भवन का कार्य पूर्ण हो गया है ? अगर नहीं, तो इसमें कितना काम बाकी है ? और यह काम कब तक पूर्ण हो जायगा ?

(३) क्या यह सही है कि इमारत की दिवारों में व पी.यू.सी. के कमरों में दरारें पड़ गई हैं ?

(४) क्या सरकार द्वारा इस की जांच कराई गई कि दीवारों में दरारें पड़ने के क्या कारण हैं ?

(५) यह काम किस के ठेके में था और किस इंजीनियर के निरीक्षण में इस का काम हुआ था ?

उत्तर

१—दो वर्ष बाद।

२—जी नहीं, हाल, क्लास रुम ३, लैक्चर थीयेटर-२, म्यूजियम व नाल, स्टोर व लाइब्रेरी अभी अपूर्ण है। यह अपूर्ण कार्य आर्थिक सुविधा होने पर पूर्ण हो सकेगा।

३—यह सही है।

४—दीवारों में दरार नहीं पड़ी थी वरन छतों पर दरार पड़ना बताया जाता है। जांच की आवश्यकता इसलिये नहीं रही कि यह निर्माण विभाग द्वारा ठीक कर दी गई है,।

५—इस कार्य का ठेका श्री देश राज लाई के नाम था तथा यह कार्य एम०एम० स्वरूप माथुर अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में हुआ।

कर्मचारियों द्वारा दिए गये सुझाव

७६६. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या विभागों में मितव्ययता के लिये सरकार ने दिनांक १-४-६६ से सजेशन स्कीम शुरू की थी ? अगर हां, तो कितने कर्मचारियों ने अपने सुझाव सरकार के पास भेजे ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(२) क्या सरकार ने इसके लिये पारितोषिक देने का निर्णय लिया था ? अगर हां, तो किसे दिया गया ?

उत्तर.

(१) जी हां । अभी तक केवल १३ कर्मचारियों ने सरकार को सुझाव भेजे हैं ।

(२) इनमें से अधिकांश सुझाव पारितोषिक के योग्य नहीं पाये गये हैं तथा कुछ अभी विचाराधीन हैं । अतः किसी को भी पारितोषिक नहीं दिया गया है ।

नये रूट्स के लिए दरख्वास्तें

७६७. श्री दिग्विजसिंह (उनियारा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि १९६५-६६ व ६६-६७ व ६७-६८ में आर. टी. ओ. जयपुर, उदयपुर, जोधपुर द्वारा कोई नए रूट्स की दरख्वास्तें मांगी गई थीं ? यदि हां, तो कुल कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुईं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि सारी दरख्वास्तें नामंजूर कर दी गईं ? यदि हां, तो क्या कारण थे ? यदि नहीं, तो किस किस दरख्वास्त पर मंजूरियां दी गईं और किस किस रूट के लिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या यह सत्य है कि निगम को नए रूट्स पर बसें चलाने के लिए आर. टी. ओज. से मंजूरी लेनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या मंजूरी देते समय निगम को प्राथमिकता (प्रिफरेन्स) नहीं दी जाती है ?

उत्तर

१—यह सही नहीं । उक्त सालों में केवल प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदपुर, ने ही ऐसी दरख्वास्तें मांगी थीं । कुल १,०२९ दरख्वास्तें प्राप्त हुईं । जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । (सूची सं० १)

२—यह सत्य नही हैं । जो दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं (सूची २)

३—परमिट लेना पड़ता है ।
जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला सवाई माधोपुर में सबडिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल के पद पर पदोन्नति

७६८. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मई सन् ६७ से अब तक कितने अध्यायकों को जिला सवाई माधोपुर में सबडिप्टी इन्स्पैक्टर ऑफ स्कूल बनाया गया और किस किस तारीख को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

(२) उक्त पदोन्नति प्राप्त अध्यापकों की प्रथम नियुक्ति किस तारीख को हुई

(श्री हरिवल्लभ)

तथा वे किस ग्रेड के अध्यापकों में से थे ? उक्त सूची में समाविष्ट करने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही नही है कि इससे कई अध्यापकों की वरिष्ठता तथा योग्यता में विशेषता जैसे महत्पूर्ण मुद्दों पर आघात पहुंचा है और इस पदोन्नति से अध्यापक वर्ग को पूरी शिकायत है ?

(४) क्या राज्य सरकार इस विषय में कुछ करने का विचार रखती है ?

(५) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

१—मई सन् १९६७ से आज तक सवाई माधोपुर जिले में जिला प्रसार अधिकारियों (सब डिप्टी इन्स्पेक्टर्स) के पद पर १० नियुक्तियां हुई। तालिका संलग्न है। नियुक्ति की तिथियां तालिका में अंकित है।

२—संलग्न तालिका में अंकित है।

३—जिला प्रसार अधिकारी बनाने के लिये बी०एड० का प्रशिक्षण प्राप्त द्वितीय वेतन श्रृंखला में नियुक्त जिलें के अध्यापकों से आवेदन पत्र मांगे गये थे। जिन अध्यापकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये, उनमें से वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रसार अधिकारी बनाये गये। जिन प्रार्थी अध्यापकों का कार्य सन्तोषका जनक था उनमें से किसी की वरिष्ठता की अवहेलना नहीं की गई।

४—प्रश्न ही नहीं उठता।

५—प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागौर जिले के विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में बिजली पर व्यय

७६९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) निर्वाचन क्षेत्र डीडवाना में १५-११-६६ से लेकर १५-२-६७ तक विद्युत् बोर्ड से बिजली पर कितना रुपया खर्च किया गया ? तथा नागौर जिले के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में कितना खर्चा हुआ ?

(२) क्या यह खर्चा जिले के दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से ज्यादा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) जो कार्य उपरोक्त अवधि में शुरू किये थे वो पूर्ण कर दिये गये हैं या अधूरे ही बन्द कर दिये गये हैं ?

(४) उपरोक्त समय में नागौर जिले के विधान सभाईनिर्वाचन क्षेत्रों में कितने कितने गांवों को नये सिरे से बिजली दी गई है ?

(सरकार को ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अलवर में प्रधान वैद्य की नियुक्ति

७७०. श्री गंगा सहाय (कठूमर-सु.): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर

(श्री गंगासहाय)

प्रधान चिकित्सालय के वर्तमान प्रधान वैद्य की नियुक्ति सन् १९६२ में हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उनकी नियुक्ति के कुछ माह बाद ही उनको प्रमोशन दे दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य की सन् १९६५ में प्रधान वैद्य के पद पर पदोन्नति कर दी गई ?

(४) क्या यह सही है कि अलवर में उक्त वैद्य से अधिक शिक्षित तथा योग्यता प्राप्त वैद्य सन् १९४९ से कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

१– जी हां। उनकी नियुक्ति २४-२-६२ को हुई है।

२– जी हां।

३– जी हां, राजाज्ञा दि० ५-५-६५ को श्री नन्दवाना को सहायक विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर पदोन्नत किया गया और बाद में उनका परिवर्तन अलवर प्रधान वैद्य पर कर दिया। चूंकि दोनों पद की वेतन श्रृंखला सामानान्तर थी।

४– जी नहीं।

सरकार द्वारा संचालित होटलों पर व्यय

७७१. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन–सु०): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार द्वारा कौन कौन से होटल कहां कहां व कब कब से चलाये जा रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) किस किस होटल का कितना कितना वार्षिक व्यय है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या इन होटलों के संचालन आदि के लिये कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां तो कृपया उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(४) इन होटलों का ऑडिट कब कब हुआ है ? इनकी नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान सरकार द्वारा कोई होटल नहीं चलाये जा रहे हैं। किन्तु राजस्थान होटल निगम द्वारा निम्नांकित होटल उनके सामने अंकित तिथि से चलाये जा रहे हैं:–

(१) राजस्थान राज्य होटल, जयपुर	१–७–६५
(२) राजस्थान राज्य होटल, उदयपुर	१–७–६५
(३) राजस्थान राज्य होटल, सिलिसेढ़ (अलवर)	१–७–६५

(मुख्य मन्त्री)

(२) उपरोक्त होटलों पर वार्षिक व्यय निम्न है :-

	१९६५-६६	१९६६-६७
जयपुर	२,५५,६९९	४, ४०,९३४
उदयपुर	७१,७२४	१, १७,१०२
सिलिसेढ	४२,००७	७३,४८९

(३) जी हां। उपरोक्त होटलों के संचालन के लिए नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) उपरोक्त होटलों का ऑडिट १९६५-६६ व १९६६-६७ में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा हो चुका है। नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगानगर से हिन्दूमल कोट तक रेल्वे की बड़ी लाइन

७७२. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर से हिन्दूमल कोट तक बड़ी रेल्वे लाइन बिछाने के भारत सरकार के इरादे के सम्बन्ध में राज्य सरकार को क्या जानकारी है ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में कभी दिल्ली में रेल्वे मन्त्री से चर्चा हुई है ?

(३) गंगानगर जिले की जनता की ओर से उस रेल्वे लाइन के निकालने में जो आर्थिक सहयोग देने की बात थी क्या वह सहयोग मिल गया है ?

(४) यदि हां, यह लाइन कब तक बिछाकर तैयार हो जावेगी ?

(५) अब तक इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्य शुरू किया गया है ?

उत्तर

(१) हिन्दूमल कोट से गंगा नगर तक बड़ी रेल्वे लाईन बिछाई जा रही है।

(२) जी हां।

(३) इस रेल्वे लाइन को निकालने के लिये यह निश्चित हुआ था कि इसकी पटरी, रेल्वे स्टेशन व प्लेटफार्म तथा यार्ड आदि बनाने के लिए मिट्टी डालने का काम जनता द्वारा श्रमदान से किया जायेगा। इसके लिए जनता से ५,८७,०००)

(यातायत मन्त्री)

रुपये की धनराशि एकत्रित की गई।

(४) हिन्दूमल कोट से गंगानगर तक रेल्वे लाईन बिछा दी गई है, एवं पुल आदि भी बना दिये गये हैं।

(५) पटरी, स्टेशन, प्लेटफार्म व यार्ड की मिट्टी डलवाने का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। गंगानगर स्टेशन की बिल्डिंग के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी हैं।

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ की सूची)

STATEMENT OF CASH COLLECTION IN NATIONAL DEFENCE FUND/CHIEF MINISTER'S DEFENCE SERVICES WELFARE FUND FROM OCTOBER 1962 TO MAY 30, 1967.

S. No	Name of District	Cash
1.	Ganganagar	38,19,170.90
2.	Udaipur	27,23,086.00
3.	Jhunjhunu	20.34,767.46
4.	Bharatpur	18,59,897.91
5.	Swawai Madhopur	16,74,964.00
6.	Ajmer	14,42,670.75
7.	Jaipur	14,24,499.51
8.	Kota	13,58,699.51
9.	Bhilwara	13,29.167.56
10.	Jodhpur	12,85,479.35
11.	Chittorgarh	12,28,441.38
12.	Nagaur	12,27,301.54
13.	Alwar	12,09,219.45
14.	Jalore	9,42,728.29
15.	Bikaner	8,60,603.01
16.	Sikar	7,86,167.87
17.	Churu	6,89,713.26
18.	Pali	6,77,412.40
19.	Tonk	6,10,648.65

20.	Dungarpur	4,47,431.83
21.	Bundi	3,85,132.00
22.	Banswara	3,77,064.00
23.	Sirohi	3,59,921.00
24.	Jhalawar	3,20,483.59
25.	Barmer	2,94,277.90
26.	Jaisalmer	72,789.16
		2,94,41,738.28

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३५६ की सूची)

संख्या	आगार का नाम	दुर्घटनाओं की संख्या	मृत	नुकसान
१—	जयपुर	१६	४ आदमी	३८७५)
२—	अजमेर	२	दो आदमी दो बच्चे	२१२८)
३—	जोधपुर	१२	दो आदमी	२८०६–५४
४—	कोटा	६	३ आदमी	१३,४८५)
५—	आबूरोड़	४	१ आदमी	———
६—	अलवर	६	२ आदमी	१०)
७—	भरतपुर	८	दो आदमी एक बैल	६३००)
८—	सिरोही	१	——	१५०)
९—	उदयपुर	६	——	५०००)
		योग—६१	१६ आदमी दो बच्चे, एक बैल	३३,७५४–५४

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३७५ की सूची)

S. No.	Name of applicant	Kind of connection required.	Load.	Date of application.	Date of Demand note	Date of depositing money.	Reasons for not given connection.
1.	Balooram.	Agriculture.	12.5 H.P.	22.11.66	—	—	All the wells are more than $1\frac{1}{2}$ mile away from existing sub-station.
2.	Mali Ram.	—do—	5 H.P.	22.11.66	—	—	—do—
3.	Sawai Singh.	—do—	—dc—	25.11.66	—	—	—do—
4.	Ridmal Singh.	—do—	—do—	25.11.66	—	—	—do—

5.	Sawai Singh Ujainsingh.	—do—	—do—	25.11.66	—	—	—do—
6.	Kajormal Mali.	—do—	—do—	9-12.66	—	—	—do—
7.	Melaram Mali.	—do—	—do—	—do—	—	—	—do—
8.	Kanaram Mali.	—do—	—do—	—do—	—	—	—do—
9.	Laduram.	—do—	—do—	—do—	—	—	—do—
10.	Baluram.	—do—	—do—	—do—	—	—	—do—
11.	Mali Ram Swami.	—do—	—do—	—do—	—	—	—do—
12.	Guljarilal Swami.	—do—	—do—	—do—	—	—	—do—
13.	Mukharam.	—do—	—do—	—do—	—	—	—do—
14.	Baloo Ram.	Industrial	5 H.P.	26.9.67	—	—	—do—

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २२ मार्च, १९६८)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१	११—१२	श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न:	श्री उपाध्यक्षः प्रश्न ।
११	अन्तिम से ८	(श्री जयकिशन शर्मा	(श्री जयकिशन शर्मा):
११	,, ६	विद्यु तीकरण	विद्यु तिकरण
१२	,, २	,,	,,
१३	२,१४	,,	,,
१५	१८	आकर्षित	आमंत्रित
१६	१८	शैक्षिक	शैक्षणिक
२०	३,६,१४,१५	कुड	कूड
,,	१४	अइल	आइल
२१	२	कूड	कूड
२२	१५	ऊपर	अपर
,,	२४	केवल	(३) केवल
,,	२६	से	में
२३	१	रजिस्ट्र शन	रजिस्ट्रेशन
,,	अन्तिम से ८	मार्फत	मार्फत
३३	७	स्थात	स्थिति

१	२	३	४
३४	२	त्ववस्था	व्यवस्था
३६	१२	पदोन्नति	पदोन्नत
३७	शीर्षक	तार्राकित	तारांकित
३७	६	में	मैं
३८	११	डिर्स्क्रिशन	डिस्क्रिशन
,,	२१	स्ट्रीक्चर्स	स्ट्रिक्चर्स
३९	१८	डिवीजन	डिसौजन
४३	अन्तिम से १०	श्रो जयकृष्ण	श्री जयकृष्ण शर्मा
४४	११	आने से से	आने से
४८	१	श्री हह्दिव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
,,	अन्तिम से ११	जौशी	जोशी
,,	,, ७	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
४९	८	विजली	बिजली
५०	३	वद्य	वैद्य
५१	५	दैंद्य	,,
,,	९	(शेम शेम)	—
,,	२०,२१	फरमा	फर्मा
५२	अन्तिम से ३	(छाबड़ा)	(घबड़ा)
५३	अन्तिम	६,७	६—७
५४	१७	गये	गये
५९	शीर्ष	श्री हरदेव	श्री हरिदेव

१	२	३	४
६१	अन्तिम	परसीक्यूट	प्रोसीक्यूट
६३	१	इम	इस
,,	३,७,१५	निर्देशक	निदेशक
६४	६	डाइरक्टर	डाइरेक्टर
,,	१४	मालुम	मालूम
७६	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
६७	अन्तिम से ११	ट्रन्ड	ट्रेन्ड
१२३	६	तालुक	ताल्लुक
१२८	६	दल	दल की
१२६	शीर्षक	महादोवल	महारावल
१३०	१७	भता	भत्ता
१३२	अन्तिम से ११	सकता	सकती
१४०	,, १३	फेलो	लेली
१४२	७	(सालूम्बर)	(सलूम्बर)
१५६	अन्तिम से २	सूचना	—
१६१	,, ६	स्थान	स्थगन
१६६	१४	गावों	गांवों
१६६	७	उसके अनुसार	—
१७२	१०	किये जाने	किये जाने वाले
,,	१३	जावे	जावे
१७६	अन्तिम से १०	) ५०	(५०

१	२	३	४
१७८	,, ६	काल	कार्य
१८५	,, ६	कर	कम कर
,,	,, ४	अनुमोदन	अनुमोदक
१८७	१८	मेटन	मेंटल्ड
१९२	१०	शीषर्क	शीर्षक
४९५	अन्तिम से ८	हंसराज आर्य	श्री हंसराज आर्य
१९६	१३	सुवालाल चौधरी	श्री सुवालाल चौधरी
१९७	शीर्ष	,, ,,	,, ,,
१७८	२	केशरीसिंह	श्री केशरीसिंह
१९९	१	देवीलाल	श्री देवीलाल
२०४	अन्तिम से ४	सौडा	सोढा
२०५	शीर्ष	,,	,,
२०९ से ३७८	शीर्षक	अनुपुरक अनुदानों की मांगों पर विचार	अनुदानों की मागों पर विचार
२११	३	ानर्माण	निर्माण
२१७	५	बनवाने	बनवायें
,,	११	घाहता	चाहता
२१८	७	कुवार्टर्स	क्वार्टर्स
२१९	अन्तिम से १३	रूड्स	रूट्स
२२०	,, १५	क्यूबिके	क्युबिक
२२१	१४	शेड्ल	शिड्यूल

१	२	३	४
२२५	शीर्ष	—	(श्री मेघराज)
२२८	५	मोटा	कोटा
२५८	१०	रवर्गीय	स्वर्गीय
२६१	६	स्नानागार	स्नानागार
२६२	अन्तिम से ७	डकू	डाकू
२६६	३	लेते	लेता
,,	४	करावेंगे	करायेंगे
,,	११	इन्दालिया	इन्दलिया
,,	१७	महोदद	महोदय
२७०	अन्तिम से ११	गंगानर	गंगानगर
,,	,, ५	पहुंचाया जा सकता	पहुँचाई जा सकती
२७१	१२	बार्डर	बार्डर
२७३	८	ब ने	बनने
२७५	अन्तिम से ६	समवर्ती	सीमावर्ती
२७७	,, १२	स्थापित	स्थापित
,,	अन्तिम	बी आर	बी. आर
२८१	अन्तिम से १४	परसेंग्ट	परसेन्ट
२८३	१६	सरकर	सरकार
,,	१६	सीमबर्ती	सीमावर्ती
२८४	१५	अक्टूवर	अक्टूबर
,	अन्तिम से ७	आर्गेनाजेशत	आर्गेनाइजेशन

१	२	३	४
२८८	१	ज य	जाय
„	अन्तिम से ८	क म	काम
२६०	अन्तिम से ५	फिलसन	फिसलन
२६६	„ १३	कारवायी	करवायी
२६६	१०—११	आकडिंग	अकाडिंग
३०८	२	सन्पत्ति	सम्पत्ति
३०६	८	जेकिन	लेकिन
„	अन्तिम से २	जैतावरण	जैतारण
३१०	„ ७	महोदय	महोदया
३१२	„ ४	बागीदुरा	बागीडोरा
३१३	१५	जाह जाह	जगह जगह
३२३	१६	पर	को
३२४	१३	का	को
३३४	अन्तिम से ३	लालचन्द	लामचन्द
३४६	४	श्री अमीनुड्डीन	श्री अमीनुद्दीन
„	१६	श्री अमीनुद्दान	„
३४८	११	सुफल	संफल
३५०	२	करप्शन करप्शन	करप्शन
„	१४,१७	श्री अमीनुद्दीन	श्री अमीनुद्दीन
३५१	११२,१८,२७	„	„
„	अन्तिम से ३	दसरा	दूसरा

१	२	३	४
,,	,,	पाय	पाये
३५२	६	श्री मैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	८	इललिए	इसलिये
,,	११	श्रार्डर	श्रॉर्डर
,,	अन्तिम से ८	भाइ	भाई
३५३	१	कंमाण्उर	कमाण्डर
३५४	८	में	मैं
३५६	५	— श्रब	श्री श्रमीनुद्दीन : श्रब
,,	अन्तिम से ८	हसारा	हमारा
३५७	६	षड़ती	पड़ती
,,	अन्तिम से १०	तौ	तो
३५९	,, ७	—	में
३६२	२	बड़े	खड़े
,,	अन्तिम से ३	इसलिमे	इसलिये
३६४	२	बताय	बताया
,,	अन्तिम से ५	घोखा	धोखा
३६५	,, ६	घन	धन
३६६	९	श्रौर	श्रोर
,,	१७	लीये	लिये
,,	२३	जा	जायें
३६७	४	श्री गोपाल प्रसाद	श्री गोकुलप्रसाद

१	२	३	४
३६७	१३	श्री अमीनुद्दीन	श्री अमीनुद्दीन
३६८	३,७,१३,१६	,,	,,
,,	१०	ह	है
३६६	६	श्री रामकिसन	श्री रामकिशन
३७०	१४	जितकी	जितनी
३७१	१५	पूराने	पुराने
३७५	१७	होगा	होगी
३७६-३७८	शीर्षक	विचार	मतदान
३८३	२	समयभाव	समयाभाव
३८६	५	रहने —	रहने के
३८७	५	को	की
,,	अन्तिम से ५	दिवारों	दीवारों
३६१	,, ३	सन्तोषका	सन्तोष
३६६	८	चार्टड	चार्टर्ड

————